

समासामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए



विशेष आकर्षण

मई

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न



इसमें शामिल है:

- समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन
- समाचार में प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन
- मई माह में महत्वपूर्ण दिवस
- समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली
- समाचारों में चर्चित पुरस्कार

महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के आलेख

योगना	97
कुरुक्षेत्र	100
डाउन टू अर्थ	106
इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली	108
फ्रंटलाइन	25

*प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न

- भारत के निर्यात में वृद्धि
- सूर्य का उपसतही मौसम
- पहलगाम आतंकी हमला
- भारत में जातिगत जनगणना
- आरएनए-आधारित एंटीवायरल विकास
- दक्षिण कर्नाटक में हाथियों की जनगणना
- केंद्र द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव
- भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता: एक ऐतिहासिक सौदा
- बंगाल की खाड़ी में मानसून में बदलाव और समुद्री उत्पादकता

- आदि शंकराचार्य
- वायु रक्षा प्रणाली
- सहकारिता में महिलाएँ
- विश्व हृदय रिपोर्ट, 2025
- परिसीमन और गहराता संघवाद
- मानव विकास रिपोर्ट, 2025: यूएनडीपी
- एमएसएमई वित्त के भविष्य को दिशा देना
- भारत द्वारा विश्व की रचनात्मक क्रांति का नेतृत्व
- नालंदा विश्वविद्यालय, वैश्विक पुनरुत्थान के लिए तैयार

अनुक्रमणिका

राजव्यवस्था एवं शासन 1

भारत में जातिगत जनगणना	1
राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ	2
डिजिटल पहुंच, दिव्यांगों का मौलिक अधिकार- सर्वोच्च न्यायालय	3
क्या निर्विरोध चुनाव जीतना असंवैधानिक है?	5
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजों की संपत्ति सार्वजनिक की	6
भारत में मध्यस्थता	7
केन्द्र द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव	7
प्रतीक अधिनियम, 1950	8
लोकसभा उपाध्यक्ष	10
रॉड्रिक की राजनीतिक त्रिविधता	11

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 13

शिमला समझौता, 1972	13
सिंधु जल संधि (IWT)	13
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध: छाल वीजा मानदंडों पर प्रतिबंध	15
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता: एक ऐतिहासिक सौदा	16
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद	17
निष्पक्ष और समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली की ओर	19
बांडुंग सम्मेलन और वैश्विक दक्षिण	19
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी	21

अर्थव्यवस्था एवं कृषि 22

विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि	22
भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना	23
भारत के निर्यात में वृद्धि	24
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	25
डिजिटल बहिष्कार और भारत के अशिक्षित गरीबों की सुभेद्यता	25
बैंक इन डोमेन	26
ऑरेंज इकोनॉमी	28
पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था	29
प्रिडेटरी प्राइसिंग	30
विज्ञानजाम बंदरगाह	31

पर्यावरण एवं भूगोल 32

दक्षिण कर्नाटक में हाथियों की जनगणना	32
संरक्षण कानून और स्वदेशी अधिकारों के बीच संतुलन	34
बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलन	35
त्सराप चू संरक्षण रिजर्व	37
जलवायु वित्त वर्गीकरण	37
यूरोपीय रेड एडमिरल तितली (वैनैसा अटलांटा)	38

हिंदूकुश हिमालय (HKH) में बर्फबारी में कमी	39
बंगाल की खाड़ी में मानसून में बदलाव और समुद्री उत्पादकता	41
मूसा इंडैडामेनेसिस	41
साओला के जीनोम का मानचित्रण	42
शहरी मकड़ी	43
नदी प्रदूषण: मानव द्वारा एंटीबायोटिक का बढ़ता सेवन एक कारण	44

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 45

इसरो का सेमीक्रायोजेनिक इंजन परीक्षण	45
सूर्य का उपसतही मौसम	46
S8 तनाव	47
बुल्सआई आकाशगंगा	48
क्षुद्रग्रह 2024 YR4	48
आरएनए-आधारित एंटीवायरल विकास	49
जीनोम-संपादित चावल की किस्में	50
याक जीनोमिक विज्ञान	51
सेमाग्लुटाइड: भारत में मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन के लिए एक क्रांतिकारी उपचार ...	52
थैलेसीमिया	53
निपाह वायरस	54
2025 तक टीबी मुक्त भारत	55
रेबीज	56
प्राकृतिक हाइड्रोजन	57

रक्षा एवं सुरक्षा 59

पहलगाम आतंकी हमला	59
ऑपरेशन सिंदूर	60
वायु रक्षा प्रणाली	60
ड्रोन युद्ध	62
ब्रह्मोस मिसाइल	64
साइबर युद्ध	64
प्रादेशिक सेना	65
पेगासस स्पाइवेयर जांच	66

सामाजिक मुद्दे 68

डब्ल्यूएचओ ने ऐतिहासिक वैश्विक महामारी समझौते को अपनाया	68
गर्भधारण पूर्व स्वास्थ्य	69
भारत में किशोर मोटापे से निपटना	70
रिपोर्ट कार्ड 19: अप्रत्याशित विश्व में बच्चों की सेहत	71
किशोर स्वास्थ्य और कल्याण	72
सहकारिता में महिलाएँ	73

इतिहास और संस्कृति 75	'योजना' से महत्वपूर्ण आलेख (मई 2025) 97
नालंदा विश्वविद्यालय वैश्विक पुनरुत्थान के लिए तैयार 75	WAVES – वैश्विक मंच के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना 97
प्राकृतिक आपदा का एक दुर्लभ ऐतिहासिक रिकॉर्ड 76	भारत द्वारा विश्व की रचनात्मक क्रांति का नेतृत्व 98
अंतर्राष्ट्रीय वेसक दिवस 77	'कुरुक्षेत्र' से महत्वपूर्ण आलेख (मई 2025) 100
कांची कामकोटि पीठम 78	भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से एमएसएमई को सशक्त बनाना 100
सरस्वती पुष्करालु 78	एमएसएमई वित्त के भविष्य को दिशा देना 103
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन 79	'डाउन टू अर्थ' से महत्वपूर्ण आलेख (मई 2025) 106
सरकारी योजनाएं 81	उभरता संकट: जलवायु परिवर्तन किस तरह भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है 106
मनरेगा 2024–25 81	पहुंच और लाभ साझाकरण: केंद्र द्वारा जैव विविधता के उपयोग के लिए नए नियम ... 106
RoDTEP योजना 82	'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' से महत्वपूर्ण आलेख (मई 2025) 108
पीएम मित्र 83	परिसीमन और गहराता संघवाद 108
स्वामित्व योजना 84	जल्दी और अक्सर: गर्म लहरों पर ध्यान 109
उद्घान योजना 85	त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन) 110
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (SEED)..... 86	मई माह के महत्वपूर्ण दिवस 110
महत्वपूर्ण रिपोर्ट 87	समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 111
भारत की जन्म दर में गिरावट 87	समाचारों में चर्चित पुरस्कार 112
WESP 2025: मध्य-वर्षीय अद्यतन 88	समाचार में महत्वपूर्ण शब्दावली 112
मानव विकास रिपोर्ट, 2025: यूएनडीपी 89	समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन 113
भारत न्याय रिपोर्ट 2025 90	मई 2025 'द हिंदू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न 114
विश्व हृदय रिपोर्ट, 2025 92	दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न 114
समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व 93	उत्तर कुंजी 128
आदि शंकराचार्य 93	दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न 128
राजा रवि वर्मा 94	
राजे रघुजी भोसले प्रथम 95	
महाराणा प्रताप 96	
डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद 96	

भारत में जातिगत जनगणना

चर्चा में क्यों: यह लेख द हिन्दू समाचार पत्र में प्रकाशित संपादकीय से ली गई जानकारी पर आधारित है।

परिचय

- कई दशकों से, जनगणना के आंकड़े भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण का आधार रहे हैं। इसने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की है। हालाँकि, आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की सरकार की हाल की घोषणा ने व्यापक बहस और ध्यान आकर्षित किया है।
- कई लोगों के लिए, यह निर्णय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बारे में विश्वसनीय सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने की दिशा में एक लंबे समय से लंबित कदम का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन साथ ही, इस बात को लेकर भी चिंताएँ हैं कि जाति के आंकड़ों पर यह ध्यान वास्तव में कल्याण के लिए है या केवल एक राजनीतिक उपकरण है। कई लोगों को चिंता है कि बेहतर डेटा की प्रतीक्षा के बहाने हाशिप पर पड़े समुदायों के लिए कल्याणकारी नीतियों में अनावश्यक रूप से देरी की गई है।

जातिगत जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

- जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि इससे भारत में विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की सटीक, तथ्य-आधारित तस्वीर मिलेगी। यह डेटा बेहतर लक्षित सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को डिजाइन करने में मदद कर सकता है और कल्याणकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता के बारे में अदालतों और नीति निर्माताओं को समझाने के लिए साक्ष्य प्रदान कर सकता है।
- एक और महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि डेटा ओबीसी श्रेणी के भीतर असमानताओं को दिखा सकता है। इससे विशेष रूप से वंचित समूहों, जैसे अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) की पहचान करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि नीतियाँ सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचें।
- हालाँकि इन तर्कों में दम है, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि जातिगत जनगणना अकेले गहरी जड़ें जमाएँ बैठी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को हल नहीं कर सकती। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जाति के डेटा को निश्चित रूप से नियमित रूप से एकत्र किया जाना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जनगणना को सबसे महत्वपूर्ण उपकरण मानना इसके वास्तविक उद्देश्य को गलत समझना होगा।
- भारत के महापंजीयक (आरजीआई) का कार्य तटस्थ, तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करना है, न कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों का सुझाव देना या निर्देश देना। जनगणना को राजनीतिक सुधारों के साधन में बदलने से इस संस्था पर अनुचित बोझ पड़ता है और इसके काम का राजनीतिकरण होने का जोखिम होता है। राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत देश में, जनगणना कार्यों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

क्या भारत में सार्वजनिक नीति हमेशा डेटा का इंतज़ार करती रही है?

- ऐतिहासिक रूप से, भारत की प्रमुख सामाजिक न्याय नीतियों ने कभी भी सही डेटा का इंतज़ार नहीं किया है। चाहे वह अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण हो, भूमि सुधार हो या मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन हो - ये कार्य विस्तृत सांख्यिकीय रिपोर्टों से नहीं, बल्कि राजनीतिक आंदोलनों, सार्वजनिक दबाव और नैतिक ज़िम्मेदारी से प्रेरित थे।
- हाल के नीतिगत फैसलों में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण मोदी सरकार द्वारा बिना किसी विस्तृत राष्ट्रीय-स्तर के डेटा या आयोग की रिपोर्ट के पेश किया गया था। यह दर्शाता है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है, तो सरकार व्यापक डेटा के साथ या उसके बिना भी काम कर सकती है।

जाति-आधारित असमानता पर मौजूदा डेटा

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जाति-आधारित असमानताओं पर पहले से ही बहुत सारे डेटा मौजूद हैं। स्वतंत्रता के बाद से, जनगणना अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) पर डेटा एकत्र कर रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस) जैसे अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षणों ने नियमित रूप से दिखाया है कि इन समुदायों को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने लगातार एससी और एसटी के खिलाफ उच्च स्तर के अपराधों की रिपोर्ट की है, जिसमें यौन हिंसा से लेकर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अत्याचार शामिल हैं।
- इसके अलावा, बिहार जाति सर्वेक्षण और पहले की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) जैसी हालिया रिपोर्टों ने ओबीसी श्रेणी के भीतर आर्थिक भेद्यता और विविधता को स्पष्ट रूप से दिखाया है। ये सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक, असुरक्षित और कम आय वाली नौकरियों में काम करता है, जिसमें बहुत कम सामाजिक सुरक्षा है।
- मौजूदा आंकड़ों की इस संपदा के बावजूद, ओबीसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साहसिक नीतिगत सुधार नहीं किए गए हैं। निजी अर्थव्यवस्था (कॉरपोरेट, आईटी, मीडिया) जैसे क्षेत्रों में एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित है। यहां तक कि उच्च शिक्षा, न्यायपालिका और शीर्ष नौकरशाही जैसे राज्य संचालित संस्थानों में भी इन समूहों का प्रतिनिधित्व खराब है।
- जनगणना का राजनीतिकरण करने का जोखिम
- जाति जनगणना को बहुत अधिक महत्व देने का एक बड़ा जोखिम यह है कि यह एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय अभ्यास का राजनीतिकरण कर सकता है। जनगणना का उद्देश्य एक तटस्थ, तथ्य-खोज अभियान होना है - न कि एक राजनीतिक हथियार। आज के ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में, जनगणना के आंकड़ों की निष्पक्षता को बरकरार रखना महत्वपूर्ण है।
- इसके अलावा, हाशिप पर पड़े समूहों के लिए कल्याणकारी नीतियों में सिर्फ इसलिए देरी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि नए डेटा का इंतज़ार है। सरकारों को उपलब्ध साक्ष्य, पिछली रिपोर्ट और जनता की आवश्यकताओं के आधार पर काम करना चाहिए।

- सामाजिक न्याय के लिए सिर्फ डेटा की नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है।
- भारत के इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक यह है कि सिर्फ डेटा ही सार्वजनिक नीति को नहीं चलाता। असली चालक राजनीतिक इच्छाशक्ति, लोगों के आंदोलन और लोकतांत्रिक दबाव हैं। जातिगत जनगणना निश्चित रूप से बेहतर जानकारी प्रदान कर सकती है, लेकिन यह अपने आप न्याय नहीं ला सकती।
- जैसा कि कहा जाता है, डेटा एक नक्शे की तरह है - यह सड़क दिखाता है, लेकिन यह आपके लिए रास्ता नहीं बना सकता। अगर भारत एक निष्पक्ष और अधिक समान समाज बनना चाहता है, तो ध्यान इसके शासक वर्ग के इरादे और साहस पर होना चाहिए। वर्तमान सरकार के लिए असली परीक्षा जाति के आंकड़े एकत्र करने में नहीं बल्कि सबसे वंचित समूहों के कल्याण के लिए साहसिक, ईमानदार नीतिगत कदम उठाने में है।

निष्कर्ष

- जातिगत जनगणना की घोषणा ने उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। यह नीति निर्माण के लिए उपयोगी होगी - लेकिन तभी जब इसे सावधानी, निष्पक्षता और ईमानदारी से संभाला जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेटा निष्क्रियता का बहाना नहीं बनना चाहिए। भारत में जाति आधारित असमानता के पहले से ही पर्याप्त सबूत हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए राजनीतिक साहस और सामाजिक प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता है। भारत की सामाजिक न्याय परियोजना का भविष्य स्प्रेडशीट और ग्राफ़ पर नहीं बल्कि इसके नेताओं की नैतिक कल्पना और इसके लोगो की लोकतांत्रिक इच्छा पर निर्भर करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत की कल्याणकारी नीति निर्माण के संदर्भ में, जाति-आधारित जनगणना के महत्व की आलोचनात्मक जांच करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना अकेले डेटा सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं दे सकता है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें। [250 शब्द | 15 अंक]

राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ

चर्चा में क्यों: एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया है।

नोट: यह संदर्भ कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय की राय चाहता है, विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने के दौरान राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या है?

अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की बुद्धिमता के माध्यम से कानून और सार्वजनिक महत्व के जटिल मामलों को स्पष्ट करने के लिए संविधान के तंत्र का हिस्सा है।

दो प्रकार के संदर्भ संभव हैं:

- **अनुच्छेद 143(1):** जब सार्वजनिक महत्व का कोई कानून या तथ्य का प्रश्न उठता है, तो राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकते हैं।

- **अनुच्छेद 143(2):** जब संविधान-पूर्व संधियों, समझौतों या व्यवस्थाओं से संबंधित कोई प्रश्न उठता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें मजबूत प्रेरक मूल्य होता है और आमतौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों द्वारा इसका सम्मान किया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सर्वोच्च न्यायालय के लिए सलाहकार क्षेत्राधिकार की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से उत्पन्न हुई। इस अधिनियम के तहत, गवर्नर-जनरल कानूनी मामलों को संघीय न्यायालय को संदर्भित कर सकता था।

अन्य देशों में भी इसी तरह का प्रावधान मौजूद है:

- **कनाडा:** कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय सरकार को सलाहकार राय प्रदान करता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** हालांकि, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सख्ती से पालन करते हुए सलाहकार राय देने से इनकार करता है।

भारत ने संवैधानिक संतुलन बनाए रखने और न्यायिक विवेक की आवश्यकता वाले जटिल मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत इस प्रावधान को बरकरार रखा।

राष्ट्रपति के संदर्भ को नियंत्रित करने वाले प्रावधान

- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर संदर्भ दे सकते हैं।
- अनुच्छेद 145 के अनुसार, मामले की सुनवाई कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी है।
- यदि सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्न अस्पष्ट या अनुचित लगते हैं तो वह उत्तर देने से मना कर सकता है।
- न्यायालय की राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें पर्याप्त नैतिक और प्रेरक अधिकार होता है।

उल्लेखनीय विगत संदर्भ

1950 से अब तक लगभग 15 ऐसे संदर्भ दिए जा चुके हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ इस प्रकार हैं:

- **दिल्ली कानून अधिनियम मामला (1951):** प्रत्यायोजित विधान के दायरे को परिभाषित किया गया - संसद द्वारा कार्यपालिका को कितनी कानून बनाने की शक्ति सौंपी जा सकती है।
- **केरल शिक्षा विधेयक (1958):** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ मौलिक अधिकारों को संतुलित किया गया, और अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया।
- **बेरुबाडी यूनियन मामला (1960):** स्पष्ट किया गया कि भारतीय क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है।
- **केशव सिंह मामला (1965):** विधायिकाओं की शक्तियों और विशेषाधिकारों की व्याख्या की गई।
- **राष्ट्रपति चुनाव मामला (1974):** निर्णय लिया गया कि राज्य विधानसभाओं में रिक्तियां होने पर भी राष्ट्रपति चुनाव होने चाहिए।
- **विशेष न्यायालय विधेयक (1978):** यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि:
 - सर्वोच्च न्यायालय किसी संदर्भ का उत्तर देने से इंकार कर सकता है।

- प्रश्न विशिष्ट और स्पष्ट होने चाहिए।
 - न्यायालय को संसदीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
 - **तृतीय न्यायाधीश मामला (1998):** उच्च न्यायापालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
- दिलचस्प बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल एक बार, 1993 में, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर अपनी राय देने से इनकार कर दिया था।

वर्तमान राष्ट्रपति संदर्भ

- नवीनतम संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद सामने आया है, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई थी। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं।
- इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने न्यायालय की राय मांगते हुए 14 कानूनी प्रश्न उठाए हैं। मुख्य मुद्दों में शामिल हैं:
 - क्या न्यायालय राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकते हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई समयसीमा मौजूद नहीं है।
 - क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के लंबित विधेयकों पर निर्णयों को विधेयक के कानून बनने से पहले न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है।
 - अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा, जो न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने की अनुमति देती है।
- यह संदर्भ विधायी प्रक्रियाओं में राज्यपाल की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष शासित राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट और आधिकारिक राय:

- राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका के इर्द-गिर्द संवैधानिक अस्पष्टताओं को हल करने में मदद कर सकती है।
- विधायी प्रक्रियाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट कर सकती है।
- लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांतों को मजबूत कर सकती है।
- ऐसे राजनीतिक विवादों का निपटारा कर सकती है जो भारत की संवैधानिक प्रणाली के सुचारू संचालन को कमजोर करने का जोखिम उठाते हैं।

यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण संदर्भ (1992) में न्यायालय के पिछले रुख को भी प्रतिध्वनित कर सकता है, जहाँ उसने कहा था कि वह अपनी सलाहकार क्षमता में पिछले निर्णयों पर अपील नहीं कर सकता है।

निष्कर्ष

- अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संवेदनशील कानूनी प्रश्नों पर कार्यपालिका को मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका प्रेरक अधिकार देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य विधायी प्रक्रियाओं में राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा वर्तमान संदर्भ, सर्वोच्च न्यायालय के लिए संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि करने और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में ग्रे क्षेत्रों को स्पष्ट करने का एक अवसर है। जैसे-जैसे भारत का लोकतंत्र परिपक्व होता है, इस तरह के तंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि जटिल विवादों को संवैधानिक ढांचे के भीतर संबोधित किया जाए - एक स्वस्थ, कार्यशील गणराज्य का संकेत।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार ने संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करने और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में कानूनी अस्पष्टताओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के संदर्भों के ऐतिहासिक विकास, प्रमुख उदाहरणों और समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा करें। [250 शब्द | 15 अंक]

डिजिटल पहुँच, दिव्यांगों का मौलिक अधिकार- सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों: समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में देश की डिजिटल अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs), विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाना है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल सेवाओं तक पहुँच अब वित्तीय, संचार और कल्याण सेवाओं तक पहुँच से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर ये डिजिटल प्रक्रियाएँ लोगों को उनकी दिव्यांगता के कारण बाहर रखती हैं, तो यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बन जाता है।

कौन से कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं?

भारत में संवैधानिक गारंटी और समर्पित दिव्यांगता कानून दोनों हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

- संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत समानता, सम्मान और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करते हैं।
- भारत, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के पूर्ण समावेश का आह्वान करता है।
- इसके आधार पर, भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 पारित किया, जो एक 'सामाजिक-बाधा' दृष्टिकोण को अपनाता है। इसका तात्पर्य है कि दिव्यांगता केवल दिव्यांगता के बारे में नहीं है, बल्कि शारीरिक, सामाजिक और संस्थागत बाधाओं के बारे में भी है जो समाज में पूर्ण भागीदारी को रोकती हैं।
- RPwD अधिनियम की धारा 42 में कहा गया है कि सभी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को सुलभ बनाया जाना चाहिए। इसमें स्क्रीन-रीडर, सांकेतिक भाषा, ऑडियो विवरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सार्वभौमिक डिज़ाइन शामिल हैं।

केवाईसी क्या है और यह अनिवार्य क्यों है?

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए करते हैं। धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत यह अनिवार्य है।

केवाईसी निम्नलिखित तक पहुँचने के लिए आवश्यक है:

- बैंक खाते
- सिम कार्ड

- बीमा
- पेंशन योजनाएँ
- डीमैट या ट्रेडिंग खाते
- आधार-आधारित सरकारी लाभ जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और छालवृत्ति

केवाईसी को सरल बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2016 में वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) शुरू की। इससे ग्राहक अपनी पहचान को दूर से ही सत्यापित कर सकते हैं:

- सेल्फी क्लिक करके
- फॉर्म पर हस्ताक्षर करके (डिजिटल या कागज़ पर)
- 30 सेकंड में ओटीपी सत्यापित करके
- स्क्रीन पर दिखाए गए कोड को पढ़कर
- स्कैन किए गए आईडी दस्तावेज़ अपलोड करके

दिव्यांगों के लिए समस्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं?

डिजिटल सुविधा के लिए जोर दिए जाने के बावजूद, दिव्यांग व्यक्तियों - विशेष रूप से दृष्टिबाधित या चेहरे की विकृति वाले व्यक्तियों - को वर्तमान डिजिटल केवाईसी नियमों के तहत गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **दुर्गम सत्यापन विधियाँ:**
 - सिस्टम में अक्सर उपयोगकर्ताओं को फ्लैशिंग कोड पढ़ने, प्रतिक्रियाएँ लिखने या अपनी आँखें झपकाने की आवश्यकता होती है ताकि यह साबित हो सके कि वे बॉट नहीं हैं।
 - ऐसी विधियाँ स्वचालित रूप से दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं या चेहरे की विकृति वाले लोगों (जैसे, एसिड अटैक सर्वाइवर) को बाहर कर देती हैं।
- **कोई सहायक सुविधाएँ नहीं:**
 - कई केवाईसी प्लेटफॉर्म और ऐप पढ़ेंच मानकों का पालन नहीं करते हैं।
 - इसमें स्क्रीन-रीडर सपोर्ट नहीं होता है, कैमरे को संरेखित करने में मदद के लिए कोई आवाज सहायता नहीं होती है, तथा प्रकाश या फोकस के लिए कोई ऑडियो संकेत भी नहीं होता है।
 - इससे दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया को पूरा करना लगभग असंभव हो जाता है।
- **बायोमेट्रिक बहिष्कार:**
 - अंगूठे के निशान, जो दृष्टिबाधित लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, वर्तमान केवाईसी प्रणाली में स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
 - आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन में टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे उपयोगकर्ताओं को मदद लेने या शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है - जो दूरस्थ केवाईसी के उद्देश्य को विफल करता है।
- **कोई मानवीय सहायता नहीं:**
 - आरबीआई के नियम केवाईसी वीडियो कॉल के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता को प्रतिबंधित करते हैं।
 - बिना "संकेत" के, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को मदद के बिना छोड़ दिया जाता है और अक्सर अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कदम उठाया। 30 अप्रैल, 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में, न्यायालय ने कहा कि 'डिजिटल एक्सेस' संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

विवरण

- **संवैधानिक अधिकार के रूप में सुलभता की पुष्टि की:** न्यायालय ने 2024 के राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ मामले सहित पहले के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें उसने फैसला सुनाया था कि गरिमा और आवागमन की स्वतंत्रता के लिए सुलभता आवश्यक है।
- **कहा कि डिजिटल बहिष्कार अधिकारों के उल्लंघन के बराबर है:** इसने नोट किया कि डिजिटल केवाईसी बाधाएँ यूपीआईआरपीडी और भारत के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का उल्लंघन करती हैं, जो समान पहुंच की मांग करते हैं।
- **'मौलिक समानता' का आह्वान किया:** निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि समान व्यवहार पर्याप्त नहीं है - जो आवश्यक है वह उचित समायोजन है जो सच्ची भागीदारी को सक्षम बनाता है।
- **समावेशी केवाईसी सुधारों का निर्देश:** आरबीआई और सेबी तथा दूरसंचार विभाग जैसी अन्य नियामक संस्थाओं को सुलभता को केंद्र में रखते हुए अपने केवाईसी दिशानिर्देशों को संशोधित करना चाहिए।

डिजिटल पहुंच से और कौन प्रभावित है?

यद्यपि न्यायालय के फैसले में दिव्यांग व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसने यह भी उजागर किया कि डिजिटल विभाजन अन्य संवेदनशील समूहों को कैसे हानि पहुंचाता है, जैसे:

- ग्रामीण आबादी
- वरिष्ठ नागरिक
- कम आय वाले लोग
- भाषाई अल्पसंख्यक

वे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करते हैं, और न्यायालय ने सरकार को सभी के लिए समावेशी डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाने के अपने कर्तव्य की याद दिलाई।

क्या बदलने की आवश्यकता है?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे न छूटे, निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

- सभी डिजिटल वित्तीय ऐप और प्लेटफॉर्म में आईसीटी पहुंच मानकों को लागू करना।
- आवाज़-आधारित पहचान, अंगूठे के निशान और मानव सहायता जैसी वैकल्पिक सत्यापन विधियों की अनुमति देना।
- स्क्रीन-रीडर और अन्य सहायक तकनीकों के साथ संगतता सुनिश्चित करते हुए सार्वभौमिक डिज़ाइन के साथ केवाईसी ऐप डिज़ाइन करना।
- PwD की आवश्यकताओं को समझने और उनका समर्थन करने के लिए बैंक कर्मचारियों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत में डिजिटल अधिकारों और दिव्यांगता समावेशन के लिए एक बड़ी जीत है। यह एक शक्तिशाली संदेश देता है कि प्रौद्योगिकी को लोगों को सशक्त बनाना चाहिए - न कि उन्हें बाहर करना चाहिए। जैसे-जैसे भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, सुलभता सुनिश्चित करना केवल एक कानूनी आवश्यकता नहीं है - यह एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व है।

आइए आशा करते हैं कि यह निर्णय एक अधिक समावेशी डिजिटल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा, जहाँ हर नागरिक - क्षमता की परवाह किए बिना - पूरी तरह से भाग ले सकता है और लाभ उठा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिनियम दिव्यांगता को परिभाषित करने के लिए विशुद्ध रूप से चिकित्सा मॉडल को अपनाता है।
2. यह अनिवार्य करता है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जाए।
3. भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) को प्रभावी करने के लिए RPwD अधिनियम बनाया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(9) : 255

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. डिजिटल समावेशन एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है।” दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं को सुलभ बनाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, भारत में वास्तविक समानता को बढ़ावा देने में डिजिटल सुलभता के महत्व पर चर्चा कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

क्या निर्विरोध चुनाव जीतना असंवैधानिक है?

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने जानना चाहा कि क्या चुनाव कानून में यह निर्धारित किया जा सकता है कि एक ही उम्मीदवार होने पर भी उसे निर्वाचित घोषित करने के लिए एक निश्चित प्रतिशत वोट अनिवार्य है।

याचिका और तर्क

- न्यायालय विधि अनुसंधान थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लोक सभा और विधानसभा चुनावों के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(2) की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था।
- **नोटा का उल्लंघन:** अगस्त 2024 में दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि एक ही उम्मीदवार के मामले में चुनाव न कराने से मतदाता उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) विकल्प चुनने से वंचित हो जाते हैं, जो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
- याचिका में पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनिन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने माना था कि नोटा चुनकर नकारात्मक वोट देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्यक्ष चुनावों में संरक्षित है।

निर्विरोध चुनाव

- याचिका में कहा गया है कि 1951 से 2024 के बीच 26 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा के लिए उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, इन वर्षों के लिए भारतीय चुनाव आयोगकी सांख्यिकीय रिपोर्टों का हवाला देते हुए।
- इन चुनावों में 82 लाख से अधिक मतदाताओं को अपना वोट डालने के अवसर से वंचित किया गया था।
- इन 26 निर्विरोध चुनावों में से सात 1957 के लोकसभा चुनाव के दौरान, 1951 और 1967 के चुनावों में पाँच-पाँच, 1962 में तीन, 1977 में दो और 1971, 1980, 1989 और 2024 के चुनावों में एक-एक चुनाव हुए।
- पिछले साल सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश कुमार दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था, क्योंकि अन्य सभी उम्मीदवार या तो चुनाव हार गए थे या उनके नामांकन खारिज कर दिए गए थे।

भारतीय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

- चुनाव आयोग ने बताया कि 1951 से 2024 तक हुए 20 लोकसभा चुनावों में से केवल नौ में सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और 1989 के बाद से तीन दशकों से अधिक समय में केवल एक उम्मीदवार निर्विरोध लोकसभा में प्रवेश कर पाया है।
- आयोग ने तर्क दिया कि यह नहीं माना जा सकता कि 'नोटा' हर चुनाव में स्वतः ही शामिल हो गया है।
- इसने न्यायालय के नोटा संबंधी निर्णय का हवाला दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में एक बटन जोड़ा जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को विकल्प दिया जा सके जो चुनाव मैदान में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं।
- ईसीआई के अनुसार, नोटा विकल्प का प्रयोग तब किया जा सकता है जब मतदान हो रहा हो, जहाँ मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर आते हैं।
- इसलिए, सभी प्रत्यक्ष निर्विरोध चुनावों में नोटा को अनिवार्य रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में मानना कानून में जगह नहीं पाता है, और इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों में विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण और सुझाव

- सर्वोच्च न्यायालय निर्विरोध चुनाव जीत की संवैधानिकता की जांच कर रहा है, खास तौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संदर्भ में।
- **प्रस्तावित न्यूनतम वोट शेयर:** न्यायालय ने सुझाव दिया कि भले ही केवल एक ही उम्मीदवार हो, उन्हें स्वचालित रूप से जीतने के बजाय, निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए निर्धारित न्यूनतम वोट शेयर (जैसे 10%, 15%) प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए।
- **लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखना:** न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए न्यूनतम वोट शेयर यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम कुछ मतदाता जो आपको पसंद करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व हो, यहां तक कि डिफॉल्ट चुनाव में भी।
- **प्रगतिशील सुधार:** न्यायालय इसे एक बहुत ही स्वागत योग्य और प्रगतिशील कदम और एक बहुत अच्छा सुधार मानता है जिससे कोई असुविधा नहीं होगी।
- **विधायी कार्यवाई का आह्वान:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस प्रश्न की जांच करने और इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ अधिनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है कि संसद के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित हथियार पर निर्णय लेने का विवेक है कि कोई उम्मीदवार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। न्यायमूर्ति कांत ने स्पष्ट किया कि न्यायालय मौजूदा कानून को खत्म करने पर विचार नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार पर इसमें एक प्रावधान जोड़ने का दबाव बना रहा है।

- **बहुदलीय संस्कृति को बढ़ावा देना:** न्यायालय का मानना है कि इस तरह के उपाय से निर्वाचन क्षेत्र के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और बहुदलीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है और जुलाई 2025 में मामले की फिर से सुनवाई करेगा। न्यायालय ने स्वीकार किया कि इस तरह के सुधार के लिए और अधिक विचार-विमर्श आवश्यक होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निर्विरोध चुनावों को चुनौती देने के पीछे कौन से कानूनी और संवैधानिक तर्क हैं? चर्चा करें कि चुनावी प्रतिस्पर्धा की कमी लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मतदाता अधिकारों को कैसे प्रभावित करती है। [250 शब्द] [15 अंक]

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजों की संपत्ति सार्वजनिक की

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अब जजों द्वारा संपत्ति की घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया है।

मुख्य विवरण

- दिल्ली उच्च न्यायालय के जज के घर पर बड़ी मात्रा में धन मिलने के बाद, जिसने संपत्ति के खुलासे पर बहस को फिर से हवा दे दी, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला किया कि उसके सभी जज अपनी संपत्ति को CJI के समक्ष सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे, ताकि उसे न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सके।
- सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2025 को फैसला सुनाया कि जजों को पदभार ग्रहण करने पर और उसके बाद जब भी वे कोई महत्वपूर्ण खरीददारी करें, तो अपनी संपत्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष घोषित करना चाहिए।
- निर्वाचित अधिकारियों और लोक सेवकों के विपरीत, न्यायिक अधिकारियों को अपनी संपत्ति को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की कानूनन आवश्यकता नहीं होती है।
- फिर भी, SC ने 1997 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि जजों को "अपने जीवनसाथी और आश्रितों सहित सभी संपत्तियों को CJI के समक्ष घोषित करना चाहिए।"
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 में न्यायाधीशों की संपत्ति को स्वेच्छा से अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने का फैसला किया।
- 1997 में न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपनाया था और जो कुछ न्यायिक मानकों और सिद्धांतों को स्थापित करता है जिनका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पालन करना चाहिए, को वर्तमान निर्णय में दोहराया गया है।

न्यायाधीशों की संपत्ति के खुलासे पर सर्वोच्च न्यायालय

- **कानूनी स्थिति:** न्यायाधीशों को कानून द्वारा अपनी संपत्ति को जनता के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
- 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव के अनुसार न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति को मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रकट करना चाहिए, लेकिन जनता के सामने नहीं।

- **2009 का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर संपत्ति के प्रकटीकरण को वैकल्पिक, लेकिन अनिवार्य नहीं, अनुमति दी गई।
- **2019 का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय:** न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायाधीशों की संपत्ति की जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में आती है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जवाबदेही से संबंधित होने पर ऐसे खुलासे व्यक्तिगत जानकारी नहीं बनते हैं।

न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997)

- न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोई भी कार्य, चाहे वह आधिकारिक हो या व्यक्तिगत, जो इस धारणा की विश्वसनीयता को नष्ट करता हो, उससे बचना चाहिए।
- बार के व्यक्तिगत सदस्यों, विशेष रूप से उसी न्यायालय में वकालत करने वालों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखने चाहिए।
- न्यायाधीश को अपने निकट परिवार के किसी सदस्य, जैसे पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद या पुत्रवधू या किसी अन्य निकट संबंधी को, यदि वह बार का सदस्य है, अपने समक्ष उपस्थित होने या किसी मामले से किसी भी तरह से संबद्ध होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- न्यायाधीश ऐसे मामले की सुनवाई और निर्णय नहीं करेगा, जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य, कोई निकट संबंधी या मित्र शामिल हो।
- एक न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निर्णयों से स्वयं अपनी बात कहे। वह मीडिया को साक्षात्कार नहीं देगा।
- न्यायाधीश अपने परिवार, मित्रों को छोड़कर किसी से उपहार या आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
- न्यायाधीश किसी ऐसे मामले की सुनवाई और निर्णय नहीं करेगा जिसमें वह कंपनी शामिल है जिसमें उसके शेयर हैं, जब तक कि उसने अपनी रुचि का खुलासा नहीं किया हो और मामले की सुनवाई और निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई हो।
- न्यायाधीश को अपने पद से जुड़ी किसी सुविधा या विशेषाधिकार के रूप में कोई वित्तीय लाभ नहीं मांगना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो। इस संबंध में किसी भी संदेह का समाधान और स्पष्टीकरण मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय की स्थिति

- मार्च 2025 तक 770 में से केवल 97 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों (13%) ने अपनी संपत्ति का खुलासा सार्वजनिक रूप से किया था।
- कई उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद, राजस्थान, बॉम्बे, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड सहित) ने सार्वजनिक प्रकटीकरण का कड़ा विरोध किया और न्यायाधीशों की संपत्ति के बारे में आरटीआई अनुरोधों को ठुकरा दिया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. न्यायाधीशों की संपत्ति के सार्वजनिक प्रकटीकरण के संबंध में हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर, भारत में न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की आलोचनात्मक जांच करें। 1997 के न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जैसे उपाय इस संतुलन को कैसे प्रभावित करते हैं? [250 शब्द | 15 अंक]

- यह तर्क देकर, केंद्र ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि वक्फ के धर्मनिरपेक्ष और प्रशासनिक पहलुओं को विनियमित करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है।

कानून में संशोधन क्यों किया गया?

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए सख्त मानदंड लाता है, जिसमें शामिल हैं:

- 8 अप्रैल, 2025 (जिस दिन कानून लागू हुआ) से सभी वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण।
- 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' की प्रथा को समाप्त करना, जहां समय के साथ धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को औपचारिक दस्तावेज के बिना वक्फ के रूप में दावा किया जा सकता था।
- वक्फ बोर्ड के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही।

सरकार का दावा है कि इन उपायों का उद्देश्य अवैध अतिक्रमणों को रोकना है, जिनमें से कुछ की रिपोर्ट मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा भी की जा रही थी।

याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को संबोधित करना

कानून का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि:

- 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' एक लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए।
- सरकारी अधिकारियों को यह तय करने की अनुमति देना कि कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर है या नहीं, एक न्यायाधीश को अपना मामला खुद तय करने देने जैसा है - पक्षपात के बारे में चिंताएँ पैदा करना।
- संशोधन वक्फ संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के बराबर हैं।

आपत्तियों पर केंद्र की प्रतिक्रिया

सॉलिसिटर-जनरल ने निम्नलिखित बिंदुओं के साथ जवाब दिया:

- 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' की अवधारणा पिछले कानून द्वारा बनाई गई थी, धर्म द्वारा नहीं। जो कानून द्वारा बनाया जाता है उसे कानून द्वारा बदला भी जा सकता है, खासकर जब सामाजिक परिस्थितियाँ इसकी माँग करती हैं।
- भारत में हिन्दुओं के लिए भी इसी तरह के कानून हैं, जहाँ वंशानुगत पुजारियों (अर्चकों) जैसी पुरानी प्रथाओं को कानूनी रूप से हटा दिया गया है। इस प्रकार, वक्फ कानूनों को अपडेट करना भी भेदभावपूर्ण नहीं है।
- जहाँ तक सरकारी अधिकारियों द्वारा जाँच करने की बात है, केंद्र ने कहा कि जब तक व्यक्तिगत पक्षपात का सबूत नहीं मिलता, तब तक यह मान लेना अनुचित है कि वे अनुचित तरीके से काम करेंगे। इसके अलावा, अपील की एक स्पष्ट प्रणाली है:
 - पहले वक्फ न्यायाधिकरण में,
 - फिर उच्च न्यायालय में,
 - और अंत में, सर्वोच्च न्यायालय में।

वक्फ और संविधान

केंद्र का व्यापक कानूनी रुख एक स्पष्ट संवैधानिक अंतर पर आधारित है:

- अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जिसमें धार्मिक मामलों का अभ्यास और प्रबंधन करने का अधिकार भी शामिल है।
- लेकिन ये स्वतंत्रताएँ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं, और राज्य को धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं, जैसे संपत्ति और वित्तीय प्रबंधन को विनियमित करने की अनुमति देती हैं।

संभावना

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर कानूनी बहस अभी खत्म नहीं हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में बहस जारी रहेगी, और अंतिम निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव इन पर पड़ेगा:

- वक्फ संपत्तियों की कानूनी स्थिति,
- धार्मिक अधिकारों और विनियामक नियंत्रण के बीच संतुलन, और
- विभिन्न समुदायों में धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन में एकरूपता।

निष्कर्ष

- केंद्र के अनुसार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 एक सुधारात्मक कदम है जिसका उद्देश्य धार्मिक धर्मार्थ संपत्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वैध प्रशासन लाना है। क्या सर्वोच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण को बरकरार रखता है या धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेता है, यह संविधान के तहत आस्था और शासन को संतुलित करने की भारत की चल रही यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राज्य द्वारा धार्मिक बंदोबस्ती के विनियमन में संवैधानिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर हाल की बहसों के आलोक में, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के दायरे और सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करें। [250 शब्द | 15 अंक]

प्रतीक अधिनियम, 1950

चर्चा में क्यों: हाल ही में दिए गए एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के तहत प्रमुख हिंदुत्व विचारक और स्वतंत्रता सेनानी वी.डी. सावरकर के नाम और विरासत की रक्षा करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

विवरण

- यह याचिका 65 वर्षीय याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जो व्यक्तिगत रूप से एक बेंच के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर के योगदान के बारे में गलतफहमी बढ़ रही है, और उन्होंने सावरकर के नाम को दुरुपयोग या अनादर से बचाने के लिए कानूनी उपाय मांगे [प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के तहत]।
- याचिकाकर्ता की याचिका 2024 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों के मद्देनजर आई थी। गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि सावरकर ने स्वयं को अंग्रेजों का "सबसे आज्ञाकारी सेवक" कहा था, जिसमें सावरकर द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान कैद में लिखे गए पत्रों का जिक्र था। इन टिप्पणियों ने देश भर में बहस छेड़ दी, खासकर राजनीतिक हलकों और इतिहासकारों के बीच।
- जवाब में, श्री गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की गई। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में ट्रायल न्यायालय के समन पर रोक लगा दी, लेकिन सावरकर जैसे राष्ट्रीय हस्तियों के खिलाफ "गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी" करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना भी की।

- याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सावरकर के नाम की रक्षा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उनके मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देने, संविधान का सम्मान करने और स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का सम्मान करने की बात करता है।
- उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायिक मंच के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्य स्थापित करने की अनुमति दी जाए ताकि सावरकर की छवि राजनीतिक आख्यानो या सार्वजनिक गलतफहमियों से धूमिल न हो।

न्यायालय की प्रतिक्रिया

- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका के आधार पर सवाल उठाया। पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है।
- चूंकि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं था, और मामले में संवैधानिक अधिकारों का कोई उल्लंघन शामिल नहीं था, इसलिए न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं मिला।

प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 - एक संक्षिप्त अवलोकन

- प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 एक ऐसा कानून है जो पेशेवर या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कुछ नामों, प्रतीकों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- यह आम तौर पर राष्ट्रीय हस्तियों, सरकारी प्रतीकों और सार्वजनिक संस्थानों पर लागू होता है। हालांकि, यह स्वचालित रूप से व्यक्तिगत ऐतिहासिक हस्तियों तक विस्तारित नहीं होता है जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित न किया जाए।
- इस मामले में याचिकाकर्ता न्यायालय से इस अधिनियम के तहत संरक्षित सावरकर के नाम की व्याख्या करने के लिए कह रहा था - लेकिन इस तरह के कदम के लिए आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना की आवश्यकता होगी, न्यायिक आदेश की नहीं।

वीर सावरकर के बारे में तथ्य

जन्म और प्रारंभिक जीवन

- **पूरा नाम:** विनायक दामोदर सावरकर
- **जन्म:** 28 मई 1883, महाराष्ट्र के नासिक के पास भगूर में

क्रांतिकारी गतिविधियाँ और संगठन

अभिनव भारत सोसाइटी

- 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित।
- मूल रूप से नासिक में मित्त मेला के रूप में शुरू हुआ।
- यह एक गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी थी जिसकी शाखाएँ भारत और लंदन में थीं, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था।

इंडिया हाउस

- 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित।
- विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादी छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य किया।
- सावरकर इसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने कई भारतीय छात्रों को कट्टरपंथी बनाया।

फ्री इंडिया सोसाइटी

- 1906 में लंदन में सावरकर द्वारा स्थापित, इतालवी राष्ट्रवादी ज्यूसेपे मेत्सिनी के विचारों से प्रेरित, जिनकी जीवनी भी सावरकर ने लिखी थी।
- क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।

वैचारिक योगदान

लेखन

- **‘भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध का इतिहास’:** 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाली एक अग्रणी रचना, जिसमें गुरिल्ला युद्ध की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई है।
- **‘हिंदुत्व: हिंदू कौन है?’:** हिंदुओं की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को परिभाषित करने के लिए हिंदुत्व शब्द गढ़ा। इस पुस्तक ने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा की नींव रखी।

हिंदू महासभा से जुड़ाव

- 1937 से 1943 तक अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- हिंदू राजनीतिक एकता और उग्र राष्ट्रवाद की वकालत की, हिंदू महासभा को कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन के विकल्प के रूप में पेश किया।

गिरफ्तारी, मुकदमा और कारावास

- **1909:** मॉर्ले-मिंटो सुधारों (भारतीय परिषद अधिनियम 1909) के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया गया।
- **1910:** क्रांतिकारी इंडिया हाउस समूह से जुड़े होने के कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया।
- **आरोप:**
 - नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या में सहायता करना।
 - आईपीसी की धारा 121-ए के तहत ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ साजिश रचना।
- **सजा:** दो मुकदमों के बाद, 50 साल की कैद (जिसे आमतौर पर काला पानी कहा जाता है) की सजा सुनाई गई और 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में भेज दिया गया।

ऐतिहासिक आख्यानों पर एक बड़ी बहस

- यह मामला भारत में एक बड़ी बहस को उजागर करता है: वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में ऐतिहासिक हस्तियों की विरासत को कैसे संरक्षित या व्याख्यायित किया जाना चाहिए? यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सार्वजनिक हस्तियों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देती है, यह राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के बारे में भी सवाल उठाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक चर्चा में जिम्मेदारी पर लगातार जोर दिया है, खासकर जब इसमें भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले लोग शामिल हों।

निष्कर्ष

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज करना संवैधानिक प्रक्रियाओं के महत्व और ऐतिहासिक व्याख्या के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के सीमित दायरे को रेखांकित करता है। जबकि वी.डी. सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित और संरक्षित करने की इच्छा समझ में आती है, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मुद्दों को उचित विधायी या सार्वजनिक मंचों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए, न कि रिट याचिकाओं के माध्यम से। यह निर्णय एक स्पष्ट संदेश देता है - कि जबकि ऐतिहासिक विरासत मान्य रखती है, न्यायिक उपायों को संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक बहस, अकादमिक शोध और जिम्मेदार राजनीतिक चर्चा भारत के जटिल और विविध स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से जुड़ने के प्राथमिक रास्ते बने हुए हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक है, लेकिन इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, खासकर जब यह राष्ट्रीय प्रतीकों और ऐतिहासिक हस्तियों से संबंधित हो। प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के तहत वी.डी. सावरकर के नाम की रक्षा करने की याचिका को खारिज करने वाले हाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, व्यक्तिगत अधिकारों, सार्वजनिक प्रवचन और राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा के बीच संवैधानिक सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करें। [250 शब्द | 15 अंक]

लोकसभा उपाध्यक्ष

चर्चा में क्यों: लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद जून 2019 से रिक्त है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबी रिक्ति है।

नोट: अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को "जितनी जल्दी हो सके" अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव करना चाहिए। हालाँकि, यह इन चुनावों के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ और विकास

- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिकाएँ भारत सरकार अधिनियम 1919 से जुड़ी हैं, जहाँ उन्हें शुरू में राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति कहा जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इन पदों को उनके वर्तमान शीर्षकों में पुनः नामित किया।
- स्वतंत्रता के बाद, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम. अनंतशयनम अयंगर थे। पिछले कुछ वर्षों में, संसदीय कार्यवाही में संतुलन को बढ़ावा देने के लिए अक्सर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा इस पद पर कब्जा किया जाता रहा है।

चुनाव और कार्यकाल

- उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने बीच से करते हैं। चुनाव आमतौर पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है और अध्यक्ष के चुनाव के तुरंत बाद होने की संभावना होती है। यद्यपि संविधान में कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, संसदीय परंपरा ने पारंपरिक रूप से उचित अवधि के भीतर उपसभापति का चुनाव सुनिश्चित किया है।
- उपाध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल की अवधि तक कार्य करता है, जब तक कि वह:
 - इस्तीफा न दे;
 - सदन का सदस्य न रह जाए;
 - प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है।

हटाने की प्रक्रिया

- **हटाने के आधार**
 - संविधान में उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई विशेष आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अविश्वास, कदाचार, पक्षपात या लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्धारित किसी अन्य कारण के आधार पर हटाया जा सकता है।
- **प्रस्ताव**
 - उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव की शुरुआत प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के इरादे की सूचना से होनी चाहिए। यह सूचना लिखित में होनी चाहिए। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए (लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार, संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है)। लोकसभा के महासचिव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- **प्रस्ताव की स्वीकार्यता**
 - लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि सूचना स्वीकार्य है या नहीं। हालाँकि, चूँकि प्रस्ताव उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है, और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 95(1) के अनुसार सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। स्वीकार किए जाने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है।
- **कार्य सूची में शामिल करना**
 - प्रस्ताव सदन के कार्य एजेंडे में सूचीबद्ध है। आम तौर पर, प्रस्ताव को नोटिस स्वीकार किए जाने के 14 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए।
- **भाग लेने का अधिकार, लेकिन अध्यक्षता नहीं**
 - संविधान के अनुच्छेद 96(1) के अनुसार: "लोक सभा की किसी भी बैठक में जब उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो उपाध्यक्ष... अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन सदन में उपस्थित रह सकते हैं और बोल सकते हैं तथा प्रस्ताव पर मतदान करने के हकदार होंगे।"
- **प्रस्ताव पर बहस**
 - नियत दिन पर सदन प्रस्ताव पर बहस करता है। उपाध्यक्ष, हालाँकि अध्यक्षता करने से प्रतिबंधित हैं, बहस में भाग ले सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। कोई भी सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में या खिलाफ बोल सकता है।
- **प्रस्ताव पर मतदान**
 - बहस के बाद, प्रस्ताव पर मतदान होता है। हटाने के लिए, इसे प्रभावी बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है: सदन की कुल सदस्यता (रिक्तियों को छोड़कर) का बहुमत, न कि केवल उपस्थित और मतदान करने वाले।

परिणाम

- यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है: उपसभापति को औपचारिक रूप से पद से हटा दिया जाता है। निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

संसदीय लोकतंत्र में महत्व

- विधायी कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करता है: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत उपाध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण लोकसभा का विधायी कामकाज ठप न हो - निर्बाध लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखता है।
- व्यवस्था बनाए रखने में अध्यक्ष का समर्थन करता है: उपाध्यक्ष संसदीय अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखने में अध्यक्ष की सहायता करता है। यह विशेष रूप से लंबे सत्रों के दौरान या जब अध्यक्ष कहीं और व्यस्त होता है (जैसे, प्रशासनिक कर्तव्य या बाहरी प्रतिनिधिमंडल) के दौरान महत्वपूर्ण होता है।
- बहुसौ की निष्पक्ष अध्यक्षता करता है: यद्यपि अध्यक्ष से आम तौर पर निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, उपाध्यक्ष को अक्सर विपक्षी दल या गैर-सत्तारूढ़ गठबंधन से चुना जाता है, जिससे अध्यक्षता की भूमिकाओं में शक्ति का संतुलन सुनिश्चित होता है। यह गैर-पक्षपातपूर्ण बहस को बढ़ावा देता है, संसदीय निष्पक्षता और विश्वास को मजबूत करता है।
- लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करता है: यह पद संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक जांच को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि पीठासीन भूमिकाएं साझा की जाती हैं, सत्तारूढ़ दल द्वारा एकाधिकार नहीं। उदाहरणों में शामिल हैं जब जवाहरलाल नेहरू ने विपक्षी सांसद सरदार हुकम सिंह को उपसभापति के रूप में समर्थन दिया - द्विदलीय सहयोग की मिसाल कायम की।
- प्रशासनिक और समिति की भूमिका: उपसभापति किसी भी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। ये विस्तृत विधायी जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो संसद की प्रभावशीलता की रीढ़ हैं।
- संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है: दुर्लभ परिस्थितियों में, जैसे कि जब अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों अनुपलब्ध हों, तो उपाध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता भी करता है।
- अध्यक्षता करते समय निर्णायक मत होता है: अध्यक्ष की तरह, उपाध्यक्ष - सदन की अध्यक्षता करते समय - पहले उदाहरण में मतदान नहीं करता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में उसके पास निर्णायक मत होता है। इससे उन्हें गतिरोध को तोड़ने और विधायी परिणामों को प्रभावित करने की शक्ति मिलती है।
- संघवाद और समायोजन की भावना को दर्शाता है: विभिन्न क्षेत्रों या राजनीतिक दलों से प्रतिनिधित्व की अनुमति देकर, उपाध्यक्ष का पद भारत के बहुलवादी लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। विपक्षी बेंचों से उनका चुनाव सहकारी संघवाद और समावेशी शासन को दर्शाता है।

निष्कर्ष

- उपाध्यक्ष के कार्यालय के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, संसद को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से चुनाव के लिए एक निश्चित समय-सीमा - जैसे कि पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर - अनिवार्य करना चाहिए। यदि देरी होती है, तो राष्ट्रपति को, प्रधान मंत्री की सलाह पर, प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उपसभापति को पीठासीन कर्तव्यों का नियमित प्रतिनिधिमंडल कार्यालय की प्रासंगिकता और प्रशासनिक उपयोगिता की पुष्टि कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न। "उपाध्यक्ष का कार्यालय एक संवैधानिक आवश्यकता है, न कि राजनीतिक सुविधा।" इस कथन के प्रकाश में, लोकसभा में उपाध्यक्ष के महत्व और वर्तमान स्थिति की आलोचनात्मक जाँच करें। [250 शब्द] [15 अंक]

रॉड्रिक की राजनीतिक त्रिविधता

चर्चा में क्यों: यह लेख द हिंदू अखबार के संपादकीय में प्रस्तुत दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित किया गया है।

परिचय

- आज, पश्चिमी दुनिया भर के लोकतंत्र गहरे संकट का सामना कर रहे हैं। ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास बढ़ रहा है और लोकलुभावनवाद का खतरनाक प्रसार हो रहा है। परिणामस्वरूप, कई देश अधिक अंतर्मुखी और राष्ट्रवादी होते जा रहे हैं।
- बीस साल से भी पहले, अर्थशास्त्री डानी रॉड्रिक ने ऐसी ही स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने "विश्व अर्थव्यवस्था की राजनीतिक त्रिविधता" नामक एक अवधारणा प्रस्तावित की, जो यह समझाने में मदद करती है कि आज लोकतंत्र क्यों संघर्ष कर रहे हैं।

रॉड्रिक की राजनीतिक त्रिविधता क्या है?

वर्ष 2000 में, डानी रॉड्रिक ने "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण कितना आगे जाएगा?" शीर्षक से एक पेपर लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया था कि देश एक साथ निम्नलिखित तीनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं:

- गहन वैश्वीकरण (अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण)
- मजबूत राष्ट्र-राज्य संप्रभुता (निर्णयों पर राष्ट्रीय नियंत्रण)
- पूर्ण लोकप्रिय लोकतंत्र (जहाँ लोग नीतियों को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं)

अधिकतम, एक देश इन तीनों में से केवल दो को ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि तीनों को प्राप्त करने का प्रयास तनाव और विरोधाभास पैदा करेगा।

सरल शब्दों में:

- यदि आप विश्व अर्थव्यवस्था में गहराई से एकीकृत होना चाहते हैं और अपने लोगों को राजनीति को पूरी तरह से नियंत्रित करने देना चाहते हैं, तो आपको कुछ राष्ट्रीय नियंत्रण छोड़ना होगा।
- यदि आप अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं और वैश्वीकरण में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको लोकतंत्र को सीमित करना पड़ सकता है।
- यदि आप लोकतंत्र और राष्ट्रीय संप्रभुता चाहते हैं, तो आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने खुलेपन को सीमित करना होगा।

उस समय, यह मुख्य रूप से एक अकादमिक सिद्धांत था। आज, यह वास्तविक दुनिया में सामने आ रहा है - विशेष रूप से पश्चिमी लोकतंत्रों में - जिसके कारण राजनीतिक संकट, सामाजिक अशांति और लोकतांत्रिक मूल्यों का कमजोर होना हो रहा है।

तीन विकल्पों को समझना

रॉड्रिक के अनुसार, आइए उन तीन मुश्किल विकल्पों पर नज़र डालें जिनका सामना देश कर रहे हैं:

वैश्वीकरण और लोकतंत्र - लेकिन संप्रभुता की कीमत पर

- देश वैश्वीकरण और लोकतंत्र दोनों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को कुछ हद तक त्याग दें। इसका एक बेहतरीन उदाहरण यूरोपीय संघ (ईयू) है।
- ईयू में, सदस्य देश एक बड़े आर्थिक और राजनीतिक संघ का हिस्सा बनने के लिए कई नीतियों - जैसे व्यापार, प्रवास और मौद्रिक मामलों - पर नियंत्रण छोड़ने पर सहमत हुए।
- ईयू ने 450 मिलियन लोगों का एक विशाल एकल बाज़ार बनाया, जिसकी जीडीपी 18.5 ट्रिलियन डॉलर है।
- यह वैश्विक व्यापार का लगभग 15% हिस्सा है और कई मायनों में आर्थिक रूप से सफल रहा है।
- हालाँकि, सभी को समान रूप से लाभ नहीं मिला है। कुछ नागरिकों को लगता है कि उन्होंने अवसर खो दिए हैं या उनकी राष्ट्रीय पहचान मुक्त आवागमन और विदेशी प्रभावों से खतरे में है।
- इस आक्रोश ने ब्रेक्सिट (यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना) जैसे राष्ट्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा दिया है।
- पूरे यूरोप में, दक्षिणपंथी पार्टियाँ मजबूत हो रही हैं, जो वैश्वीकरण और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता के एक सख्त, अलगाववादी संस्करण के पक्ष में हैं।

वैश्वीकरण और संप्रभुता - लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर

- देश राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने और वैश्वीकरण में भाग लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक निर्णयों पर लोकप्रिय लोकतंत्र के प्रभाव को सीमित करना होगा।
 - इस मॉडल में:
 - केंद्रीय बैंक और नियामक प्राधिकरण जैसी स्वतंत्र संस्थाएँ आर्थिक नीतियाँ बनाती हैं।
 - इन निकायों को लोकप्रिय राजनीतिक दबावों से बचाया जाता है।
- रॉड्रिक ने उल्लेख किया कि कई विकासशील देशों में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ सरकारों को निवेशकों और लेनदारों के पक्ष में सख्त आर्थिक सुधारों का पालन करने के लिए मजबूर करती हैं, जो अक्सर लोगों की इच्छा को अनदेखा करते हैं।
- उदाहरण के लिए, केन्या में, सख्त राजकोषीय अनुशासन की मांग करने वाली IMF समर्थित नीतियों ने व्यापक सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया। लोगों को लगा कि विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए उनके कल्याण और जरूरतों की बलि दी गई।
- इस प्रकार, वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में, लोकतंत्र और वास्तविक संप्रभुता दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है।

लोकतंत्र और संप्रभुता - लेकिन वैश्वीकरण की कीमत पर

- तीसरा रास्ता वह है जिसे रॉड्रिक ने "ब्रेटन वुड्स समझौता" कहा है। यहाँ, देश लोकतंत्र और संप्रभुता बनाए रखते हैं लेकिन वैश्वीकरण को सीमित करते हैं।
- उदाहरणों में शामिल हैं:
 - **भारत:** संरक्षणवादी नीतियों, विदेशी निवेशों पर प्रतिबंधों और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से, भारत ने वैश्विक बाजारों के साथ अपने जुड़ाव को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा है।

- **चीन और पूर्वी एशियाई टाइगर्स (जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान):** उन्होंने चुनिंदा विदेशी निवेश की अनुमति दी और निर्यात को प्रोत्साहित किया, लेकिन कड़ा राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखा और विदेशी प्रभाव को प्रतिबंधित किया, खासकर मीडिया और सूचना पर।
- यह मॉडल आर्थिक रूप से अच्छा काम कर रहा है - इन देशों ने तेजी से विकास हासिल किया। लेकिन यह अक्सर राजनीतिक स्वतंत्रता और असहमति को रोकने की कीमत पर आया, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल उठे।

पश्चिमी संकट: वैश्वीकरण के खिलाफ़ प्रतिक्रिया

दशकों तक, पश्चिमी लोकतंत्रों ने तीनों को संतुलित करने की कोशिश की - लोकतंत्र, संप्रभुता और वैश्वीकरण - यह मानते हुए कि वे एक साथ सभी के लाभों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यह संतुलन असंभव साबित हुआ है।

वैश्वीकरण ने समग्र रूप से धन में वृद्धि करते हुए, विजेताओं और हारने वालों को भी बनाया:

- यू.एस., यू.के. और यूरोप के कई हिस्सों में विनिर्माण रोजगार विलुप्त हो गए क्योंकि उद्योग सस्ते श्रम वाले देशों में चले गए।
- उन श्रमिकों और छोटे व्यवसायों में आर्थिक असुरक्षा बढ़ी जो पीछे छूट गए थे।
- डोनाल्ड ट्रम्प (यूएसए), गीर्ट वाइल्डर्स (नीदरलैंड) और विक्टर ऑर्बन (हंगरी) जैसे लोकलुभावन नेता इन कुंठाओं का फायदा उठाकर सत्ता में आए।

आज, यह है:

- मुख्यधारा के राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है;
- आव्रजन, मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के खिलाफ़ प्रतिक्रिया;
- संरक्षणवाद और राष्ट्रवादी बयानबाजी बढ़ रही है।

देश अब जलवायु परिवर्तन और विकास सहायता जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग से पीछे हट रहे हैं, और पहले "अपने लोगों की रक्षा" करना चाहते हैं।

आज पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए चुनौती है:

- वैश्वीकरण के लाभों को अधिक निष्पक्ष रूप से फैलाना;
- लोकतांत्रिक संस्थाओं को सभी नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना;
- लोकलुभावनवाद द्वारा दिए जाने वाले आसान लेकिन खतरनाक उत्तरों से बचना।

एक सावधान, विचारशील मार्ग की आवश्यकता है - प्रणालियों को लापरवाही से खत्म करने की नहीं, बल्कि उन्हें अधिक मजबूत और अधिक समावेशी बनाने के लिए पुनर्निर्माण करने की।

निष्कर्ष

रॉड्रिक की राजनीतिक त्रिविधता से पता चलता है कि देशों को सब कुछ नहीं मिल सकता है - उन्हें सावधानी से चुनना होगा कि वे किन दो तत्वों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। यदि वे समझदारी से व्यापार-नापसंद को समझने में विफल रहते हैं, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं: सामाजिक अशांति, कमजोर लोकतंत्र और एक खराब भविष्य।

शिमला समझौता, 1972

चर्चा में क्यों: पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा की और भारत के साथ वाघा सीमा को बंद करने की घोषणा की, जिससे इस बिंदु के माध्यम से सभी सीमा पार आवाजाही बंद हो गई।

शिमला समझौते के बारे में

- इस समझौते पर 1971 के युद्ध के बाद भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, और इसे एक महत्वपूर्ण सफलता माना गया था।

पृष्ठभूमि: 1971 का युद्ध

- 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध आधिकारिक तौर पर 3 दिसंबर को शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने आठ भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले करने का आदेश दिया।
- उस शाम, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि हवाई हमले "भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा" थे।
- जमीन पर, भारतीय सेना ने तीन-तरफा हमला किया, जबकि एक साथ पश्चिम में पाकिस्तानी हमलों को रोकना और अपने स्वयं के क्षेत्रीय लाभ प्राप्त किए।
- 16 दिसंबर को, भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया। जीत की कोई उम्मीद न होने के कारण, पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण करने की अंतिम चेतावनी स्वीकार कर ली।
- 1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ।

शिमला समझौता, 1972

- 2 जुलाई, 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- उद्देश्य:** विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समझौते की आधिकारिक प्रति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटना था।
- समझौते में कहा गया कि दोनों देश शत्रुता समाप्त करने तथा शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- इसका लक्ष्य राष्ट्रीय संसाधनों को संघर्ष से हटाकर अपने लोगों के कल्याण में सुधार की दिशा में पुनर्निर्देशित करना था।
- मुख्य प्रावधान**
 - **द्विपक्षीय विवाद समाधान:** भारत और पाकिस्तान कश्मीर सहित सभी विवादों को सीधे, द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से निपटाने पर सहमत हुए। यह खंड तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के विरुद्ध भारत के तर्क का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया।
 - **नियंत्रण रेखा (एलओसी) की स्थापना:** समझौते ने जम्मू और कश्मीर में 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा (एलओसी) में बदल दिया। दोनों पक्षों ने इसे एकतरफा रूप से नहीं बदलने का वचन दिया, जिससे सैन्य यथास्थिति मजबूत हुई।

- **अधिकृत क्षेत्र की वापसी:** भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की गई 13,000 वर्ग किमी से अधिक भूमि वापस कर दी, जबकि लद्दाख में तुरतुक और चालुंका जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बरकरार रखा।
- **बांग्लादेश को मान्यता:** हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसने पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को अंततः राजनयिक मान्यता देने की नींव रखी।

निलंबन के संभावित परिणाम

- नियंत्रण रेखा तनाव का केंद्र रही है, जिसमें संघर्ष विराम उल्लंघन और घुसपैठ के प्रयास शामिल हैं। यदि शिमला समझौते के सिद्धांतों का अब और सम्मान नहीं किया जाता है, तो इससे सीमा पर शत्रुता बढ़ सकती है और व्यापक सैन्य तनाव पैदा हो सकता है।
- पाकिस्तान का निलंबन काफी हद तक प्रतीकात्मक है, यह देखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार उल्लंघनों के कारण समझौते ने अपना व्यावहारिक महत्व खो दिया है।
- निलंबन क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है, खासकर परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच, और इससे राजनयिक और सैन्य तनाव बढ़ सकता है, जिससे सार्थक बातचीत की संभावना कम हो सकती है।
- पाकिस्तान की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना का कारण बन सकती है, जिससे भारत की यह स्थिति मजबूत होगी कि पाकिस्तान एक अविश्वसनीय भागीदार है।

निष्कर्ष

- शिमला समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति को बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय ढांचे की नींव रखी। हालांकि इसने दशकों तक बड़े पैमाने पर संघर्षों को टालने में मदद की, लेकिन इसके बार-बार उल्लंघन ने इसकी प्रासंगिकता को कमजोर कर दिया। पाकिस्तान द्वारा समझौते को हाल ही में निलंबित करने से न केवल कूटनीतिक तंत्र कमजोर हुआ है, बल्कि पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में तनाव बढ़ने का जोखिम भी है, खासकर दो परमाणु-सशस्त्र राज्यों के बीच।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. शिमला समझौते, 1972 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? शिमला समझौते ने समय के साथ भारत-पाकिस्तान संबंधों को कैसे आकार दिया है? [150 शब्द] [10 अंक]

सिंधु जल संधि (IWT)

चर्चा में क्यों: भारत ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को तत्काल प्रभाव से 'स्थगित' रखा जाएगा, जब तक कि इस्लामाबाद सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।

- **सिंधु बेसिन:** सिंधु नदी बेसिन में छह नदियाँ हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज; तिब्बत से निकलती हैं और हिमालय पर्वतमाला से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, और कराची के दक्षिण में समाप्त होती हैं।
 - प्रारंभ में, मई 1948 में अंतर-डोमिनियन समझौता अपनाया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने यह निर्णय लिया कि भारत, पाकिस्तान को वार्षिक भुगतान के बदले में जल उपलब्ध कराएगा। हालाँकि, यह समझौता जल्द ही टूट गया क्योंकि दोनों देश इसकी आम व्याख्याओं पर सहमत नहीं हो सके।
- 1951 में, जल-बंटवारे के विवाद की पृष्ठभूमि में, दोनों देशों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी-अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक से आवेदन किया, जिस पर विश्व बैंक ने संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की।
- 1960 में, लगभग एक दशक तक तथ्य-खोज, बातचीत, विश्व बैंक द्वारा प्रस्ताव और उनमें संशोधन के बाद, दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ।
- सिंधु जल संधि (IWT) पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।
- विश्व बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष डब्ल्यू.ए.बी. इलिफ़ ने भी संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

संधि के प्रावधान

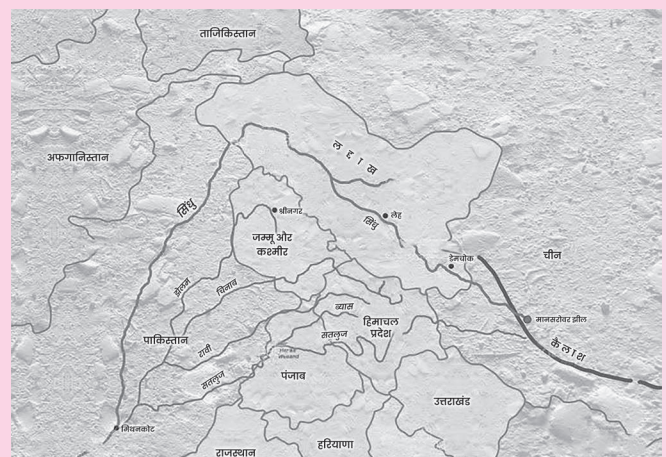
- संधि में निर्धारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों का जल कैसे साझा किया जाएगा।
- **नदीजल आवंटन:** इसने तीन पश्चिमी नदियों- सिंधु, चिनाब और झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर, अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया और तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया।
- इसका अर्थ यह हुआ कि जल का 80% हिस्सा, या लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट (MAF), पाकिस्तान को चला गया, जबकि शेष 33 MAF या 20% जल भारत के उपयोग के लिए रह गया।
- **सिंधु आयोग:** इसने दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग स्थापित करने की भी आवश्यकता बताई, जिसका गठन दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा किया जाएगा।
 - आयोग के कार्यों में नदियों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, निरंतर सहयोग के लिए और संघर्षों के समाधान के लिए पहला पड़ाव के रूप में कार्य करना शामिल है।
- यद्यपि पाकिस्तान के पास झेलम, चिनाब और सिंधु के जल पर अधिकार है, IWT के अनुलग्नक C के तहत भारत को कुछ कृषि उपयोगों की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक D उसे 'रन ऑफ़ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाएं बनाने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए जल के वास्तविक भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है।
- संधि में पाकिस्तान को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि भारत द्वारा निर्मित ऐसी परियोजनाएं विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं तो वह उन पर आपत्ति उठा सकता है।
- **सूचना साझा करना:** भारत को परियोजना के डिजाइन या उसमें किए गए परिवर्तनों के बारे में जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करनी होगी, जिसके लिए पाकिस्तान को प्राप्ति के तीन महीने के भीतर आपत्तियों (यदि कोई हो) के साथ जवाब देना होगा।

संधि को स्थगित रखना

- पाकिस्तान में कुछ वर्गों के आरोपों के विपरीत, संधि को स्थगित रखने का मतलब पाकिस्तान को मिलने वाले जल प्रवाह को रोकना नहीं है।
- इसका अर्थ यह है कि भारत पश्चिमी नदियों से संबंधित संधि के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा उन्हें अनुकूलतम बनाएगा।
- भारत के पास वर्तमान में पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को रोकने के लिए भंडारण क्षमता का अभाव है।
- हालाँकि, भारत मौजूदा बांधों से तलछट निकासी का कार्य कर सकता है।
- संधि को स्थगित रखना पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक संकेत भी है कि "सामान्य रूप से काम करना" अब संभव नहीं है।
- भारत ने ऐतिहासिक रूप से एक जिम्मेदार ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में कार्य किया है, तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए संधि प्रक्रियाओं का पालन किया है, लेकिन अब यह संकेत दे रहा है कि संधि को जारी रखने के लिए नई शर्तों की आवश्यकता है।

सिंधु नदी प्रणाली

- सिंधु नदी प्रणाली विश्व स्तर पर सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नदी घाटियों में से एक है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, जो उपजाऊ भूमि और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता देती है।
- **इस प्रणाली में छह प्रमुख नदियाँ शामिल हैं:** सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और इसने दक्षिण एशिया के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के भीतर, यह कई राज्यों को कवर करती है।
- जम्मू और कश्मीर में सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्यास, सतलुज और रावी नदियाँ बहती हैं।
- पंजाब में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और घग्गर नदियाँ बहती हैं। यह जटिल नदी नेटवर्क कृषि, जल आपूर्ति और पूरे क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।



विवाद समाधान तंत्र (अनुच्छेद IX) से जुड़े मुद्दे

- संधि के अनुच्छेद IX में विवादों को सुलझाने के लिए तीन-स्तरीय तंत्र की रूपरेखा दी गई है।
- इस तंत्र में भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच शुरुआती चर्चा शामिल है, जिसके बाद विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ और अंत में हेग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (सीओए) के समक्ष मामला उठाया जाता है।
- पाकिस्तान ने इस तंत्र का इस्तेमाल भारत द्वारा बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं में देरी करने के लिए किया है।
- **उदाहरण:** सलाल बांध पर आपत्ति, बगलिहार को तटस्थ विशेषज्ञ के पास ले जाना, 1987 से तुलबुल नौवहन परियोजना को रोकना और किशनगंगा परियोजना को मध्यस्थता के लिए मजबूर करना (जहां भारत ने अंततः जीत हासिल की लेकिन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा)।
- चूंकि भारत पाकिस्तान के साथ मुद्दों के लिए द्विपक्षीय समाधान को प्राथमिकता देता है, इसलिए सिंधु संधि में भी द्विपक्षीय विवाद समाधान तंत्र होना चाहिए।
- यह ध्यान देने योग्य है कि संधि की शुरुआती सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल में इंजीनियरों की तुलना में वकीलों की संख्या अधिक थी, जिससे इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने और भारत को अपनी ऊपरी तटवर्ती स्थिति का दुरुपयोग करने के रूप में चित्रित करने का प्रयास करने का संकेत मिलता है। संशोधित संधि में इसके विरुद्ध प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

आगे की राह और निष्कर्ष

- भारत और पाकिस्तान दोनों के वर्गों ने दावा किया है कि यह संधि उनके देश के लिए अनुचित है और दूसरे के लिए बहुत उदार है।
- भारत में कुछ लोगों ने संधि को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है।
- जब संधि पर फिर से बातचीत की जाती है, तो भारत के लिए दो प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
 - **शिकायत निवारण तंत्र:** भारत को विवाद समाधान तंत्र में बदलाव के लिए दबाव डालना चाहिए, आदर्श रूप से द्विपक्षीय प्रक्रिया की ओर, ताकि देरी और मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोका जा सके।
 - **संधि की निर्देशात्मकता और प्रौद्योगिकी:** वर्तमान संधि को बांध निर्माण के संबंध में बहुत ही निर्देशात्मक बताया गया है। चूंकि बांध निर्माण तकनीक 1960 के बाद से काफी उन्नत हो गई है, इसलिए भारत को संधि की शर्तों में इन आधुनिक तकनीकी तत्वों को शामिल करने के लिए फिर से बातचीत करनी चाहिए।
- **चीन की भागीदारी:** चीन के साथ जल तनाव को दूर करने के लिए, भारत को ब्रह्मपुल पर अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ रणनीतिक निम्न-तटीय साझेदारी बनाने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण गतिशीलता के बावजूद, सीमा पार जल संबंधी चिंताओं पर एक एकीकृत मोर्चा पेश किया जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वर्षों की बातचीत के बाद, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।
2. यह भारत को तीन पूर्वी नदियों यानी चिनाब, रावी और सतलुज का अप्रतिबंधित उपयोग देता है।

3. संधि के तहत, भारत पश्चिमी नदियों के जल को पाकिस्तान में जाने देने के लिए बाध्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(C) 1999 (D) 2000

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. सीमापार नदी जल बंटवारे के एक मॉडल के रूप में प्रशंसित होने के बावजूद, सिंधु जल संधि को हाल के वर्षों में बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ा है। संधि से जुड़ी चुनौतियों की जाँच करें और वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में इसके संशोधन के लिए भारत की चिंताओं और माँगों का मूल्यांकन करें। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध: छाल वीजा मानदंडों पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों: 2025 की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी छाल वीजा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए, जो सीधे भारतीय आवेदकों को प्रभावित करेंगे। इन संशोधनों में नए वास्तविक छाल (जीएस) आवश्यकता के तहत कड़ी जाँच, वीजा शुल्क में वृद्धि और कुछ भारतीय राज्यों से आवेदनों का अस्थायी निलंबन शामिल है।

प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

- **वास्तविक छाल (जीएस) आवश्यकता का परिचय:** पिछले वास्तविक अस्थायी प्रवेशार्थी (जीटीई) मानदंड को प्रतिस्थापित करते हुए, जीएस आवश्यकता आवेदकों को पाठ्यक्रम और संस्थान की अपनी पसंद के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य करती है, जिससे उनके शैक्षणिक और कैरियर लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है।
- **वीजा आवेदन शुल्क में वृद्धि:** 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी, छाल वीजा आवेदन शुल्क को AUD 710 से बढ़ाकर AUD 1,600 कर दिया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों की संख्या को प्रबंधित करना और यह सुनिश्चित करना है कि आवेदक वित्तीय रूप से प्रतिबद्ध हैं।
- **नामांकन की अनिवार्य पुष्टि (सीओई):** जनवरी 2025 से, सभी छाल वीजा आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैध सीओई प्रदान करना होगा, जिससे केवल प्रस्ताव पत्र के साथ आवेदन करने की पिछली अनुमति समाप्त हो जाएगी।
- **विशिष्ट भारतीय राज्यों से आवेदनों का निलंबन:** कई ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने वीजा अखंडता और अनुपालन पर चिंताओं का हवाला देते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और जम्मू और कश्मीर सहित छह भारतीय राज्यों से आवेदनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

ऑस्ट्रेलिया की नीति में बदलाव के कारण

- **वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को संबोधित करना:** ऑस्ट्रेलियाई सरकार का लक्ष्य छाल वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना है, यह सुनिश्चित करना है कि प्रवेशकर्ता वैकल्पिक प्रवास मार्गों की तलाश करने वाले व्यक्तियों के बजाय वास्तविक छाल हैं।
- **आप्रवासन स्तरों का प्रबंधन:** आवास की कमी और बुनियादी ढांचे के तनाव पर बढ़ती चिंताओं के साथ, ऑस्ट्रेलिया अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या को सीमित करने सहित आप्रवासन स्तरों को नियंत्रित करने के उपायों को लागू कर रहा है।

- **शैक्षिक मानकों को बढ़ाना:** वीजा आवश्यकताओं को कड़ा करके, ऑस्ट्रेलिया अपनी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संस्थान गंभीर और प्रतिबद्ध छात्रों को आकर्षित और बनाए रखें।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

आर्थिक और व्यापारिक जुड़ाव

- दिसंबर 2022 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के कार्यान्वयन से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय निर्यात में 14% की वृद्धि हुई है।
- इस गति को आगे बढ़ाते हुए, दोनों देश वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को और अधिक उदार बनाने के लिए एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर बातचीत कर रहे हैं। मुख्य फोकस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिज, कृषि और प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव के लिए ऑस्ट्रेलिया के 2025 रोडमैप में रक्षा, खेल, संस्कृति, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगभग 50 लक्षित अवसरों की पहचान की गई है। इस रणनीतिक योजना का उद्देश्य व्यापार संबंधों में विविधता लाना और दोनों देशों के लिए आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना है।

रक्षा एवं सामरिक सहयोग

- रक्षा सहयोग भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी की आधारशिला है। 2020 में हस्ताक्षरित पारस्परिक रसद सहायता समझौता सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संयुक्त प्रशिक्षण और संचालन में वृद्धि होती है। दोनों देश नियमित रक्षा अभ्यासों में भाग लेते हैं, जिसमें द्विवार्षिक अभ्यास तरंग शक्ति भी शामिल है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर-संचालन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इसके अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के सक्रिय सदस्य हैं। क्वाड रणनीतिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो एक स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। आगामी बैठकों का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है।

सहयोग के उभरते क्षेत्र

- पारंपरिक क्षेत्रों से परे, भारत और ऑस्ट्रेलिया उभरते क्षेत्रों में अपनी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें भारत अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक ऑस्ट्रेलिया के समृद्ध संसाधनों तक पहुँच चाहता है। सौर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित स्वच्छ ऊर्जा में संयुक्त पहल भी चल रही है।
- प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, दोनों देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में आम चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए सहयोग के रास्ते तलाश रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे आपसी समझ और सांस्कृतिक प्रशंसा को बढ़ावा मिल रहा है।

निष्कर्ष

- ऑस्ट्रेलिया की संशोधित छाल वीजा नीतियाँ उसके आत्रजन प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और उसके शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्यों को दर्शाती हैं। जबकि ये उपाय भारतीय छात्रों के लिए चुनौतियाँ पेश करते हैं, भारत-ऑस्ट्रेलिया के व्यापक संबंध मजबूत बने हुए हैं, जो मजबूत आर्थिक और रक्षा सहयोग पर आधारित हैं। आपसी चिंताओं को दूर करने और इस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. व्यापार, रक्षा और उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के प्रमुख आयामों पर चर्चा करें। इस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने में कौन सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं? [150 शब्द] [10 अंक]

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता: एक ऐतिहासिक सौदा

चर्चा में क्यों: भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता(एफटीए), जो भारत के विकसित भारत 2047 विजन और यूके के विकास पथ के अनुरूप है, की घोषणा हाल ही में भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के सर कीर स्टारमर द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

भारत-यूके एफटीए की मुख्य विशेषताएँ

- इसे एक बेंचमार्क समझौता माना जाता है और यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित सबसे महत्वाकांक्षी एफटीए में से एक है, जो समावेशी विकास, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, गुणवत्तापूर्ण रोजगार और डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करता है।
- **टैरिफ में कमी और व्यापार में वृद्धि**
 - लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% है - इससे भारतीय निर्यात को काफी मदद मिलेगी।
- वर्तमान में व्यापार का मूल्य 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2030 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है।
- **विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएँ:**
 - **ऐसे क्षेत्र जिनमें बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है:** कपड़ा, समुद्री भोजन, चमड़े के सामान, जूते, खिलौने, कीमती पत्थर और आभूषण, और खेल उपकरण।
 - **प्रौद्योगिकी पर निर्भर क्षेत्र:** इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटोमोबाइल घटक, मोटर, कार्बनिक यौगिक।
- यह समझौता अन्य देशों की तुलना में यूके के बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।
- **सेवा क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि:**
 - आईटी/आईटीईएस, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, वाणिज्यिक और अनुदेशात्मक सेवाएं जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन द्वारा की गई सबसे साहसिक प्रतिज्ञाओं में से एक।
 - इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारतीय सेवा प्रदाताओं का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में समावेश बढ़ेगा।
- **कुशल श्रम शक्ति के लिए गतिशीलता:**
 - संविदा सेवा प्रदाताओं, कॉर्पोरेट अतिथियों, वित्तपोषकों, अंतर-कंपनी स्थानान्तरित व्यक्तियों (आईसीटी), स्व-नियोजित पेशेवरों (जैसे, योग शिक्षक, रसोइया, कलाकार), आईसीटी के जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए आवागमन को सुगम बनाता है, जिन्हें काम करने का अधिकार है।
 - एफटीए भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए यूके के उन्नत डिजिटल सेवा क्षेत्र में व्यापक अवसर खोलता है।
- **डुअल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्वेंशन:**
 - अधिकतम तीन वर्षों के लिए, भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को यूके सामाजिक सुरक्षा करों का भुगतान करने से छूट दी गई है।

- भारतीय पेशेवरों को अधिक लागत-प्रतिस्पर्धी बनाकर, यह नीति नौकरी की वृद्धि का समर्थन करेगी और पर्याप्त वित्तीय लाभ प्रदान करेगी।
- **विनियामक और संरचनात्मक परिवर्तन:**
 - भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर गैर-टैरिफ बाधाओं और अनुचित व्यापार सीमाओं से निपटता है।

- खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) 1981 में स्थापित एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसे बढ़ते क्षेत्रीय तनावों, विशेष रूप से 1979 की ईरानी क्रांति और 1980 से 1988 तक चले ईरान-इराक युद्ध के जवाब में बनाया गया था।

पत्रिका के मार्च 2025 अंक में भारत-ब्रिटेन संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) क्या है?

- मुक्त व्यापार समझौता राष्ट्रों या क्षेत्रों के बीच एक संधि है जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए व्यापार बाधाओं (जैसे टैरिफ और कोटा) को कम करना या हटाना है।
- **दायरा:** इसमें न केवल सामान और सेवाएँ शामिल होती हैं, बल्कि इसमें निवेश, बौद्धिक संपदा के अधिकार, सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद, प्रतिस्पर्धा के लिए नियामक उपाय भी शामिल हो सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत-यूके एफटीए एक समकालीन, साहसिक और सर्वव्यापी समझौता है जो दो लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक आर्थिक कूटनीति का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यापार एकीकरण को मजबूत करता है, बाजार पहुंच में सुधार करता है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है और वैश्विक मुद्दों से मिलकर निपटने की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

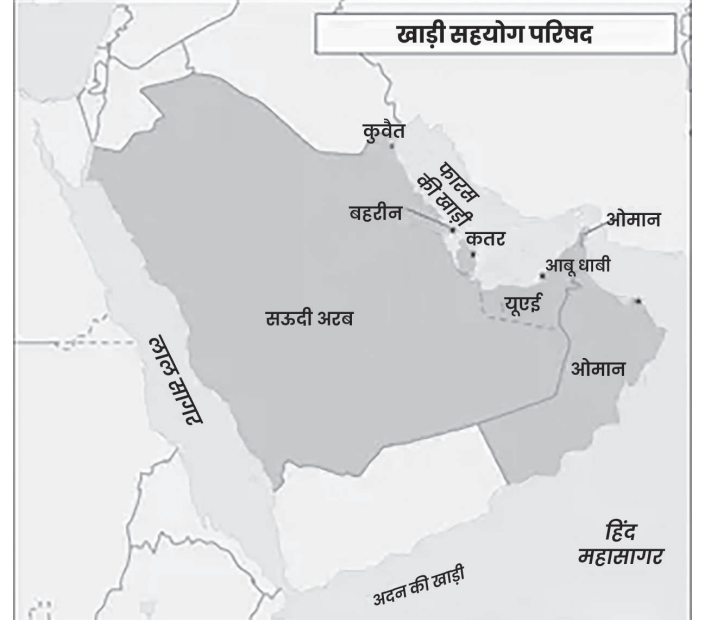
प्रश्न. हाल ही में संपन्न भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को भारत द्वारा हस्ताक्षरित सबसे महत्वाकांक्षी और व्यापक व्यापार समझौतों में से एक बताया गया है। समझौते की प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक जांच करें और समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और भारत के रणनीतिक व्यापार उद्देश्यों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता का मूल्यांकन करें। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद

चर्चा में क्यों: भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और व्यापार घाटे को दूर करने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्यों के साथ सक्रिय रूप से व्यापार समझौते कर रहा है।

भारत-जीसीसी संबंध

- खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ भारत के संबंध बहुआयामी हैं, जो ऐतिहासिक संबंधों से आगे बढ़कर रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों को भी शामिल करते हैं।
- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई से मिलकर बना जीसीसी भारत के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि यह उसका विस्तारित पड़ोस है।



रणनीतिक महत्व और संवाद

- **साझा सुरक्षा चिंताएँ:** भारत और जीसीसी दोनों खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा की इच्छा रखते हैं। यह शांति और स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयासों में तब्दील हो जाता है, जिससे भविष्य में सहयोग के अवसर पैदा होते हैं।
 - बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और भू-राजनीतिक घटनाक्रम, जैसे कि यूक्रेन और गाजा में युद्ध, ईरान और इजरायल के बीच छद्म युद्ध और अन्य क्षेत्रों में तनाव, अधिक सहयोग की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित करते हैं।
- **रणनीतिक वार्ता का विकास**
 - पहली भारत-जीसीसी राजनीतिक वार्ता 26 सितंबर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई थी।
 - विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की रियाद यात्रा के दौरान 10 सितंबर, 2022 को परामर्श के तंत्र पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
 - पहली भारत-जीसीसी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 मार्च, 2023 को रियाद में आयोजित की गई थी।
 - सामरिक वार्ता के लिए पहली भारत-जीसीसी संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक 9 सितंबर, 2024 को रियाद में आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जीसीसी मंत्रिस्तरीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में की। इस बैठक में सभी जीसीसी राज्यों के विदेश मंत्रियों और जीसीसी महासचिव ने भाग लिया।
- **संयुक्त कार्य योजना:** मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, एक संयुक्त कार्य योजना 2024-2028 को अपनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा और संस्कृति सहित विविध क्षेत्रों में विभिन्न संयुक्त गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें और क्षेत्रों को जोड़ने का विकल्प भी शामिल है।

- **व्यापार की माला और संतुलन**
 - जीसीसी भारत के विदेशी व्यापार के लिए सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉकों में से एक है।
 - वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत और जीसीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार 161.59 बिलियन डॉलर रहा। इसमें भारत के कुल विदेशी व्यापार का 14.22% हिस्सा शामिल था।
 - भारत द्वारा बड़ी माला में तेल और गैस आयात के कारण व्यापार संतुलन जीसीसी के पक्ष में है। वित्त वर्ष 2023-24 में, जीसीसी से भारत का आयात \$105.49 बिलियन (या \$105.3 बिलियन) था, जबकि निर्यात \$56.3 बिलियन था।
 - अलग-अलग जीसीसी देशों के लिए विशिष्ट व्यापार आंकड़े सऊदी अरब और यूएई को प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में दिखाते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा**
 - जीसीसी देशों के पर्याप्त तेल और गैस भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
 - ऐतिहासिक रूप से, भारत के हाइड्रोकार्बन आयात का लगभग 50-60% जीसीसी देशों से आता था।
 - यद्यपि भारत ने अपने ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाई है और रूसी कच्चे तेल के आयात में वृद्धि की है, भारत की तेल और गैस आपूर्ति में जीसीसी का योगदान 2023-24 में 28% पर महत्वपूर्ण बना हुआ है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत भारत के कच्चे तेल और गैस के शीर्ष 10 आपूर्तिकर्ताओं में से हैं।
 - रूसी शिपिंग पर संभावित कड़े प्रतिबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी की प्रासंगिकता को मजबूत करते हैं।
- **निवेश के अवसर**
 - जीसीसी देश भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं।
 - अप्रैल 2000 और जून 2024 के बीच, भारत को जीसीसी देशों से 24.66 बिलियन डॉलर का सामूहिक एफडीआई प्राप्त हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं हैं।
 - व्यापार का विस्तार जीसीसी के लिए भारत में निवेश के अवसर भी खोलता है, विशेष रूप से डाउनस्ट्रीम ऊर्जा परियोजनाओं में। कुछ सदस्यों, विशेष रूप से सऊदी अरब ने भारतीय पेट्रोलियम शोधन क्षमता में निवेश किया है, हालांकि क्षमता का बड़े पैमाने पर दोहन नहीं किया गया है। रूस अब तक भारत के डाउनस्ट्रीम ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेशक रहा है।
 - जीसीसी का भारतीय इक्विटी में भी काफी निवेश है, और कर संधियाँ भविष्य की भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं।
- **भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)**
 - एफटीए पर चर्चाओं ने गति पकड़ी है, खासकर भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करने के बाद।
 - एफटीए के लिए प्रारंभिक रूपरेखा समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद 2006 और 2008 में दो दौर की वार्ता हुई थी।
 - क्षेत्र में राजनीतिक चुनौतियों (अरब स्प्रिंग 2010-11) के कारण चर्चा बाधित हुई, लेकिन नवंबर 2022 में एफटीए को पुनर्जीवित करने के इरादे की घोषणा की गई और वार्ता जारी है।

लोगों से लोगों के बीच संपर्क

- **भारतीय प्रवासी:** जीसीसी देश विश्व के सबसे बड़े प्रवासी भारतीय समुदायों में से एक हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 8.5 मिलियन है, जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों का सबसे बड़ा संकेन्द्रण है।
- **प्रेषण:** जीसीसी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी भारत में भेजे जाने वाले धन का दुसरा सबसे बड़ा हिस्सा हैं। 2023 में भारत में प्राप्त होने वाले लगभग 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रेषण में वे सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। हालांकि जीसीसी से भेजे जाने वाले धन का हिस्सा 2016-17 में 50% से घटकर 2020-21 में लगभग 30% रह गया, लेकिन यह अभी भी भारत के कुल आवक प्रेषण का एक बड़ा हिस्सा है।
- **कल्याण संबंधी चिंताएँ:** खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण को लेकर भारत की चिंताएँ जायज़ हैं। व्यापार और निवेश संधियों पर बातचीत में भारत की ओर से इसे एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे जीसीसी को निपटना होगा क्योंकि इसके सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ विविधतापूर्ण हो रही हैं।

आगे की राह: विकसित होता सहयोग और भविष्य की चुनौतियाँ

- **जीसीसी अर्थव्यवस्थाओं का विविधीकरण:** जीसीसी देश तेल-पश्चात अर्थव्यवस्था की तैयारी में आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, यह प्रक्रिया अरब स्प्रिंग और कोविड-19 के बाद से तेज हो गई है। यह विविधीकरण भारत के साथ सहयोग के लिए नए रास्ते खोलता है।
- **सहयोग के नए क्षेत्र**
 - स्वास्थ्य सेवा
 - बुनियादी ढांचे का विकास
 - खाद्य सुरक्षा
 - डिजिटल अर्थव्यवस्था
 - एआई और मशीन लर्निंग
 - अंतरिक्ष अन्वेषण
 - जलवायु परिवर्तन से लड़ना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना
 - स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना
- **सुरक्षा और रक्षा संबंध:** भारत और जीसीसी ने आतंकवाद निरोध, समुद्री और तटीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है। भारत संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ रक्षा व्यापार को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है, जिसमें संभावित संयुक्त विनिर्माण भी शामिल है।
- **रणनीतिक अभिसरण:** भारत की आर्थिक वृद्धि और क्षमता इसे जीसीसी देशों के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण बनाती है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव के बीच बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी विकसित करना चाहते हैं। आर्थिक समृद्धि, भूमि और समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, खाद्य, स्वास्थ्य और जलवायु सुरक्षा, सांस्कृतिक सहयोग और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने की साझा चुनौतियाँ उनके बढ़ते रणनीतिक अभिसरण में सबसे आगे हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत और जीसीसी के बीच रणनीतिक अभिसरण के प्रमुख चालक क्या हैं? भारत और जीसीसी के संबंध पारंपरिक ऊर्जा और व्यापार से परे कैसे विकसित हुए हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

निष्पक्ष और समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली की ओर

चर्चा में क्यों: हाल ही में पेरिस में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक में, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने और गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कारण होने वाली व्यापार विकृतियों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

वर्तमान वैश्विक व्यापार परिदृश्य में चुनौतियाँ

- **WTO विवाद निपटान तंत्र की निष्क्रियता:** WTO का अपीलीय निकाय, जो व्यापार विवादों के लिए अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करता है, दिसंबर 2019 से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नए सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध करने के कारण निष्क्रिय है। इस निष्क्रियता ने WTO की विश्वसनीयता और वैश्विक व्यापार नियमों को लागू करने की इसकी क्षमता को कमजोर किया है, जिससे नियम-आधारित व्यवस्था कमजोर हुई है।
- **संरक्षणवादी उपायों का उदय:** व्यापार युद्धों के बढ़ने, विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच, ने संरक्षणवादी नीतियों में उछाल ला दिया है। टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, जिससे विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं जो निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- **एकतरफा हरित बाधाओं में वृद्धि:** जबकि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय व्यापार बाधाओं की शुरुआत - जैसे यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) - अक्सर गरीब देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं की अनदेखी करता है। ये हरित उपाय नव-संरक्षणवादी उपकरण बनने का जोखिम उठाते हैं जो स्थिरता की आड़ में विकासशील देशों के लिए बाजार तक पहुँच को प्रतिबंधित करते हैं।
- **जटिल विनियामक ढाँचे:** भारत ने जटिल विनियामक ढाँचों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की ओर इशारा किया है, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में, जो निर्बाध व्यापार और निवेश में बाधा डाल सकते हैं। बेहतर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन विनियमों को सरल बनाना महत्वपूर्ण है।
- **डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स नियमों में असमानता:** डेटा स्थानीयकरण, सीमा पार डिजिटल प्रवाह और डिजिटल दिग्गजों के कराधान जैसे उभरते क्षेत्र ऐसे मानदंडों द्वारा शासित होते हैं जो तकनीक-भारी विकसित देशों के पक्ष में हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ बाध्यकारी वैश्विक नियमों पर सहमत होने से पहले अपनी स्वयं की डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करने के लिए नीतिगत स्थान की माँग करती हैं।
- **प्रतिनिधित्व और आवाज़ की कमी:** वैश्विक व्यापार वार्ता अक्सर वैश्विक दक्षिण को हाशिए पर डाल देती है। कई निम्न-विकसित और कम आय वाले देशों में निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए संसाधनों या बातचीत की शक्ति का अभाव है, जिसके कारण व्यापार के परिणाम ऐसे होते हैं जो उनकी अनूठी चुनौतियों और विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं।
- **विकसित देशों का असंगत प्रभाव:** मौजूदा व्यापार व्यवस्था अक्सर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाती है, जिससे वे विकासशील देशों की चिंताओं को दरकिनार करते हुए अपने पक्ष में नियम बनाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, विकसित देश अपने व्यापार नियमों को बनाए रखते हैं। कृषि के लिए उच्च सब्सिडी, जबकि विकासशील देशों से अपने किसानों के लिए समर्थन कम करने का आग्रह करना - एक असमान खेल मैदान बनाना।

पत्रिका का जनवरी 2025 का अंक विश्व व्यापार संगठन के बारे में गहन कवरेज प्रदान करता है।

एक निष्पक्ष व्यापार प्रणाली की दिशा में भारत की पहल

- **WTO सुधारों की वकालत:** भारत WTO में सुधार की आवश्यकता के बारे में मुखर रहा है ताकि इसे और अधिक समावेशी और विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला बनाया जा सके। अपीलीय निकाय को बहाल करना और विवाद निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना:** भारत पारस्परिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से, भारत भागीदार देशों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है, जिससे साझा विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **रणनीतिक व्यापार समझौते:** भारत ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है, जो महत्वपूर्ण खनिजों, सेवाओं, कृषि और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन समझौतों का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना और पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करना है।
- **समावेशी विकास पर जोर:** भारत की व्यापार नीतियाँ तेजी से समावेशिता पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यापार का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। कृषि और लघु उद्योगों जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर, भारत का लक्ष्य व्यापार को व्यापक विकास का साधन बनाना है।

निष्कर्ष

- भारत विश्व व्यापार संगठन में सुधारों पर जोर देकर, व्यापार विकृतियों को संबोधित करके और हरित और डिजिटल संरक्षणवाद का विरोध करके एक अधिक निष्पक्ष और समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली की वकालत कर रहा है। रणनीतिक व्यापार साझेदारी, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करके, भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वैश्विक व्यापार नियम विकासशील देशों की जरूरतों के लिए न्यायसंगत और उत्तरदायी हों।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. विश्व व्यापार संगठन में बढ़ते संरक्षणवाद और प्रणालीगत चुनौतियों के मद्देनजर, निष्पक्ष और समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए भारत का प्रयास समयोचित और आवश्यक दोनों है। वैश्विक व्यापार सुधारों के लिए भारत के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक जांच करें और विकासशील देशों के लिए इसके निहितार्थों का मूल्यांकन करें। [250 शब्द] [15 अंक]

बांडुंग सम्मेलन और वैश्विक दक्षिण

चर्चा में क्यों: वर्ष 2025 प्रथम एशिया-अफ्रीका शिखर सम्मेलन की 70वीं वर्षगांठ होगी, जो 18 से 24 अप्रैल, 1955 तक बांडुंग, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था।

बांडुंग सम्मेलन के बारे में

- बांडुंग सम्मेलन, जिसे एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन था जो 18 से 24 अप्रैल, 1955 को बांडुंग, इंडोनेशिया में हुआ था।
- यह एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्रता नेताओं की पहली शिखर-स्तरीय बैठक थी।
- इस बैठक के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों की उनतीस सरकारों के प्रतिनिधि एकत्र हुए।

- सम्मेलन के सह-प्रायोजकों में बर्मा, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व से अतिरिक्त चौबीस देशों को एक साथ लाया।
- उल्लेखनीय रूप से, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, बर्मा के प्रधानमंत्री यू नू और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर उपस्थित नेताओं में से थे।

ऐतिहासिक संदर्भ और प्रेरणा

- सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद की लहर के संदर्भ में हुआ। भाग लेने वाले कई देशों ने हाल ही में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
- संयोजक नए स्वतंत्र, विकासशील राष्ट्रों के रूप में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए संप्रभु, स्वतंत्र और सामूहिक कार्रवाई का एक नया मार्ग तैयार करने के सामान्य लक्ष्यों से प्रेरित थे।
- वे वैश्विक मंच के हाशिये पर होने से असंतुष्ट थे।
- नेताओं को एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण कारक अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ बातचीत में पूर्व औपनिवेशिक अधिपतियों और अन्य पश्चिमी शक्तियों द्वारा अनिच्छा और निरंतर आधिपत्यपूर्ण कार्यवाहियाँ थीं।
- **बांडुंग स्पिरिट:** बांडुंग में एकल होने को उनके पूर्वजों और युवा पीढ़ी के लोगों द्वारा किए गए बलिदानों के परिणामस्वरूप देखा गया।

मुख्य सिद्धांत

- मौलिक मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए सम्मान।
- सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान।
- सभी जातियों की समानता और सभी राष्ट्रों, बड़े और छोटे, की समानता की मान्यता।
- किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप या दखलंदाजी से परहेज।
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप, प्रत्येक राष्ट्र के अकेले या सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करने के अधिकार का सम्मान।
- किसी भी बड़ी शक्ति के विशेष हितों की पूर्ति के लिए सामूहिक रक्षा की व्यवस्था के उपयोग से परहेज। किसी भी देश द्वारा अन्य देशों पर दबाव डालने से परहेज।
- किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध आक्रामकता या बल के उपयोग की धमकियों या कृत्यों से बचना।
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप, सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा, जैसे कि बातचीत, सुलह, मध्यस्थता या न्यायिक निपटान, साथ ही पार्टियों की अपनी पसंद के अन्य शांतिपूर्ण तरीके।
- आपसी हितों और सहयोग को बढ़ावा देना।
- न्याय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के प्रति सम्मान।

सम्मेलन की विरासत

- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन:** बांडुंग सम्मेलन और इसके अंतिम प्रस्ताव ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की नींव रखी। एनएएम की स्थापना 1961 में हुई थी।
- इसके बाद 1964 में ग्रुप ऑफ 77 (जी77) की स्थापना हुई।
- इन दो बहुपक्षीय समूहों ने विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को व्यक्त करने और एकता को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान किया।
- सम्मेलन ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग और एकजुटता की एक नई लहर को गति दी। तीसरी दुनिया या दक्षिण की अवधारणा भी इसी बैठक से उत्पन्न हुई।

- बांडुंग के मूल सिद्धांत - पारस्परिक हित, एकजुटता और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति सम्मान - विकासशील देशों के बीच संबंधों का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं।
- शुरुआती गति और एनएएम और जी77 के बाद के गठन के बावजूद, ग्लोबल साउथ एक अवधि के लिए वैश्विक भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के हाशिये पर रहा।
- बांडुंग की भावना से उत्पन्न एकजुटता 1960 के दशक के अंत तक कमजोर हो गई थी, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि अधिकांश मूल नेता अब सत्ता में नहीं थे।

चुनौतियाँ

- बांडुंग द्वारा समर्थित आर्थिक स्वतंत्रता और समतावादी विकास पथ अभी भी काफी हद तक साकार नहीं हुआ है।
- सम्मेलन के सत्तर साल बाद, वैश्विक दक्षिण को अभी भी स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करते हुए वर्णित किया जाता है, जबकि उत्तर को अभी भी निर्णय लेने वाला माना जाता है और दक्षिण को "उधार के सपनों" की कीमत चुकानी पड़ती है।
- कई उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रों ने, बांडुंग के आदर्शों को अपनाने के कुछ समय बाद, कथित तौर पर साम्राज्यवाद का विरोध करने और स्वतंत्र विकास रणनीतियों को आगे बढ़ाने की इच्छा खो दी।
- 1970 के दशक में विकास गतिरोध का सामना करते हुए, कई लोगों ने वैश्विक वित्त की ओर रुख किया और विदेशी पूंजी का सामना करने और घरेलू क्षमताओं का निर्माण करने के बजाय नवउदारवाद को अपनाया।

वर्तमान प्रासंगिकता

- सत्तर साल बाद, बांडुंग सम्मेलन के सिद्धांतों को आज भी उतना ही प्रासंगिक माना जाता है जितना कि वे 1965 में थे।
- वैश्विक दक्षिण के देशों को उभरते बहुध्रुवीय विश्व को आकार देने में सबसे आगे होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक समुदाय पर केंद्रित है।
- सिद्धांत समकालीन चुनौतियों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय असमानता, ऋण जाल, जलवायु संकट की जिम्मेदारी, तथा विकसित देशों का अंतर्मुखी होना, से निपटने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

आगे की राह और निष्कर्ष

- वैश्विक दक्षिण को बांडुंग भावना की नई प्रासंगिकता को पहचानने तथा विश्व मंच पर अपनी सामूहिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- इसमें साझा चुनौतियों तथा साझा हितों से निपटने के लिए आपस में तथा समान विचारधारा वाले वैश्विक उत्तर देशों के साथ नई साझेदारी बनाने में नेतृत्व का प्रदर्शन करना शामिल है।
- अपने अधूरे आर्थिक लक्ष्यों और वैश्वीकरण तथा नवउदारवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, बांडुंग भावना दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रेरित और सक्रिय करती रहती है।
- वैश्विक दक्षिण द्वारा अपने विकास एजेंडे को पुनः प्राप्त करने के लिए इस भावना को पुनर्जीवित करना आवश्यक माना जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. बांडुंग सम्मेलन के सिद्धांत कैसे विकसित हुए हैं और आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं? वर्तमान बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में वैश्विक दक्षिण क्या भूमिका निभा सकता है? [250 शब्द] [15 अंक]

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

चर्चा में क्यों: वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान के हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में किसी भी परमाणु सुविधा से कोई विकिरण रिसाव या उत्सर्जन नहीं हुआ।

मुख्य विवरण

- IAEA एक वैश्विक संगठन है जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना है, जबकि परमाणु हथियारों जैसे सैन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को रोकना है।
- मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया
- इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में की गई थी।
- यद्यपि संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से बनाया गया है, IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है।
- परमाणु प्रौद्योगिकियों के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर, IAEA वैश्विक शांति और सुरक्षा में सहायता करता है और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति का समर्थन करता है।
- IAEA जिनेवा, न्यूयॉर्क, टोरंटो और टोक्यो में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ ऑस्ट्रिया, इटली और मोनाको में स्थित अनुसंधान प्रयोगशालाओं का संचालन करता है।
- IAEA परमाणु प्रौद्योगिकी और शक्ति के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक वैश्विक अंतर-सरकारी मंच के रूप में कार्य करता है।
- IAEA की पहल परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग की उन्नति को बढ़ावा देती है; परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक सुरक्षा उपाय प्रदान करती है; और परमाणु सुरक्षा (विकिरण सुरक्षा सहित) के साथ-साथ परमाणु सुरक्षा मानकों की स्थापना और प्रवर्तन की वकालत करती है।
- IAEA प्रबंधन:** IAEA में दो निर्णय लेने वाली इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें शामिल हैं:
 - महासभा और शासी बोर्ड

- महासभा
 - ◆ इसमें IAEA के सभी सदस्य राष्ट्र शामिल हैं।
 - ◆ यह एक वार्षिक बैठक में बुलाई जाती है।
- शासी बोर्ड
 - ◆ इसमें, सदस्यों की कुल संख्या 35 है।
 - ◆ बोर्ड आम तौर पर सालाना पाँच बार बुलाई जाती है।
 - ◆ यह संगठन के कार्यक्रम, वित्तीय रिपोर्ट और बजट के संबंध में IAEA के महाधिवेशन का विश्लेषण करता है और सुझाव देता है।
 - ◆ बोर्ड सदस्यता आवेदनों की समीक्षा करता है, सुरक्षा समझौतों का समर्थन करता है और IAEA के सुरक्षा मानकों को जारी करने को अधिकृत करता है।
 - ◆ यह महाधिवेशन की स्वीकृति के लंबित रहने तक IAEA के महानिदेशक को भी नामित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- इसे 1957 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति जवाबदेह है।
- यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और ऑस्ट्रिया और मोनाको जैसे देशों में अनुसंधान प्रयोगशालाएँ संचालित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(C) :2020

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल **CCHAAHAL**
ACADEMY

‘द हिंदू’ और ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें





The Indian EXPRESS



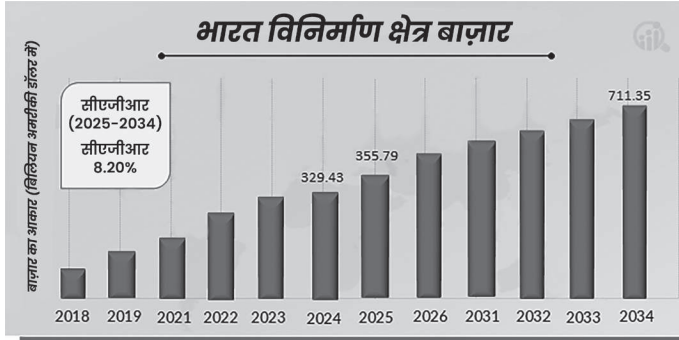
THE HINDU

विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि

चर्चा में क्यों: हालिया अध्ययन भारत में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के लिए उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार-प्रेरित उद्योगों के माध्यम से एक मौलिक पुनर्संरखन की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की वर्तमान स्थिति:

- जीडीपी योगदान:** विनिर्माण क्षेत्र वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 17% का योगदान देता है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदर्शन:** विनिर्माण क्षेत्र ने उत्पादन में ₹14 लाख करोड़ और निर्यात में ₹5.3 लाख करोड़ हासिल किए और 11.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये।
- विकास दर:** विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले दशक में 5.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 23 में 14.3 प्रतिशत का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) हुआ और इसी अवधि के दौरान उत्पादन में 35.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही।
- विनिर्माण के लिए ऋय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई):** यह वित्त वर्ष 24 के सभी महीनों में लगातार 50 की सीमा मूल्य से ऊपर रहा।



चुनौतियाँ

- विनिर्माण में प्रति व्यक्ति मूल्य वर्धन:** भारत के लिए, 2023 में, प्रति व्यक्ति मूल्य वर्धन \$0.32K (K:1000) रहा है, और उत्पादकता \$8.9 K है, जबकि विश्व औसत के लिए ये आँकड़े क्रमशः \$2 K और \$32 K हैं।
- भारत के लिए कुल मूल्य वर्धन \$461 बिलियन है, जबकि चीन के लिए यह \$4,658 बिलियन और अमेरिका के लिए \$2,497 बिलियन है।
- अवसंरचना:** डिजिटल और भौतिक अवसंरचना दोनों में अपर्याप्त कनेक्टिविटी विनिर्माण और परिचालन व्यय की लागत को बढ़ाती है।
- ऋण उपलब्धता:** बैंक जैसे वित्तीय संस्थान एमएसएमई को उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं, सख्त संपार्श्विक आवश्यकताओं के साथ ऋण तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** चीन और जापान जैसे स्थापित देशों के साथ-साथ वियतनाम और मैक्सिको जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से, उनके बेहतर बुनियादी ढांचे और कम उत्पादन लागत के कारण।

- श्रम मुद्दे:** एक बड़ी श्रम शक्ति होने के बावजूद, कुशल श्रम की दुर्लभ उपलब्धता विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता को प्रभावित करती है।
- विनियामक कोलेस्ट्रॉल:** विभिन्न कानून और विनियमन (श्रम, पर्यावरण, आदि) विनिर्माण गतिविधियों में देरी करते हैं, जिससे निवेशक हतोत्साहित होते हैं।
- अनुसंधान और विकास निवेश:** सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.65% अनुसंधान और विकास की ओर जाता है, यह नवाचार-आधारित विनिर्माण में गंभीर रूप से बाधा डालता है और इसे व्यापक रूप से अपनाया जाता है।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन

- इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। यह मिशन 'मेक इन इंडिया' विजन को आगे बढ़ाने के लिए सभी आकार के उद्योगों- छोटे, मध्यम और बड़े- को लक्षित करता है।
- यह पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: व्यापार करने की आसानी और लागत में सुधार, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करना, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित करना और उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों दोनों के लिए नीति समर्थन, विस्तृत कार्यान्वयन योजनाएँ और मजबूत शासन और निगरानी तंत्र प्रदान करेगी।
- मिशन, घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर और नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइट्स, पवन टर्बाइन, उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन गियर और ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण जैसे उत्पादों के लिए एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना चाहता है। यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी बढ़ावा देगा।

आगे की राह

- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई):** श्रम-प्रोत्साहन क्षेत्रों में पीएलआई प्रोत्साहनों का विस्तार उच्च विकास और रोजगार पैदा करने में मदद करेगा।
- विनियामक कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना:** विभिन्न श्रम और पर्यावरण विनियमों का अनुपालन करने के लिए एकल-खिड़की निकासी प्रणाली बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार ताकि व्यापार करने में आसानी हो सके।
- विनिर्माण में महिलाएँ:** विश्व बैंक के हालिया अनुमानों के अनुसार, यदि अधिक महिलाएँ कार्यबल में शामिल होती हैं तो भारत का विनिर्माण उत्पादन 9% तक बढ़ सकता है।
- बुनियादी ढांचा:** रसद और बिजली उत्पादन में निवेश दक्षता को बहुत बढ़ा सकता है और माल की ढुलाई के समय और लागत को कम कर सकता है।
- श्रमिकों का कौशल:** आधुनिक विनिर्माण की माँगों को पूरा करने के लिए श्रमिकों को आवश्यक कौशल से लैस करना।
- डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना:** विनिर्माण प्रक्रिया में डिजिटल तकनीकों को एकीकृत करने से दक्षता और उत्पादकता में सुधार हो सकता है।

- **एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करना:** एमएसएमई भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 45% का योगदान करते हैं और लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं।

निष्कर्ष

वैश्विक विनिर्माण और व्यापार तेजी से नवाचार-संचालित और उच्च तकनीक वाले उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार, एक विकसित वैश्विक वातावरण में अभिनव नीतियों को डिजाइन करने के लिए एक ठोस नीति प्रणाली की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने हाल के वर्षों में मध्यम वृद्धि हासिल की है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अभी भी पीछे है। इस खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करें और समावेशी और संधारणीय विनिर्माण विकास के लिए एक रोडमैप सुझाएं। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना

चर्चा में क्यों: नीति आयोग ने 'भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना' पर रिपोर्ट जारी की, जिसे नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (आईएफसी) के सहयोग से तैयार किया है।

रिपोर्ट में वित्तपोषण, कौशल, नवाचार और बाजार पहुंच में व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट से मुख्य बिंदु

- **क्षेत्रीय और स्वामित्व संरचना**
 - स्वामित्व और साझेदारी एमएसएमई में 74.3% कर्मचारी गैर-कृषि क्षेत्र में हैं।
 - 81% एमएसएमई स्वामित्व के रूप में काम करते हैं, जिनमें से 80% सूक्ष्म-उद्यमों के रूप में वर्गीकृत हैं।
- **नीतिगत अंतराल**
 - अनेक नीतियों के बावजूद, उनका प्रभाव कम जागरूकता और अपर्याप्त हितधारक सहभागिता के कारण सीमित है।
 - अधिक अनुकूली, डेटा-संचालित और क्षेत्रीय रूप से समन्वित नीति ढांचों की आवश्यकता है।

भारत में एमएसएमई का महत्व

- **भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार:** एमएसएमई को भारत की अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें पारंपरिक कारीगरों से लेकर उन्नत इंजीनियरिंग फर्मों तक की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- **वे दोहरी भूमिका निभाते हैं:**
 - सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।
 - भविष्य की आर्थिक वृद्धि और नवाचार को आगे बढ़ाना।
- **जीडीपी:** वित्तीय वर्ष 2021-22 में, एमएसएमई सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 29.2% था।
- **विनिर्माण:** इसी अवधि में भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई विनिर्माण उत्पादन का हिस्सा 36.2% था।

- **निर्यात:** एमएसएमई-निर्दिष्ट उत्पादों ने भारत के कुल निर्यात का 45% प्रतिनिधित्व किया।
- **रोजगार सृजन:** एमएसएमई ने भारत में विभिन्न उद्योगों में लगभग 120 मिलियन रोजगारों का सृजन किया है।
- **क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में भूमिका:** वे खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं।

एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- **वित्तीय बाधाएं**
 - उच्च जोखिम की धारणा और लागत औपचारिक ऋण तक पहुंच को सीमित करती हैं।
 - अपर्याप्त वित्त अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी उन्नयन में निवेश को प्रतिबंधित करता है।
- **तकनीकी अंतराल**
 - वैश्विक प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच।
 - उच्च लागत और संसाधन की कमी घरेलू नवाचार में बाधा डालती है।
- **कौशल और क्षमता की कमी**
 - व्यापक वित्तीय निरक्षरता और कौशल अंतराल।
 - सरकारी पहलों और क्षमता निर्माण के अवसरों के बारे में जागरूकता की कमी।
- **विनियामक और बाजार बाधाएं**
 - अनौपचारिक संचालन की प्रधानता वित्त और वैश्विक बाजारों तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है।
 - कमजोर ब्रांडिंग और सीमित उत्पाद विविधता एमएसएमई को बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है।

एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सिफारिशें

- **वित्त तक पहुंच**
 - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) की विनियामक निगरानी को मजबूत करना।
 - महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए 100% गारंटीकृत कवरेज और कम प्रीमियम दरों के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना।
 - बेहतर ऑन-लेंडिंग संरचनाओं और कम दर वाले थोक वित्तपोषण के साथ NBFC का समर्थन करना।
 - एमएसएमई वित्तपोषण के लिए NBFC को बैंक ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों को बहाल करना।
- **कौशल चुनौतियों का समाधान करना**
 - गतिशील, प्रासंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए सरकार, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच साझेदारी बनाना।
 - प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने को सब्सिडी देने के लिए लागत-साझाकरण या अनुदान-आधारित मॉडल लागू करना।
 - व्यावसायिक मानकों को अद्यतन करने और समय-समय पर उद्योग की जरूरतों के साथ प्रशिक्षण को संरेखित करने के लिए बोर्ड स्थापित करना।
- **तकनीकी विकास और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण**
 - वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में एमएसएमई की भागीदारी को सक्षम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण में सुधार करना।

- रसद, डिजिटल लिंकेज और व्यापार बुनियादी ढांचे में निवेश करना।
- नवाचार और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज प्लेटफॉर्म और व्यापार मेलों जैसी क्षेत्र-विशिष्ट पहलों का समर्थन करना।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का लाभ उठाना**
 - डेटा सुरक्षा और एआई अपनाने पर सरकार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान शुरू करना।
 - एमएसएमई को एआई विशेषज्ञों और संस्थानों से जोड़ने वाले सहयोगी प्लेटफॉर्म बनाना।
 - वित्तीय सहायता (अनुदान, सब्सिडी, कर प्रोत्साहन) प्रदान करना और किफायती, क्लाउड-आधारित एआई समाधानों को बढ़ावा देना।
- **जोखिम प्रबंधन को बढ़ाना**
 - किफायती डिजिटल जोखिम प्रबंधन और बीमा समाधानों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले एमएसएमई के लिए।
 - परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए वास्तविक समय निगरानी उपकरणों (जैसे, सेंसर-आधारित ट्रेकिंग) को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

- भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता वित्तीय, तकनीकी, कौशल और नीति चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित प्रयासों पर निर्भर करती है। एमएसएमई की विकास क्षमता को अनलॉक करने और भारत के आर्थिक विकास में उनके निरंतर योगदान को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीति हस्तक्षेप और क्षमता निर्माण के साथ एक क्लस्टर-आधारित, डेटा-संचालित दृष्टिकोण आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए एमएसएमई के महत्व पर चर्चा करें। भारतीय एमएसएमई की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालने वाली महत्वपूर्ण बाधाएँ क्या हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

भारत के निर्यात में वृद्धि

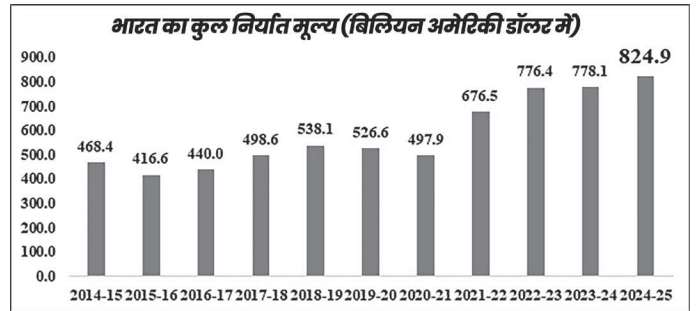
चर्चा में क्यों: भारत का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में \$824.9 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले वर्ष के FY24 के \$778.1 बिलियन के निर्यात आंकड़े की तुलना में 6.01% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालक

- भारत के कुल निर्यात में मजबूत वृद्धि मुख्य रूप से सेवा निर्यात में उछाल के कारण हुई, जिसके पूरक के रूप में गैर-पेट्रोलियम माल निर्यात में वृद्धि हुई।
- **सेवा निर्यात**
 - सेवा निर्यात ने अपनी मजबूत वृद्धि गति जारी रखी, जो वित्त वर्ष 25 में \$387.5 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
 - यह पिछले वर्ष (FY24) के \$341.1 बिलियन से 13.6% की वृद्धि दर्शाता है।
 - यह उछाल भारत की आईटी, व्यापार, वित्तीय और यात्रा-संबंधी सेवाओं की निरंतर वैश्विक मांग को दर्शाता है।

व्यापारिक निर्यात

- वित्त वर्ष 25 के दौरान व्यापारिक निर्यात का संचयी मूल्य \$437.42 बिलियन था, जो वित्त वर्ष 24 में \$437.07 बिलियन की तुलना में 0.08% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर व्यापारिक निर्यात, वित्त वर्ष 25 में रिकॉर्ड \$374.1 बिलियन तक पहुंच गया।
- इस खंड ने वित्त वर्ष 24 में \$352.9 बिलियन से 6% की वृद्धि दर्ज की, जो अब तक का सबसे अधिक वार्षिक गैर-पेट्रोलियम व्यापारिक निर्यात है।
- **वित्त वर्ष 25 में व्यापारिक निर्यात वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता निम्नलिखित थे:**
 - ◆ **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ:** चावल, कॉफी, मांस, चाय, जूट, फल और सब्जियां।
 - ◆ **औद्योगिक सामान:** इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, आरएमजी वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, खनिज।



निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण कारक

- **बाजार विविधीकरण:** दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बढ़ती मांग ने वैश्विक आर्थिक मंदी का मुकाबला करने में मदद की।
- **व्यापार समझौते:** भारत-यूईई सीईपीए जैसे समझौतों ने बाजार पहुंच का विस्तार किया और व्यापार बाधाओं को कम किया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं के लिए।
- **नीति समर्थन:** सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति, लक्षित क्षेत्रीय योजनाओं, व्यापार सुविधा, निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों और एमएसएमई सहायता के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया।
- **आपूर्ति श्रृंखला बदलाव:** भारत चीन-प्लस-वन रणनीतियों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा, जिसने वैश्विक फर्मों से रुचि आकर्षित की।

व्यापार घाटा और महत्वपूर्ण रुझान

- मजबूत निर्यात प्रदर्शन के बावजूद, वित्त वर्ष 25 में भारत का कुल माल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 24 में \$241.14 बिलियन की तुलना में बढ़कर \$282.82 बिलियन हो गया।
- मार्च 2025 में, भारत का व्यापार घाटा फरवरी में तीन साल के निचले स्तर 14.05 बिलियन डॉलर से बढ़कर 21.54 बिलियन डॉलर हो गया।
- वित्त वर्ष 25 के लिए व्यापारिक आयात 720.24 बिलियन डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 24 में 678.21 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- **अमेरिका के साथ व्यापार संबंध:** अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष वित्त वर्ष 25 में 16.6% बढ़कर 41.18 बिलियन डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 35.32 बिलियन डॉलर था। यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे।

- अमेरिका को भारतीय माल निर्यात 11.6% बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 77.52 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 25 में 86.51 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि अमेरिका से आयात 7.42% बढ़कर 42.20 बिलियन डॉलर से 45.33 बिलियन डॉलर हो गया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

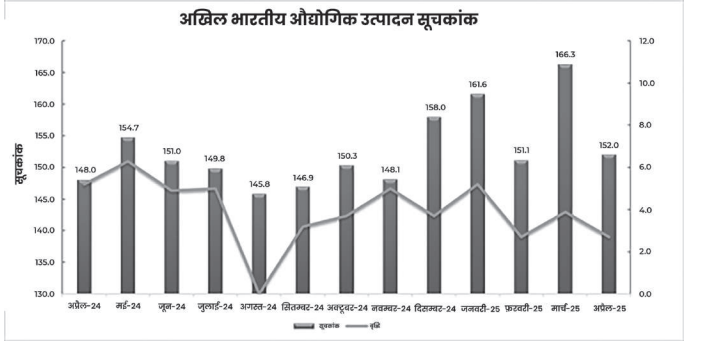
प्रश्न: भारत के हालिया निर्यात वृद्धि के पीछे प्रमुख चालक क्या हैं, और भारत के कुल व्यापार में माल निर्यात की तुलना में सेवा निर्यात कितना महत्वपूर्ण है? [150 शब्द] [10 अंक]

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

चर्चा में क्यों: हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के अनुसार, फरवरी 2025 में औद्योगिक उत्पादन में केवल 2.9% की वृद्धि हुई, जो छह महीनों में सबसे धीमी वृद्धि को दर्शाता है, जो बाजार की 4% की उम्मीद से काफी कम है।

मुख्य विवरण

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) एक प्रमुख सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय उद्योगों में उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है।
- यह आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह एक विशिष्ट समय सीमा में औद्योगिक गतिविधि के विस्तार या संकुचन पर प्रकाश डालता है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का एक प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO), IIP प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है।
- सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। इस आधार वर्ष को समकालीन उत्पादन पैटर्न और औद्योगिक संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, क्योंकि इसे पिछले आधार वर्षों से समय-समय पर संशोधित किया गया था।
- आईआईपी की भारण-वार क्षेत्रीय संरचना:**
 - विनिर्माण: कुल भार का 77.63% - 809 मद
 - खनन: कुल भार का 14.37% - 29 मद
 - बिजली: 7.99% - 1 मद
 - फरवरी क्षेत्रीय वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष):
 - खनन: फरवरी 2024 में 8.1% से, यह अचानक गिरकर 1.6% हो गया।
 - उत्पादन: 2.9% बढ़ा, जो पिछले वर्ष की 4.9% वृद्धि से कम है।
 - बिजली के लिए उत्पादन वृद्धि फरवरी 2024 में 7.6% से गिरकर 3.6% हो गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय जैसे सरकारी संगठन नीतियों को तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
- तिमाही और अग्रिम जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुमान अभी भी IIP पर बहुत अधिक निर्भर हैं।



आठ प्रमुख उद्योग

आईआईपी में भारत: 40.27%

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

घटते भारण क्रम में सूचीबद्ध

- रिफाइनरी उत्पाद
- बिजली
- इस्पात
- कोयला
- कच्चा तेल
- प्राकृतिक गैस
- सीमेंट
- उर्वरक

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में, निम्नलिखित में से किसको सबसे कम महत्व दिया गया है?

- (a) कोयला उत्पादन (b) इस्पात उत्पादन
(c) उर्वरक उत्पादन (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(c) : 258

डिजिटल बहिष्कार और भारत के अशिक्षित गरीबों की सुभेद्यता

चर्चा में क्यों: फ्रंटलाइन पत्रिका में हाल ही में एक कॉलम और केस स्टडी जिसमें बताया गया है कि कैसे डिजिटल इंडिया को अशिक्षित लोगों को उनके अपने पैसे तक पहुँच से वंचित नहीं करना चाहिए।

संदर्भ: जैसे-जैसे भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लाखों नागरिक, खासकर जो अशिक्षित हैं या जिनकी डिजिटल साक्षरता कम है, उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने और उन्हें प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि डिजिटल बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है, कई लोगों के लिए वास्तविकता एक जटिल और अक्सर बहिष्कृत प्रणाली है।

वित्तीय पहुँच में डिजिटल विभाजन

- सतही समावेशन
 - खाता स्वामित्व बनाम प्रयोज्यता: अब कई लोगों के पास बैंक खाते और स्मार्टफोन हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कौशल की कमी है।
 - पहुँच में बाधाएँ: ओटीपी पढ़ना, बैंकिंग ऐप नेविगेट करना और डिजिटल प्रक्रियाओं को समझना सीमित साक्षरता वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ आती हैं।
- बढ़ी हुई भेद्यता
 - घोटालों के संपर्क में आना: अशिक्षित व्यक्ति अक्सर वित्तीय घोटालों और फ्रिशिंग प्रयासों के निशाने पर होते हैं, जो अक्सर वैध संचार को धोखाधड़ी से अलग करने में असमर्थ होते हैं।
 - सुरक्षा जोखिम: पासवर्ड या पिन पर निर्भरता, जिन्हें मदद के लिए दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है, अनधिकृत पहुँच और चोरी के जोखिम को बढ़ाता है।

डिजिटल डिवाइड: आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच रखने वाले लोगों और उन लोगों के बीच का अंतर जिनके पास नहीं है। इससे आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक असमानताएँ पैदा हो सकती हैं।

डिजिटल बहिष्कार: यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्ति या समूह डिजिटल तकनीकों तक पहुँचने या उनका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हाशिप पर चले जाते हैं। यह तकनीक तक पहुँच की कमी, अपर्याप्त कौशल या डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की प्रेरणा की कमी जैसे कारकों के कारण हो सकता है।

प्रणालीगत और संस्थागत चुनौतियाँ

- जटिल बैंकिंग प्रक्रियाएँ
 - KYC अनुपालन: सख्त 'अपने ग्राहक को जाने' (KYC) मानदंडों के लिए सटीक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जो अक्सर ग्रामीण और अशिक्षित आबादी के लिए अपर्याप्त या असंगत होता है।
 - खाता फ्रीज: दस्तावेज़ों में मामूली विसंगतियाँ भी खाता निलंबन का कारण बन सकती हैं, जिसके लिए जटिल और लंबी समाधान प्रक्रियाएँ आवश्यक हो जाती हैं।
- निर्भरता और शोषण
 - बिचौलियों पर निर्भरता: कई लोग अपने खालों तक पहुँचने के लिए पढ़े-लिखे परिवार के सदस्यों या परिचितों पर निर्भर होते हैं, जिससे उनका दुरुपयोग और शोषण होने की संभावना बनी रहती है।
 - सीमित शिकायत निवारण: औपचारिक प्रक्रियाओं या कमियों से अपरिचित लोगों के लिए शिकायत और समाधान प्रणाली को नेविगेट करना मुश्किल होता है।

व्यापक सामाजिक निहितार्थ

- कल्याणकारी योजनाओं से बहिष्करण
 - लाभों तक पहुँच: सरकारी योजनाओं के लिए डिजिटल आवश्यकताएँ उन लोगों को बाहर कर सकती हैं जो तकनीकी या दस्तावेज़ीकरण मानकों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे उन्हें हकदार लाभों से वंचित किया जा सकता है।
 - ग्रामीण-शहरी अंतराल: शहरी आबादी डिजिटल प्रणालियों को अधिक आसानी से अपना लेती है, जबकि ग्रामीण और आदिवासी समुदाय पिछड़े जाते हैं, जिससे मौजूदा असमानताएँ और गहरी हो जाती हैं।

- सामाजिक और आर्थिक जोखिम
 - स्वास्थ्य और सुरक्षा: स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुँच वित्तीय कमज़ोरी को बढ़ाती है।
 - प्रवासन और श्रम शोषण: प्रवासी श्रमिकों और घरेलू सहायकों को अक्सर वेतन चोरी और खराब कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जागरूकता या समर्थन की कमी के कारण उनके पास कोई सहारा नहीं होता।

मुख्य बिंदु

- डिजिटल साक्षरता आवश्यक है: वास्तविक वित्तीय समावेशन के लिए न केवल प्रौद्योगिकी तक पहुँच की आवश्यकता है, बल्कि इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता भी आवश्यक है।
- प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है: वर्तमान बैंकिंग और डिजिटल सिस्टम अशिक्षित या वंचित आबादी की वास्तविकताओं के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं।

आगे की राह: सिफारिशें

- सरलीकृत केवाईसी और बैंकिंग प्रक्रियाएँ: सीमित साक्षरता वाले लोगों के लिए वैकल्पिक सत्यापन और खाता प्रबंधन प्रक्रियाएँ विकसित करना।
- वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पहल: ऑडियो-विजुअल सामग्री का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में व्यापक शिक्षा अभियान लागू करना।
- सामुदायिक सहायता प्रणाली: दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित निगरानी के साथ लेन-देन में सहायता के लिए विश्वसनीय मध्यस्थों या सामुदायिक बैंकिंग एजेंटों की स्थापना करना।
- नीति समायोजन: कमजोर समूहों के लिए विभेदित विनियामक ढांचे और सुरक्षा की वकालत करना।
- बेहतर शिकायत तंत्र: सीमित शिक्षा या डिजिटल कौशल वाले लोगों के लिए शिकायत प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाना।

निष्कर्ष

- भारत में वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण बहुत आशाजनक है, लेकिन अशिक्षित और डिजिटल रूप से बहिष्कृत लोगों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी है। लक्षित सुधारों और समावेशी नीतियों के बिना, लाखों लोगों को अपने स्वयं के धन और सरकारी लाभों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी भेद्यता बढ़ेगी और गरीबी और बहिष्कार का चक्र जारी रहेगा। एक सच्चे समावेशी डिजिटल इंडिया को सभी नागरिकों के आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन अंतरालों को दूर करना होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. संवेदनशील आबादी के लिए डिजिटल बहिष्करण के आर्थिक प्रभाव क्या हैं? निरक्षरता डिजिटल तंत्र को नेविगेट करने की चुनौतियों को कैसे बढ़ाती है? [250 शब्द] [15 अंक]

बैंक इन डोमेन

चर्चा में क्यों: डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए .bank.in डोमेन को शुरू करने का फैसला किया है।

मुख्य विवरण

- '.in' भारत का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन (ccTLD) है।
- घरेलू बैंकों के लिए यह विशेष इंटरनेट डोमेन साइबर सुरक्षा खतरों को कम करेगा और देश की डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगा।
- RBI ने बैंकों से 31 अक्टूबर, 2025 तक .bank.in डोमेन पर माइग्रेट करने को कहा है।

.bank.in डोमेन पर माइग्रेशन

- RBI ने फरवरी 2025 में भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन 'bank.in' की शुरुआत की घोषणा की।
- डोमेन नाम का उपयोग वेबसाइट खोजने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए एक अनूठा और याद रखने में आसान पता है।
- नए इंटरनेट डोमेन नाम का संचालन बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) के माध्यम से किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI) द्वारा इस डोमेन के लिए विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- '.IN' डोमेन भारत का अपना ccTLD है, जो एक दो-अक्षर की स्ट्रिंग है (जैसे, <https://www.india.gov.in>) जिसे डोमेन नाम के अंत में जोड़ा जाता है।
- ccTLD किसी वेब पते में सिर्फ एक स्ट्रिंग से ज़्यादा काम करता है। इसे वैश्विक इंटरनेट पर राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक माना जाता है।
- नए डोमेन में माइग्रेशन के साथ, देश के सभी बैंकों का डोमेन नाम '.bank.in' होगा। फ़िलहाल, बैंक अपने डोमेन नाम के रूप में या तो '.com' या '.co.in' का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा सामान्य है।
- माइग्रेशन हो जाने के बाद, ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर वे किसी बैंक की वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो डोमेन '.bank.in' होना चाहिए। और, अगर उन्हें अपने बैंक से कोई ईमेल मिलता है, जिसका डोमेन '.bank.in' पर खत्म होता है, तो उसे असली माना जा सकता है। और, अगर उन्हें अपने बैंक से '.bank.in' डोमेन के साथ ईमेल मिलता है, तो इसे वास्तविक माना जा सकता है।

डोमेन परिवर्तन के पीछे तर्क

- '.bank.in' डोमेन नाम के संचालन के साथ, RBI-विनियमित बैंकों को छोड़कर किसी भी इकाई के लिए '.bank.in' के साथ पंजीकरण करना मुश्किल होगा। इससे बैंक की वेबसाइट का उपयोग करके डिजिटल धोखाधड़ी की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।
- नया इंटरनेट डोमेन साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को कम करेगा और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़ेगा।

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (NIXI) के बारे में

- NIXI एक गैर-लाभकारी संगठन है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को आपस में जोड़ने के लिए स्थापित किया गया है ताकि घरेलू ट्रैफ़िक को अमेरिका/विदेश में ले जाने के बजाय देश के भीतर रूट किया जा सके, जिससे सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो और अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ पर बचत करके ISP के लिए बैंडविड्थ शुल्क कम हो।

बैंकिंग घोटाले

- बैंकिंग घोटाले या धोखाधड़ी में अपराधी धोखाधड़ी करने के लिए धोखाधड़ी करने वाली रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पीड़ितों से पैसे या संवेदनशील जानकारी चुराई जा सके। जालसाज ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल और फर्जी वेबसाइट जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोगों को धोखा देकर उनके वित्तीय विवरण का खुलासा किया जा सके।
- कुछ सामान्य बैंकिंग धोखाधड़ी
 - फ़िशिंग और स्पीयर-फ़िशिंग: घोटालेबाज पीड़ितों को धोखा देकर खाता विवरण, क्रेडिट कार्ड की जानकारी और पिन जैसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए नकली ईमेल या संदेश भेजते हैं।
 - सिंथेटिक पहचान धोखाधड़ी: जालसाज ऋण प्राप्त करने या खाता खोलने के लिए पहचान बनाने के लिए वास्तविक और नकली जानकारी को मिलाते हैं, पहचान से बचने के लिए डेटा उल्लंघनों और एआई का लाभ उठाते हैं।
 - मोबाइल बैंकिंग धोखाधड़ी: साइबर अपराधी दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) को बायपास करने के लिए फ़ोन नंबरों को हार्डजैक करते हैं और वाहक की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर धन चुराते हैं।
 - जमा राशि में अचानक वृद्धि: जालसाज पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए छोटी-छोटी राशि जमा करते हैं और फिर फर्जी रिफंड अनुरोध शुरू करते हैं, जिससे वे अपने यूपीआई पिन का खुलासा कर लेते हैं।
 - एटीएम स्क्रीमिंग और कार्ड क्लोनिंग: IoT डिवाइस का उपयोग एटीएम या भुगतान टर्मिनलों से कार्ड डेटा चुराने के लिए किया जाता है, जिससे धोखाधड़ी वाले लेनदेन या कार्ड डुप्लीकेशन संभव हो जाता है।
 - सरकारी धोखेबाज़ घोटाले: धोखेबाज़ पीड़ितों को व्यक्तिगत डेटा साझा करने या धोखाधड़ी वाले भुगतान करने के लिए सरकारी अधिकारी बनकर धोखा देते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (एनआईएक्सआई) का मुख्य कार्य है?

- (a) भारत में सभी डिजिटल बैंकिंग लेनदेन के लिए प्राथमिक नियामक के रूप में कार्य करना।
- (b) देश के भीतर घरेलू इंटरनेट ट्रैफ़िक को रूट करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की पीयरिंग की सुविधा प्रदान करना।
- (c) धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों को ब्लैकलिस्ट करके डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का सीधे मुकाबला करना।
- (d) भारत में वेबसाइटों के लिए सभी .in डोमेन नाम पंजीकृत करना।

(9) :258

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. नया .bank.in डोमेन भारतीय डिजिटल बैंकिंग में विश्वास और सुरक्षा को कैसे बढ़ाता है? इस नए डोमेन पहल को लागू करने में कौन से सरकारी और संगठनात्मक निकाय शामिल हैं? [150 शब्द] [10 अंक]

अर्रेंज इकोनॉमी

चर्चा में क्यों: WAVES 2025 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्रेंज इकोनॉमी के उदय की सराहना की।

अर्रेंज इकोनॉमी के बारे में

- अर्रेंज इकोनॉमी संगीत, फिल्म, भोजन, गेमिंग और एनीमेशन के रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल करने वाली आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है।
- यह उन उद्योगों को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत रचनात्मकता, कौशल और प्रतिभा पर निर्भर करते हैं। इनमें संगीत, फिल्म, डिजाइन, फैशन, प्रकाशन, कला, विज्ञापन और सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक नेटवर्क द्वारा परिभाषित, अर्रेंज इकोनॉमी सांस विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देने की क्षमता है, खासकर विकासशील देशों में, जबकि सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित किया जाता है।
- अर्रेंज इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल पहली बार कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ब्यूक मार्केज़ और पूर्व संस्कृति मंत्री फिलिप बुइट्रेगो ने किया था।
 - अर्रेंज इसलिए चुना गया क्योंकि यह रंग रचनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संस्कृतियों में गूँजता है।

अर्रेंज इकोनॉमी में भारत का रणनीतिक फोकस और निवेश

- भारत रणनीतिक रूप से अपनी क्रिएटर इकोनॉमी को औपचारिक रूप दे रहा है, एक संरचित उद्योग के रूप में इसकी क्षमता को पहचान रहा है। यह औपचारिकता क्रिएटर इकोनॉमी को केवल अनौपचारिक या साइड-हसल संचालित के रूप में देखने से एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है।
- सरकार, क्रिएटर्स को आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव के प्रमुख चालक के रूप में देखती है। सरकार इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है।
- भारत की विस्तारित क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1 बिलियन डॉलर के फंड की घोषणा की गई है, जो क्रिएटर्स को पूंजी, कौशल विकास के अवसरों, बेहतर उत्पादन क्षमताओं और वैश्विक बाजार संबंधों तक पहुंच प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) की स्थापना के लिए 391 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो डिजिटल और रचनात्मक प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता बनाने पर केंद्रित एक संस्थान है। इन पहलों का उद्देश्य रचनाकारों के कौशल को बढ़ावा देना, सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करना और वैश्विक बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।

अर्रेंज इकोनॉमी का आर्थिक प्रभाव और संभावनाएँ

- **विशाल आर्थिक प्रभाव:** क्रिएटर इकोनॉमी, भारत में उपभोक्ता व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिएटर पहले से ही भारत में सालाना 350 बिलियन डॉलर से ज्यादा के खर्च को प्रभावित करते हैं। अनुमान है कि यह आंकड़ा 2030 तक संभावित रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा।
- **प्रत्यक्ष राजस्व में तीव्र वृद्धि:** पारिस्थितिकी तंत्र से प्रत्यक्ष राजस्व आज के \$20-25 बिलियन से बढ़कर दशक के अंत तक \$100-125 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

- **उपभोक्ता व्यय में महत्वपूर्ण हिस्सा:** क्रिएटर द्वारा संचालित व्यय 2030 तक देश में कुल उपभोक्ता व्यय का 25-30% हो सकता है।
- **महानगरों और जनरेशन Z से परे विस्तार:** जो कभी महानगरों और जनरेशन Z-केंद्रित घटना थी, वह अब छोटे शहरों सहित आयु समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गई है।
- **अग्रणी क्षेत्र:** फैशन, सौंदर्य और मनोरंजन जैसी श्रेणियाँ वर्तमान में अग्रणी हैं।
- लाइव कॉमर्स और वर्चुअल गिफ्टिंग जैसे उभरते मुद्दीकरण मॉडल क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए मूल्य सृजन को फिर से परिभाषित कर रहे हैं।
- **मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए अनुमान:** रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी ने अनुमान लगाया कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग अगले दशक में तीन गुना से अधिक बढ़कर 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है। भारत में वर्तमान स्थिति और क्रिएटर परिदृश्य
- अनुमान है कि भारत में 1,000 से अधिक फॉलोअर वाले 2 से 2.5 मिलियन सक्रिय डिजिटल क्रिएटर हैं। हालांकि, इनमें से केवल 8-10% क्रिएटर ही अपनी सामग्री का प्रभावी ढंग से मुद्दीकरण कर सकते हैं, जो बड़ी अप्राप्य क्षमता को दर्शाता है।
- शॉर्ट-फॉर्म वीडियो सबसे प्रमुख फॉर्मेट बना हुआ है, जिसमें YouTube शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और Moj जैसे प्लेटफॉर्म प्रमुख हैं।
- लोकप्रिय सामग्री शैलियों में कॉमेडी, फ़िल्में, डेली सोप और फैशन शामिल हैं।
- भारत में प्रभावशाली लोगों की संख्या 2020 में 962,000 से बढ़कर 2024 में 4.06 मिलियन हो गई, जो 322% की वृद्धि है।
- ब्रांड अपनी मार्केटिंग रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं; प्रभावशाली लोग उत्पाद के प्रचार से आगे बढ़कर रणनीतिक भागीदार बन गए हैं। ब्रांड अब ऐसे रचनाकारों की तलाश कर रहे हैं जो प्रामाणिक, संदर्भ-संचालित सामग्री तैयार कर सकें।
- गेमिंग, यात्रा और जीवनशैली जैसी श्रेणियाँ असाधारण वृद्धि का अनुभव कर रही हैं, जो ब्रांडों को ऐसे रचनाकारों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान करती हैं जो इन दर्शकों को समझते हैं।

अर्रेंज इकोनॉमी की सॉफ्ट पावर और वैश्विक पहुँच

- प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न स्थानों और डोमेन (संगीतकार, पॉडकास्टर, गेम डिजाइनर, फिल्म निर्माता) के रचनाकार भारत के बढ़ते रचनात्मक क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।
- उन्होंने वैश्विक सॉफ्ट पावर पर उनके संभावित प्रभाव की तुलना अभिनेता राज कपूर और हिंदी सिनेमा की विरासत से की।
 - प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा में "नई ऊर्जा" ला रही है।
 - वैश्विक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने WAVES बाज़ार लॉन्च किया, जो एक वैश्विक ई-मार्केटप्लेस है जिसका उद्देश्य भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और सहयोगियों से जोड़ना।
 - यह प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को काम दिखाने, प्रोजेक्ट पेश करने, विदेशों में व्यावसायिक अवसर खोजने की अनुमति देता है और अंततः भारत को कंटेंट का शुद्ध निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखता है।

WAVES शिखर सम्मेलन

- विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) 2025 मुंबई में आयोजित किया गया।
- यह भारत का पहला WAVES शिखर सम्मेलन था।

- **उद्देश्य:** शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था।
- **थीम:** “रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना”
- **परिणाम और प्रभाव**
 - WAVES बाज़ार के परिणामस्वरूप रचनाकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ एक हज़ार तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक के व्यापारिक सौदे हुए।
 - वैश्विक मीडिया संवाद में 77 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा WAVES घोषणा को अपनाया गया।
 - सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पारंपरिक लोक नृत्यों, मार्शल आर्ट प्रदर्शनों और ढोल बजाने के प्रदर्शनों के माध्यम से भारत की विशाल कलात्मक विविधता को उजागर किया।
 - शिखर सम्मेलन ने भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन केंद्र के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया और इसे विश्व मंच पर भारत की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया।

निष्कर्ष

- भारत की ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी और वाणिज्य के संगम पर खड़ी है, जो आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक प्रभाव के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है। रणनीतिक निवेश, संस्थागत समर्थन और बढ़ती डिजिटल भागीदारी के साथ, भारत रचनात्मक उद्योगों में वैश्विक नेता बनने के लिए तैयार है। यह क्षेत्र न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाता है बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करता है, जिससे यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "ऑरेंज इकोनॉमी" शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है?

- कृषि उत्पादन और खट्टे फलों का निर्यात।
- प्राकृतिक खनिजों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण।
- रचनात्मकता, बौद्धिक संपदा और सांस्कृतिक सामान/सेवाएँ।
- नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता।

(C) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. ऑरेंज इकोनॉमी को परिभाषित करें और भारत में इसका रणनीतिक महत्व बताएं। वैश्विक स्तर पर भारत की नारंगी अर्थव्यवस्था का आर्थिक प्रभाव और क्षमता क्या है? [250 शब्द] [15 अंक]

पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों: द हिंदू में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में यह स्वीकार किया गया है कि पारिस्थितिकी का सिद्धांत दुनिया की स्थायी अर्थव्यवस्था है, जिससे मानव अस्तित्व, आर्थिक स्थिरता और जलवायु लचीलेपन के आधार के रूप में पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित होगा।

पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता

- **डेटा**
 - जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन से दुनिया को सालाना ~300 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है।
 - भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर है।
 - 57% ग्रामीण समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं।
- **पारिस्थितिक क्षरण के परिणाम:** सूखा, मरुस्थलीकरण, खाद्य और जल असुरक्षा, बड़े पैमाने पर विस्थापन और फसल की पैदावार में कमी।
- **वास्तविक दुनिया का उदाहरण:** कोविड-19 लॉकडाउन ने कृषि चक्र को बाधित कर दिया और उसके बाद अभूतपूर्व बाढ़ आई, जो पारिस्थितिकी अस्थिरता के कारण आजीविका की भेद्यता को दर्शाती है।

आजीविका पर पुनर्विचार: रोजगार सृजन से परे

- **सेवा प्रदाता के रूप में प्राकृतिक पूंजी:** प्रकृति कच्चे माल से परे आवश्यक सेवाएं (जैसे ऑक्सीजन, जल विनियमन, परागण) प्रदान करती है।
- **एकीकृत संसाधन प्रबंधन:** आर्थिक और पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए पुनर्योजी कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपल अर्थव्यवस्थाओं (पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण) की वकालत करता है।

पारिस्थितिकी संक्रमण में आर्थिक अवसर

- **वैश्विक रोजगार सृजन क्षमता**
 - भूमि और जल का सतत प्रबंधन 2030 तक 395 मिलियन रोजगारों का सृजन कर सकता है।
 - पुनर्योजी खेती, मछली पकड़ने और वानिकी से 3.6 ट्रिलियन डॉलर के व्यावसायिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
- **भारत की आर्थिक उन्नति:** जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने से आपदा लागत में कमी और प्रकृति पर निर्भर क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ने के माध्यम से भारत की शुद्ध आय 25 गुना बढ़ सकती है।
- **कृषि वानिकी लाभ:** अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई कृषि वानिकी पैदावार को 64% तक बढ़ा सकती है और जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है।

उत्तरजीविता और लचीलापन

- **उत्तरजीविता अनिवार्य:** चरम मौसम, महामारी और संसाधन असुरक्षा के विरुद्ध लचीलापन के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी-अर्थव्यवस्था रणनीतियाँ आवश्यक हैं।
- **बीमा के रूप में जैव विविधता:** देशी परागणकों और फसल किस्मों को संरक्षित करने से जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि लचीलापन बढ़ता है।

पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने के लिए रणनीतियाँ और कार्य

- **व्यवसायों की भूमिका**
 - **प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश करना:** दीर्घकालिक लाभ और प्रीमियम मूल्य निर्धारण के लिए कृषि वानिकी, जैविक खेती और संधारणीय प्रथाओं का समर्थन करना।

- **कॉर्पोरेट लेखा सुधार:** वास्तविक लागत और लाभों को दर्शाने के लिए लाभ/हानि विवरण में पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को शामिल करना।
- **बहाली और पुनःवनीकरण:** व्यवसायों को वनों और पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने में अग्रणी होना चाहिए, जिससे समुदायों और उनकी अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं दोनों को लाभ हो।
- **सरकारी कार्यवाहियाँ**
 - **ग्रीन रिकवरी प्लान:** ग्रामीण समुदायों, वन बहाली, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित बुनियादी ढांचे में निवेश करना।
 - **वनरोपण से सामुदायिक लाभ:** स्थानीय समुदायों के लिए पारदर्शी, जवाबदेह लाभ-साझाकरण और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।
 - **मानकीकृत कृषि वानिकी नीतियाँ:** जैव विविधता के अनुकूल कृषि का समर्थन करने के लिए कृषि वानिकी नीतियों को लागू करें और उनका विकेंद्रीकरण करना।
 - **एकीकृत, प्रकृति-केंद्रित नीतियाँ:** पृथक जलवायु नीतियों से समग्र दृष्टिकोण की ओर बदलाव जो प्रकृति को विकास की नींव के रूप में पहचानते हैं।

निष्कर्ष

- पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था से अलग नहीं है; यह इसकी नींव है। एक स्थायी भविष्य के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। प्रकृति से मानवीय वियोग को भावनात्मक और सांस्कृतिक पुनर्संयोजन के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। जलवायु संकट एक नैतिक और अस्तित्वगत चुनौती है जितनी कि यह एक वैज्ञानिक चुनौती है। वैश्विक स्थिरता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जीवनशैली में बदलाव महत्वपूर्ण हैं

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. पारिस्थितिक स्वास्थ्य और मानव आर्थिक कल्याण और अस्तित्व के बीच मूलभूत संबंध क्या है? दीर्घकालिक समृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था शोषण से पारिस्थितिक प्रबंधन की ओर कैसे परिवर्तित हो सकती है? [250 शब्द] [15 अंक]

प्रिडेटरी प्राइसिंग

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रिडेटरी प्राइसिंग पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न लागतों के लिए नई परिभाषाएँ पेश कीं।

2025 CCI अधिसूचना की मुख्य विशेषताएँ

- **औसत परिवर्तनीय लागत**
 - किसी उत्पाद या सेवा की “औसत परिवर्तनीय लागत”, जिसकी गणना किसी निश्चित समय अवधि में उसके कुल उत्पादन से उसकी कुल परिवर्तनीय लागत को विभाजित करके की जाती है, उसे उसकी लागत माना जाता है।
 - यहाँ, “कुल परिवर्तनीय लागत” का अर्थ है “कुल लागत” (उस वस्तु या सेवा के उत्पादन से जुड़ी सभी लागतों सहित) में से उत्पाद से संबंधित “निश्चित लागत” और “निश्चित ओवरहेड” घटाना।

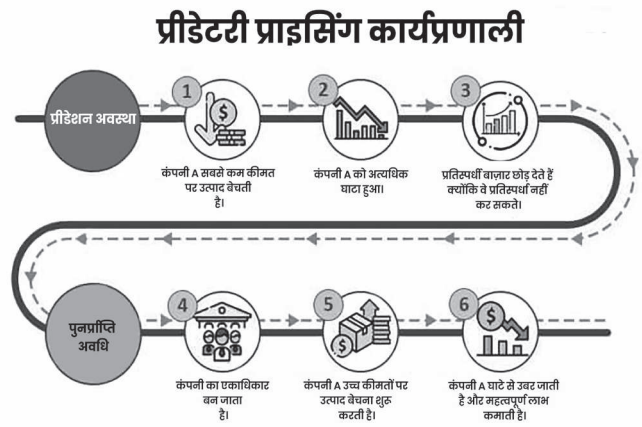
- CCI अपनी सहायता से यह आकलन करने में सक्षम होगा कि किसी वस्तु या सेवा के लिए कंपनी की कीमत प्रिडेटरी है या नहीं।
- **लचीला ढांचा**
 - यह ढांचा क्षेत्र-विशिष्ट मीट्रिक के बजाय केस-दर-केस मूल्यांकन की अनुमति देता है, जिससे आयोग को शिकारी व्यवहार के दावों का आकलन करते समय डिजिटल बाजारों की विशिष्ट विशेषताओं और बदलती गतिशीलता को ध्यान में रखने की अनुमति मिलती है।
- **बाजार मूल्य पर हितधारकों के सुझावों को अस्वीकार करता है**
 - क्योंकि यह सब्सिडी, ब्रांड मूल्य या उपभोक्ता धारणाओं से प्रभावित हो सकता है।

महत्व

- **छोटी कंपनियों की सुरक्षा:** यह शक्तिशाली कंपनियों को मूल्य युद्धों के माध्यम से छोटे प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने से रोकता है।
- **विनियमन सरलता:** सीसीआई की क्षमता में सुधार करता है ताकि वह लगातार प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की जांच, माप और निर्णय ले सके।
- **कानूनी स्पष्टता:** लागत बेंचमार्किंग के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है जो ठोस आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है।

प्रिडेटरी प्राइसिंग क्या है?

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अनुसार, प्रिडेटरी प्राइसिंग तब होता है जब कोई कंपनी प्रतिस्पर्धा को दबाने और प्रतिद्वंद्वियों को बाहर निकालने के इरादे से किसी वस्तु या सेवा को उसकी लागत से कम कीमत पर पेश करती है।



भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आता है।
- इसके प्राथमिक उद्देश्यों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाना, स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना शामिल है।
- CCI को कार्टेल, मूल्य-निर्धारण और प्रमुख बाजार स्थितियों के दुरुपयोग जैसी अनुचित प्रथाओं की जाँच करने का अधिकार है। यह दंड भी लगा सकता है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी कर सकता है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार आचरण को बढ़ावा मिलता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था/सरकारी निकाय भारत में 'प्रिडेटरी प्राइसिंग' की निगरानी और विनियमन करता है?

- (a) भारतीय रिजर्व बैंक
- (b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
- (c) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(c) : 2020

विज्ञानजाम बंदरगाह

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में विज्ञानजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और केरल में एक समर्पित गहरे पानी के ट्रांसशिपमेंट के उद्घाटन के साथ भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

विज्ञानजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का महत्व

- **रणनीतिक स्थिति:** विज्ञानजाम बंदरगाह पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से सिर्फ 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। अपने आदर्श स्थान के कारण, यह बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश बिंदु के रूप में काम कर सकता है।
- **व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** भारत में प्रत्यक्ष ट्रांसशिपिंग हब की स्थापना के साथ निर्यात-आयात संचालन को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से टर्नअराउंड समय और रसद दक्षता में वृद्धि होगी। नए शिपिंग लेन बनाने और भारतीय निर्यात को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा और प्रतिस्पर्धी बनाने से, यह वैश्विक व्यापार क्षेत्र में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बहुत बढ़ाएगा।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** इसका उन्नत बुनियादी ढांचा अर्ध-स्वचालन और आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी में विकसित एआई-संचालित पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली के साथ सुरक्षित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करता है।
- **भौगोलिक बढ़त:** बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को समायोजित कर सकता है, जिसमें 24,000 टीईयू से अधिक क्षमता वाले अगली पीढ़ी के जहाज शामिल हैं, जो इसकी लगभग 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई के कारण है।
- **न्यूनतम तटीय बहाव:** विज्ञानजाम के तटीय इलाके के कारण, तटीय बहाव कम है, जो लगातार ड्रेजिंग और रखरखाव लागत की आवश्यकता को कम करता है। यह अंतर्निहित लाभ दीर्घकालिक परिचालन दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- **क्षेत्रीय विकास:** बंदरगाह से दक्षिणी केरल में रोजगार के अवसरों और रसद, परिवहन, भंडारण और संबंधित क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के माध्यम से आर्थिक गतिविधि की शुरुआत होने की संभावना है।
- **बढ़ी हुई कनेक्टिविटी:** बंदरगाह के उत्कृष्ट रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्शन अंतर्देशीय क्षेत्रों से आसान माल परिवहन की गारंटी देते हैं। अंतर्देशीय परिवहन अभी भी लागत प्रभावी और कुशल है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 केवल 2 किमी दूर है और 12 किमी के भीतर रेल मार्ग भी हैं।

विज्ञानजाम बंदरगाह के बारे में

- केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर विज्ञानजाम में स्थित यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह और देश का पहला अर्ध-स्वचालित बंदरगाह है।
- 8,900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित इस बंदरगाह का संचालन अडानी समूह द्वारा किया जाता है, जबकि केरल सरकार के पास बहुलांश स्वामित्व है।
- विज्ञानजाम बंदरगाह में भारत का सबसे गहरा ब्रेकवाटर है, जो करीब तीन किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसका प्राकृतिक ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है।
- यह देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एआई-संचालित पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली से भी सुसज्जित है, जिसे आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी में बनाया गया है।

निष्कर्ष

विज्ञानजाम में आधुनिक कंटेनर टर्मिनल, गोदाम और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और इस प्रकार यह क्षेत्रीय व्यापार में एक प्रमुख भागीदार भागीदार बनने के लिए तैयार है, जो संभावित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच वाणिज्य के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर रहा है।



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में विज्ञानजाम बंदरगाह समाचारों में देखा गया, यह कहाँ स्थित है?

- (a) केरल
- (b) तमिलनाडु
- (c) आंध्र प्रदेश
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(a) : 2020

दक्षिण कर्नाटक में हाथियों की जनगणना

चर्चा में क्यों: हाल ही में एक समन्वित अंतरराज्यीय प्रयास के तहत आयोजित तीन दिवसीय हाथी जनगणना संपन्न हुई, जिसके परिणामों से दक्षिण कर्नाटक में हाथियों की महत्वपूर्ण जनसंख्या प्रवृत्तियों का पता चलने की संभावना है। यह आदेश जनगणना अंतरराज्यीय समन्वय समिति (ICC) के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत में हाथियों की संख्या और उनकी आवाजाही के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझना था।

हाथियों की जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

- हाथी न केवल शानदार जानवर हैं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रजाति भी हैं, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हालांकि, हाल के वर्षों में, विशेष रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव-हाथी संघर्ष बढ़ रहे हैं।
- यह जानना कि हाथी कहाँ हैं और वे कैसे रहते हैं, बेहतर संरक्षण रणनीतियों की योजना बनाने और मानव-पशु संघर्ष को कम करने में मदद करता है।

तीन दिवसीय जनगणना अभ्यास

गणना तीन दिनों तक चली और इसमें डेटा संग्रह की तीन प्रमुख विधियाँ शामिल थीं:

- पहला दिन – ब्लॉक सैंपलिंग / डायरेक्ट काउंट विधि:** वन कर्मचारियों और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने पूर्वनिर्धारित वन ब्लॉकों में सीधे हाथियों का अवलोकन किया। यह विधि हाथियों के घनत्व और वितरण का अनुमान लगाने में मदद करती है।
- दूसरा दिन – लाइन ट्रांसेक्ट विधि:** पर्यवेक्षक हाथियों की गिनती करने के लिए जंगल में तय रास्तों (ट्रांसेक्ट) पर चले। यह विधि कम पहुँच वाले क्षेत्रों में हाथियों की मौजूदगी के बारे में डेटा प्रदान करती है।
- तीसरा दिन – वाटरहोल काउंट विधि:** अंतिम दिन वाटरहोल की निगरानी के लिए समर्पित था, हाथियों के उन पर आने की संभावना थी। इससे हाथियों के झुंड की उम्र और लैंगिक संरचना का आकलन करने में मदद मिलती है।

हालाँकि, पूरे क्षेत्र में भारी बारिश ने इसे मुश्किल बना दिया, क्योंकि प्राकृतिक जल उपलब्धता का अर्थ था कि हाथियों को विशिष्ट जल स्रोतों पर एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं थी।

कर्नाटक में शामिल प्रमुख स्थान

गणना कर्नाटक के कई महत्वपूर्ण वन और वन्यजीव क्षेत्रों में आयोजित की गई, जिनमें शामिल हैं:

- बांदीपुर बाघ अभयारण्य

- नागरहोल बाघ अभयारण्य
- बिलिगिरी रंगनाथ (बीआरटी) बाघ अभयारण्य
- भद्रा बाघ अभयारण्य
- कावेरी वन्यजीव अभयारण्य
- माले महादेश्वर (एम.एम.) हिल्स
- मदिकेरी (प्रादेशिक और वन्यजीव प्रभाग)
- विराजपेट प्रभाग
- बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान
- कोलार प्रभाग
- चिकमगलुरु और शिवमोग्गा वन्यजीव प्रभाग

भारत में हाथियों पर मुख्य तथ्य

हाथियों के बारे में

- भारत का प्राकृतिक विरासत पशु:** हाथी भारत की प्राकृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में एक विशेष दर्जा रखता है।
- क्रीस्टोन प्रजातियाँ:** हाथी वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बिना, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा।
- अत्यधिक बुद्धिमान:** उनके पास किसी भी भूमि जानवर की तुलना में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, जो उन्नत स्मृति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है।

पारिस्थितिक महत्व

- बीज फैलाने वाले:** हाथी बड़ी मात्रा में बीजों का सेवन करते हैं और उन्हें फैलाते हैं, जिससे जंगलों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है।
- वन इंजीनियर:** पेड़ों को तोड़कर, साफ-सफाई करके और छल खोलकर, वे सूर्य के प्रकाश को जंगल के तल तक पहुँचने देते हैं - जिससे पौधों की विविधता को बढ़ावा मिलता है।
- पानी की पहुँच:** शुष्क परिस्थितियों में, हाथी भूमिगत जल की खुदाई करते हैं, जिससे उन्हें और अन्य वन्यजीवों को लाभ होता है।

भारत में हाथी

- भारत में दुनिया के जंगली एशियाई हाथियों की लगभग 60% आबादी रहती है।
- 2017 प्रोजेक्ट एलीफेंट सेंसस के अनुसार, भारत में 29,964 जंगली हाथी हैं।
- जनसंख्या के हिसाब से शीर्ष राज्य:**
 - कर्नाटक – सबसे ज़्यादा
 - उसके बाद असम और केरल हैं।

संरक्षण की स्थिति

वर्ग	हाथी का प्रकार	स्थिति
आईयूसीएन लाल सूची	अफ्रीकी वन हाथी	गंभीर रूप से संकटग्रस्त
	अफ्रीकी सवाना हाथी	संकटग्रस्त
	एशिया हाथी (एलिफस मैक्सिमस)	संकटग्रस्त
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972	एशियाई हाथी	अनुसूची I (उच्चतम संरक्षण)
CITES	एशियाई हाथी	परिशिष्ट I (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति नहीं)
	अफ्रीकी सवाना हाथी	परिशिष्ट II
प्रवासी प्रजातियों संबंधी कन्वेंशन	एशियाई हाथी	परिशिष्ट I
	अफ्रीकी वन हाथी	परिशिष्ट II

भारत की हाथी संरक्षण पहल

प्रोजेक्ट हाथी (1992)

- हाथियों, उनके पर्यावासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया।
- 23 राज्यों में लागू किया गया।
- 1992 में ~25,000 से 2021 तक ~30,000 तक जनसंख्या बढ़ाने में मदद की।

हाथी अभयारण्य

- 33 हाथी अभयारण्य स्थापित किए गए।
- कुल क्षेत्रफल: लगभग 80,777 वर्ग किमी।
- ये रिजर्व सुरक्षित पर्यावास प्रदान करते हैं और प्रवास गलियारे सुनिश्चित करते हैं।

मानव-हाथी संघर्षों का प्रबंधन

- पशु-मानव संघर्षों को कम करने के लिए 40+ हाथी गलियारे और 88 वन्यजीव क्रॉसिंग विकसित किए गए।
- संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बफर जोन 17,000+ वर्ग किमी में फैले हुए हैं।
- संघर्ष-ग्रस्त राज्यों में त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए।
- पर्यावरण-अनुकूल उपायों के लिए 110 रेलवे खंडों की पहचान की गई जैसे:
 - हाथियों के लिए अंडरपास
 - बेहतर दृश्यता के लिए वनस्पतियों की सफाई
 - ट्रेन की टक्करों को रोकने के लिए रैंप और चेतावनी प्रणाली

समुदाय की भागीदारी

- गज यात्रा:** हाथियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।
- गज शिल्पी:** स्थानीय कलाकार और समुदाय संदेश फैलाने के लिए शामिल हैं।
- गज गौरव पुरस्कार:** हाथियों के संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता।

वैश्विक सहयोग

हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE कार्यक्रम)

- 1997 में CITES द्वारा शुरू किया गया, भारत में 2003 से कार्यरत है।
- इसका उद्देश्य है:
 - हाथियों की मृत्यु दर और अवैध शिकार पर निगरानी रखना।
 - बेहतर प्रबंधन और प्रवर्तन का समर्थन करना।
- हाथियों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण में मदद करता है।

भारत में MIKE स्थल:

- चिरांग-रिपु (असम)
- देवमाली (अरुणाचल प्रदेश)
- दिहिंग पटकाई (असम)
- गारो हिल्स (मेघालय)
- पूर्वी दोआर्स (पश्चिम बंगाल)
- मयूरभंज (ओडिशा)
- शिवालिक (उत्तराखंड)
- मैसूर (कर्नाटक)
- नीलगिरि (तमिलनाडु)
- वायनाड (केरल)

निष्कर्ष

हाथी न केवल भारत के प्राकृतिक विरासत पशु हैं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रोजेक्ट हाथ, अभयारण्य और कॉरिडोर के निर्माण, सामुदायिक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे निरंतर प्रयासों के माध्यम से, भारत अपनी हाथी आबादी के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय हाथियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- हाथियों के समूह की प्रमुख मादा होती है।
- अधिकतम गर्भधारण अवधि 22 महीने हो सकती है।
- एक हाथी सामान्यतः 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे दे सकता है।
- भारत के राज्यों में सबसे अधिक हाथी केरल में हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 3 (d) केवल 1, 3 और 4

(e) : 2024

संरक्षण कानून और स्वदेशी अधिकारों के बीच संतुलन

चर्चा क्यों में: हाल ही में, द हिंदू में एक लेख छपा जिसमें चर्चा की गई कि कैसे संरक्षण कानून और नीतियाँ दुनिया के कई हिस्सों में अधिक बहिष्कारपूर्ण होती जा रही हैं।

बहिष्कारपूर्ण संरक्षण का ऐतिहासिक संदर्भ: किला संरक्षण मॉडल

- औपनिवेशिक पृष्ठभूमि:** संरक्षण विज्ञान और कानूनी ढाँचे औपनिवेशिक विचारधाराओं में निहित हैं जो मानव प्रभाव से रहित प्राचीन प्रकृति को आदर्श मानते हैं।
- संरक्षित क्षेत्र:** यह मॉडल बहिष्कारपूर्ण क्षेत्र बनाता है (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य) केंद्रीकृत राज्य नियंत्रण द्वारा प्रबंधित, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों (आईपीएलसी) को अतिक्रमणकारी के रूप में अपराधी बनाता है।

भारत का कानूनी ढांचा और संरक्षण नीतियाँ

चुनौतियाँ और विरोधाभास

राष्ट्रीय जैव विविधता टणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी)

- 2025 अद्यतन:** इसमें उर्ध्वगामी दृष्टिकोण का दावा किया गया है, लेकिन एफआरए के नेतृत्व वाली शम सभाओं की तुलना में राज्य के नेतृत्व वाले संरक्षण (जैसे वन विभाग) को प्राथमिकता दी गई है।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएनसी) की सीमाएँ:** खराब कार्यक्षमता और एफआरए संस्थानों के साथ तालमेल की कमी।

शोषण का जोखिम

- आईटीएम के नुकसान:** एफआरए अनुपालन के बिना, आईटीएम कंप्यूटर्ड शोषण को संभल कर सकते हैं।
- सीबीडी एवं बीडीए:** इन रूपरेखाओं से आईपीएलसी लाभ सुनिश्चित किए बिना पारंपरिक ज्ञान को चटतु बना देने का जोखिम है।

नीति विच्छेद

- वन्यजीव संरक्षण बनाम एफआरए:** संरक्षित क्षेत्र अक्सर सामुदायिक अधिकारों पर हानी हो जाते हैं।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय की चेतावनियाँ (2024):** जैव विविधता नियमों के मजबूत को वन अधिकार अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए और शम सभा की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

- वैश्विक विस्थापन:** शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्रोजेक्ट टाइगर और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के कारण भारत में 6 लाख सहित दुनिया भर में 10-20 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं।
- उदाहरण:** स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय (आईपीएलसी)
 - केन्या के मासाई और ओगीक समुदाय
 - युगांडा के बटवा
 - पेरू के अशानिका
 - भारत के आदिवासी
- जैव विविधता विरोधाभास:** अधिकांश जैव विविधता वाले क्षेत्र आईपीएलसी क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होते हैं, फिर भी उनके प्रबंधन की अक्सर अनदेखी की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे और आईपीएलसी अधिकार

- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी)**
 - उद्देश्य:** संरक्षण, सतत उपयोग और समान लाभ-साझाकरण (अनुच्छेद 8 (जे))।
 - पारंपरिक ज्ञान के सम्मान का आग्रह करता है लेकिन प्रवर्तन का अभाव है।
 - COP-16 (2024) ने IPLCs के लिए एक स्थायी सहायक निकाय की स्थापना की, जो वृद्धिशील प्रगति का संकेत है।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF)**
 - 30 बाय 30 लक्ष्य:** 2030 तक 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना।
 - जोखिम:** संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार IPLCs को और भी विस्थापित कर सकता है।
 - अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM) का उद्देश्य समुदाय-प्रबंधित भूमि को शामिल करना है लेकिन सुरक्षा उपायों के बिना शोषण का जोखिम है।
- स्वदेशी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (2007)**
 - भारत का रुख:** भारत ने पक्ष में मतदान किया लेकिन अनुसूचित जनजातियों (जनसंख्या का 8.6%) की संवैधानिक मान्यता का हवाला देते हुए स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।

आगे की राह: अधिकार और संरक्षण का एकीकरण

एफआरए ढांचे को मजबूत करना

- सीएफआर मान्यता को प्राथमिकता देना:** वन अधिकारों के निपटान में तेजी लाना, विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों में।
- कानूनी तालमेल:** सुनिश्चित करना कि बीडीए, आईटीएम और एनबीएसएपी एफआरए के विकेन्द्रीकृत शासन के साथ संरेखित हों।

समुदाय-नेतृत्व संरक्षण

- पारंपरिक ज्ञान एकीकरण:** राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में आईपीएलसी की भूमिका को औपचारिक बनाना।
- संरक्षित क्षेत्रों से परे:** एफआरए अनुपालन और सामुदायिक सहमति के साथ आईटीएम का विस्तार करना।

वैश्विक कालत

- सीबीडी कार्यान्वयन:** बाध्यकारी अधिकार मान्यता के लिए दबाव बनाने हेतु नई आईपीएलसी सहायक संस्था का लान उठाना।
- 30 बाय 30 मुद्दा:** समवेदी लक्ष्यों की कालत करना जो विस्थापन की तुलना में सामुदायिक प्रबंधन को प्राथमिकता देते हैं।

- **जैविक विविधता अधिनियम (बीडीए), 2002**
 - **लिस्तेरीय प्रणाली:** राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी)।
 - पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन जैव विविधता के मुद्दीकरण के लिए आलोचना की गई।
- **वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006:** यह आदिवासी और वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने वाला एक ऐतिहासिक कानून है।
 - **प्रमुख प्रावधान:-**
 - ◆ सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकार
 - ◆ जैव विविधता और बौद्धिक संपदा की रक्षा के अधिकार।
 - **चुनौतियाँ:** खराब कार्यान्वयन, 2023 तक केवल 3% सीएफआर दावों को मान्यता दी गई।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय**
 - **अनुच्छेद 244 और 244ए:** अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान।
 - **पेसा अधिनियम, 1996:** स्वशासन का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों तक करता है।

निष्कर्ष

- यद्यपि जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे आईपीएलसी की भूमिकाओं को स्वीकार करते हैं, उनका कार्यान्वयन राज्य-केंद्रित और बहिष्कृत रहता है। भारत का एफआरए एक क्रांतिकारी मॉडल पेश करता है, लेकिन इसके लिए तत्काल संचालन की आवश्यकता है। न्यायसंगत संरक्षण का मार्ग आईपीएलसी को कानूनी रूप से सशक्त बनाने, कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने और औपनिवेशिक प्रतिमानों से परे "संरक्षण" को फिर से परिभाषित करने में निहित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. स्वदेशी अधिकारों के साथ संरक्षण लक्ष्यों को समेटने में भारत के वन अधिकार अधिनियम (2006) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। [250 शब्द] [15 अंक]

बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन

चर्चा में क्यों: बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की सत्रहवीं बैठक (बीसी सीओपी-17), रॉटरडैम कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की बारहवीं बैठक (आरसी सीओपी-12) और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की बारहवीं बैठक (एससी सीओपी-12) 28 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिनेवा में लगातार आयोजित की गई।

कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टिज

- कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टिज (सीओपी) उन देशों की औपचारिक बैठकों को संदर्भित करता है जिन्होंने किसी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके सदस्य हैं।

- सीओपी का दायरा "सम्मेलन के कार्यान्वयन और सीओपी द्वारा अपनाए गए किसी भी अन्य कानूनी साधन की समीक्षा करना और सम्मेलन के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लेना है।"
- सीओपी में, पक्ष सम्मेलनों के एजेंडे पर प्रगति की समीक्षा करने और नई प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करने के लिए वार्षिक या नियमित अंतराल पर मिलते हैं।
- वे संबंधित सम्मेलनों के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय हैं।

स्टॉकहोम कन्वेंशन: स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)

- **उन्मूलन के लिए सूचीबद्ध नए पीओपी**
 - प्रस्तावित तीन पीओपी में से दो, क्लोरपाइरीफोस (एक कीटनाशक) और लंबी श्रृंखला वाले परफ्लुओरोकार्बोक्सिलिक एसिड (एलसी-पीएफसीए) (पीएफएएस या "हमेशा के लिए रसायनों" का एक उपसमूह), स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुलग्नक A के तहत सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किए गए। यह उनके उत्पादन और उपयोग पर वैश्विक प्रतिबंध को दर्शाता है, हालांकि कुछ विशेष छूट के साथ।
 - ◆ क्लोरपाइरीफोस बच्चों के विकासशील मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है।
 - ◆ एलसी-पीएफसीए में पानी, तेल, गंदगी और ग्रीस विकर्षक गुण होते हैं और ये व्यक्तिगत देखभाल, सफाई उत्पादों, वस्त्र और पैकेजिंग सहित विभिन्न उत्पादों में पाए जाते हैं।
- **मध्यम-श्रृंखला क्लोरीनयुक्त पैराफिन (MCCPs) के लिए चल रही बातचीत**
 - मध्यम-श्रृंखला क्लोरीनयुक्त पैराफिन (MCCPs) के लिए बातचीत अभी भी चल रही थी, जो पदार्थों का एक समूह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक एडिटिव्स के रूप में किया जाता है।
 - चर्चाओं में छूट और तकनीकी पहलुओं जैसे रासायनिक पहचान, पता लगाने की क्षमता और प्रतिबंधित होने के बाद इन रसायनों वाले उत्पादों को ट्रेक करने की पारदर्शिता शामिल थी।
- **छूट और वैज्ञानिक अनुशंसाओं को कमतर आंकने के बारे में चिंताएँ**
 - एक महत्वपूर्ण चिंता पार्टियों के सम्मेलन (COP) की वार्ता के दौरान और अधिक छूट को जोड़ना है, विशेष रूप से क्लोरपाइरीफोस के लिए, जिस पर शुरू में POP समीक्षा समिति (POPRC), एक वैज्ञानिक सहायक निकाय द्वारा चर्चा या अनुशंसा नहीं की गई थी।
 - यह अभ्यास दर्शाता है कि पार्टियों के राजनीतिक विकल्प वैज्ञानिक सिफारिशों को कमजोर कर रहे हैं, संभावित रूप से मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और स्टॉकहोम कन्वेंशन की प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं।
 - **यूवी-328 छूट के लिए अभूतपूर्व प्रस्ताव**
 - ◆ विवाद का एक प्रमुख मुद्दा और वार्ता में देरी का एक कारण प्लास्टिक में उपयोग किए जाने वाले यूवी अवशोषक यूवी-328 के लिए एक नई छूट जोड़ने का प्रस्ताव था, जिसे पहले से ही 2023 में विशिष्ट छूट के साथ उन्मूलन के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
 - ◆ इस प्रस्ताव को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा अभूतपूर्व माना जा रहा है और इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रतिबंधित पीओपी पर पिछले निर्णयों को फिर से खोलने की अनुमति देकर एक खराब मिसाल कायम कर सकता है, जिससे कन्वेंशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है।

- ◆ यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रस्ताव को बड़े आर्थिक हितों, विशेष रूप से एयरलाइनों के हितों ने प्रभावित किया है, न कि यह केवल प्रस्तावित देश, अर्थात् इथियोपिया द्वारा संचालित है।

बेसल कन्वेंशन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

- **2019 संशोधन और पूर्व सूचित सहमति (PIC)**
 - 2019 में अपनाए गए संशोधनों ने अधिकांश प्रकार के प्लास्टिक कचरे के लिए पूर्व सूचित सहमति (PIC) प्रक्रिया को बढ़ा दिया।
 - PIC में आयात और पारगमन राज्यों के अधिकारियों को इच्छित अपशिष्ट आंदोलनों के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ सूचित करना शामिल है।
 - यह विकास आंशिक रूप से चीन की सभी प्लास्टिक कचरे का आयात न करने की नीति की प्रतिक्रिया थी।
- **वर्तमान कार्यान्वयन चुनौतियाँ और चर्चाएँ**
 - पार्टियाँ अब इन संशोधनों के कार्यान्वयन का आकलन कर रही हैं, क्योंकि प्लास्टिक कचरे के अवैध निर्यात और डंपिंग की रिपोर्टें जारी हैं।
 - PIC प्रक्रिया के तहत नियंत्रण को मजबूत करने के लिए चर्चाएँ चल रही हैं, विशेष रूप से फ्लोरिनेटेड पॉलिमर जैसे कुछ पॉलिमर के लिए, जो खतरनाक होने के बावजूद, विशिष्ट परिस्थितियों में रीसाइक्लिंग के लिए भेजे जाने पर कवर नहीं होते हैं।
 - इसका उद्देश्य आदर्श रूप से सभी प्लास्टिक कचरे को मजबूत नियंत्रण के लिए PIC के अधीन करना है।
- **पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन पर तकनीकी दिशा-निर्देश**
 - विभिन्न प्रकार के कचरे के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशा-निर्देशों पर चर्चा जारी रही।
 - 2023 COP में प्लास्टिक की “केमिकल रीसाइक्लिंग” की विवादास्पद तकनीक को पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना गया। इसे फिर से शुरू करने के प्रयासों की निगरानी की जा रही है।

बीआरएस सीओपी 2025 में भारत की भूमिका और वकालत

- **कार्यान्वयन के साधनों पर जोर:** बीआरएस कन्वेंशन का प्रभावी निष्पादन वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग तक पहुंच पर काफी हद तक निर्भर करता है।
- **घरेलू विनियामक ढांचा:** कन्वेंशन को लागू करने के लिए भारत के एकीकृत दृष्टिकोण में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियम और ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 जैसे राष्ट्रीय कानून शामिल हैं, जो बुनियादी ढांचे में निवेश द्वारा समर्थित हैं।
- **प्लास्टिक प्रदूषण पर नेतृत्व**
 - भारत ने अपनी घरेलू पहलों का प्रदर्शन किया, जिसमें पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) का कार्यान्वयन शामिल है।
 - भारत ने UNEA-4 में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर एक प्रस्ताव पेश करके अंतराष्ट्रीय पर्यावरण शासन में एक अग्रणी भूमिका का प्रदर्शन किया है, जिससे यह मुद्दा वैश्विक ध्यान में आया है।
- **वैश्विक साधनों के लिए समर्थन:** द्विपक्षीय बैठकों के दौरान, भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतराष्ट्रीय साधन के विकास और रसायनों और अपशिष्ट पर एक विज्ञान-नीति पैनल की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया।
- **बहुपक्षीय सहयोग के लिए प्रतिबद्धता:** भारत बहुपक्षीय पर्यावरण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, विकासशील देशों के हितों की वकालत करते हुए न्यायसंगत, विज्ञान-आधारित और संधारणीय समाधानों का अनुसरण करता है।

बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन (BRS)

बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते हैं, जिनका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरनाक रसायनों और कचरे से बचाना है।

- **बेसल कन्वेंशन**
 - खतरनाक कचरे की ट्रांसबाउंड्री आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन दुनिया भर में खतरनाक कचरे के अनुचित प्रबंधन के नकारात्मक प्रभावों से लोगों और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया था।
 - यह समझौता 1989 में अपनाया गया था और 1992 में लागू हुआ था।
 - यह सबसे व्यापक वैश्विक संधि है जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन और परिवहन से लेकर अंतिम उपयोग और निपटान तक उनके जीवन चक्र से संबंधित है।
- **रॉटरडैम कन्वेंशन**
 - अंतराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन पार्टियों को खतरनाक रसायनों के खिलाफ रक्षा प्रदान करता है।
 - यह समझौता 1998 में अपनाया गया था और 2004 में लागू हुआ।
 - यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतराष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देता है, साथ ही देशों को यह तय करने में सक्षम बनाता है कि वे कन्वेंशन में सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों का आयात करना चाहते हैं या नहीं।
- **स्टॉकहोम कन्वेंशन**
 - स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक खतरनाक, लंबे समय तक चलने वाले रसायनों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है, जो उनके उत्पादन, उपयोग, व्यापार, रिलीज और भंडारण को प्रतिबंधित और अंततः समाप्त कर देता है।
 - यह समझौता 2001 में अपनाया गया था और 2004 में लागू हुआ।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कन्वेंशन पर विचार करें:

कन्वेंशन	संबंधित विवरण
1. बेसल कन्वेंशन	खतरनाक कचरे के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट पर नियंत्रण
2. रॉटरडैम कन्वेंशन	खतरनाक रसायनों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया
3. स्टॉकहोम कन्वेंशन	स्थायी कार्बनिक प्रदूषक

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) इनमें से कोई नहीं

(C) : 2025

त्सराप चू संरक्षण रिजर्व

चर्चा में क्यों: हिमाचल प्रदेश के त्सराप चू संरक्षण रिजर्व को भारत के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

मुख्य विवरण: त्सराप चू संरक्षण रिजर्व के बारे में

- **अवस्थिति:** त्सराप चू संरक्षण रिजर्व लाहौल-स्पीति क्षेत्र में, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है।
- यह किब्बर और चंद्र ताल वन्यजीव अभयारण्यों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36ए(1) के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- त्सराप चू हिमाचल प्रदेश में पाँचवाँ संरक्षण रिजर्व है, जो दरलाघाट, नैना देवी, पॉटर हिल और शिल्ली को जोड़ता है।
- **क्षेत्र:** 1585 वर्ग किमी
- **उद्देश्य:** उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीवों की रक्षा करना।
- त्सराप चू को हिम तेंदुओं का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की सबसे अधिक घनत्व वाली प्रजातियों में से एक है।
- **जीव:** हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िये, आइबेक्स, किआंग्स (जंगली गधा), भारल (नीली भेड़), तिब्बती अर्गाली

संरक्षण रिजर्व

- भारत में संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व भारत के संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाने वाले शब्द हैं जो आम तौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या कनेक्टर और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं।
- ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित किया जाता है यदि वे निर्जन हैं और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, लेकिन समुदायों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किए जाते हैं, और सामुदायिक क्षेत्र यदि भूमि का कुछ हिस्सा निजी स्वामित्व में है।
- इन संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों को पहली बार वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 में पेश किया गया था, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन था।
- इन श्रेणियों को भूमि के निजी स्वामित्व और भूमि उपयोग के कारण मौजूदा या प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास कम सुरक्षा के कारण जोड़ा गया था।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व, त्सराप चू, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

- (a) सिक्किम (b) मणिपुर
(c) हिमाचल प्रदेश (d) लद्दाख

(c) : 2018

जलवायु वित्त वर्गीकरण

चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण के लिए मसौदा रूपरेखा जारी की।

जलवायु वित्त वर्गीकरण क्या है?

- जलवायु वित्त वर्गीकरण एक ऐसी प्रणाली है जो वर्गीकृत करती है कि अर्थव्यवस्था के किन हिस्सों को संधारणीय निवेश के रूप में विपणन किया जा सकता है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह निवेशकों और बैंकों को खरबों डॉलर के निवेश को प्रभावी निवेश की ओर निर्देशित करने में मदद करता है।
- जलवायु-संबंधित वित्तीय साधनों (जैसे ग्रीन बॉन्ड) को वर्गीकृत करने के लिए मानक निर्धारित करने के लिए वर्गीकरण का अक्सर उपयोग किया जाता है, लेकिन तेजी से, वे अन्य उपयोग के मामलों में भी काम आते हैं, जहाँ बेंचमार्किंग सुविधा को लाभकारी माना जाता है, जिसमें जलवायु जोखिम प्रबंधन, नेटज़ीरो संक्रमण योजना और जलवायु प्रकटीकरण के क्षेत्र शामिल हैं।
- कई देशों ने या तो अपने वर्गीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है या एक को अंतिम रूप दे दिया है। दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा और मैक्सिको कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्गीकरण विकसित किया है।

टैक्सोनॉमी (वर्गीकरण) का महत्व

- **नेट-जीरो अर्थव्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता:** वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के बढ़ने के साथ, देशों को नेट-जीरो अर्थव्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है।
- **सतत आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करने में टैक्सोनॉमी की भूमिका:** टैक्सोनॉमी ऐसा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है क्योंकि वे यह पता लगाने में मदद कर सकती हैं कि क्या आर्थिक गतिविधियाँ विश्वसनीय, विज्ञान-आधारित संक्रमण मार्गों के साथ संरेखित हैं।
- **जलवायु पूंजी को बढ़ावा देना और ग्रीनवाशिंग को रोकना:** वे जलवायु पूंजी की तैनाती को भी गति दे सकते हैं और ग्रीनवाशिंग के जोखिमों को कम कर सकते हैं।
- **भारत के जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी का महत्व:** भारत के लिए, टैक्सोनॉमी अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से अधिक जलवायु निधि ला सकती है। भारत में ग्रीन फाइनेंस का प्रवाह देश की मौजूदा जरूरतों से बहुत कम हो रहा है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि सतत गतिविधि क्या है।

भारत में हरित निवेश की संभावना

- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2018 से 2030 तक 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जलवायु-स्मार्ट निवेश क्षमता है।
- निवेश के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र इलेक्ट्रिक-वाहन क्षेत्र में है, जो 667 बिलियन डॉलर है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने सभी नए वाहनों को विद्युतीकृत करना है।
- भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भी 403.7 बिलियन डॉलर के साथ एक अच्छा निवेश क्षेत्र बना हुआ है।
- **भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ**
 - भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य अर्थव्यवस्था हासिल करना है।
 - भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का भी संकल्प लिया है।

- भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है।

● फ्रेमवर्क में क्या है?

● जलवायु कार्टवाइ के प्रमुख स्तंभ

- **धमन:** उत्सर्जन में कमी लाना (जेसे नवीकरणीय ऊर्जा)।
- **अनुकूलन:** लचीलापन बढ़ाना (जेसे कृषि, जल सुरक्षा)।
- **संक्रमण:** कठिन क्षेत्रों (जेसे सीमेंट, लोहा, इस्पात) को समर्थन प्रदान करना।

- **कवर किए गए क्षेत्र:** बिजली, गतिशीलता, भवन, कृषि, खाद्य/जल सुरक्षा, और जटिल उद्योग (प्रारंभिक ध्यान सीमेंट और इस्पात पर)।

● दृष्टिकोण

- **गुणात्मक:** यह निर्धारित करने के लिए उद्देश्य/सिद्धांत निर्धारित करता है कि कोई गतिविधि जलवायु-प्रासंगिक है या नहीं।
- **मात्रात्मक:** गुणात्मक सिद्धांतों को मापने योग्य प्रदर्शन सीमाओं में परिवर्तित करता है (उदाहरण के लिए, जीएचजी कटौती लक्ष्य)।

● गतिविधि वर्गीकरण

● जलवायु सहायक

- **टियर 1:** पूर्ण उत्सर्जन परिहार या प्रमुख तीव्रता में कटौती, जलवायु अनुकूलन और लचीलापन
- **टियर 2:** इसमें आगे सुधार के लिए परिभाषित मार्गों के साथ उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के उपाय शामिल हैं।

● संक्रमण सहायक:

- उन क्षेत्रों में दक्षता या तीव्रता में सुधार जहां क्षुब्ध-उत्सर्जन अभी तक संभव नहीं है।

निष्कर्ष

- भारत का जलवायु वित्त वर्गीकरण वास्तव में संधारणीय परियोजनाओं में निवेश को निर्देशित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हरित निधियों को आकर्षित करने, फर्जी दावों को रोकने और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करने में मदद करेगा। जलवायु के अनुकूल गतिविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके, यह ढांचा स्वच्छ ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे भारत के जलवायु लक्ष्य अधिक प्राप्त करने योग्य और पारदर्शी बनेंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत का जलवायु वित्त वर्गीकरण, हरित निवेशों की संरचना और वर्गीकरण का लक्ष्य कैसे रखता है? [150 शब्द] [10 अंक]

यूरोपीय रेड एडमिरल तितली (वैनेसा अटलांटा)

चर्चा में क्यों: हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पहली बार यूरोपीय रेड एडमिरल तितली देखी गई।

मुख्य विवरण

- हिमाचल प्रदेश में व्यापक रूप से वितरित प्रवासी तितली प्रजाति यूरोपीय रेड एडमिरल (वैनेसा अटलांटा) को देखा गया और उसका दस्तावेजीकरण किया गया।
- यह प्रजाति धौलाधार पर्वत श्रृंखला में धर्मशाला के पास देखी गई, जो देश में इसकी पहली उपस्थिति थी।
- धर्मशाला के पास थाथर्ना हिल में 2,500 मीटर की ऊंचाई पर एक नमूना दर्ज किया गया था।

महत्व

● जैव विविधता प्रभाव

- हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई कुल तितली प्रजातियों की संख्या 440 तक बढ़ जाती है।
- प्रवासी प्रजातियों के लिए क्षेत्र की पारिस्थितिक समृद्धि और महत्व पर प्रकाश डालता है।

- **क्षेत्रीय दुर्लभता:** चीन, मंगोलिया या अफगानिस्तान में पहले से कोई पुष्टि नहीं हुई है।

- **अनिश्चितता:** यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह दृश्य एक बार के प्रवास या प्रजनन आबादी की शुरुआत को दर्शाता है।

- **संरक्षण:** प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हिमालयी आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता को मजबूत करता है।

● अनुसंधान निर्देश

- संभावित प्रजनन व्यवहार की निगरानी करना।
- प्रजातियों के वितरण पर जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक बदलावों के प्रभावों का अध्ययन करना।

- **वैश्विक संदर्भ:** एशिया में प्रवासी तितली गतिशीलता की समझ में वृद्धि करता है।

पारिस्थितिकीय कारक जो इस दृश्य को प्रभावित करते हैं:

- **मेजबान पौधे की उपलब्धता:** तितली के लार्वा चुभने वाली बिछुआ (उर्टिका डायोइका) खाते हैं, जो पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।

- **जलवायु प्रभाव:** अनुकूल जलवायु परिस्थितियों ने भारत में प्रवास को सुगम बनाया होगा।

यूरोपीय रेड एडमिरल (वैनेसा अटलांटा) के बारे में



- रेड एडमिरल तितली (वैनेसा अटलांटा) उत्तरी अमेरिका और दुनिया भर में पाई जाने वाली एक आम प्रजाति है।

• विशेषताएँ और आकारिकी

- वयस्क रेड एडमिरल तितलियों के पंख खुले होते हैं जो आकार में 1.75 - 3 इंच तक होते हैं।
- इसका पृष्ठभूमि रंग काला है।
- एक आकर्षक दृश्य विशेषता नारंगी से लाल रंग की धारियाँ हैं जो उनके अगले और पिछले पंखों पर सीमांत पट्टियाँ बनाती हैं।
- अंडे हरे से क्रीम रंग के होते हैं और छोटे बालों जैसी संरचनाओं से ढके होते हैं, जो बिछुआ के पत्तों पर छिपने में मदद करते हैं।
- लार्वा अपने मेजबान पौधे की पत्तियों को खाते हैं और लगभग 1.25 इंच की लंबाई तक बढ़ते हैं।

• सीमा और पर्यावास

- रेड एडमिरल तितली (वैनेसा अटलांटा) का वितरण उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया में विस्तृत है।
- जंगली में, वी. एटलांटा आमतौर पर जंगलों के पास नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

• IUCN स्थिति: कम चिंताग्रस्त (Least Concern)

- रिपोर्ट में मेकांग (-51.9%) और सालवीन (-48.3%) घाटियों में बर्फबारी में सबसे ज़्यादा चिंताजनक गिरावट का पता चलता है, इसके बाद तिब्बती पठार (-29.1%), ब्रह्मपुत्र (-27.9%), यांगत्ज़ी (-26.3%) और गंगा (-24.1%) घाटियाँ हैं।

बर्फ के दीर्घस्थायित्व का तात्पर्य है कि बर्फ ज़मीन पर कितने समय तक रहती है। जैसे-जैसे यह बर्फ पिघलती है, यह लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को पानी की आपूर्ति करती है

हिंदू कुश हिमालय (HKH) के बारे में

- HKH को इसके विशाल बर्फ भंडार के कारण दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इस क्षेत्र में दो ध्रुवीय क्षेत्रों से परे बर्फ और बर्फ का सबसे बड़ा भंडार है।
- HKH क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में म्यांमार तक आठ देशों के सभी या कुछ हिस्सों में 3,500 किमी तक फैला हुआ है।
- यह दस बड़ी एशियाई नदी प्रणालियों का स्रोत है - अमु दरिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र (यारलुंगत्सानपो), इरावदी, साल्विन (नू), मेकांग (लंकांग), यांगत्से (जिंशा), येलो रिवर (हुआंगहे), और तारिम (दयान) - और इस क्षेत्र में लगभग 240 मिलियन लोगों की आबादी को पानी, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ और आजीविका का आधार प्रदान करता है।
- इन नदियों के बेसिन 1.9 बिलियन लोगों को पानी उपलब्ध कराते हैं, जो दुनिया की आबादी का एक चौथाई है

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा पादप वर्ग का रेड एडमिरल तितलियाँ मुख्य रूप से अपने लार्वा के लिए मेजबान पौधों के रूप में उपयोग करती हैं?

- | | |
|----------------|-----------------|
| (a) डेज़ी वर्ग | (b) सरसों वर्ग |
| (c) गुलाब वर्ग | (d) बिच्छू वर्ग |

(p) :2118

हिंदूकुश हिमालय (HKH) में बर्फबारी में कमी

चर्चा में क्यों: इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की एक हालिया रिपोर्ट में हिंदूकुश हिमालय (HKH) में बर्फबारी के स्तर में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इस क्षेत्र के दो अरब से ज़्यादा लोगों के लिए जल और जलवायु सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

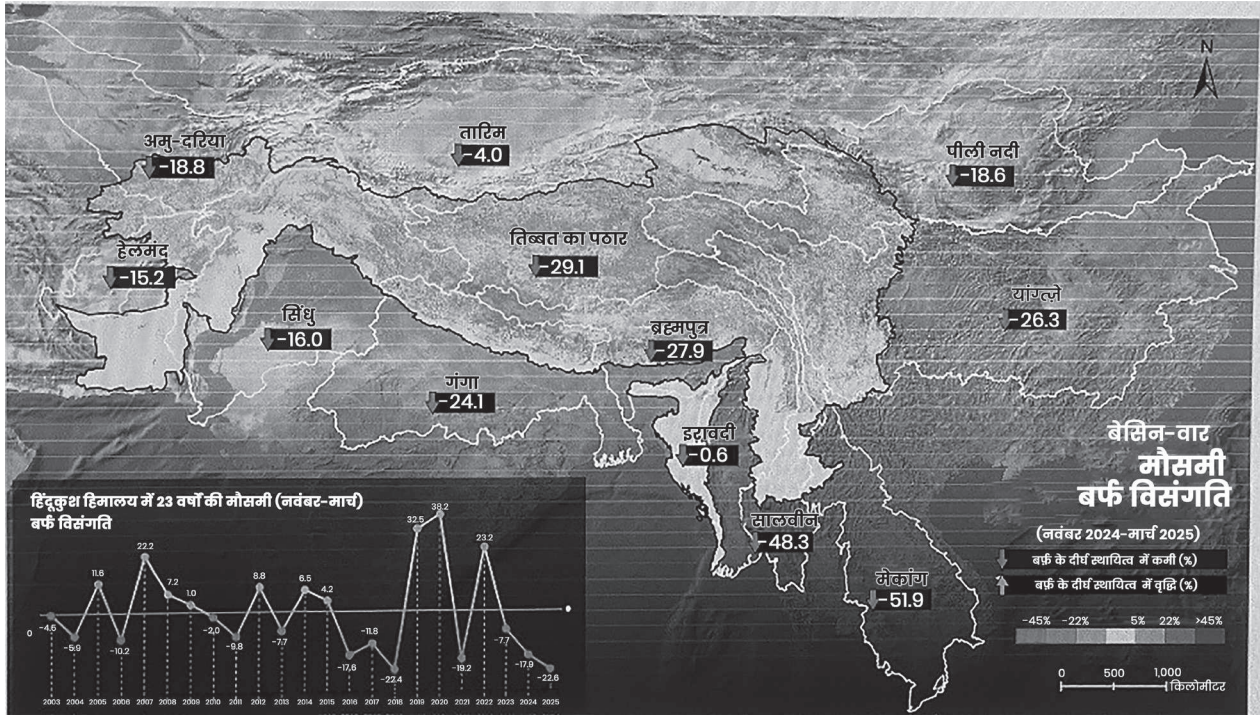
सो अपडेट रिपोर्ट 2025 के मुख्य निष्कर्ष

- 2020 से लेकर अब तक, हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में चार सर्दियों में सामान्य से कम बर्फबारी देखी गई है।
- 2024-2025 की सर्दियों में HKH में बर्फबारी का स्तर रिकॉर्ड 23.6% तक गिर गया। यह पिछले 23 वर्षों में दर्ज किया गया सबसे कम स्तर है।
- सभी बारह प्रमुख नदी घाटियों में बर्फबारी का स्तर नकारात्मक रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD)

- अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) हिंदू कुश हिमालय (HKH) के लोगों की ओर से काम करने वाला एक अंतर-सरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र है।
- **मुख्यालय:** काठमांडू
- आठ क्षेत्रीय सदस्य देश - अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान।
- यह HKH के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने और पर्वतीय पर्यावरण और संस्कृतियों की रक्षा करने के लिए काम करता है।
- **मिशन:** ज्ञान का निर्माण और साझा करना जो क्षेत्रीय नीति और कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और निवेश को आकर्षित करता है जो HKH के विविध देशों और समुदायों को हरित, अधिक समावेशी और जलवायु-लचीले विकास में संक्रमण करने में सक्षम बनाता है।
- **मुख्य स्तंभ**
 - आजीविका में वृद्धि
 - संसाधनों को बनाए रखना
 - संस्कृति को महत्व देना



बर्फ आवरण में कमी का प्रभाव

- **जल उपलब्धता:** सर्दियों के मौसम में बर्फ के जल्दी पिघलने के कारण, वसंत और गर्मियों के महीनों में जल उपलब्धता कम हो सकती है, जिससे HKH क्षेत्र में नदी घाटियों में दो अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- **नदी प्रवाह और व्यवधान:** ग्लेशियरों के घटने से धारा प्रवाह में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है, खासकर गर्मियों में।
 - **नदी प्रवाह में परिवर्तन -** पानी की मात्रा, धारा की तीव्रता, प्रवाह का मार्ग - आस-पास की जैव विविधता, नदी के पानी पर निर्भर मानवीय गतिविधियों और मिट्टी की उर्वरता, वन आवरण और पानी की उपलब्धता जैसे अन्य पारिस्थितिक घटकों पर भारी प्रभाव डालेगा।
- **कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर प्रभाव:** पर्याप्त बर्फबारी से रबी और खरीफ दोनों मौसमों को लाभ होता है क्योंकि इससे पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है और फसल क्षेत्र में वृद्धि होती है। बर्फबारी कम होने के साथ-साथ सूखे और फसलों के खराब होने का जोखिम बढ़ सकता है।
- **ऊर्जा की कमी:** जलप्रवाह की गति, मात्रा और दिशा में व्यवधान मौजूदा और आने वाली जलविद्युत परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है। HKH में बर्फ के आवरण में कमी और ग्लेशियरों के सिकुड़ने से अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है और भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के लिए चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं।

अनुकूलन रणनीतियाँ

- **जल प्रबंधन रणनीतियाँ और सूखे की तैयारी:** इनमें कई घटक शामिल हैं जैसे विभिन्न समूहों द्वारा पानी की मांग और उपयोग का प्रबंधन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पानी का आवंटन, पानी के उपयोग का विनियमन, पानी की बर्बादी को कम करना और इस्तेमाल किए गए पानी के पुनः उपयोग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, संभावित पानी की कमी के लिए चेतावनी प्रणाली स्थापित करना और सूखे की प्रतिक्रिया रणनीतियों को लागू करना।

- **बेसिन-स्तरीय लक्षित कार्यवाहियाँ:** चूंकि विभिन्न बेसिनों में बर्फ के बने रहने का स्तर अलग-अलग होता है, इसलिए प्रत्येक बेसिन के लिए अलग-अलग रणनीतियाँ मददगार होंगी।
- **राष्ट्रीय स्तर की तैयारी:** इसमें हिमालयी क्षेत्र में उद्योगों, बुनियादी ढाँचे और शहरी विकास जैसे आर्थिक क्षेत्रों का विनियमन शामिल है। खाद्य प्रणालियों, फसलों के चयन आदि में एक आदर्श बदलाव। हाइब्रिड सोलरहाइड्रो या माइक्रो-हाइड्रो-सोलर-बैटरी प्लांट, समुदाय के स्वामित्व वाली माइक्रो-हाइड्रो परियोजनाएँ आदि जैसी ऊर्जा लचीली प्रणालियाँ स्थापित करना।

निष्कर्ष

- हिंदू कुश हिमालय में बर्फ का तेजी से कम होना अरबों लोगों के लिए जल आपूर्ति, खेती और ऊर्जा को खतरे में डालता है। इससे निपटने के लिए हमें स्मार्ट जल प्रबंधन, अनुकूलित क्षेत्रीय योजनाएँ और मजबूत ऊर्जा प्रणालियों की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में लोगों और प्रकृति दोनों की रक्षा के लिए एक साथ काम करना और जल्दी से अनुकूलन करना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. भारत	2. पाकिस्तान	3. चीन
---------	--------------	--------

उपर्युक्त देशों में से कितने देश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएएमओडी) के सदस्य हैं?

(a) केवल एक	(b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी	(d) इनमें से कोई नहीं

(C) : 255

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ के स्तर में गिरावट जल और जलवायु सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा कर रही है। जल सुरक्षा और जैव विविधता पर बर्फ के घटते आवरण के प्रभाव पर चर्चा करें। इन प्रभावों को दूर करने के लिए अनुकूलन रणनीतियों का सुझाव दें। [250 शब्द] [15 अंक]

बंगाल की खाड़ी में मानसून में बदलाव और समुद्री उत्पादकता

चर्चा में क्यों: पिछले 22,000 वर्षों में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (आईएसएम) में उतार-चढ़ाव की खोज करने वाले एक अध्ययन में पाया गया है कि मजबूत और कमजोर मानसून बंगाल की खाड़ी में समुद्री उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं।

मुख्य विवरण

- समुद्री उत्पादकता प्लवक वृद्धि के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करती है, जो जलीय जीवन के पोषण का प्राथमिक स्रोत है।
- वैश्विक महासागर के 1% से भी कम क्षेत्र को कवर करने के बावजूद, बंगाल की खाड़ी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो दुनिया के लगभग 8% मत्स्य उत्पादन की आपूर्ति करता है।
- इसके तटों पर रहने वाले लाखों लोग प्रोटीन और आजीविका के लिए इन समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं।

समुद्री उत्पादकता पर प्रभाव

- नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि सदियों से अत्यधिक मानसून की स्थिति के कारण सतह पर समुद्री जीवन के लिए उपलब्ध भोजन में 50% की कमी आई है।
- समुद्री उत्पादकता में यह गिरावट, जो कि प्लवक के विकास को सहारा देने की महासागर की क्षमता है, समुद्री खाद्य जाल की नींव है।
- प्लवक, जिसमें फाइटोप्लांकटन और जूप्लांकटन शामिल हैं, इस जाल का आधार बनाते हैं, जिसमें फाइटोप्लांकटन अपना भोजन और अन्य समुद्री जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
- प्लवक की वृद्धि में कमी से पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आने की संभावना है, जिससे अंततः मछली भंडार कम हो जाएगा और तटीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

अत्यधिक मानसून से होने वाले प्रभाव के तंत्र

- तीव्र मानसून**
 - नदियों से बड़ी मात्रा में मीठे पानी का निर्वहन समुद्र की सतह पर मीठे पानी की एक परत बनाता है।
 - यह परत एक कैप के रूप में कार्य करती है, जो गहरी परतों से आवश्यक पोषक तत्वों को सूर्य के प्रकाश वाले ऊपरी पानी तक पहुँचने से रोकती है जहाँ प्लवक पनपते हैं।
 - इन पोषक तत्वों के बिना, प्लवक की वृद्धि कम हो जाती है, जिससे मछली सहित पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है।
- कमजोर मानसून**
 - कमजोर मानसून के परिणामस्वरूप समुद्री परिसंचरण और हवा से चलने वाले मिश्रण में कमी आती है।
 - इससे प्लवक को पोषक तत्वों की आपूर्ति भी अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उत्पादकता में भी गिरावट आती है।

- बेहद कमजोर और मजबूत मानसून अवधियाँ समुद्र के गहरे और सतही क्षेत्रों के बीच मिश्रण को बाधित करती हैं, जिससे पोषक तत्व ऊपरी क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाते जहाँ समुद्री जीवन पनपता है।

भविष्य के अनुमान: जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएँ

- जलवायु परिवर्तन के तीव्र होने और मानसून की परिवर्तनशीलता में वृद्धि होने की संभावना है।
- भविष्य के अनुमानों से पता चलता है कि गर्म सतही जल और बढ़े हुए मीठे पानी के अपवाह जैसी स्थितियाँ पिछले अंतरालों को प्रतिबिंबित कर सकती हैं जब समुद्री उत्पादकता में तेज़ी से गिरावट आई थी।
- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में चलनी वाली हवाएँ इतनी मजबूत नहीं हो सकतीं कि पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए पानी की विभिन्न परतों को मिश्रित कर सकें, जिससे जोखिम बढ़ सकता है।

आगे की राह

- इस खतरे से निपटने के लिए, भविष्य के जलवायु अनुमानों को परिष्कृत करना और मत्स्य पालन और तटीय संसाधनों के सतत प्रबंधन की जानकारी देना महत्वपूर्ण है।
- अरब सागर तक अनुसंधान का विस्तार करने से उत्तरी हिंद महासागर में व्यापक समकालिक प्रभावों का पता चलेगा।
- जलवायु परिवर्तन को सक्रिय रूप से संबोधित करना आवश्यक है, क्योंकि इससे मानसून के अधिक तीव्र और परिवर्तनशील होने की संभावना है, जिससे ये जोखिम और बढ़ जाएंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. बंगाल की खाड़ी में बदलते मानसून पैटर्न समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं? [150 शब्द] [10 अंक]

मूसा इंडैडामेनेंसिस

चर्चा में क्यों: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जंगली केले की एक प्रजाति में लगभग 4.2 मीटर का फलन दर्ज किया गया है, जो इसे दुनिया भर में केले में दर्ज किया गया सबसे लंबा फलन बनाता है।

मुख्य विवरण: खोज के बारे में

- जंगली केले की एक स्थानिक प्रजाति, मूसा इंडैडामेनेंसिस में फलन दर्ज किया गया था।
 - फलन वह शाखायुक्त या शाखारहित अक्ष होता है जिस पर फल व्यवस्थित होते हैं।
- नमूना अवस्थिति:** निकोबार द्वीप समूह में कैपबेल खाड़ी
- महत्व:** यह केले की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जैव विविधता को उजागर करता है (एएनआई)।

मूसा इंडडामानेसिस के बारे में

- **अवस्थिति:** मूसा इंडडामानेसिस एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त जंगली केले की प्रजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) के सुदूर उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती है।
- **खोज:** 2012 में लिटिल अंडमान में कृष्णा नाला रिजर्व वन के पास डॉ. लाल जी सिंह, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) के एक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया। इस प्रजाति का औपचारिक रूप से 2014 में वर्णन किया गया था।
- **भौतिक विशेषताएँ**
 - यह पौधा लगभग 11 मीटर लंबा होता है।
 - यद्यपि लिटिल अंडमान के पहले के नमूनों में तने की परिधि 100 सेमी से कम थी, हाल ही में खोजे गए निकोबार नमूनों में 110 सेमी की मोटाई दिखाई देती है, जो संभावित अंतर-प्रजाति भिन्नता को दर्शाता है।
- **पर्यावास:** मूसा इंडडामानेसिस झरनों या धाराओं के पास पनपता है, जो नमी वाले, छायादार वातावरण पर निर्भरता का संकेत देता है।
- **फलों का गुच्छा:** इसका फल गुच्छा फलन (लक्स) लगभग 1 मीटर मापता है, जो सामान्य प्रजातियों की तुलना में तीन गुना लंबा है। 2012 में शुरू में 3 मीटर दर्ज किया गया, 4.2 मीटर का नमूना इस प्रजाति की असाधारण वृद्धि क्षमता को उजागर करता है।
- **फूल:** अधिकांश केले के शंक्राकार फूलों के विपरीत, इसमें बेलनाकार, हरे फूल होते हैं।
- **फल:** खाने योग्य, मीठा और पौष्टिक रूप से समृद्ध, इसका गूदा आश्चर्यजनक रूप से नारंगी रंग का होता है, जो सामान्य केले के सफेद या पीले रंग के विपरीत होता है।
- **बीज:** खेती की जाने वाली किस्मों के विपरीत, इसके बीज अंकुरण के लिए व्यवहार्य होते हैं, जो प्रसार की क्षमता प्रदान करते हैं।
- **कृषि क्षमता:** मूसा इंडडामानेसिस के बड़े फल और मजबूत आनुवंशिक गुण संकरण के माध्यम से केले की पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र को संभावित रूप से लाभ मिल सकता है।



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में चर्चा में रहा मूसा इंडडामानेसिस निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है:

- (a) जंगली बेरी
- (b) केला
- (c) गोभी
- (d) संतरा

(9) : 2022

साओला के जीनोम का मानचित्रण

चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने साओला (स्यूडोरिक्स नेघेटिनहेसिस) के जीनोम का मानचित्रण किया है, जो दुनिया का सबसे दुर्लभ विशाल स्थलीय स्तनपायी है।

मुख्य विवरण: अध्ययन के बारे में

- **जीनोम अनुक्रमण:** शोधकर्ताओं ने शिकारियों के घरों से एकल किए गए 26 साओला के अवशेषों का विश्लेषण किया ताकि पूर्ण जीनोम तैयार किया जा सके।
- **जनसंख्या विभाजन**
 - आनुवंशिक डेटा से पता चला है कि साओला 5,000-20,000 साल पहले दो अलग-अलग आबादियों में विभाजित हो गया था, संभवतः अंतिम हिमनद अधिकतम के दौरान आवास विखंडन के कारण।
 - लगभग 4,000 साल पहले मानवीय गतिविधियों (जैसे शिकार, चावल की खेती, वनों की कटाई) ने आबादी को और अलग-थलग कर दिया।
- **आनुवंशिक विविधता का नुकसान**
 - दोनों आबादियों ने आनुवंशिक विविधता में गिरावट का अनुभव किया, लेकिन एक समूह में खोई हुई विविधता ने दूसरे को पूरक बनाया।
 - दो आबादियों को मिलाने से खोए हुए वेरिएंट की भरपाई करके आनुवंशिक स्वास्थ्य को बहाल किया जा सकता है।
- **महत्व:** अध्ययन संरक्षण रणनीतियों के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है, जिसमें तत्काल जमीनी कार्रवाई के साथ आनुवंशिक डेटा को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

साओला के बारे में

- एशियाई यूनिकॉर्न के रूप में जाना जाता है।
- साओला को नुकीले सिरे वाले दो समानांतर सींगों से पहचाना जाता है, जो लंबाई में 20 इंच तक पहुँच सकते हैं और नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं।
- साओला के चेहरे पर आकर्षक सफेद निशान होते हैं और थूथन पर बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनका उपयोग उनके क्षेत्र को चिह्नित करने या साथी को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है।
- **अवस्थिति:** वे केवल लाओस और वियतनाम के एनामाइट पहाड़ों में पाए जाते हैं।
- **पर्यावास:** बहुत कम या बिना शुष्क मौसम वाले सदाबहार जंगल
- **IUCN स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- **CITES:** परिशिष्ट I



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत साओलास का प्राकृतिक आवास है?

- (a) अल्ताई पर्वत
- (b) एनामाइट पर्वत
- (c) काकेशस पर्वत
- (d) यूराल पर्वत

(9) : 2022

शहरी मकड़ी

चर्चा में क्यों: नेब्रास्का-लिनकन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने फ़नल-बुनाई मकड़ियों (एजेलेनोप्सिस पेनसिल्वेनिका) में एक आकर्षक शहरी अनुकूलन का खुलासा किया है। ये मकड़ियाँ शहरी वातावरण के कारण होने वाले शोर हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपने जालों को संशोधित कर रही हैं। यह पहले ज्ञात मामलों में से एक है जहाँ कोई जानवर शोर प्रदूषण से निपटने के लिए न केवल व्यवहार बल्कि अपनी संवेदी ग्रहण संरचनाओं को भी बदलता है।

मुख्य निष्कर्ष

- **शहरी बनाम ग्रामीण मकड़ियाँ:** शोरगुल वाले शहरी क्षेत्रों की मकड़ियाँ ऐसे जाल बनाती हैं जो कंपनी की एक विस्तृत श्रृंखला को कम करते हैं, संभवतः अप्रासंगिक शोर को फ़िल्टर करने और वास्तविक खतरों या भोजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए।
- इसके विपरीत, ग्रामीण मकड़ियाँ (जब प्रयोगशाला में शहरी शोर के संपर्क में आती हैं) ऐसे जाल बनाती हैं जो कंपनी को बढ़ाते हैं, संभवतः एक अपरिचित, शोर भरे वातावरण में धारणा को बेहतर बनाने के लिए।
- इससे पता चलता है कि मकड़ियों में पर्यावरण शोर के संपर्क में आने के कारण जाल बनाने में अनुकूल लचीलापन होता है।

कार्यप्रणाली

मकड़ियाँ अपने जालों पर कंपनी को महसूस करके शिकार का पता लगाती हैं। अध्ययन से पता चला है कि मकड़ियाँ:

- रेशम के तनाव और धागे के लेआउट को बदल सकती हैं।
- जाल के धागों के आकार और घनत्व को बदल सकती हैं।
- ध्वनि कंपनी को बेहतर तरीके से अवशोषित या संचारित करने के लिए जाल की संरचना को संशोधित कर सकती हैं।

मकड़ियों के बारे में

- मकड़ियाँ एराज़िड समूह से संबंधित हैं, कीट वर्ग से नहीं। कीटों के विपरीत, जिनके छह पैर और दो आँखें होती हैं, मकड़ियों के आठ पैर और आम तौर पर छह या आठ आँखें होती हैं।
- जबकि ज़्यादातर मकड़ियाँ मांसाहारी होती हैं जो कीटों का शिकार करती हैं और उन्हें खाती हैं, मध्य अमेरिका में एक ऐसी प्रजाति है जो मुख्य रूप से पौधों पर फ़ीड करती है।
- वे विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित तरल से उत्पादित रेशम का उपयोग करके कीटों को फँसाने के लिए रेशम के जाले बुनने के लिए प्रसिद्ध हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर, मकड़ियाँ दुनिया भर में पाई जाती हैं।
- मकड़ियाँ भोजन को बाहरी रूप से पचाती हैं। एक बार जब वे अपने शिकार को पकड़ लेती हैं, तो वे उसके ऊपर पाचन तरल पदार्थ छोड़ती हैं। ये रस शिकार के शरीर को एक तरल में घोल देते हैं, जिसे मकड़ी फिर पी जाती है।



निहितार्थ

शहरी वन्यजीवों के लिए

- दर्शाता है कि कैसे अकशेरुकी भी मानव निर्मित तनावों के अनुकूल हो सकते हैं।
- शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी प्रजातियों की लचीलापन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- संकेत देता है कि व्यवहारिक लचीलापन शहरों में जैव विविधता को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

मनुष्यों के लिए

- शहरी शोर प्रदूषण के छिपे हुए प्रभावों को उजागर करता है - न केवल लोगों पर बल्कि वन्यजीवों पर भी।
- बेहतर शहरी नियोजन और शोर नियंत्रण का आग्रह करता है, विशेष रूप से हरे भरे स्थानों और वन्यजीव गलियारों में।
- जैव-प्रेरित प्रौद्योगिकियों की संभावना को खोलता है, जैसे कि कंपनी फ़िल्टर या स्पाइडर वेब यालिकी पर आधारित ध्वनिरोधी सामग्री।

महत्व

- यह शोध वन्यजीवों पर मानव-प्रेरित ध्वनि प्रदूषण के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। जबकि इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया है कि जानवर शोर भरे वातावरण में अपनी आवाज़ कैसे बदलते हैं, यह अध्ययन संवेदी सूचना के ग्रहण में अनुकूलन को प्रदर्शित करने वाले पहले अध्ययनों में से एक है।
- यह संचार के पारिस्थितिक अध्ययनों में संकेतों के उत्पादन और ग्रहण दोनों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

- शहरी शोर प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए अपने जाले को संशोधित करने वाली मकड़ियों की खोज उन जटिल तरीकों को उजागर करती है जिनसे वन्यजीव मानव-परिवर्तित वातावरण के अनुकूल होते हैं। जैसे-जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं और शोर का स्तर बढ़ता जा रहा है, जैव विविधता पर शहरीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने में इन प्राकृतिक अनुकूलनों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा कथन शहरी वातावरण में फ़नल-बुनाई मकड़ियों (एजेलेनोप्सिस पेनसिल्वेनिका) के बारे में हाल के निष्कर्षों की सबसे उचित व्याख्या करता है?

1. शहरी मकड़ियाँ, शोर प्रदूषण से निपटने के लिए कंपनी की एक विस्तृत श्रृंखला को कम करने वाले जाल बुनती हैं।
2. ग्रामीण मकड़ियाँ कंपनी को बढ़ाने वाले जाल बुनती हैं, खासकर अपरिचित शोर वाले वातावरण में।
3. अध्ययन से पता चलता है कि वेब निर्माण पूरी तरह से आनुवंशिक है और अनुभव से प्रभावित नहीं है।
4. यह अनुकूलन मुखर संचार के बजाय संवेदी फ़िल्टरिंग से जुड़ा हुआ है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

(e) : 2118

नदी प्रदूषण: मानव द्वारा एंटीबायोटिक का बढ़ता सेवन एक कारण

चर्चा में क्यों: पीएनएएस नेक्सस में हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि मानव द्वारा एंटीबायोटिक का बढ़ता सेवन नदियों के बड़े पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रहा है।

मुख्य विवरण

- एंटीबायोटिक प्रदूषण दुनिया भर में लाखों किलोमीटर नदियों में मौजूद है, जिसकी सांद्रता इतनी अधिक है कि यह जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है और दवा प्रतिरोध को बढ़ावा दे सकता है।
- शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में नदी प्रणालियों में लगभग 8,500 टन एंटीबायोटिक्स या लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष खपत की जाने वाली मात्रा का लगभग एक तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है, जबकि ये अक्सर अपशिष्ट जल प्रणालियों से होकर गुजरते हैं।
- एंटीबायोटिक्स के लिए दीर्घकालिक और संघयी पर्यावरणीय जोखिम अभी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, भले ही व्यक्तिगत एंटीबायोटिक्स के अवशेषों की मात्रा अधिकांश नदियों में बहुत कम सांद्रता में बदल जाती है, जिससे उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है।
- घरेलू स्रोतों से एंटीबायोटिक दवाओं के केवल 43% भार को अपशिष्ट जल प्रणालियों द्वारा संसाधित किया जाता है।
- छह मिलियन किलोमीटर या नदियों का 25% हिस्सा एंटीबायोटिक संदूषण के लिए उच्च जोखिम वाले स्तर से ऊपर है।
 - भारत में 80% से अधिक नदियों को उच्च या अत्यधिक उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है।
- दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन, सबसे अधिक जोखिम वाले स्तरों पर मौजूद होने की संभावना है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में, जहाँ बढ़ते उपयोग और सीमित अपशिष्ट जल उपचार ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

कारण

- **मनुष्यों में अपूर्ण चयापचय:** उपभोग की गई एंटीबायोटिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानव शरीर द्वारा पूरी तरह से चयापचय नहीं किया जाता है और उत्सर्जित होता है, जो अंततः जल प्रणालियों तक पहुँच जाता है।
- **अकुशल अपशिष्ट जल उपचार:** मौजूदा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र अक्सर एंटीबायोटिक अवशेषों को पूरी तरह से हटाने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे नदियों और झीलों में प्रवेश कर जाते हैं।

- **पशुधन और जलीय कृषि में व्यापक उपयोग:** एंटीबायोटिक्स का उपयोग पशुपालन और मछली पालन में बीमारी को रोकने और विकास को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से किया जाता है, जिससे पर्यावरण में अवशेषों का सीधा निर्वहन होता है।
- **दवा निर्माण से औद्योगिक उत्सर्जन:** एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन के दौरान अनुचित हैंडलिंग और रिसाव पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देता है, विशेष रूप से विनिर्माण केंद्रों के पास।
- **जलवायु परिवर्तन प्रभाव:** बढ़ते तापमान बैक्टीरिया की वृद्धि दर को बढ़ाते हैं और क्षैतिज जीन स्थानांतरण को बढ़ाते हैं, जिससे रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विकास और प्रसार में तेजी आती है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है?

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
- दवा प्रतिरोध के परिणामस्वरूप, एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं, और संक्रमण का इलाज करना मुश्किल या असंभव हो जाता है, जिससे बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी, विकलांगता और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
- एएमआर दुनिया में मृत्यु दर का तीसरा सबसे बड़ा कारण है।
- वैश्विक स्तर पर, 1 मिलियन से अधिक मौतें सीधे बैक्टीरियल एएमआर से जुड़ी हैं और 5 मिलियन मौतें अप्रत्यक्ष रूप से।

आगे की राह

- **वांश पहल:** एएमआर के प्रसार को रोकने के लिए, अस्पतालों के प्रबंधन और व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वच्छता तक बुनियादी पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।
- **चेन्नई घोषणा:** ओवर-द-काउंटर एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए, नया एच 1 नियम जो केवल दूसरी और तीसरी पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, उसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।
- **एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** “एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण”, एक व्यापक रणनीति जो मानव स्वास्थ्य को हमारे साझा पर्यावरण से जोड़ती है, को सभी एएमआर पहलों के लिए आधार के रूप में काम करना चाहिए।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश:** सरकारी बजट और निजी निवेश में वृद्धि अस्पतालों और प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाने में मदद कर सकती है।
- **नए एंटीबायोटिक अनुसंधान एवं विकास में मजबूत निवेश:** प्रमुख हितधारकों को शक्तिशाली और नवीन एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. पर्यावरण में अनियंत्रित एंटीबायोटिक प्रदूषण वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध संकट में एक मूक योगदानकर्ता है। कारणों की जांच करें और इस चुनौती से निपटने के लिए नीति-स्तरीय हस्तक्षेप का सुझाव दें। [250 शब्द | 15 अंक]

इसरो का सेमीक्रायोजेनिक इंजन परीक्षण

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने महेंद्रगिरि, तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी) में अपने सेमीक्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों के लिए 2000 kN थ्रस्ट सेमीक्रायोजेनिक इंजन के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मुख्य विवरण

- **परीक्षण विन्यास:** परीक्षण में इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (PHTA) सम्मिलित था, जिसमें थ्रस्ट चैंबर को छोड़कर सभी इंजन सिस्टम सम्मिलित हैं।
- **अवधि और प्रदर्शन:** इंजन को प्रज्वलित किया गया और 3.5 सेकंड के लिए संचालित किया गया, जो अपने रेटेड पावर स्तर के 60% तक पहुंच गया, जिससे स्थिर और नियंत्रित प्रदर्शन हुआ।
- **उद्देश्य:** परीक्षण का उद्देश्य इंजन के स्टार्टअप अनुक्रम को मान्य करना और कम दबाव और उच्च दबाव वाले टर्बो पंप, प्री-बर्नर और संबंधित नियंत्रण प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करना था।
- **भविष्य की योजनाएँ:** इंजन प्रणाली को व्यापक रूप से मान्य करने के लिए आगे के योग्यता परीक्षण निर्धारित हैं, जो इसरो के प्रक्षेपण वाहनों में इसके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

महत्व

- **बढ़ी हुई प्रक्षेपण क्षमताएँ:** लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) और केरोसिन प्रणोदक संयोजन का उपयोग करने वाला सेमीक्रायोजेनिक इंजन LVM3 रॉकेट के मौजूदा L110 कोर लिक्विड स्टेज को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अपग्रेड से जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़कर 5 टन होने की संभावना है।
- **पर्यावरण और परिचालन लाभ:** गैर-विषाक्त और गैर-खतरनाक प्रणोदकों का उपयोग मौजूदा प्रणोदन प्रणालियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है।
- **सामरिक महत्व:** स्वदेशी अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी विकसित करने से भारत उन्नत रॉकेट इंजन क्षमताओं वाले चुनिंदा देशों के समूह में सम्मिलित हो गया है, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ गई है।

सेमीक्रायोजेनिक इंजन क्या है?

सेमीक्रायोजेनिक इंजन एक प्रकार का रॉकेट प्रणोदन सिस्टम है जो क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइज़र और गैर-क्रायोजेनिक ईंधन के संयोजन का उपयोग करता है। विशेष रूप से, यह आमतौर पर ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरल ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग करता है - जिसे क्रायोजेनिक तापमान (लगभग -183 डिग्री सेल्सियस) पर संग्रहीत किया जाता है - और ईंधन के रूप में केरोसिन

(RP-1) का उपयोग करता है, जिसे परिवेश के तापमान पर संग्रहीत किया जा सकता है। यह इसे पूरी तरह से क्रायोजेनिक इंजनों से अलग बनाता है जो क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइज़र दोनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। रूस के RD-180 और स्पेसएक्स के मर्लिन इंजन सहित कई वैश्विक लॉन्च सिस्टम सेमीक्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करते हैं।

- **यह कैसे काम करता है:** LOX को क्रायोजेनिक तापमान तक ठंडा किया जाता है और केरोसिन के साथ मिलाया जाता है, जो दहन कक्ष में उच्च दक्षता से जलता है।

लाभ:

- पूर्ण क्रायोजेनिक सिस्टम की तुलना में सरल और अधिक मजबूत;
- गैर-विषाक्त और अपेक्षाकृत सुरक्षित ईंधन;
- उच्च थ्रस्ट और लागत प्रभावी;
- तरल हाइड्रोजन की तुलना में भण्डार करना और संभालना आसान;

सीमाएँ:

- पूर्ण क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में थोड़ी कम दक्षता;
- अभी भी क्रायोजेनिक को संभालना सम्मिलित है;

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. इसरो के सेमीक्रायोजेनिक इंजन में निम्नलिखित में से किस प्रणोदक संयोजन का उपयोग किया जाता है?

- तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन
- तरल ऑक्सीजन और केरोसिन
- ठोस प्रणोदक और तरल ऑक्सीजन
- हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड

(9) :258

सूर्य का उपसतही मौसम

चर्चा में क्यों: सौर भौतिकविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने सूर्य की सतह के नीचे प्लाज्मा के विशाल ज्वार का पता लगाया है, जिसे निकट-सतह अपरूपण परत (NSSL) कहा जाता है।

मुख्य विवरण

- प्लाज्मा धाराएँ, सूर्य की चुंबकीय चाल के साथ बदलती हैं और अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती हैं।
- निकट-सतह अपरूपण परत (NSSL), जो लगभग 35,000 किमी गहराई तक फैली हुई है, सूर्य की सतह के नीचे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
 - यह अलग-अलग घूर्णी व्यवहारों द्वारा चिह्नित है जो गहराई के साथ और अंतरिक्ष और समय के साथ परिवर्तनों द्वारा भिन्न होते हैं, जो सक्रिय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्रों और सौर चक्र से संबंधित हैं।

अध्ययन के बारे में

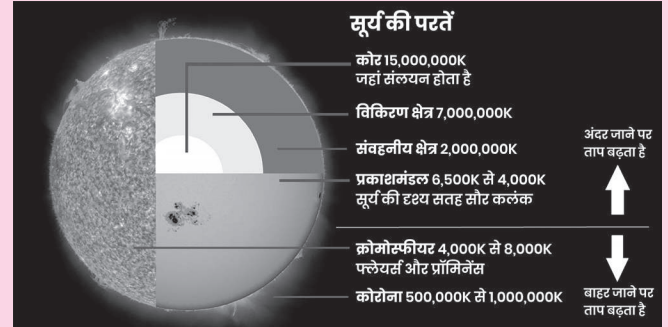
- प्लाज्मा धाराओं की खोज**
 - अध्ययन से पता चलता है कि NSSL में प्लाज्मा धाराएँ सूर्य के 11-वर्षीय सनस्पॉट चक्र के साथ तालमेल बिठाती हैं।
 - ये धाराएँ गतिशील हैं और सौर चक्र के साथ कार्यरत हैं, जो सूर्य के आंतरिक प्रवाह और उसके चुंबकीय चाल के बीच एक मजबूत संबंध को दर्शाता है।
- कार्यप्रणाली**
 - शोधकर्ताओं ने सौर पदार्थ की गति में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए हेलियोसिस्मोलॉजी नामक तकनीक का उपयोग किया, जो सूर्य के माध्यम से यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों को ट्रैक करती है।
 - विश्लेषण में नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी/हेलियोसिस्मिक और मैग्नेटिक इमेजर (SDO/HMI) और नेशनल सोलर ऑब्जर्वेटरी (NSO), यूएसए के ग्राउंडबेस्ड ग्लोबल ऑसिलेशन नेटवर्क ग्रुप (GONG) के एक दशक से अधिक के डेटा का उपयोग किया गया।
- प्रवाह पैटर्न और परिसंचरण कोशिकाएँ**
 - सतही प्लाज्मा प्रवाह सक्रिय सनस्पॉट अक्षांशों की ओर अभिसरित होते देखे गए।
 - NSSL के मध्य में, ये प्रवाह दिशा बदल देते हैं और बाहर की ओर बढ़ते हैं, जिससे परिसंचरण कोशिकाएँ बनती हैं।
 - कोरिओलिस बल, जो पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करता है, इन प्रवाहों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे घुमावदार गति होती है और सूर्य के घूर्णन अपरूपण को संशोधित किया जाता है।
- सौर गतिशीलता के लिए निहितार्थ**
 - NSSL के भीतर स्थानीय प्लाज्मा धाराएँ सूर्य के बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय प्रवाह (मरोड़ दोलन) को संचालित नहीं करती हैं, जो यह सुझाव देती हैं कि गहरी, फिर भी अज्ञात प्रक्रियाएँ इन वैश्विक प्रवाहों को शक्ति प्रदान करती हैं।
 - निष्कर्ष इस बारे में नई जानकारी प्रदान करते हैं कि सूर्य का आंतरिक भाग उसके बाहरी चुंबकीय व्यवहार से कैसे जुड़ा है और सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

प्रभाव और आगे की राह

- अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी**
 - इन छिपे हुए प्लाज्मा पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौर गतिविधि पृथ्वी पर उपग्रहों, विद्युत् ग्रिड और संचार को बाधित कर सकती है।
 - सूर्य की आंतरिक गतिशीलता के बारे में बेहतर जानकारी सौर व्यवहार और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव की अधिक सटीक भविष्यवाणियों को जन्म दे सकती है।
- अध्ययन संकेत देता है कि सूर्य के भीतर गहरी परतें हो सकती हैं जो इसकी वैश्विक गतिशीलता को संचालित करती हैं, जो आगे की जांच की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं।

सूर्य

- सूर्य लगभग 4.6 बिलियन वर्ष प्राचीन है और इसका व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है। इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 °C है, जबकि इसके केंद्र का तापमान आश्चर्यजनक रूप से 16 मिलियन °C तक पहुँच जाता है।
- सूर्य का औसत घनत्व पानी के घनत्व से 1.41 गुना है, जिसका घनत्व 999.97 किलोग्राम/मी³ है। इसकी तुलना में, पृथ्वी का कुल घनत्व पानी के घनत्व से लगभग 5.5 गुना है।
- सूर्य की सतह का गुरुत्वाकर्षण 274 मीटर/सेकेंड² पर अत्यधिक मजबूत है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण (9.8 मीटर/सेकेंड²) से लगभग 28 गुना अधिक है और चंद्रमा (1.62 मीटर/सेकेंड²) से काफी अधिक है।



सौर चक्र

- सूर्य विद्युत आवेशित गर्म गैस का एक विशाल गोला है। यह आवेशित गैस गति करती है, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र से गुजरता है, जिसे सौर चक्र कहा जाता है।
- हर 11 वर्ष या उसके बाद, सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से पलट जाता है। इसका तात्पर्य है कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह बदल लेते हैं। फिर सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को फिर से पलटने में लगभग 11 वर्ष लगते हैं।
- सौर चक्र सूर्य की सतह पर गतिविधि को प्रभावित करता है, जैसे कि सनस्पॉट, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होते हैं। जैसे-जैसे चुंबकीय क्षेत्र बदलते हैं, वैसे-वैसे सूर्य की सतह पर गतिविधि की मात्रा भी बदलती है।

- सौर चक्र को ट्रैक करने का एक तरीका सनस्पॉट की संख्या गिनना है। सौर चक्र की शुरुआत एक सौर न्यूनतम होती है, या जब सूर्य पर सबसे कम सनस्पॉट होते हैं। समय के साथ, सौर गतिविधि और सनस्पॉट की संख्या बढ़ती जाती है।
- सौर चक्र का मध्य सौर अधिकतम होता है, या जब सूर्य पर सबसे अधिक सनस्पॉट होते हैं। जैसे-जैसे चक्र समाप्त होता है, यह वापस सौर न्यूनतम पर आ जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सौर चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सौर चक्र लगभग 11 वर्ष की अवधि है जो सूर्य की सतह पर सनस्पॉट और सौर गतिविधि की संख्या में उतार-चढ़ाव से चिह्नित है।
2. प्रत्येक सौर चक्र के दौरान, सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र और ध्रुवता अपरिवर्तित रहती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(B) : 2018

S8 तनाव

चर्चा में क्यों: सुबारू टेलीस्कोप के हाइपर-सुप्राइम कैम द्वारा एकलित डेटा के आधार पर S8 तनाव के नए अनुमानों से पता चलता है कि तनाव का संबंध डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से है।

S8 तनाव के बारे में

- S8 (सिग्मा आठ) ब्रह्मांड विज्ञान में एक प्रमुख पैरामीटर है जो ब्रह्मांड में पदार्थ (दृश्यमान और डार्क मैटर दोनों सहित) के “क्लंपनेस” या क्लस्टरिंग को मापता है, विशेष रूप से लगभग 8 मेगापार्सेक (लगभग 26 मिलियन प्रकाश वर्ष) के पैमाने पर।
- यह पदार्थ घनत्व में उतार-चढ़ाव के मूल माध्य वर्ग से प्राप्त होता है जब पदार्थ वितरण को इस पैमाने पर समतल किया जाता है।
- उच्च S8 मान का अर्थ है कि अधिक पदार्थ एक साथ एकलित है, जबकि कम मान अधिक समान वितरण को इंगित करता है।
- S8 तनाव दो अलग-अलग प्रकार के खगोलीय प्रेक्षणों से प्राप्त S8 के मानों के बीच एक निरंतर और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण विसंगति को संदर्भित करता है, अर्थात्
 - **कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) माप:** ये प्रारंभिक ब्रह्मांड की जांच करते हैं और आमतौर पर उच्च S8 मान (लगभग 0.83) देते हैं।
 - **बड़े पैमाने पर संरचना और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग सर्वेक्षण:** ये वर्तमान ब्रह्मांड की जांच करते हैं और लगातार कम S8 मान (लगभग 0.76-0.78) पाते हैं।

S8 को मापना

- **CMB से:** यह फोटॉनों का एक भण्डार है, प्रकाश के कण, जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वे बिग बैंग, उसके बाद की चमक से बचे हुए हैं। ब्रह्मांड विज्ञानी बिग बैंग के बाद के CMB में तापमान में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करते हैं, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि मानक Λ CDM (लैम्ब्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल) के अनुसार ब्रह्मांडीय इतिहास में पदार्थ कैसे एकलित हुआ होगा।
- **गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग और गैलेक्सी सर्वेक्षण से:** दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश कैसे हस्तक्षेप करने वाले पदार्थ (कॉस्मिक शियर) द्वारा विकृत होता है, इसका अवलोकन पदार्थ के एकलित होने का प्रत्यक्ष, वर्तमान माप प्रदान करता है।
- **ब्रह्मांड विज्ञान में महत्व**
 - **मानक मॉडल का परीक्षण:** S8, Λ CDM मॉडल के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मांड की संरचना और विकास का वर्णन करने वाला प्रचलित सिद्धांत है। S8 तनाव से पता चलता है कि या तो हमारे माप या ब्रह्मांडीय संरचना निर्माण की हमारी समझ अधूरी हो सकती है।
 - **डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के लिए निहितार्थ:** तनाव यह संकेत दे सकता है कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी वर्तमान में मानी जाने वाली धारणा से अलग तरीके से व्यवहार करती है, या यह कि नए भौतिकी, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच परस्पर क्रिया, संशोधित गुरुत्वाकर्षण, या समय-भिन्न स्थिरांक, अवलोकनों को समझाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
 - **हबल तनाव से तुलना:** बेहतर ज्ञात हबल तनाव (जिसमें ब्रह्मांड के विस्तार दर में विसंगतियां सम्मिलित हैं) की तरह, S8 तनाव ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो संभावित रूप से ब्रह्मांड के मौलिक कामकाज की हमारी समझ में अंतराल की ओर इशारा करता है।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

सुबारू टेलीस्कोप

- सुबारू टेलीस्कोप की वेधशाला आधिकारिक तौर पर अप्रैल 1997 में हिलो, हवाई में अपनी आधार सुविधा भवन के पूरा होने के बाद स्थापित की गई थी।
- सुबारू टेलीस्कोप या तो टेलीस्कोप या संपूर्ण वेधशाला संगठन को संदर्भित कर सकता है।
- सुबारू टेलीस्कोप मौनाकेया के शिखर क्षेत्र में स्थित है, जो हवाई के बड़े द्वीप पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है।
- मौनाकेया का शिखर एक पृथक शिखर है जो पृथ्वी की अधिकांश मौसम प्रणालियों से ऊपर फैला हुआ है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: S8 तनाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है?

- (a) मैक्रोइकॉनॉमिक्स (b) कृषि आनुवंशिकी
(c) ब्रह्मांड विज्ञान (d) चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी

(Q) : 2018

बुल्सआई आकाशगंगा

चर्चा में क्यों: अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में नौ छल्लों वाली एक आकाशगंगा की खोज की है। उन्होंने इसे एक अप्रत्याशित खोज कहा क्योंकि पिछली छल्लों वाली आकाशगंगाओं में अधिकतम दो या तीन छल्लों का ही प्रदर्शन हुआ है।

बुल्सआई आकाशगंगा की खोज और विशेषताएँ

- हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके आठ छल्लों की उपस्थिति की पुष्टि की गई।
- हवाई में डब्ल्यू.एम. केक वेधशाला से प्राप्त डेटा ने नौवें छल्ले के अस्तित्व की पुष्टि की।
- आकाशगंगा का आधिकारिक नाम LEDA 1313424 है, लेकिन इसे आमतौर पर बुल्सआई आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है।
- बुल्सआई आकाशगंगा, मिल्की वे आकाशगंगा से लगभग 2.5 गुना बड़ी है, जिसका व्यास 250,000 प्रकाश वर्ष है।
- **छल्लों का निर्माण:** लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले, एक नीली बौनी आकाशगंगा एक बड़ी आकाशगंगा के केंद्र से सीधे गुजरी, जिससे गैस की लहरें जैसी लहरें निकलीं, जिससे रिंग पैटर्न में तारा निर्माण शुरू हो गया। बौनी आकाशगंगा अब भी पास ही स्थित है, लगभग 1,30,000 प्रकाश-वर्ष दूर, और एक पतली गैस की धार के माध्यम से अब भी जुड़ी हुई है।

विशाल निम्न पृष्ठभूमि चमक वाली (GLSB) आकाशगंगा में संभावित विकास

- बुल्सआई आकाशगंगा भी संकेत देती है कि यह एक दिन विशाल निम्न पृष्ठभूमि चमक वाली (GLSB) आकाशगंगा में विकसित हो सकती है।
- डार्क मैटर के अध्ययन में GLSB आकाशगंगाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **निम्न पृष्ठभूमि चमक वाली आकाशगंगाओं (LSB) की विशेषता है:**
 - हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों की कमी।
 - हाइड्रोजन से भारी बड़ी डिस्क होने के बावजूद बहुत कम तारा निर्माण। इसे एक विरोधाभास के रूप में वर्णित किया गया है जिसे वैज्ञानिक समझा नहीं सकते हैं।
 - माना जाता है कि वे डार्क मैटर से भरे हुए हैं, जो उन्हें इस रहस्यमयी पदार्थ के लिए उत्कृष्ट अध्ययन लक्ष्य बनाता है।
 - उनके केंद्रों के पास द्रव्यमान का अधिक समान वितरण, जो ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल का खंडन करता है जो सघन केंद्रों की भविष्यवाणी करता है। यह विसंगति वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है।
- GLSB आकाशगंगाएँ, LSB का सबसे बड़ा प्रकार हैं।
- **उदाहरण:** मालिन 1, मिल्की वे से लगभग 6.5 गुना चौड़ी और ज्ञात सबसे बड़ी सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक।

बुल्सआई आकाशगंगा के वैज्ञानिक निहितार्थ

- **अनुसंधान के अवसर**
 - टकराव वाली रिंग आकाशगंगा के GLSB आकाशगंगा में विकसित होने के प्रत्यक्ष प्रमाण को देखने की क्षमता।
 - GLSB आकाशगंगा अध्ययनों के माध्यम से डार्क मैटर वितरण में अंतर्दृष्टि।
- **अनसुलझे प्रश्न**
 - छल्ले वाली आकाशगंगा से GLSB आकाशगंगा में संक्रमण अभी भी सैद्धांतिक है।
 - सिद्धांतों को मान्य करने के लिए ब्रह्माण्ड संबंधी सिमुलेशन की आवश्यकता (उदाहरण के लिए, तीव्र डार्क मैटर हेलो स्पिन)।



यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बुल्सआई आकाशगंगा की असामान्य मल्टी-रिंग संरचना के निर्माण के लिए प्राथमिक प्रस्तावित तंत्र क्या है?

- इंटर-गैलेक्टिक अंतरिक्ष से गैस और धूल का क्रमिक संचय तरंगों में तारा निर्माण का कारण बनता है।
- एक विशाल आकाशगंगा के साथ एक करीबी गुरुत्वाकर्षण टकराव जो डिस्क को आकार देने के लिए ज्वारीय बलों का कारण बनती है।
- लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले एक नीली बौनी आकाशगंगा का इसके केंद्र से सीधा, सामने से गुजरना।
- आकाशगंगा के कोर के भीतर नियमित चक्रीय प्रक्रियाओं के कारण लाखों वर्षों में विस्तारित रिंगों में तारे बनते हैं।

(C) 2024

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

चर्चा में क्यों: जब क्षुद्रग्रह 2024 YR4 का पहली बार पता चला था, तो खगोलविदों को डर था कि यह पृथ्वी से टकरा सकता है। हालाँकि, विस्तृत ट्रैकिंग और विश्लेषण के बाद, वैज्ञानिकों ने अब पृथ्वी के लिए किसी भी खतरे से इनकार किया है।

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

- क्षुद्रग्रह 2024 YR4 एक पृथ्वी के निकट का क्षुद्रग्रह है। जब क्षुद्रग्रह 2024 YR4 की खोज की गई थी, तो अनुमान लगाया गया था कि 22 दिसंबर, 2032 को पृथ्वी से टकराने की इसकी बहुत कम संभावना है।
- अधिक अवलोकनों के बाद, नासा ने निष्कर्ष निकाला कि यह 2032 और उसके बाद पृथ्वी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव जोखिम नहीं पैदा करता है।
- **खोज:** 2024 YR4 को सबसे पहले 27 दिसंबर, 2024 को चिली में NASA द्वारा वित्तपोषित क्षुद्रग्रह स्थलीय-प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली (ATLAS) द्वारा माइनर प्लेनेट सेंटर (छोटे पिंडों की स्थिति माप के लिए अंतराष्ट्रीय समाशोधन गृह) को रिपोर्ट किया गया था। ATLAS में दुनिया भर के कई दूरबीन सम्मिलित हैं और इसका प्रबंधन हवाई विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है।
- **आकार:** मार्च 2025 में NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किए गए अवरक्त अवलोकनों के आधार पर, क्षुद्रग्रह 2024 YR4 का अब अनुमान 174-220 फीट (53-67 मीटर) है।

- **क्षुद्रग्रहों की प्रभाव संभावना का निर्धारण**
 - नासा का निकट-पृथ्वी वस्तु अवलोकन कार्यक्रम अनदेखे क्षुद्रग्रहों की खोज करने और मौजूदा संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रहों को ट्रैक करने के लिए वेधशालाओं को निधि देता है।
 - अवलोकन डेटा का उपयोग करते हुए, नासा की टीमें कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके निकट-पृथ्वी वस्तु कक्षाओं की गणना और परिशोधन करती हैं।
 - एक बार क्षुद्रग्रह की कक्षा की गणना हो जाने के बाद, नासा के निकट-पृथ्वी वस्तु अध्ययन केंद्र के ये वही कंप्यूटर मॉडल यह अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले वर्षों और दशकों में क्षुद्रग्रह पृथ्वी के कितने करीब आ सकता है।
- **प्रभाव संभावना में लगातार परिवर्तन**
 - प्रभाव संभावना का निर्धारण वैज्ञानिक प्रक्रिया है।
 - जैसे-जैसे नासा और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क में सम्मिलित अन्य लोग क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के बारे में और अधिक अवलोकन एकत्र करते हैं, क्षुद्रग्रह के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।
- **क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के विक्षेपण की संभावना**
 - नासा के दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण (DART) मिशन जैसा गतिज प्रभावक अंतरिक्ष यान एक क्षुद्रग्रह विक्षेपण तकनीक है जिसका उपयोग भविष्य में संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है।
 - प्रत्येक क्षुद्रग्रह अद्वितीय है और विक्षेपण क्षुद्रग्रह के आकार, भौतिक गुणों, कक्षा और खोज चेतावनी समय पर निर्भर करेगा।
 - 2024 YR4 ग्रह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव जोखिम नहीं रखता है, और इसलिए इस क्षुद्रग्रह के लिए संभावित विक्षेपण तकनीकों पर अटकलें लगाना जल्दबाजी होगी।
- **चंद्रमा पर प्रभाव:** क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के 22 दिसंबर, 2032 को चंद्रमा से टकराने की बहुत कम संभावना है। यदि क्षुद्रग्रह चंद्रमा से टकराता है, तो यह अपनी कक्षा में कोई बदलाव नहीं करेगा।

मुख्य विवरण

- **ककड़ी मोज़ेक वायरस (सीएमवी):** सीएमवी लगभग 90 प्रजातियों के एफ़ीड्स द्वारा फैलता है और खीरे, स्कैश, अनाज और औषधीय पौधों सहित कई प्रकार के पौधों को संक्रमित करता है। संक्रमित पौधे पत्तियों पर मोज़ेक पैटर्न दिखाते हैं, विकास में बाधा डालते हैं और बिक्री योग्य फल नहीं देते।
- **आरएनए-आधारित एंटीवायरल विकास:** एमएलयू शोध टीम ने शक्तिशाली छोटे हस्तक्षेप करने वाले आरएनए (siRNAs) से समृद्ध कुशल डबल-स्ट्रैंडेड आरएनए अणु (edsRNAs) तैयार किए। ये edsRNAs, पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करने पर, siRNAs में संसाधित होते हैं जो विशेष रूप से वायरल RNA को लक्षित करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं, जिससे पौधे की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है।
- **प्रयोगशाला निष्कर्ष:** मॉडल प्लांट निकोटियाना बेंथमियाना का उपयोग करके नियंत्रित प्रयोगों में, RNA-आधारित उपचार ने उल्लेखनीय प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया। जबकि सभी अनुपचारित पौधे उच्च वायरल लोड के आगे झुक गए, उपचारित पौधों में से 80-100% बच गए, जो सीएमवी संक्रमण के प्रबंधन में इस दृष्टिकोण की क्षमता को दर्शाता है।
- **आवेदन विधियाँ:** वर्तमान में, एंटीवायरल एजेंट प्रयोगशाला सेटिंग्स में मैनुअल रूप से लागू होते हैं। हालाँकि, बड़े पैमाने पर कृषि उपयोग की सुविधा के लिए, अधिक व्यावहारिक अनुप्रयोग विधियों, जैसे कि पर्ण स्प्रे, को विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं।
- **तीन प्रमुख लाभ:**
 - **उच्च परिशुद्धता:** पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के सबसे कमजोर आनुवंशिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित होती है, जिससे संक्रमण प्रतिरोध में सुधार होता है।
 - **मजबूत रक्षा:** dsRNA एक साथ कई जीनोम क्षेत्रों को लक्षित करता है, जिससे वायरस के उत्परिवर्तित होने और प्रतिरक्षा पहचान से बचने की संभावना कम हो जाती है।
 - **तीव्र अनुकूलनशीलता:** नए वायरल उपभेदों का मुकाबला करने के लिए dsRNA अनुक्रम को एक महीने के भीतर फिर से डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे उभरते खतरों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो जाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. “2024 YR4”, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, एक है:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| (a) AI माइक्रोचिप प्रोसेसर | (b) संचार उपग्रह |
| (c) निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह | (d) पृथ्वी के आकार का ग्रह |

(c) : 2024

आरएनए-आधारित एंटीवायरल विकास

चर्चा में क्यों: मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हेल-विटेनबर्ग (एमएलयू), जर्मनी के शोधकर्ताओं ने एक नया आरएनए-आधारित एंटीवायरल एजेंट विकसित किया है जो दुनिया भर में 1,200 से अधिक पौधों की प्रजातियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण पादप रोगजनक, ककड़ी मोज़ेक वायरस (सीएमवी) के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है।

RNA-आधारित एंटीवायरल क्या है?

- RNA-आधारित एंटीवायरल एक उपचार रणनीति है जो वायरल रोगजनकों के खिलाफ पौधे की सहज प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए डबल-स्ट्रैंडेड आरएनए (dsRNA) अणुओं का उपयोग करती है।
- जब इन डबल-स्ट्रैंडेड आरएनए (dsRNA) को पौधे में प्रविष्ट कराया जाता है, तो ये छोटे हस्तक्षेपकारी आरएनए (siRNA) में परिवर्तित हो जाते हैं, जो समान अनुक्रम वाले वायरल आरएनए को नष्ट करने का मार्गदर्शन करते हैं। इससे वायरस को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है और उसकी प्रतिकृति बनने से रोका जाता है।
- यह विधि पौधों में प्राकृतिक आरएनए हस्तक्षेप (RNAi) मार्ग का उपयोग करती है, जो रोग प्रबंधन के लिए एक लक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करती है।

महत्व

- **कृषि प्रभाव:** सीएमवी वैश्विक कृषि के लिए एक बड़ा खतरा है, भारत में वायरस के कारण केले के बागानों में 25-30% उपज का नुकसान हो रहा है। एक प्रभावी एंटीवायरल एजेंट का विकास इन नुकसानों को काफी हद तक कम कर सकता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ा सकता है।

- **गैर-जीएमओ दृष्टिकोण:** आरएनए-आधारित एंटीवायरल रणनीति एक गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (गैर-जीएमओ) समाधान प्रदान करती है, जो नियामक मानकों और सार्वजनिक स्वीकृति के साथ संरेखित होती है। यह दृष्टिकोण पौधे की आनुवंशिक संरचना में बदलाव किए बिना उसके प्राकृतिक रक्षा तंत्र का लाभ उठाता है।
- **अनुकूलनशीलता:** सीएमवी जैसे आरएनए वायरस की उच्च उत्परिवर्तन दर को देखते हुए, विभिन्न वायरल जीनोम क्षेत्रों को लक्षित करने वाले नए edsRNA को जल्दी से डिजाइन और तैनात करने की क्षमता उभरते वायरल उपभेदों के प्रबंधन के लिए एक लचीला और उत्तरदायी उपकरण प्रदान करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की रक्षा तंत्र में छोटे हस्तक्षेपकारी आरएनए (siRNAs) के कार्य का सबसे उचित वर्णन करता है?

- (a) वे प्रोटीन को एनकोड करते हैं जो सीधे रोगजनकों पर हमला करते हैं।
- (b) वे विशिष्ट वायरल आरएनए अनुक्रमों के क्षरण का मार्गदर्शन करते हैं।
- (c) वे वायरल प्रतिकृति के लिए टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं।
- (d) वे पौधे संरचनात्मक प्रोटीन के संश्लेषण को रोकते हैं।

(9) :2022

जीनोम-संपादित चावल की किस्में

चर्चा में क्यों: मई 2025 में, भारत ने दुनिया की पहली जीनोम-संपादित चावल की किस्में- DRR धान 100 (कमला) और पूसा DST चावल 1 जारी की।

मुख्य विवरण

- **विकास और प्रौद्योगिकी:** जीनोम-संपादित चावल की किस्मों को CRISPR-Cas12 तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था, जिससे विदेशी DNA को सम्मिलित किए बिना पौधे के अपने जीन का सटीक संपादन किया जा सकता है। यह विधि जीनोम संपादन को पारंपरिक आनुवंशिक संशोधन से अलग करती है।
 - ICAR द्वारा विकसित, ये उच्च उपज देने वाली, जल-कुशल और जलवायु-लचीली किस्में टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
- **विनियामक ढांचा:** भारत ने कुछ जीनोम-संपादित फसलों (विशेष रूप से SDN1 और SDN2 श्रेणियों) को कड़े जैव सुरक्षा नियमों से छूट दी है, जिससे तेजी से विकास और तैनाती की सुविधा मिलती है।

नई किस्में

डीआरआर धान 100 (कमला)

- **पैतृक:** लोकप्रिय सांबा महसूरी (बीपीटी5204) किस्म से व्युत्पन्न।
- **विशेषताएं:**
 - **कम परिपक्वता:** 125-130 दिनों में परिपक्व होती है, अपनी मूल किस्म से लगभग 20 दिन पहले।

- **अधिक उपज:** प्रति पैनेकल अधिक अनाज पैदा करती है, जिससे कुल उपज में वृद्धि होती है।
- **संसाधन दक्षता:** कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है।

पूसा डीएसटी चावल 1

- **पैतृक:** एमटीयू1010 से विकसित, एक व्यापक रूप से खेती की जाने वाली किस्म।
- **विशेषताएं:**
 - **तनाव सहिष्णुता:** सूखे और लवणता के प्रति बढ़ी हुई सहिष्णुता प्रदर्शित करती है।
 - **उपज में सुधार:** विशेष रूप से खारे और क्षारीय मिट्टी में उपज में 9.66% से 30.4% की वृद्धि दर्शाता है।

जीन संपादन तकनीक क्या है?

यह तकनीकों के एक समूह को संदर्भित करता है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के डीएनए को विशिष्ट आनुवंशिक सामग्री को जोड़कर, हटाकर या बदलकर संशोधित करने में सक्षम बनाता है। ये संशोधन व्यक्तिगत कोशिकाओं में परिवर्तन से लेकर पूरे जीव में परिवर्तन तक हो सकते हैं।

जीन संपादन कैसे काम करता है?

जीन संपादन दो प्राथमिक वितरण विधियों के माध्यम से संचालित होता है:

- **एक्स विवो संपादन:** इस दृष्टिकोण में, कोशिकाओं को रोगी से निकाला जाता है, प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है।
- **इन विवो एडिटिंग:** यहाँ, जीन-एडिटिंग उपकरण सीधे रोगी के शरीर में पहुँचाए जाते हैं ताकि विशिष्ट कोशिकाओं को लक्षित और संशोधित किया जा सके।

संपादन प्रक्रिया में इंजीनियर न्यूक्लियस - आणविक “तकनीक” - जैसे कि CRISPR-Cas9, TALENs, या जिंक फिंगर न्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है। ये न्यूक्लियस लक्षित DNA अनुक्रमों पर सटीक कट बनाते हैं। कोशिका की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली फिर इन कटों को ठीक करती है, जिससे आनुवंशिक सामग्री को सम्मिलित, हटाया या सुधारा जा सकता है।

चिकित्सा में अनुप्रयोग

जीन संपादन विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में परिवर्तनकारी क्षमता रखता है:

- **आनुवंशिक विकार:** सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे स्थितियों को अंतर्निहित आनुवंशिक उत्परिवर्तन को ठीक करके संबोधित किया जा सकता है।
- **कैंसर थेरेपी:** कैंसर कोशिकाओं को बेहतर ढंग से पहचानने और उन पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संशोधित करके, जीन संपादन इम्यूनोथेरेपी की प्रभावकारिता को बढ़ाता है।
- **संक्रामक रोग:** जीन संपादन संभावित रूप से कोशिकाओं को संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधी बना सकता है, जिससे उपचार के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।
- **व्यक्तिगत चिकित्सा:** किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना के आधार पर उपचार तैयार करने से उच्च प्रभावकारिता और कम दुष्प्रभाव सुनिश्चित होते हैं।

जीनोम संपादन और आनुवंशिक संशोधन के बीच अंतर को समझना

- जीनोम संपादन और आनुवंशिक संशोधन दोनों ही ऐसी तकनीकें हैं जिनका उपयोग जीवों के आनुवंशिक मेकअप को बदलने के लिए किया जाता है, लेकिन वे दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी और विनियामक उपचार में काफी भिन्न हैं। जीनोम संपादन एक अत्यधिक सटीक विधि है जिसमें किसी जीव के अपने डीएनए में विदेशी जीन को सम्मिलित किए बिना लक्षित परिवर्तन करना सम्मिलित है। CRISPR-Cas9 जैसी तकनीकों का उपयोग विशिष्ट जीन को संपादित या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को सूखा प्रतिरोध या जल्दी परिपक्वता जैसे वांछनीय लक्षणों को बढ़ाने में मदद मिलती है।
- भारत में, जीनोम-संपादित फसलें जिनमें विदेशी डीएनए सम्मिलित नहीं है, उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जो अधिक अनुकूल और कम प्रतिबंधात्मक विनियामक ढांचे की अनुमति देता है।
- इसके विपरीत, आनुवंशिक संशोधन (या जीएम प्रौद्योगिकी) में आम तौर पर अन्य प्रजातियों के जीन को लक्षित जीव में सम्मिलित करना सम्मिलित होता है ताकि नए लक्षण पेश किए जा सकें - जैसे कि कीट प्रतिरोध या शाकनाशी सहिष्णुता। यद्यपि जीएमओ ने कुछ संदर्भों में कृषि उत्पादकता में योगदान दिया है, उन्हें खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय परिणामों और प्रजातियों में आनुवंशिक सामग्री के मिश्रण के नैतिक निहितार्थों के कारण महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा है।

महत्व

- कृषि प्रभाव**
 - बढ़ी हुई उत्पादकता:** नई चावल की किस्में महत्वपूर्ण उपज सुधार का वादा करती हैं, जो बढ़ती आबादी की खाद्य मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
 - जलवायु लचीलापन:** सूखा और लवणता सहनशीलता जैसे गुण इन किस्मों को चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
 - संसाधन दक्षता:** कम पानी का उपयोग और कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन संधारणीय खेती प्रथाओं में योगदान देता है।
- आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ**
 - किसान लाभ:** उच्च पैदावार और लचीलापन किसानों के लिए आय में वृद्धि और जोखिम को कम कर सकता है।
 - खाद्य सुरक्षा:** बेहतर चावल उत्पादन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों का समर्थन करता है।
 - वैश्विक नेतृत्व:** जीनोम संपादन में भारत की उन्नति इसे टिकाऊ कृषि में अग्रणी बनाती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- विनियामक और नैतिक मुद्दे**
 - सार्वजनिक जागरूकता:** जीनोम-संपादित फसलों की सुरक्षा और लाभों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करना जनता का विश्वास हासिल करने के लिए आवश्यक है।
 - बौद्धिक संपदा:** CRISPR-Cas9 जैसी पेटेंट तकनीकों का उपयोग किसानों के लिए पहुँच और सामर्थ्य के बारे में चिंताएँ पैदा कर सकता है।
- पर्यावरणीय विचार**
 - जैव विविधता:** जीनोम-संपादित फसलों के जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है।

निष्कर्ष

- भारत द्वारा जीनोम-संपादित चावल की किस्मों का विकास स्थायी कृषि की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर, देश का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, किसानों की आजीविका का समर्थन करना और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। हालाँकि, इन नवाचारों को जिम्मेदारी से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढाँचों, सार्वजनिक धारणा और नैतिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. “कृषि में जीनोम संपादन स्थायी खाद्य सुरक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन यह विनियामक, नैतिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को जन्म देता है।” भारत द्वारा हाल ही में जीनोम-संपादित चावल की किस्मों के विकास और अनुमोदन के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक जाँच करें। [250 शब्द] [15 अंक]

याक जीनोमिक विज्ञान

चर्चा में क्यों: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के चार संस्थानों के विशेषज्ञों ने भारतीय याक के गुणसूत्र-स्तर के जीनोम को पहली बार एकत्रित किया है।

शोध के बारे में

- प्राथमिक उपलब्धि, भारतीय याक के गुणसूत्र-स्तर के जीनोम की सफल असेंबली है।
- कार्यप्रणाली:** अनुसंधान दल ने गुणसूत्र-स्तर असेंबली उत्पन्न करने के लिए अत्याधुनिक लॉन्ग-रीड सीक्वेंसिंग तकनीक और जैव सूचना विज्ञान उपकरणों का उपयोग किया।
- सहयोगी संस्थान**
 - अरुणाचल प्रदेश में याक पर ICAR-राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र
 - ICAR-भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
 - ICAR-केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, मेरठ
 - ICAR-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
- सार्वजनिक उपलब्धता**
 - एकत्रित जीनोम अब व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
 - इस उपलब्धता का उद्देश्य सहयोग को प्रोत्साहित करना और इस अनोखे जीव पर आगे के शोध में तेजी लाना है।

महत्व और संभावित प्रभाव

- इस जीनोमिक उपलब्धि में याक प्रजनन कार्यक्रमों और संरक्षण रणनीतियों को बदलने की क्षमता है।
- यह याक की आनुवंशिक जटिलताओं और हिमालयी क्षेत्र में इसकी पारिस्थितिक भूमिका की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाएगा।
- प्रत्याशित परिणाम**
 - आनुवंशिक रूप से विविध याक आबादी की पहचान करना और उनका संरक्षण करना।

- दुग्ध उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे वांछनीय गुणों को बढ़ाना।
- कठोर वातावरण में याक के अद्वितीय अनुकूलन के पीछे आनुवंशिक तंत्र को स्पष्ट करना।
- अन्य गोजातीय प्रजातियों के विकास और अनुकूलन में अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
- जीनोम संसाधन को लक्षित प्रजनन कार्यक्रम विकसित करने और शीत सहिष्णुता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक सटीकता के साथ दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए आनुवंशिक मार्करों की पहचान करने के लिए मूल्यवान माना जाता है।
- इस शोध से याक आबादी की दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करने और याक चरवाहों की आजीविका में सकारात्मक योगदान देने की संभावना है।
- **एलील खनन:** इस डेटा और अन्य गोजातीय प्रजातियों का उपयोग करके तुलनात्मक जीनोमिक्स से जैविक और अजैविक तनावों और गुणवत्ता लक्षणों में योगदान देने वाले उपयोगी जीनों के लिए एलील खनन के अवसर खुलने की संभावना है।

भारतीय (बोस ग्रुन्नियेंस)

याक



अवस्थिति : भारतीय याक लद्दाख, मिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं।

उच्च ऊंचाई वाली अर्धव्यवस्थाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन जानवरों को **अक्सर हिमालय का जहाज** कहा जाता है।

वे 7,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं जहां कुछ ही अन्य पशुधन प्रजातियां जीवित रह पाती हैं।

संरक्षण स्थिति और सुरक्षा

- ◆ IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
- ◆ CITES: परिशिष्ट 1।
- ◆ भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची 1।

याक आबादी के लिए खतरा

- ◆ घटते चरागाह क्षेत्र
- ◆ जलवायु परिवर्तन
- ◆ रोग
- ◆ आनुवंशिक क्षरण

वैज्ञानिक अनुसंधान अनुप्रयोग

- **आनुवंशिक विविधता संरक्षण:** आनुवंशिक रूप से विविध याक आबादी की पहचान करने और उन्हें संरक्षित करने की बढ़ी हुई क्षमता।
- **अनुकूलन तंत्र:** जटिल वातावरण में याक के अनुकूलन के पीछे आनुवंशिक तंत्र की गहरी समझ।
- **तुलनात्मक जीनोमिक्स:** अन्य गोजातीय प्रजातियों में विकास और अनुकूलन पैटर्न की अंतर्दृष्टि।
- **रोग प्रतिरोध:** चरम स्थितियों में रोग प्रतिरोध में योगदान देने वाले आनुवंशिक कारकों की पहचान।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार करें:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. चरागाह क्षेत्रों का सिकुड़ना | 2. जलवायु परिवर्तन |
| 3. रोग | 4. आनुवंशिक क्षरण |

उपर्युक्त में से कितने याक आबादी के लिए खतरा हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

(P) : 2022

सेमाग्लूटाइड: भारत में मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन के लिए एक क्रांतिकारी उपचार

चर्चा में क्यों: ओज़ेम्पिक, वेगोवी और राइबेलसस जैसे ब्रांड नामों के तहत विपणन किए जाने वाले सेमाग्लूटाइड ने टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन और वजन घटाने को बढ़ावा देने में अपनी दोहरी प्रभावकारिता के लिए भारत में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।

सेमाग्लूटाइड के बारे में मुख्य विवरण

- सेमाग्लूटाइड एक ग्लूकागन जैसा पेप्टाइड-1 (GLP-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट है।
- यह प्राकृतिक हार्मोन GLP-1 की क्रिया की नकल करता है, इंसुलिन स्राव को बढ़ाता है, ग्लूकागन रिलीज को दबाता है, गैस्ट्रिक खाली करने की गति को धीमा करता है और भूख को कम करता है।
- ये संयुक्त प्रभाव बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण और वजन घटाने में योगदान करते हैं।

क्रियान्वन

- **ओज़ेम्पिक:** इसे त्वचा के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए।
- **वेगोवी:** उच्च खुराक वाली एक इंजेक्टेबल फॉर्मूलेशन, जिसे दीर्घकालिक वजन प्रबंधन के लिए अनुमोदित किया गया है।
- **राइबेलसस:** मौखिक टैबलेट रूप, जो मधुमेह के उपचार के लिए इंजेक्शन का एक विकल्प प्रदान करता है।

• **नैदानिक प्रभावकारिता:** नैदानिक परीक्षणों ने प्रदर्शित किया है कि सेमाग्लूटाइड HbA1c के स्तर को काफी कम करता है और पर्याप्त वजन घटाने में मदद करता है। कुछ अध्ययनों में, रोगियों ने शरीर के वजन में 15% तक की कमी का अनुभव किया, जो मोटापे के उपचार में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

प्रासंगिकता

- **मधुमेह और मोटापे का बढ़ता प्रचलन:** भारत टाइप 2 मधुमेह और मोटापे के बढ़ते बोझ का सामना कर रहा है, जिसे अक्सर “डायबिटीज” कहा जाता है। सेमाग्लूटाइड की दोहरी क्रिया दोनों स्थितियों को एक साथ संबोधित करती है, एक व्यापक चिकित्सीय दृष्टिकोण प्रदान करती है।

- **कार्डियोवैस्कुलर लाभ:** ग्लाइसेमिक नियंत्रण और वजन घटाने से परे, सेमाग्लूटाइड को हृदय संबंधी प्रमुख प्रतिकूल घटनाओं में कमी के साथ जोड़ा गया है, जिसमें दिल के दौरों और स्ट्रोक सम्मिलित हैं, जो भारतीय मधुमेह रोगियों के बीच प्रचलित जटिलताएं हैं।
- **रोगी अनुपालन:** इंजेक्शन और मौखिक दोनों तरह के फॉर्मूलेशन की उपलब्धता रोगी के उपचार के नियमों का पालन बढ़ाती है, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को पूरा करती है और समग्र परिणामों में सुधार करती है।

संभावित दुष्प्रभाव और विचार

- **गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं:** आम दुष्प्रभावों में मतली, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और कब्ज सम्मिलित हैं। ये लक्षण आमतौर पर क्षणिक होते हैं और निरंतर उपयोग से कम हो सकते हैं।
- **दुर्लभ लेकिन गंभीर जोखिम:**
 - **अग्राशयशोथ:** अग्राशय की सूजन के मामले सामने आए हैं, लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
 - **थायराइड ट्यूमर:** जानवरों पर किए गए अध्ययनों ने थायराइड सी-सेल ट्यूमर के संभावित जोखिम का संकेत दिया है, हालांकि मानव डेटा अनिर्णायक है।
 - **दृष्टि परिवर्तन:** मधुमेह रेटिनोपैथी जटिलताओं के उदाहरण देखे गए हैं, जिसके लिए नियमित रूप से आंखों की जांच की आवश्यकता होती है।
- **अन्य विचार:** मरीजों को इंजेक्शन स्थल पर प्रतिक्रियाएँ, हाइपोग्लाइसीमिया (विशेषकर जब इसे अन्य मधुमेहरोधी दवाओं के साथ लिया जाए) और संभावित रूप से गुर्दों की कार्यप्रणाली में बदलाव का अनुभव हो सकता है। नियमित निगरानी और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

- सेमाग्लूटाइड टाइप 2 मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य के लिए प्रासंगिक है। ग्लाइसेमिक नियंत्रण, वजन घटाने और हृदय संबंधी जोखिम शमन सहित इसके बहुआयामी लाभ इसे पुरानी बीमारी के प्रबंधन में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में स्थान देते हैं। हालांकि, संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता और व्यक्तिगत रोगी मूल्यांकन चिकित्सीय परिणामों को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में समाचारों में देखे गए सेमाग्लूटाइड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सेमाग्लूटाइड एक जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है जिसका उपयोग टाइप 2 मधुमेह और मोटापे दोनों के उपचार में किया जाता है।
2. यह इंसुलिन स्राव को दबाने और गैस्ट्रिक खाली करने में तेजी लाने का काम करता है।
3. भारत में, सेमाग्लूटाइड केवल इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है।
4. नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि यह मधुमेह रोगियों में हृदय संबंधी जोखिम को कम कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 3 और 4
(e) 1, 2, 3, 4

थैलेसीमिया

चर्चा में क्यों: विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया, जिसका विषय था, थैलेसीमिया के लिए एक साथ: समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना।

थैलेसीमिया के बारे में

- थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो परिवारों के माध्यम से (वंशानुगत रूप से) पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, जिसमें शरीर असामान्य प्रकार का या अपर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन बनाता है।
- हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को वहन करता है। यह विकार बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने का कारण बनता है, जिससे एनीमिया (खून की कमी) हो जाती है।

थैलेसीमिया का कारण

- **हीमोग्लोबिन दो प्रोटीनों से बना होता है:**
 - अल्फा ग्लोबिन
 - बीटा ग्लोबिन
- थैलेसीमिया तब होता है जब किसी जीन में कोई ऐसा वैरिएंट होता है जो इन प्रोटीनों में से किसी एक के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है।

थैलेसीमिया के प्रकार

- अल्फा थैलेसीमिया तब होता है जब अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से संबंधित एक या एक से अधिक जीन अनुपस्थित होते हैं या उनमें कोई बदलाव (वैरिएंट) होता है।
 - अल्फा थैलेसीमिया दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, चीन और अफ्रीकी मूल के लोगों में सबसे अधिक बार होता है।
- बीटा थैलेसीमिया तब होता है जब समान जीन दोष बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
 - बीटा थैलेसीमिया भूमध्यसागरीय मूल के लोगों में सबसे अधिक बार होता है। कुछ हद तक, चीनी, अन्य एशियाई और अफ्रीकी अमेरिकी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।
- थैलेसीमिया के कई रूप हैं। प्रत्येक प्रकार के कई अलग-अलग उपप्रकार हैं। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया दोनों में निम्नलिखित दो रूप सम्मिलित हैं:
 - थैलेसीमिया मेजर
 - थैलेसीमिया माइनर
- थैलेसीमिया मेजर विकसित करने के लिए व्यक्ति को दोनों माता-पिता से भिन्न जीन विरासत में मिलना चाहिए।
- थैलेसीमिया माइनर तब होता है जब आपको वैरिएंट जीन केवल एक माता-पिता से मिलता है। इस प्रकार के विकार वाले लोग रोग के वाहक होते हैं। अधिकांश समय, उनमें कोई लक्षण नहीं होते।

लक्षण

- अल्फा थैलेसीमिया मेजर का सबसे गंभीर रूप स्टिलबर्थ (जन्म के दौरान या गर्भावस्था के अंतिम चरण में अजन्मे बच्चे की मृत्यु) का कारण बनता है।
- बीटा थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हुए बच्चे जन्म के समय सामान्य होते हैं, लेकिन जीवन के पहले वर्ष के दौरान गंभीर एनीमिया विकसित करते हैं।
- **अन्य लक्षण**
 - चेहरे पर हड्डी की विकृति
 - थकान
 - विकास विफलता
 - सांस की तकलीफ
 - पीली त्वचा (पीलिया)

उपचार

- थैलेसीमिया का कोई निश्चित इलाज नहीं है, उपचार के विकल्पों में लक्षणों का प्रबंधन करना सम्मिलित है।
- थैलेसीमिया मेजर के उपचार में अक्सर नियमित रक्त आधान और फोलेट सप्लीमेंट सम्मिलित होते हैं।
- जिन लोगों को बार-बार रक्त आधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) की आवश्यकता होती है, उन्हें एक उपचार की ज़रूरत होती है जिसे केलेशन थेरेपी कहा जाता है। यह उपचार शरीर से अतिरिक्त आयरन को निकालने के लिए किया जाता है।
- अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कुछ लोगों, विशेष रूप से बच्चों में रोग के उपचार में मदद कर सकता है।

विश्व थैलेसीमिया दिवस का इतिहास

- विश्व थैलेसीमिया दिवस की स्थापना थैलेसीमिया अंतर्राष्ट्रीय संघ (TIF) द्वारा 1994 में TIF के संस्थापक पैनोस एंगलज़ोस के बेटे जॉर्ज एंगलज़ोस की याद में की गई थी।
- जॉर्ज की मृत्यु थैलेसीमिया के कारण हुई थी, और इस दिन को वैश्विक स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को याद करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है जो इससे प्रभावित हैं। तब से, इस दिन को प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों में अभियान, रक्तदान अभियान और नीति वार्ता के साथ मनाया जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) हड्डियाँ और उपास्थि (b) अपर्याप्त फेफड़ों की क्षमता

(c) रक्त (d) मांसपेशियों की कमजोरी

(c) : 2019

निपाह वायरस

चर्चा में क्यों: केरल के मलप्पुरम जिले में 42 वर्षीय महिला निपाह के लिए सकारात्मक पाई गई, जो एक जूनोटिक वायरस है जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है।

मुख्य विवरण

- केरल में 2018 से निपाह के पाँच प्रकोप हुए हैं।
- अब तक केवल छह लोग ही पॉजिटिव पाए जाने के बाद जीवित रह पाए हैं — एक कोझिकोड में 2018 में, एक कोच्चि में 2019 में, और चार मामले कोझिकोड में 2023 में सामने आए।

निपाह वायरस के बारे में:

- निपाह वायरस (NiV) एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों और इंसानों के बीच फैल सकता है।
- **उत्पत्ति:** निपाह वायरस की पहली बार पहचान 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सूअरों और इंसानों में एक प्रकोप के दौरान हुई थी।
- **भारत में प्रकोप:** भारत में 2001 और 2007 में पश्चिम बंगाल से, जो बांग्लादेश की सीमा से सटा है, मानवों में निपाह वायरस के दो प्रकोप दर्ज किए गए।
- **प्राकृतिक स्रोत:** Pteropus जाति के बड़े फलाहारी चमगादड़** निपाह वायरस के प्राकृतिक वाहक होते हैं।
- निपाह वायरस से सूअरों और इंसानों दोनों में बीमारी हो सकती है।
- NiV संक्रमण आमतौर पर दिमाग की सूजन (encephalitis) से जुड़ा होता है और यह हल्की से लेकर गंभीर बीमारी तथा मृत्यु तक का कारण बन सकता है।

निपाह वायरस का संचरण:

- संक्रमित जानवरों, जैसे चमगादड़ या सूअर, या उनके शरीर के तरल पदार्थों (जैसे रक्त, मूत्र या लार) के सीधे संपर्क में आने से।
- ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जो संक्रमित जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों से दूषित हुए हों (जैसे संक्रमित चमगादड़ द्वारा दूषित खजूर का रस या फल)।
- निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति या उनके शरीर के तरल पदार्थों (जैसे नाक या सांस की बूंदें, मूत्र या रक्त) के निकट संपर्क में आने से।

संकेत और लक्षण

- लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 4-14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं।
- यह बीमारी शुरू में 3 से 14 दिनों तक बुखार और सिरदर्द के रूप में प्रकट होती है, और अक्सर इसमें श्वसन संबंधी लक्षण जैसे खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई भी शामिल होती हैं।
- निपाह वायरस संक्रमण के मामलों में लगभग 40 से 75% तक मृत्यु हो सकती है। इस संक्रमण से बचने वाले लोगों में दीर्घकालिक दुष्प्रभाव देखे गए हैं, जिनमें लगातार दौरे पड़ना (convulsions) और व्यक्तित्व में बदलाव (personality changes) शामिल हैं।

रोग की पहचान (Diagnosis):

- NiV संक्रमण की पहचान के लिए विभिन्न परीक्षण उपलब्ध हैं।
- बीमारी के प्रारंभिक चरण में, प्रयोगशाला परीक्षण रीयल-टाइम पॉलीमरेज़ चेन रिप्लिकेशन (RT-PCR) के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें गले और नाक के स्वैब, मस्तिष्कमेरु द्रव (cerebrospinal fluid), मूत्र और रक्त का नमूना लिया जाता है।
- बीमारी के बाद के चरणों में या सुधार के बाद, एंटीबॉडी की जांच के लिए एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे (ELISA) का उपयोग किया जाता है।

निपाह का उपचार

- वर्तमान में निपाह वायरस संक्रमण के लिए कोई दवा या टीका नहीं है, हालांकि डब्ल्यूएचओ ने निपाह को डब्ल्यूएचओ अनुसंधान और विकास ब्लूप्रिंट के लिए प्राथमिकता वाली बीमारी के रूप में पहचाना है।
- गंभीर श्वसन और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं के इलाज के लिए गहन सहायक देखभाल की सिफारिश की जाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो मुख्य रूप से चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलता है।
2. वर्तमान में निपाह वायरस संक्रमण के लिए कोई दवा या टीका नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(c) : 2025

2025 तक टीबी मुक्त भारत

चर्चा में क्यों: विश्व टीबी दिवस 2025 पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 से पांच साल पहले 2025 तक टीबी मुक्त भारत प्राप्त करने के लिए तीव्र, लक्षित कार्रवाई का आह्वान किया।

मुख्य विवरण

- **लक्षित हस्तक्षेपों पर जोर:** प्रधानमंत्री ने भूगोल (शहरी बनाम ग्रामीण) और व्यवसाय के आधार पर टीबी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के महत्व को रेखांकित किया, विशेष रूप से निर्माण, खनन और कपड़ा जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षण और उपचार के लिए संवेदनशील समूहों की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता देना है।
- **निदान और उपचार में प्रगति:** बैठक में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास की समीक्षा की गई, जिसमें टीबी निदान नेटवर्क का विस्तार कर 8,540 NAAT प्रयोगशालाएं और 87 कल्चर एवं ड्रग सेंसिटिविटी (दवा प्रतिरोध जांच) प्रयोगशालाएं शामिल हैं। अब तक 26,700 से अधिक एक्स-रे इकाइयां कार्यशील हो चुकी हैं, जिनमें 500 एआई-सक्षम (AI-enabled) हैंडहेल्ड डिवाइसेज भी शामिल हैं, और अतिरिक्त 1,000 इकाइयां प्रक्रिया में हैं।
- **सामुदायिक जुड़ाव और समर्थन:** प्रधानमंत्री ने जागरूकता और उपचार पालन को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव टूल के माध्यम से निक्षय मिलों और टीबी रोगियों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) पर बढ़ती चिंताएँ:** यह नया फोकस उस बढ़ती हुई चिंता के बीच आया है जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को लेकर है, क्योंकि यह टीबी नियंत्रण में दशकों की प्रगति को कमजोर कर सकता है।

क्षय रोग (टीबी) क्या है?

- क्षयरोग (टीबी) एक संक्रामक बीमारी है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। टीबी तब फैलती है जब फेफड़ों में सक्रिय टीबी से ग्रसित व्यक्ति खांसते, छींकते या बात करते हैं, जिससे हवा में सूक्ष्म बूंदें (droplets) निकलती हैं, जिनमें यह बैक्टीरिया मौजूद होता है। इन बूंदों के श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करने से अन्य लोग संक्रमित हो सकते हैं।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) क्या है?

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी) दवाओं के प्रभावों का प्रतिरोध करने के लिए विकसित होते हैं, जिससे मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं। टीबी के संदर्भ में, एएमआर दवा प्रतिरोधी उपभेदों को जन्म देता है, जिससे बीमारी का इलाज करना अधिक कठिन और महंगा हो जाता है।

उपचार

- भारत में, क्षय रोग (टीबी) का इलाज चार प्रथम-पंक्ति दवाओं के मानक छह महीने के उपचार का उपयोग करके किया जाता है: आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पाइराज़िनामाइड और एथम्ब्यूटोल (एचआरजेडई), जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
- दवा-प्रतिरोधी टीबी (MDR/XDR) के उपचार में द्वितीय-पंक्ति की दवाओं जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन, बेडाक्विलिन, डेलामैनिड, लाइनेज़ोलिड और क्लोफाज़िमिन का उपयोग किया जाता है। ये दवाएं लंबे और अधिक जटिल उपचार योजनाओं में दी जाती हैं, जो अधिकतम 24 महीनों तक चल सकती हैं। हाल ही में नई, कम अवधि वाली MDR-TB उपचार योजनाएं (9-11 महीने) विकसित की गई हैं, जो पूरी तरह से मौखिक दवाओं जैसे बेडाक्विलिन और लेवोफ्लॉक्सासिन पर आधारित हैं। अब इन्हें अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।
- टीबी रोगियों के करीबी संपर्कों को आइसोनियाज़िड या रिफ़ापेंटिन के साथ निवारक उपचार भी दिया जाता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण

- **एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग:** मनुष्यों और जीवों में एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित तरीके से प्रिस्क्राइब और उपयोग।
- **खराब संक्रमण नियंत्रण:** स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में अपर्याप्त स्वच्छता और सफ़ाई।
- **त्वरित निदान की कमी:** प्रतिरोधी संक्रमणों की पहचान में देरी से अनुचित उपचार होता है।
- **अधूरे उपचार पाठ्यक्रम:** रोगी निर्धारित एंटीबायोटिक उपचार पूरा नहीं करते।
- **कृषि पद्धतियाँ:** विकास संवर्धन और रोग की रोकथाम के लिए पशुधन में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग।

भारत में टीबी: डेटा और सांख्यिकी

डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत ने टीबी नियंत्रण में महत्वपूर्ण प्रगति की है:

- **घटनात्मक दर:** 2015 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 237 मामलों से 2023 में 195 तक 17.7% की कमी।
- **मृत्यु दर:** इसी अवधि के दौरान प्रति 100,000 जनसंख्या पर 28 से घटकर 22 मृत्यु हो गई।

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)

पूर्व में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के रूप में जाना जाता है, एनटीईपी का लक्ष्य 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करना है। प्रमुख रणनीतियों में सम्मिलित हैं:

- **रोकथाम:** टीकाकरण और जन जागरूकता अभियान।
- **पता लगाना:** बेहतर स्क्रीनिंग और नैदानिक सेवाएं।
- **उपचार:** निःशुल्क, गुणवत्ता-सुनिश्चित टीबी विरोधी दवाएँ और रोगी सहायता प्रदान करना।

- **निर्माण:** स्वास्थ्य प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- **निक्षय पोषण योजना:** टीबी रोगियों को उपचार के दौरान प्रति माह ₹1000 का पोषण सहायता प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे 2018 से 1.28 करोड़ से अधिक रोगियों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त, 2.55 लाख निक्षय मित्रों द्वारा 29.4 लाख खाद्य टोकरीयाँ वितरित की गई हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. क्षय रोग (टीबी) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) टीबी वायरस के कारण होता है।
- (b) टीबी मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है।
- (c) टीबी दूषित पानी से फैलता है।
- (d) टीबी एक वायुजनित जीवाणु संक्रमण है।

(P) : 2018

रेबीज

चर्चा में क्यों: केरल में रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है, कथित तौर पर पिछले चार से पांच वर्षों में यह दर खतरनाक रूप से बढ़ रही है।

रेबीज के बारे में

- रेबीज एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में प्रगतिशील और घातक सूजन का कारण बनती है।
- रेबीज स्तनधारियों से मनुष्यों में फैलने वाली एक वायरल बीमारी है जो तीव्र इंसेफेलाइटिस का कारण बनती है।
- रेबीज के नैदानिक रूप
 - उग्र रेबीज - अति सक्रियता और मतिभ्रम की विशेषता। उग्र रेबीज मानव रेबीज का सबसे आम रूप है।
 - लकवाग्रस्त रेबीज - पक्षाघात और कोमा की विशेषता।
- रेबीज संक्रमित जानवरों, जैसे पागल कुत्तों, चमगादड़ों और कभी-कभी अन्य प्रजातियों के श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में आने से फैलता है।
- **रेबीज का संक्रमण:** रेबीज वायरस मुख्य रूप से किसी पागल जानवर की लार से फैलता है जब वह किसी व्यक्ति को काटता या खरोंचता है। घाव, खरोंच, टूटी हुई त्वचा या मुंह और नाक की परत को चाटने से भी वायरस फैल सकता है।
 - हालांकि, रेबीज वायरस भी पाया गया है और संभवतः आंसू और तंत्रिका ऊतक जैसे अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से भी फैल सकता है। रेबीज वायरस रक्त या मल में नहीं पाया जाता है।
 - रेबीज का मानव-से-मानव संचरण अत्यंत दुर्लभ है।
 - स्तन के दूध या पके हुए मांस सहित दूध के सेवन से मानव रेबीज होने की कोई साक्ष्य-आधारित रिपोर्ट नहीं है।
- **मनुष्यों में रेबीज का विकास**
 - मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद, जैसे कि किसी जानवर के काटने से, रेबीज वायरस परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क) में चला जाता है।

- जब वायरस मस्तिष्क में पहुंचता है, तो संक्रमित व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और नैदानिक लक्षण दिखाई देते हैं।
- नैदानिक लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 2-3 महीने बाद दिखाई देते हैं।
- असाधारण मामलों में, नैदानिक लक्षण कुछ दिनों के बाद या छह महीने से अधिक समय के बाद विकसित हो सकते हैं।
- **मनुष्यों में रेबीज के लक्षण**
 - काटने के घाव के स्थान पर बेचैनी, दर्द, चुभन या खुजली महसूस होना;
 - तंत्रिका संबंधी विकार, जो कुछ दिनों में बढ़ जाता है, जिसमें चिंता, भ्रम और उत्तेजना सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, व्यक्ति को भ्रम, मतिभ्रम, अनिद्रा और अन्य असामान्य व्यवहार का अनुभव हो सकता है;
 - एरोफोबिया (हवा का डर);
 - हाइड्रोफोबिया (पानी का डर); बाद के चरण में, पानी को देखने मात्र से गर्दन और गले में ऐंठन हो सकती है;
 - शोर, तेज रोशनी या झपट के प्रति असहिष्णुता;
 - अति सक्रियता (आमतौर पर उग्र रेबीज में);
 - निगलने में कठिनाई, मतली, उल्टी;
 - स्थानीयकृत कमजोरी, पक्षाघात सिंड्रोम;
 - कोमा और मृत्यु

रेबीज
150 से अधिक देशों
और क्षेत्रों में पाया जाता है

.....

यह सभी जूनोटिक रोगों में सबसे घातक है - वे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं

.....

प्रतिवर्ष 59,000 से अधिक मौतें
- एशिया और अफ्रीका में
95% से अधिक

.....

रेबीज से होने वाली लगभग 50% मौतें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होती हैं



- **उपचार:** नैदानिक लक्षण दिखने के बाद मानव रेबीज लगभग हमेशा घातक होता है। वर्तमान में दुनिया में कहीं भी रेबीज के रोगियों के लिए कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है, जिनमें पहले से ही रोग के नैदानिक लक्षण दिखाई देते हैं।
- **रोकथाम:** कुत्तों के बीच और कुत्तों से मनुष्यों में रेबीज के संक्रमण को रोकने के लिए कुत्तों का टीकाकरण और काटने की रोकथाम महत्वपूर्ण है। रेबीज को उसके स्रोत पर रोकना जीवन बचाने का एक लागत प्रभावी तरीका है।

- फोटोबायोलॉजिकल प्रक्रियाएँ हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए बैक्टीरिया और हरे शैवाल की प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण गतिविधि का उपयोग करती हैं।
- फोटोइलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रियाएँ पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने के लिए विशेष अर्धचालकों का उपयोग करती हैं।
- सौर थर्मोकैमिकल हाइड्रोजन उत्पादन पानी के विभाजन प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए केंद्रित सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, अक्सर धातु ऑक्साइड जैसी अन्य प्रजातियों के साथ।
- **जैविक प्रक्रियाएँ**
 - जैविक प्रक्रियाएँ बैक्टीरिया और सूक्ष्म शैवाल जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करती हैं और जैविक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकती हैं।
 - माइक्रोबियल बायोमास रूपांतरण में, सूक्ष्मजीव हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए बायोमास या अपशिष्ट जल जैसे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जबकि फोटोबायोलॉजिकल प्रक्रियाओं में, सूक्ष्मजीव ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में हाइड्रोजन के स्वच्छ, व्यापक उपयोग से जुड़ी चुनौतियाँ

- **उच्च लागत:** कम कार्बन ऊर्जा से हाइड्रोजन का उत्पादन करना इस समय महंगा है।
- **बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ:** हाइड्रोजन के बुनियादी ढाँचे का विकास धीमा है और व्यापक रूप से अपनाने में बाधा बन रहा है।
- **CO₂ उत्सर्जन:** हाइड्रोजन की आपूर्ति आज लगभग पूरी तरह से प्राकृतिक गैस और कोयले से की जाती है।
- **हाइड्रोजन भंडारण चुनौतियाँ:** हाइड्रोजन को सुरक्षित, कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से संग्रहीत करना, विशेष रूप से वाहनों में, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और चल रहे शोध का केंद्र बिंदु है।
- **विनियामक बाधाएँ:** विनियमन वर्तमान में स्वच्छ हाइड्रोजन उद्योग के विकास को सीमित करते हैं।

हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव

- दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीतियों में हाइड्रोजन की भूमिका स्थापित करना। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और शहर की सरकारें भविष्य की अपेक्षाओं का मार्गदर्शन कर सकती हैं। कंपनियों के पास स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य भी होने चाहिए।
- स्वच्छ हाइड्रोजन की व्यावसायिक मांग को बढ़ावा देना। स्वच्छ हाइड्रोजन तकनीकें उपलब्ध हैं, लेकिन लागतें चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। स्वच्छ हाइड्रोजन के लिए स्थायी बाजार बनाने वाली नीतियाँ, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित हाइड्रोजन से उत्सर्जन को कम करने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और उपयोगकर्ताओं द्वारा निवेश को कम करने के लिए आवश्यक हैं।
- लागत कम करने के लिए R&D का समर्थन करना। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लागत में कमी के साथ-साथ, ईंधन कोशिकाओं, हाइड्रोजन आधारित ईंधन और इलेक्ट्रोलाइज़र सहित लागत कम करने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए R&D महत्वपूर्ण है।
- पहले कदम उठाने वालों के निवेश जोखिमों को संबोधित करना। हाइड्रोजन के लिए नए अनुप्रयोग, साथ ही स्वच्छ हाइड्रोजन आपूर्ति और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ, परिनियोजन वक्र के सबसे जोखिम भरे बिंदु पर हैं। लक्षित और समय-सीमित ऋण, गारंटी और अन्य उपकरण निजी क्षेत्र को निवेश करने, सीखने और जोखिम और पुरस्कारों को साझा करने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- प्राकृतिक हाइड्रोजन एक स्वच्छ और आशाजनक ऊर्जा विकल्प प्रदान करता है, लेकिन इसके व्यापक उपयोग में उच्च लागत, भंडारण संबंधी समस्याएँ और सीमित बुनियादी ढाँचे जैसी चुनौतियाँ हैं। लक्षित निवेश, सहायक नीतियों और अनुसंधान एवं विकास के साथ, यह संधारणीय ऊर्जा के लिए वैश्विक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़ी प्राथमिक उत्पादन विधियाँ क्या हैं? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में हाइड्रोजन को एकीकृत करने से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। [250 शब्द] [15 अंक]



पहलगाम आतंकी हमला

चर्चा में क्यों: 22 अप्रैल को पहलगाम (बैसरन घाटी) में आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान समर्थित हमलावरों ने एक गांव में धावा बोला, लोगों से उनका धर्म पूछा और उन्हें मार डाला, जिसके परिणामस्वरूप 26 लोगों की मौत हो गई। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का यह स्पष्ट प्रयास था, इसने सीमा पार से होने वाले हमलों से भारत को अंदर से विभाजित करने की ओर बदलाव को चिह्नित किया।

मुख्य विवरण

- **नागरिकों पर हमला:** 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर में यह पहली बड़ी नागरिक-लक्षित आतंकी घटना है।
- **जिम्मेदार अभिकर्ता:** लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने हमले की जिम्मेदारी ली।

पहलगाम हमले का प्रभाव

- **सुरक्षा चुनौतियाँ:** हमले कश्मीर घाटी में सुरक्षा बुनियादी ढांचे के बारे में लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं।
- **पर्यटन:** हाल ही में हुए आतंकी हमलों ने क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और साथ ही पर्यटन पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- **सांप्रदायिकता का खतरा:** पीड़ितों की हत्या करने से पहले धर्म पूछने की हरकत सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे सामाजिक बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है।

बैसरन घाटी

- पहलगाम से लगभग 5 किमी दूर स्थित, बैसरन पर्यटकों और ट्रेकर्स दोनों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य स्थल है।
- मोटर से जाने की सुविधा न होने के कारण, यहाँ केवल पैदल या टट्टू से ही पहुँचा जा सकता है, जिसने हाल ही में हुई आतंकी घटना में बचाव प्रयासों के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कीं।
- अक्सर 'मिनी स्विटजरलैंड' के नाम से मशहूर, बैसरन अपने हरे-भरे घास के मैदानों, घने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लुभावने दृश्यों के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो यूरोपीय परिदृश्यों के आकर्षण को बारीकी से दर्शाता है।
- पहलगाम विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक के रूप में इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांत परिवेश की प्रशंसा करता है।
- यह घास का मैदान पहलगाम और लिहुर घाटी के आश्चर्यजनक पैनोरमा के लिए प्रसिद्ध ट्यूलियन झील के रास्ते में ट्रेकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण आधार शिविर के रूप में कार्य करता है।
- लिहुर नदी के व्यापक दृश्यों के साथ बैसरन का प्राकृतिक आकर्षण पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करता है, चाहे ग्रीष्मकाल की गर्मी हो या बर्फ से ढके सर्दियों के महीने।

भारत की प्रतिक्रिया

- **सिंधु जल संधि का निलंबन:** भारत ने संधि को निलंबित करके स्पष्ट बयान दिया: "पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।"
- अटारी-वाघा सीमा को भारत ने तुरंत बंद कर दिया। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।
- **व्यापारिक संबंध:** भारत और पाकिस्तान के बीच सभी द्विपक्षीय व्यापार भी रोक दिए गए। इसने कपड़ा और सीमेंट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं का निर्यात बंद कर दिया। इस कार्रवाई से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बुरी तरह से बाधित हुए, जिससे मुख्य भूमि-आधारित व्यापार मार्ग कट गया।
- **बीजा निरस्तीकरण:** भारत ने देश में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों को तुरंत निर्वासित कर दिया और उनके बीजा निरस्त कर दिए, जिससे आतंकवाद के खिलाफ अपने मजबूत रुख का प्रदर्शन हुआ। सार्क बीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत, पाकिस्तानी नागरिक भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
- **सांस्कृतिक संबंध:** सभी प्रदर्शन, स्क्रिनिंग, संगीत रिलीज़ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को निलंबित कर दिया गया, और पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया।
- **उच्चायोग संबंध:** नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उच्चायोगों की कुल संख्या को और अधिक कटौती के माध्यम से वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा।

आगे की राह

- **एआई संचालित खतरे का पता लगाना:** विशेष रूप से खतरनाक और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एआई-संचालित खतरे का पता लगाने जैसी अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों का उपयोग करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क की निगरानी और पाकिस्तानी आतंकी बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के साथ आतंकवाद विरोधी गठबंधनों को मजबूत करना।
- **सामान्य स्थिति बहाल करना:** तत्काल कार्रवाई सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित होनी चाहिए।
- **डी-रेडिकलाइजेशन और सामुदायिक सहभागिता:** कट्टरपंथी बन चुके लोगों के लिए पुनर्वासि पहल करना। चरमपंथी प्रचार का खंडन करने के लिए अंतर-धार्मिक चर्चाओं को बढ़ावा देना।
- **आर्थिक:** समृद्धि के माध्यम से शांति को मजबूत करना, पर्यटन रिकवरी पैकेज शुरू करना और स्थानीय व्यापार मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

निष्कर्ष

पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया कानूनी और नैतिक आधार पर दृढ़ है। इतिहास इसे नेतृत्व, नैतिकता और रणनीतिक सटीकता द्वारा आकार दिए गए एक सैद्धांतिक और संतुलित प्रतिशोध के रूप में याद रखेगा।

ऑपरेशन सिंदूर

चर्चा में क्यों: ऑपरेशन सिंदूर को सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने और 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान के रूप में डिज़ाइन किया गया था।

मुख्य विवरण

- बहावलपुर और मुरीदके सहित नौ प्रमुख आतंकी शिविरों का पता लगाया गया और उन्हें पूरी तरह से बहु-एजेंसी खुफिया जानकारी के बाद समन्वित हवाई और जमीनी अभियानों के माध्यम से नष्ट कर दिया गया।

उद्देश्य

- ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों और उनके योजनाकारों को दंडित करने के इरादे से बनाया गया था।
- सीमा पार आतंकी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने का इरादा।

खुफिया जानकारी और लक्ष्य चयन

- टीम ने आतंकी परिदृश्य की सूक्ष्म जांच की।
- बड़ी संख्या में प्रशिक्षण मैदानों और आतंकी शिविरों की पहचान की।

संयम और परिचालन नैतिकता

- संपार्श्विक क्षति को रोकने के लिए आत्म-संयम का प्रयोग किया।
- नागरिकों की सुरक्षा के लिए, केवल आतंकवादी लक्ष्यों को नष्ट किया गया।

हमलों के परिणाम

- कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।
- पाकिस्तान में ग्यारह हवाई ठिकाने नष्ट कर दिए गए।
- जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठ को काफ़ी नुकसान पहुँचाकर जवाब दिया।

मारे गए आतंकवादी लक्ष्यों में शामिल हैं:

- अब्दुल मलिक और यूसुफ अजहर अहमद रऊफ मुदस्सिर।
- ये लोग पुलवामा विस्फोट और आईसी-814 अपहरण से जुड़े थे।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

- 7, 8 और 9 मई की शाम को, पाकिस्तान ने हताश और भयावह प्रतिक्रिया में भारतीय नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों का इस्तेमाल किया।
- लेकिन इससे पहले कि वे महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचा पाते, भारत के सुरक्षा बल सतर्क थे और मानव रहित हवाई वाहनों और मिसाइल खतरों की लहर को रोकने और खत्म करने के लिए तैयार थे।

भारत की जवाबी कार्रवाई

- भारत ने गुरजनवाला के नज़दीक रडार सुविधाओं को नष्ट कर दिया और लाहौर में रडार प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले किए।
- नौ आतंकवादी ठिकानों पर - चार पाकिस्तान में (बहावलपुर और मुरीदके सहित) और पाँच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में (मुजफ्फराबाद और कोटली सहित) - भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीक और अच्छी तरह से समन्वित मिसाइल हमले किए। ये स्थल लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के लिए महत्वपूर्ण कमांड सेंटर के रूप में काम करते थे, जो मुंबई (2008) और पुलवामा (2019) जैसे महत्वपूर्ण हमलों के प्रभारी थे।

- नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जैकोबाबाद सहित ग्यारह सैन्य प्रतिष्ठानों को भारत ने तीन घंटे के अंतराल में निशाना बनाया।
- सरगोधा और भोलारी सहित प्रमुख गोला-बारूद डिपो और हवाई अड्डे, जहाँ F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान स्थित थे, हमले के निशाने पर थे। इससे पाकिस्तान की वायु सेना के लगभग 20% बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर दिया गया।

रणनीतिक महत्व

- एक नई रणनीतिक लाल रेखा:** ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लाल रेखा खींची- अगर आतंक राष्ट्र की नीति है, तो इसका सामना एक स्पष्ट और सशक्त प्रतिक्रिया के साथ किया जाएगा। इसने निरोध से प्रत्यक्ष कार्रवाई की ओर बदलाव को चिह्नित किया।
- आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के लिए समान दंड:** भारत ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों के बीच कृत्रिम अलगाव को खारिज कर दिया, दोनों पर एक साथ हमला किया।
- पाकिस्तान की वायु रक्षा कमजोरियों का खुलासा:** भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान की चीनी आपूर्ति वाली वायु रक्षा प्रणालियों को दरकिनार कर दिया और उन्हें जाम कर दिया, राफेल जेट, SCALP मिसाइलों और हैमर बमों का उपयोग करके केवल 23 मिनट में मिशन पूरा किया, जिससे भारत की तकनीकी बढ़त का प्रदर्शन हुआ।

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया - निष्क्रिय प्रतिरोध से सक्रिय प्रतिशोध तक। आतंकवादियों और उनके राज्य प्रायोजकों दोनों को लक्षित करके, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता की रक्षा के लिए अपने संकल्प को मजबूत किया। ऑपरेशन ने न केवल एक मजबूत सैन्य प्रतिक्रिया दी, बल्कि भारत ने सीमा पार आतंकवाद का सामना कैसे किया, इस पर रणनीतिक कथा को भी नया रूप दिया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में, भारतीय सशस्त्र बलों ने किसकी प्रतिक्रिया में 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया?

- भारत में राजनीतिक अस्थिरता
- पहलगाम आतंकवादी हमला
- इज़राइल-गाजा संघर्ष
- उपर्युक्त में से कोई नहीं

(Q) : 2025

वायु रक्षा प्रणाली

चर्चा में क्यों: मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत की स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली आकाशतीर ने पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए हवाई हमले को सफलतापूर्वक रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्वदेशी तकनीक की परिचालन शक्ति का प्रदर्शन हुआ।

मुख्य विवरण

- S-400 ट्रायम्फ प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई मिसाइलों और अस्सिगार्ड सोंगर ड्रोन को रोककर और नष्ट करके अपनी परिचालन प्रभावशीलता साबित की, जिससे एक तेज़ और सशक्त रक्षात्मक प्रतिक्रिया मिली।

भारत की वायु रक्षा प्रणाली

- वायु रक्षा प्रणाली हथियारों, सेंसर, कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मियों के एक एकीकृत नेटवर्क को संदर्भित करती है, जिसे दुश्मन के विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने, रोकने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इससे पहले कि वे नुकसान पहुंचाएँ।

वायु रक्षा प्रणालियों का कार्य तंत्र

- वायु रक्षा प्रणाली पता लगाने, ट्रैकिंग, अवरोधन और बेअसर करने के संयोजन के माध्यम से काम करती है:
 - **पता लगाना:** आने वाले खतरों की पहचान करने के लिए रडार और सेंसर का उपयोग करना।
 - **ट्रैकिंग:** खतरे के प्रक्षेप पथ और गति की निगरानी करना।
 - **अवरोधन:** खतरे के लक्ष्य तक पहुँचने से पहले उसे बेअसर करने के लिए मिसाइलों या अन्य प्रतिवादों को तैनात करना।
 - **एकीकरण:** आकाशतीर जैसी प्रणालियाँ कुशल खतरा प्रबंधन के लिए विभिन्न घटकों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करती हैं।

वायु रक्षा प्रणालियों के प्रकार:

- **कम दूरी:** बिंदु रक्षा के लिए (उदाहरण के लिए, आयरन डोम, आकाश)।
- **मध्यम दूरी:** क्षेत्र रक्षा के लिए (उदाहरण के लिए, बराक-8, मुख्यालय-16)।
- **लंबी दूरी:** रणनीतिक रक्षा के लिए (उदाहरण के लिए, एस-400, थाड, प्रोजेक्ट कुशा विकास में है)।

आयातित प्रणालियाँ

- **S-400 ट्रायम्फ (रूस)**
 - S-400 ट्रायम्फ दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है, जिसे भारत ने 2018 में रूस के साथ हस्ताक्षरित 5.4 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत हासिल किया है।
 - **रेंज और क्षमताएँ:** 400 किमी तक की दूरी और 30 किमी की ऊँचाई पर हवाई खतरों - जिसमें विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं - को शामिल करने में सक्षम।
 - **रडार सिस्टम:** 91N6E बिग बर्ड अधिग्रहण रडार और 92N6E ग्रेव स्टोन एंगेजमेंट रडार से लैस है, जो एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है।
 - **मिसाइल के प्रकार:** एक स्तरित रक्षा लिफाफ़ा बनाने के लिए चार प्रकार की मिसाइलों (40N6, 48N6, 9M96E2 और 9M96E) के मिश्रण का उपयोग करता है।
 - **ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका:** पाकिस्तान से आने वाले सोंगर ड्रोन और मिसाइल खतरों को सफलतापूर्वक रोकना, सक्रिय युद्ध में रणनीतिक मूल्य का प्रदर्शन किया।
- **SPYDER (इज़राइल)**
 - SPYDER (सतह से हवा में मार करने वाला पायथन और डर्बी) इज़राइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित एक त्वरित प्रतिक्रिया मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है।

- **रेंज:** SPYDER-एसआर की रेंज लगभग 15 किमी है, जबकि SPYDER-एमआर 35-50 किमी है।
- **मिसाइल सिस्टम:** पायथन-5 (इन्फ्रारेड होमिंग) और डर्बी (सक्रिय रडार होमिंग) मिसाइलों का उपयोग करता है।
- **तैनाती:** उच्च-मूल्य की संपत्तियों की रक्षा करने और कम दूरी के अवरोधन अंतराल को भरने के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- **लचीलापन:** सभी मौसम की स्थिति में विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री को शामिल कर सकता है।

स्वदेशी प्रणालियाँ

- **आकाश**
 - DRDO द्वारा विकसित और बीईएल तथा बीडीएल द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल प्रणाली, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
 - **रेंज और गति:** मैक 2.5 की गति से 25-30 किमी तक हवाई लक्ष्यों को रोकने में सक्षम।
 - **रडार एकीकरण:** ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल के लिए राजेंद्र 3डी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के साथ जोड़ा गया।
 - **वेरिऍंट:** इसमें आकाश एमके-1, सीकर गाइडेंस के साथ आकाश-1एस और 70 किमी तक की रेंज और बेहतर गतिशीलता के साथ आकाश-एनजी शामिल हैं।
 - **लक्ष्य स्पेक्ट्रम:** लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी।
- **बराक-8 (भारत-इज़राइल संयुक्त विकास)**
 - DRDO और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा विकसित, बराक-8 नौसेना और भूमि-आधारित दोनों उपयोग के लिए एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) है।
 - **रेंज:** वैरिऍंट के आधार पर 70 से 100 किमी के बीच भिन्न होती है (विस्तारित रेंज के लिए बराक-8ER)।
 - **सीकर:** सक्रिय रडार होमिंग और दो-तरफ़ा डेटा लिंक से लैस, पैतरेबाज़ी लक्ष्यों के खिलाफ भी उच्च मार संभावना सुनिश्चित करता है।
 - **तैनाती:** भारतीय नौसेना (विध्वंसक और फ्रिगेट पर) और भारतीय वायु सेना द्वारा रणनीतिक आधार सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।
 - **क्षमताएँ:** स्टील्थ एयरक्राफ्ट, यूएवी, सी-स्किमिंग मिसाइलों और अन्य उच्च गति वाले खतरों को रोक सकता है।
- **आकाशतीर**
 - आकाशतीर DRDO द्वारा भारतीय सेना की वायु रक्षा तोपखाने इकाइयों के लिए विकसित एक स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली है।
 - **कार्यक्षमता:** वास्तविक समय हवाई खतरे का पता लगाने, ट्रैकिंग और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सेंसर (रडार), हथियार प्रणाली (मिसाइल, बंदूकें) और संचार नेटवर्क को एकीकृत करता है।
 - **ऑपरेशन मोड:** नेटवर्क-केंद्रित युद्ध वातावरण में संचालित होता है, एक साथ कई फायर यूनिट्स का प्रबंधन करता है।
 - **युद्ध में भूमिका:** दुश्मन के यूएवी और रॉकेट को बेअसर करने वाले मिसाइल लॉन्च का समन्वय करके ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **महत्व:** विभिन्न वायु रक्षा तत्वों के बीच प्रतिक्रिया की गति, खतरे की प्राथमिकता और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाता है।

भावी विकास: प्रोजेक्ट कुशा

प्रोजेक्ट कुशा DRDO की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत S-400 के बराबर क्षमताओं वाली स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित की जाएगी:

- **मल्टी-टियर्ड इंटरसेप्टर:** इस प्रणाली में तीन प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जिनकी रेंज 150 किमी (M1), 250 किमी (M2) और 350 किमी (M3) होगी।
- **उन्नत रडार:** लंबी दूरी की निगरानी और फायर कंट्रोल रडार से लैस, जो एक साथ कई लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है।
- **एकीकरण:** आकाश और S-400 जैसी मौजूदा प्रणालियों के साथ मिलकर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक व्यापक वायु रक्षा कवच प्रदान करता है।

वैश्विक वायु रक्षा शक्तियाँ: एक तुलनात्मक अवलोकन

- **संयुक्त राज्य अमेरिका**
 - **पैट्रियट मिसाइल सिस्टम (PAC-3):** सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और विमानों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली। व्यापक रूप से निर्यात और युद्ध-परीक्षण किया गया।
 - **THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस):** हिट-टू-किल तकनीक का उपयोग करके अपने टर्मिनल चरण के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 - **एजिस कॉम्बैट सिस्टम:** SM-3 और SM-6 मिसाइलों के साथ एक नौसेना-आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली, जो लंबी दूरी और समुद्र-आधारित बैलिस्टिक मिसाइल अवरोधन प्रदान करती है।
- **चीन**
 - **HQ-9:** लंबी दूरी की SAM प्रणाली की तुलना अक्सर S-300 और पैट्रियट सिस्टम से की जाती है। एंटी-एयरक्राफ्ट और एंटी-क्रूज़ मिसाइल भूमिकाओं के लिए उपयोग किया जाता है।
 - **HQ-16 और HQ-22:** उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार कवरेज के साथ विमान और यूएवी को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई मध्यम दूरी की प्रणाली।
 - **FD-2000:** HQ-9 का निर्यात संस्करण; पश्चिमी प्रणालियों के लिए लागत प्रभावी विकल्प के रूप में पेश किया गया। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों द्वारा तैनात।
 - **HQ-19 और HQ-26 (विकासाधीन):** बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए अभिप्रेत, भविष्य के प्रदर्शन में अमेरिकी THAAD को टक्कर देगा।
- **रूस**
 - **S-400 ट्रायम्फ:** विश्व स्तर पर सबसे उन्नत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों में से एक, जो 400 किमी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
 - **S-300:** अभी भी उपयोग में है; यह रूस के साथ गठबंधन करने वाले कई देशों की वायु रक्षा का आधार है।

- **S-500 प्रोमेट्री (प्रवेश के अधीन):** निचली पृथ्वी की कक्षा में स्टील्थ विमान, हाइपरसोनिक मिसाइलों और उपग्रहों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया; यह रणनीतिक वायु रक्षा की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है।

निष्कर्ष

- आकाशतीर और प्रोजेक्ट कुशा जैसी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों को विकसित करने पर भारत का ध्यान रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। ये प्रगति न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाती है बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. “भारत की वायु रक्षा रणनीति विदेशी प्लेटफार्मों पर निर्भरता से स्वदेशी, एकीकृत और बहुस्तरीय प्रणालियों की ओर विकसित हो रही है।” भारत की वायु रक्षा क्षमताओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें, प्रमुख स्वदेशी विकास, आयातित प्रणालियों और प्रोजेक्ट कुशा जैसी भविष्य की रणनीतिक पहलों पर प्रकाश डालें। [250 शब्द | 15 अंक]

ड्रोन युद्ध

चर्चा में क्यों: मई 2025 में, भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर झड़पों के दौरान अपने पहले बड़े पैमाने पर ड्रोन युद्ध में भाग लिया, जिसने दक्षिण एशियाई सैन्य गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस घटना ने आधुनिक युद्ध में मानव रहित हवाई वाहनों (यूपीवी) के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया और मजबूत काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

आधुनिक युद्ध में ड्रोन के प्रकार

- **निगरानी और टोही ड्रोन:** वास्तविक समय की खुफिया जानकारी जुटाने, सीमा की निगरानी और युद्ध के मैदान का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरणों में भारत के हेरॉन और रुस्तम-II ड्रोन शामिल हैं। 24x7 निगरानी में सहायता के लिए एचडी कैमरे, इन्फ्रारेड सेंसर और नाइट विजन से लैस।
- **लड़ाकू ड्रोन / यूसीएवी (मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन):** बिना किसी पायलट के मिसाइलों या बमों को ले जाने और तैनात करने में सक्षम। भारत लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता के लिए अमेरिका से MQ-9B सीगार्डियन/रीपर ड्रोन खरीद रहा है।
- **स्वॉर्म ड्रोन:** दुश्मन की सुरक्षा को नष्ट करने या रडार सिस्टम को भ्रमित करने के लिए समन्वित कई स्वायत्त ड्रोन। आक्रामक हमलों, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या डिफेंस मिशन में उपयोग किया जाता है। अक्सर AI-संचालित, जैविक स्वॉर्म व्यवहार की नकल करते हुए।
- **FPV (फर्स्ट पर्सन व्यू) ड्रोन:** रियल-टाइम वीडियो फीड का उपयोग करके संचालित, ऑपरेटरों को कॉकपिट जैसा दृश्य देता है। नज़दीकी हमलों में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से शहरी या खाई युद्ध में प्रभावी। भारत के रक्षा अनुसंधान विंग ने हाल ही में पैदल सेना के उपयोग के लिए स्वदेशी FPV ड्रोन को शामिल किया है।
- **AI-सक्षम ड्रोन:** बिना किसी प्रत्यक्ष मानव नियंत्रण के स्वायत्त निर्णय लेने, लक्ष्य की पहचान करने और सटीक हमले करने में सक्षम। यूक्रेन ने टैंकों और बंकरों के खिलाफ स्वायत्त मिशनों के लिए AI-ड्रोन का बीड़ा उठाया है।

ड्रोन आधारित युद्ध के लाभ



1 लागत प्रभावी संचालन: ड्रोन का निर्माण और तेजाती लड़ाकू विमानों या हेलीकॉप्टरों की तुलना में सस्ती है। वे टसद लागत को कम करते हैं और व्यापक निगरानी कवरेज की अनुमति देते हैं।

2 न्यूनतम मानवीय जोखिम: चूंकि ड्रोन मानव रहित होते हैं, इसलिए ये शत्रुतापूर्ण वातावरण में पायलटों के लिए खतरे को खत्म कर देते हैं। विवादित क्षेत्रों या एलओसी और एलएसी जैसे विवादित क्षेत्रों में ये विशेष रूप से उपयोगी होते हैं।

3 उन्नत सामरिक सटीकता: ड्रोन लक्ष्य के ऊपर गंढराते टह सकते हैं, जिससे हमला करने से पहले दुश्मन की स्थिति की पुष्टि करने के लिए अधिक समय मिलता है। लक्षित हत्याओं, सजिकल हमलों और बुनियादी ढाँचे की तोड़फोड़ में उपयोगी।

4 वास्तविक समय डेटा और निष्पत्ति समर्थन: निगरानी ड्रोन से प्राप्त लाइव डेटा कमांड सेंटर्स द्वारा तेज़, अधिक सूचित निष्पत्ति लेने में सहायता करता है। परिचालन प्रतिक्रिया और समन्वय को बढ़ाता है।

5 विविध भूभागों में अनुकूलनशीलता: ड्रोन पहाड़ों, रेगिस्तानों, महासागरों और शहरी क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जिससे वे भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्रों के लिए आदर्श बन जाते हैं।

ड्रोन से चुनौतियाँ और खतरे



1 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की कमजोरियाँ: ड्रोन को जाम किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है या साइबर युद्ध उपकरणों के ज़रिए अपहरण भी किया जा सकता है। दुश्मन असुरक्षित संचार चैनलों या जीपीएस लिंक का फायदा उठा सकते हैं।

2 कम रडार दृश्यता: छोटे वाणिज्यिक ड्रोनों को पारंपरिक सैन्य रडार पर पहचानना मुश्किल होता है। उनकी कम उड़ान ऊँचाई उन्हें फ़ायदातर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों से बचने में मदद करती है।

3 गैर-सहकारी तत्वों द्वारा हथियारीकरण: सतह ड्रोन को आतंकवादियों या विद्रोही समूहों द्वारा विस्फोटकों से लैस किया जा सकता है। इनका उपयोग सीमा पार तस्करी, टोही या समन्वित हमलों में किया जाता है (जैसा कि भारतीय सीमाओं पर देखा गया है)।

4 कानूनी और नैतिक दुविधाएँ: एआई-सक्षम ड्रोन स्वायत्त घातक निर्णयों के बारे में सवाल उठाते हैं। जवाबदेही में चुनौतियाँ, अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन, और नागरिक हताहतों की संभावना।

5 ड्रोन पर निर्भरता जोखिम: यूएवी पर अत्यधिक निर्भरता पारंपरिक खुफिया तरीकों को कमजोर कर सकती है और भावी युद्ध में रणनीतिक अंध बिन्दु (Blind spot) स्थान बना सकती है।

ड्रोन तकनीक में भारत के नवाचार और क्षमताएँ

- इंद्रजाल सिस्टम:** हैदराबाद में ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विकसित, इंद्रजाल सिस्टम एक AI-संचालित ड्रोन रक्षा ग्रिड है जो 4,000 वर्ग किलोमीटर तक की सुरक्षा करने में सक्षम है। यह शत्रुतापूर्ण ड्रोन का पता लगाने, उन्हें बाधित करने और गुमराह करने के लिए ऑप्टिकल, RF और रडार सेंसर को जैमर और स्पूफर्स के साथ जोड़ता है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह व्यापक क्षेत्र, स्वायत्त हवाई क्षेत्र सुरक्षा प्रदान करता है।
- भारगवस्त माइक्रो-मिसाइल सिस्टम:** भारगवस्त भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो-मिसाइल काउंटर-ड्रोन सिस्टम है। यह मोबाइल लॉन्चर, प्रॉक्सिमिटी वॉरहेड और सटीक इन्फ्रारेड और रडार मार्गदर्शन का उपयोग करके 5 किमी तक की ऊँचाई तक के छोटे यूएवी को बेअसर कर सकता है। यह कम उड़ान वाले ड्रोन खतरों के खिलाफ एक कॉम्पैक्ट और प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
- स्वदेशी एफपीवी ड्रोन:** भारतीय सेना द्वारा विकसित, इन फर्स्ट-पर्सन व्यू ड्रोन का उपयोग क्लोज-कॉम्बैट और शहरी युद्ध परिदृश्यों में किया जाता है। वे आगे के क्षेत्रों में निगरानी और स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों में।

- रुस्तम-II / TAPAS:** रुस्तम-II (TAPAS) एक मध्यम-ऊँचाई वाला अधिक-सहन सीमा वाला यूएवी है जो निगरानी और सीमित स्ट्राइक भूमिकाओं के लिए विकास के अधीन है। एक बार चालू होने के बाद, यह भारत के प्रमुख स्वदेशी ISR प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
- MQ-9B प्रीडेटर अधिग्रहण:** भारत तीनों सेनाओं के उपयोग के लिए अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन प्राप्त कर रहा है। 36 घंटे की धीरज, उपग्रह नियंत्रण और सटीक हमला करने की क्षमता के साथ, ये सशस्त्र ड्रोन भारत की लंबी दूरी की निगरानी और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएंगे, खासकर समुद्री और सीमावर्ती क्षेत्रों में।

वैश्विक परिदृश्य: भारत की स्थिति

- यूएसए:** संयुक्त राज्य अमेरिका मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों (यूसीएवी) और लंबी दूरी के आईएसआर (खुफिया, निगरानी, टोही) प्लेटफॉर्मों में अग्रणी है, जिसमें एमक्यू-9 रीपर और ग्लोबल हॉक जैसी उन्नत प्रणालियाँ हैं, जो अपनी वैश्विक हड़ताल और निगरानी क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं।
- चीन:** चीन ड्रोन का एक प्रमुख निर्माता और निर्यातक है, जो विंग लुंग II और CH-5 जैसी लागत-प्रतिस्पर्धी प्रणालियाँ प्रदान करता है, जिन्हें एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में व्यापक रूप से अपनाया जाता है। ये प्लेटफॉर्म अपनी सीमा, पेलोड क्षमता और सामर्थ्य के लिए जाने जाते हैं।
- तुर्की:** तुर्की अपने बायरकटर टीबी2 के माध्यम से तेजी से एक ड्रोन शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने लीबिया, सीरिया, नागोर्नो-करबाख और यूक्रेन में सफल युद्ध उपयोग देखा है। इसके ड्रोन लागत प्रभावी हैं, संचालित करने में आसान हैं, और सीमित रक्षा बजट वाले कई देशों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गए हैं।
- रूस:** रूस, पारंपरिक युद्ध में पारंपरिक रूप से मजबूत होने के बावजूद, स्वायत्त ड्रोन प्रौद्योगिकियों में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि, इसने यूक्रेन युद्ध के दौरान कई प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिनमें ओरियन यूएवी शामिल है, जो ISR और हल्के हमले की भूमिकाओं में सक्षम है, और लैसेट लोइटरिंग म्यूनिशन, जिसका उपयोग सटीक कामिकेज़-शैली के हमलों के लिए किया जाता है। यू.एस. या तुर्की प्रणालियों की तुलना में सीमित स्वायत्तता और निर्यात अपील के बावजूद, सामरिक ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन पर रूस का जोर काफी बढ़ गया है, खासकर विवादित हवाई क्षेत्र परिदृश्यों में।
- ईरान:** ईरान ने शाहेद-136 और मोहजर-6 जैसे कम लागत वाले, लंबी दूरी के ड्रोन विकसित करने के लिए कुख्याति प्राप्त की है, जिनका असममित और छद्म युद्ध में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये ड्रोन आम तौर पर लोइटरिंग म्यूनिशन (जिन्हें "कामिकेज़ ड्रोन" भी कहा जाता है) होते हैं और इन्हें यूक्रेन संघर्ष में उपयोग सहित राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं को निर्यात किया गया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मानव रहित हवाई वाहनों (यूपीवी) और ड्रोन युद्ध का उदय आधुनिक संघर्ष की प्रकृति को फिर से परिभाषित कर रहा है। भारत की तैयारियों और हाल के नवाचारों के विशेष संदर्भ के साथ युद्ध में ड्रोन प्रौद्योगिकी के रणनीतिक, परिचालन और नैतिक निहितार्थों पर चर्चा करें। [250 शब्द | 15 अंक]

- ड्रोन युद्ध ने 21वीं सदी के संघर्षों की गतिशीलता को बदल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की भागीदारी, स्वदेशी एफपीवी ड्रोन की तैनाती और इंद्रजाल और भार्गवस्त्र जैसी एकीकृत रक्षा प्रणालियों का विकास भारत के सैन्य सिद्धांत में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। जबकि वैश्विक खिलाड़ी एआई और ड्रोन के साथ सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं, भारत नवाचार, सहयोग और केंद्रित नीति पहलों के माध्यम से अंतर को पाट रहा है।

ब्रह्मोस मिसाइल

चर्चा में क्यों: ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या स्थल से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है।
- ब्रह्मोस एक दो-चरणीय मिसाइल है जिसमें पहले चरण के रूप में एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन है, जो इसे सुपरसोनिक गति तक लाता है और फिर अलग हो जाता है।
 - लिक्विड रैमजेट या दूसरा चरण मिसाइल को क्रूज चरण में 3 मैक गति के करीब ले जाता है।
- उन्नत एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के साथ स्टीलथ तकनीक और मार्गदर्शन प्रणाली मिसाइल को विशेष सुविधाएँ प्रदान करती है।
- रेंज: मिसाइल की उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक है और पूरी उड़ान के दौरान इसकी गति सुपरसोनिक है, जिससे उड़ान का समय कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों का कम फैलाव, त्वरित जुड़ाव समय और दुनिया में किसी भी ज्ञात हथियार प्रणाली द्वारा अवरोधन न होना सुनिश्चित होता है।
- यह 'फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत' पर काम करता है, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कई तरह की उड़ानें अपनाता है।
- प्रभाव पर बड़ी गतिज ऊर्जा के कारण इसकी विनाशकारी शक्ति बढ़ जाती है। इसकी क्रूजिंग ऊँचाई 15 किलोमीटर तक हो सकती है, और टर्मिनल ऊँचाई 10 मीटर जितनी कम है।
- यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक वारहेड ले जाता है।
- मौजूदा अत्याधुनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में, ब्रह्मोस में है:
 - 3 गुना अधिक वेग
 - 2.5 से 3 गुना अधिक उड़ान रेंज
 - 3 से 4 गुना अधिक सीकर रेंज
 - 9 गुना अधिक गतिज ऊर्जा
- मिसाइल में भूमि, समुद्र और उप-समुद्री प्लेटफार्मों के लिए एक समान विन्यास है और परिवहन, भंडारण और प्रक्षेपण के लिए ट्रांसपोर्ट लॉन्च कैनिस्टर (TLC) का उपयोग करता है।
- स्थिति
 - ब्रह्मोस पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे सेवा में रखा गया है। भारतीय नौसेना में ब्रह्मोस हथियार परिसर के पहले संस्करण को शामिल करना 2005 में शुरू हुआ।
 - भारतीय सेना ने भी 2007 से कई ब्रह्मोस रेजिमेंट को शामिल किया है।
 - भारतीय वायुसेना ने सुखोई-30MKI फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान से लैस ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रणाली को सफलतापूर्वक शामिल किया है।

सेवा में

- जहाज-आधारित हथियार परिसर (झुका हुआ और ऊर्ध्वाधर विन्यास)
- भूमि-आधारित हथियार परिसर (मोबाइल स्वायत्त लांचर से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण विन्यास)
- हवा से प्रक्षेपित संस्करण (सु-30MKI लड़ाकू विमान पर एकीकृत)
- संयुक्त उद्यम
 - ब्रह्मोस एयरोस्पेस का गठन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और संयुक्त स्टॉक कंपनी "सैन्य औद्योगिक संघ" "NPO मशीनोस्ट्रुयेनिया" (जिसे पहले रूस के संघीय राज्य एकात्मक उद्यम NPOM के रूप में जाना जाता था) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया था।
 - कंपनी की स्थापना भारत में 12 फरवरी, 1998 को भारत गणराज्य और रूसी संघ के बीच हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी समझौते के माध्यम से की गई थी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक सुपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी उड़ान सीमा 290 किमी तक है।
2. इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(9) :255

साइबर युद्ध

चर्चा में क्यों: मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर, भारत को साइबर खतरों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना करना पड़ा। इनमें विरोधी देशों और हैकटिविस्ट समूहों द्वारा समन्वित साइबर हमले शामिल थे, जो आधुनिक संघर्षों में साइबर युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं।

साइबर युद्ध के बारे में

- साइबर युद्ध में एक देश द्वारा दूसरे देश के महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने के लिए डिजिटल हमलों का उपयोग शामिल है, जिसका उद्देश्य क्षति, मृत्यु या विनाश करना है।
- पारंपरिक युद्ध के विपरीत, साइबर युद्ध की विशेषता इसकी गुप्तता, गुमनामी और आरोप लगाने की कठिनाई है।
- इसमें हैकिंग, मेलवेयर फैलाना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से समझौता करने, संवेदनशील डेटा चुराने या गलत सूचना फैलाने के लिए सेवा से वंचित करने वाले हमले शुरू करने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

साइबर युद्ध की मुख्य विशेषताएँ

- **असममित उपकरण:** छोटे राज्यों या गैर-राज्य अभिनेताओं को पारंपरिक सैन्य बल के बिना मजबूत देशों को चुनौती देने की अनुमति देता है।
- **कम आरोपण:** साइबर हमलों का पता लगाना मुश्किल है, जिससे जवाबदेही और प्रतिशोध जटिल हो जाता है।
- **गैर-गतिज और गुप्त:** बिना भौतिक विनाश के संचालित होता है; हमले चुपचाप, तेज़ और अक्सर तब तक पता नहीं चलते जब तक नुकसान न हो जाए।
- **व्यापक लक्ष्य स्पेक्ट्रम:** न केवल सैन्य प्रणालियों को बल्कि स्वास्थ्य, बिजली, बैंकिंग और मीडिया जैसे नागरिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।
- **वैश्विक और दूरस्थ:** हमले कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, भौगोलिक सीमाओं को पार कर वैश्विक लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं।
- **सूचना व्यवधान:** इसमें गलत सूचना, प्रचार और समाज को अस्थिर करने के उद्देश्य से मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन शामिल हैं।

भारत की स्थिति और तैयारी

भारत उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी साइबर क्षमताओं को मजबूत करने पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहा है:

- **साइबर कमांडो प्रशिक्षण:** सरकार ने अगले पांच वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इन विशेषज्ञों को सीबीआई, एनआईए और राज्य पुलिस बलों जैसी एजेंसियों में शामिल किया जाएगा, जिससे डिजिटल फोरेंसिक, साइबर धोखाधड़ी का पता लगाने और नेटवर्क निगरानी में क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा।
- **शैक्षिक सहयोग:** चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) जैसे संस्थानों ने सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ भागीदारी की है, जिसका उद्देश्य सैन्य कर्मियों को उन्नत साइबर कौशल से लैस करना है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना, जैसे कि पटना में CDAC के सहयोग से, साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो नवाचार और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **नीति और शासन:** भारत सरकार साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नीतियों को तैयार करने में सक्रिय रही है, जिसमें वास्तविक समय के खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल के लिए केंद्रीकृत रूपरेखा का विकास शामिल है।

भारत में प्रमुख साइबर हमले - एक झलक

- **एम्स दिल्ली रैनसमवेयर हमला (2022):** दो सप्ताह से अधिक समय तक रोगी सेवाएं और डेटा तक पहुंच बाधित रही; हमलावरों ने बड़ी क्रिप्टो फिरीती की मांग की, जिससे स्वास्थ्य सेवा साइबर कमजोरियां उजागर हुईं।
- **मुंबई पावर ग्रिड आउटेज (2020):** सीमा पर तनाव के बीच चीनी समूहों द्वारा साइबर हमले के कारण बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट; महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे में कमजोरियों को उजागर किया।
- **कुडनकुलम परमाणु संयंत्र मैलवेयर (2019):** उत्तर कोरिया के लाजरस समूह से जुड़ा मैलवेयर एक गैर-महत्वपूर्ण प्रणाली में पाया गया; परमाणु सुविधाओं में साइबर सुरक्षा पर चिंता जताई।

निष्कर्ष

- साइबर युद्ध के बढ़ते प्रचलन के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विशेष कर्मियों को प्रशिक्षित करने, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की पहल इसकी साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालाँकि, आधुनिक डिजिटल परिदृश्य में विकसित हो रहे साइबर खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए निरंतर निवेश, नीति विकास और वैश्विक सहयोग आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. साइबर युद्ध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. साइबर युद्ध हमेशा राज्य अभिकर्ताओं द्वारा शुरू किया जाता है और इसमें भौतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है।
2. साइबर हमलों का किसी विशिष्ट स्रोत से संबंध स्थापित करना अक्सर मुश्किल होता है।
3. साइबर युद्ध केवल सैन्य प्रतिष्ठानों और वर्गीकृत रक्षा प्रणालियों को लक्षित करता है।
4. गलत सूचना अभियान और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी साइबर युद्ध के उपकरण माने जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) केवल 2 और 4 | (b) केवल 1 और 3 |
| (c) केवल 2, 3 और 4 | (d) केवल 1, 2 और 4 |
- (e) 2, 3, 4

प्रादेशिक सेना

चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्रालय ने सेना प्रमुख को फरवरी 2028 तक देश भर में तैनाती के लिए प्रादेशिक सेना (टीए) की 32 पैदल सेना बटालियनों में से 14 को सक्रिय करने का अधिकार दिया है।

प्रादेशिक सेना (टीए) के बारे में

- प्रादेशिक सेना (टीए) भारत में नियमित सेना का एक हिस्सा है, जिसे नियमित सेना को स्थैतिक कर्तव्यों से मुक्त करने और प्राकृतिक आपदाओं, आवश्यक सेवाओं के रखरखाव या देश की सुरक्षा को खतरा होने पर नागरिक प्रशासन की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे अक्सर नागरिक सेना के रूप में जाना जाता है।

भूमिका और उद्देश्य

- **नियमित सेना को राहत देना:** नियमित सेना के कर्मियों को स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना।
- **नागरिक प्रशासन की सहायता करना:** इसमें निम्नलिखित पर प्रतिक्रिया देना शामिल है:
 - प्राकृतिक आपदाएँ (जैसे भूकंप, चक्रवात)।
 - आवश्यक सेवाओं के रखरखाव को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ।
 - ऐसी स्थितियाँ जहाँ देश की सुरक्षा को खतरा हो।

- रिपोर्ट प्रकटीकरण पर बहस: विवाद का एक प्रमुख बिंदु समिति की रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकटीकरण रहा है।
 - रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा गया था।
 - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पाइवेयर के कथित दुरुपयोग पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से यह मुद्दा सड़क-स्तर की बहस का विषय बन जाएगा। इसने आगे कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित कोई भी रिपोर्ट गोपनीय रहनी चाहिए और उसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

पेगासस स्पाइवेयर

- इजरायली कंपनी NSO द्वारा निर्मित और विपणन किया गया, पेगासस एक स्पाइवेयर है जो अनधिकृत तरीके से मास्टर सर्वर पर डेटा स्थानांतरित करके डिवाइस को संक्रमित करता है और पीड़ित पर जासूसी करता है। कंपनी इसे दुनिया भर में केवल “जांच की गई विदेशी सरकारों” को बेचने का दावा करती है।
- पेगासस की कार्य प्रणाली
 - अपने मूल रूप में, पेगासस उन डिवाइस को संक्रमित कर सकता है जो इंटरनेट से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि कुछ अपडेट किए गए संस्करण पीड़ित द्वारा किसी लिंक या संदेश पर क्लिक किए बिना भी फोन को संक्रमित कर सकते हैं।
 - अधिकांश स्पाइवेयर और स्टॉकरवेयर ऐप खुद को एंटी-थेफ्ट एप्लिकेशन के रूप में छिपाते हैं जिनका उपयोग चोरी या खोए हुए डिवाइस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। जबकि वायरस और मैलवेयर को एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाया जा सकता है, स्पाइवेयर और स्टॉकरवेयर ऐप खुद को उपयोगी के रूप में छिपाते हैं और उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना चोरी किए गए डेटा को केंद्रीय सर्वर पर भेजते हैं।

यह किसी डिवाइस को कैसे संक्रमित करता है?

- स्पाइवेयर ऐप्स के लिए, सबसे आसान तरीका प्रीमियम ऐप्स के अनधिकृत संस्करणों के अंदर जासूसी कोड को छिपाना है। दूसरी ओर, स्टॉकरवेयर ऐप अपनी स्थापना के समय स्पष्ट अनुमतियाँ मांगते हैं।
- ऐसे स्टॉकरवेयर एप्लिकेशन, एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद, खुद को बैकग्राउंड में छिपा लेते हैं, जहाँ से वे काम करना जारी रखते हैं।

इसी तरह, पेगासस पीड़ितों के फ़ोन और कंप्यूटर को या तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप जैसे कि WhatsApp, iMessage या SMS में कमज़ोरियों के ज़रिए संक्रमित करता है। सॉफ्टवेयर “रूट विशेषाधिकार” हासिल करने की कोशिश करता है ताकि वह डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर बन सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. पेगासस स्पाइवेयर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह WhatsApp या iMessage जैसे ऐप में कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर बिना उपयोगकर्ता की सहभागिता (जैसे, क्लिक) के डिवाइस को संक्रमित कर सकता है।
2. यह आमतौर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए खुद को सिस्टम अपडेट एप्लिकेशन के रूप में छिपाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(ए) :2022

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



‘द हिंदू’ और ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें



डब्ल्यूएचओ ने ऐतिहासिक वैश्विक महामारी समझौते को अपनाया

चर्चा में क्यों: भविष्य के स्वास्थ्य संकटों का सामना करने के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और निष्पक्ष विश्व बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से विश्व का पहला महामारी समझौता अपनाया है।

मुख्य विवरण

- यह ऐतिहासिक निर्णय जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, डब्ल्यूएचओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के दौरान लिया गया।
- यह वैश्विक समझौता COVID-19 महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बाद शुरू की गई तीन वर्षों से अधिक की गहन वार्ता का समापन है।
- यह देशों द्वारा पिछली गलतियों को दोहराने से बचने और भविष्य की महामारियों का तीव्र, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की वैश्विक क्षमता को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतिम समझौते को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य सभा के पूर्ण सत्र में अपनाया गया था, जब इसे समिति द्वारा भारी समर्थन के साथ पहली बार अनुमोदित किया गया था - 124 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, किसी ने विरोध नहीं किया और 11 ने मतदान में भाग नहीं लिया।
- समझौते को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनोम चेबरेयेसस ने कहा:

“ऐतिहासिक डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते को अपनाने के लिए हमारे सदस्य देशों के नेतृत्व, सहयोग और प्रतिबद्धता की बदौलत आज विश्व सुरक्षित है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, विज्ञान और बहुपक्षीय कार्रवाई की जीत है।”

यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है

डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते को अपनाना COVID-19 संकट के दौरान उजागर हुई वैश्विक पीड़ा और असमानताओं की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में महामारी के खतरों का सामना करने के लिए विश्व बेहतर तरीके से तैयार और अधिक एकजुट हो।

समझौते के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को मजबूत करना।
- विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए टीकों, दवाओं और निदान तक उचित और समय पर पहुँच सुनिश्चित करना।
- वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर तैयारी और रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाना।
- डेटा साझाकरण, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ावा देना।

- स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन और कार्यबल प्रशिक्षण में सुधार।

यह समझौता इस विचार को पुष्ट करता है कि कोई भी देश अकेले महामारी का सामना नहीं कर सकता है, और व्यापक पीड़ा, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य प्रणाली के पतन को रोकने के लिए एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया आवश्यक है।

समानता और न्याय पर ध्यान केंद्रित करना

- समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समानता पर इसका ध्यान केंद्रित करना है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान, कई देशों - विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में - को जीवन रक्षक टीकों और दवाओं तक पहुँचने में गंभीर देरी और कमी का सामना करना पड़ा।
- नया महामारी समझौता यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करके इसे बदलने का प्रयास करता है कि सभी देशों को, आय स्तर की परवाह किए बिना, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों तक समान पहुँच हो।
- यह एक बढ़ती हुई आम सहमति को दर्शाता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए, और यह समानता वैश्विक तैयारियों का केंद्र है।

आगे की राह

हालाँकि महामारी समझौते को अपनाना एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि देश इसके प्रावधानों को कितनी अच्छी तरह लागू करते हैं। आगे बढ़ते हुए, सरकारों को निम्न करने की आवश्यकता होगी:

- समझौते के सिद्धांतों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों में एकीकृत करना।
- स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे और कार्यबल में निवेश करना।
- वित्त पोषण, तकनीकी सहायता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना।

डब्ल्यूएचओ वैश्विक प्रयासों के समन्वय, प्रगति की निगरानी और मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण में देशों का समर्थन करने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहेगा।

निष्कर्ष

डब्ल्यूएचओ महामारी समझौता वैश्विक समुदाय द्वारा पिछले अनुभवों से सीखने और भविष्य के लिए अधिक समझदारी से तैयारी करने की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता है। यह दर्शाता है कि विश्व बहुपक्षवाद, एकजुटता और साझा जिम्मेदारी की भावना से एक साथ आ सकती है।

डॉ. टेड्रोस के शब्दों में:

“हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन को फिर कभी इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। यह समझौता एक ऐसे भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है जहाँ महामारी को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके और मानवीय पीड़ा को कम किया जा सके।”

इस वैश्विक समझौते के साथ, विश्व एक ऐसे भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाती है जो स्वास्थ्य आपात स्थितियों के सामने अधिक सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत और अधिक लचीला है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते को अपनाया वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस समझौते के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक जांच करें। इसके कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, और भारत इस वैश्विक पहल का लाभ उठाने के लिए अपनी स्वास्थ्य कूटनीति को कैसे संरेखित कर सकता है? [250 शब्द | 15 अंक]

गर्भधारण पूर्व स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों: यह लेख द हिंदू अखबार में छपे संपादकीय में प्रस्तुत अंतर्दृष्टि पर आधारित है।

परिचय

- चिकित्सा अभ्यास के लगभग चार दशकों में, एक बात स्पष्ट रूप से स्पष्ट रही है - भारत में बहुत सी महिलाएँ अपनी गर्भावस्था की यात्रा पहले से ही अज्ञात एनीमिया से पीड़ित होकर शुरू करती हैं। हम अक्सर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान ही मातृ स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन स्वस्थ गर्भावस्था की असली नींव बहुत पहले ही रखी जाती है - गर्भधारण से पहले।
- आज, 57% से अधिक भारतीय महिलाएँ अपने प्रजनन वर्षों (15-49 वर्ष) में एनीमिया से पीड़ित हैं, फिर भी उनमें से अधिकांश को इसका पता भी नहीं है। वे थकावट, चक्कर आना और कमज़ोरी के साथ रहती हैं, लेकिन इन संकेतों को सामान्य मानकर अनदेखा कर दिया जाता है। जब वे गर्भवती हो जाती हैं, तो उनके हीमोग्लोबिन के निम्न स्तर से गंभीर जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है जैसे:
 - समय से पहले जन्म
 - जन्म के समय कम वजन
 - प्रीक्लेम्पसिया
 - प्रसवोत्तर रक्तस्राव (प्रसव के बाद गंभीर रक्तस्राव)

ये सभी स्थितियाँ मातृ और शिशु मृत्यु, या माँ और बच्चे दोनों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं।

वर्तमान स्थिति

भारत ने प्रगति की है। मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) घटकर 1,00,000 जीवित जन्मों पर 93 हो गया है। लेकिन आगे बढ़ने और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने के लिए, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हम गर्भावस्था तक इंतजार नहीं कर सकते - हमें गर्भधारण से पहले के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

केवल यह पूछने के बजाय कि, “क्या आप माँ बनने के लिए तैयार हैं?”, हमें यह भी पूछना चाहिए कि, “क्या आपका शरीर गर्भावस्था के लिए तैयार है?”

वर्तमान एनीमिया उपचार की सीमाएँ

- कई वर्षों से, एनीमिया से निपटने की मुख्य रणनीति मौखिक आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की टैबलेट रही है। ये टैबलेट मदद तो करती हैं, लेकिन इनके साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे:
 - मतली

- कब्ज़
- डायरिया
- आयरन का निम्न अवशोषण

- इन साइड इफेक्ट की वजह से कई महिलाएँ टैबलेट लेना बंद कर देती हैं या फिर नियमित रूप से नहीं लेती हैं। जिन महिलाओं को लंबे समय से एनीमिया है, उनके लिए गर्भावस्था के दौरान सिर्फ़ ओरल टैबलेट से कमी को ठीक करना बहुत मुश्किल है।
- नतीजतन, न सिर्फ़ माँ कमज़ोर रहती है, बल्कि बच्चे को भी पर्याप्त आयरन नहीं मिल पाता, जिससे मस्तिष्क का विकास और वृद्धि प्रभावित होती है।

एक बेहतर विकल्प (IV आयरन उपचार)

मध्यम से गंभीर एनीमिया को ठीक करने के लिए, एक बेहतर और तेज़ उपाय उपलब्ध है: अंतःशिरा फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोज़ (IV FCM)। यह उपचार:

- आयरन को सीधे रक्तप्रवाह में पहुंचाता है;
- हीमोग्लोबिन के स्तर को जल्दी से बहाल करता है;
- पाचन को बायपास करता है, इसलिए यह तब भी काम करता है जब अवशोषण एक समस्या है;
- हेपसीडिन से प्रभावित नहीं होता है, एक हार्मोन जो मौखिक आयरन अवशोषण को रोकता है।

नोट: IV FCM एक जीवन-परिवर्तनकारी हस्तक्षेप हो सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो लंबे समय से या गंभीर एनीमिया से पीड़ित हैं।

अन्य कमियाँ

बहुत से लोग सोचते हैं कि एनीमिया केवल आयरन की कमी के कारण होता है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण कमियाँ भी हैं:

- **विटामिन बी12 की कमी:**
 - भारत में प्रजनन आयु की लगभग 49% महिलाओं में पाया जाता है।
 - लाल रक्त कोशिका उत्पादन और मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करता है।
 - अगर इलाज न किया जाए तो जन्म दोष हो सकता है।
- **थायरॉइड विकार:**
 - हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म जैसी स्थितियाँ एनीमिया को और खराब कर सकती हैं।
 - भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को भी नुकसान पहुंचाती हैं।
- **गर्भकालीन मधुमेह:**
 - अक्सर गर्भावस्था के अंत तक इसका निदान नहीं हो पाता।
 - माँ और बच्चे दोनों के लिए जटिलताएँ पैदा कर सकता है।

जटिलताओं को वास्तव में रोकने के लिए, डॉक्टरों को गर्भधारण करने से पहले ही महिलाओं की इन समस्याओं के लिए जांच कर लेनी चाहिए। इंजेक्शन के ज़रिए विटामिन बी12, फोलेट और IV आयरन का संयोजन रिफ़्रैक्टरी एनीमिया (एनीमिया जो बुनियादी उपचार से ठीक नहीं होता) से निपटने के लिए आदर्श है।

समुदाय और परिवारों की भूमिका

गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के सिर्फ इलाज से लेकर गर्भावस्था से पहले इसे रोकने तक के हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए समुदाय के समर्थन की आवश्यकता है।

- परिवारों को युवा महिलाओं को गर्भधारण से पहले जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अपने नियमित काम में गर्भावस्था से पहले स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना चाहिए।
- सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रसवपूर्व देखभाल की तरह ही गर्भधारण से पहले देखभाल को भी आवश्यक मानना चाहिए।

एक सामूहिक जिम्मेदारी

मातृ स्वास्थ्य में सुधार केवल डॉक्टर का काम नहीं है - यह निम्नलिखित की साझा जिम्मेदारी है:

- परिवार
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाता
- नीति निर्माता
- स्थानीय समुदाय

गर्भावस्था से पहले एनीमिया का पता लगाने और उसका इलाज करने में विफल रहने से, हम न केवल माताओं के जीवन को जोखिम में डालते हैं, बल्कि उनके बच्चों की भविष्य की संभावनाओं को भी सीमित करते हैं।

आगे की राह

- गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच को गर्भावस्था जांच की तरह सामान्य बनाना।
- एनीमिया से तेजी से उबरने के लिए जहां आवश्यक हो वहां IV FCM के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- गर्भावस्था से पहले जांच में विटामिन B12, फोलेट, थायरॉयड और शुगर टेस्ट को शामिल करना।
- खुराक के पैटर्न को बदलकर मौखिक IFA के पालन में सुधार करना (उदाहरण के लिए, साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए वैकल्पिक दिन या सप्ताह में दो बार)।
- जागरूकता फैलाने के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उपकरण और प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

- किसी भी महिला को एनीमिया होने पर गर्भावस्था शुरू नहीं करनी चाहिए। किसी भी महिला को आयरन, विटामिन B12, थायरॉयड या शुगर के स्तर की उचित देखभाल के बिना गर्भावस्था से गुजरना नहीं चाहिए और किसी भी महिला को प्रसव के बाद पहले से कमजोर नहीं होना चाहिए। गर्भधारण से पहले अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना वैकल्पिक नहीं है - यह आवश्यक, आवश्यक और परिवर्तनकारी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य के बच्चे होशियार और स्वस्थ हों, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी माताएँ गर्भधारण से पहले ही स्वस्थ हों।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विफलता है जो गर्भावस्था से बहुत पहले शुरू होती है। भारत की मातृ स्वास्थ्य नीतियों के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक जाँच करें। मौजूदा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गर्भधारण पूर्व देखभाल को एकीकृत करने के लिए एक रोडमैप सुझाएँ। [250 शब्द | 15 अंक]

भारत में किशोर मोटापे से निपटना

चर्चा में क्यों: यह लेख द हिंदू अखबार में प्रकाशित एक लेख में प्रस्तुत दृष्टिकोणों पर आधारित है।

परिचय

- भारत में किशोर मोटापे को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल के महीनों में यह मुद्दा सार्वजनिक और नीतिगत चर्चाओं में और भी ज़्यादा तेज़ी से उभरा है। पिछले महीने आयोजित पोषण पखवाड़ा के सातवें संस्करण में बचपन और किशोरावस्था के मोटापे के साथ-साथ जीवन के पहले 1,000 दिनों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- इसके साथ ही, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया, यूनिसेफ़ इंडिया और अन्य की अगुवाई में 'लेट्स फ़िक्स अवर फूड' पहल ने किशोरों के लिए स्वस्थ भोजन वातावरण बनाने का आग्रह करते हुए नीतिगत संक्षिप्त विवरण जारी किए।
- एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को स्पष्ट और पारदर्शी खाद्य लेबलिंग नियमों को अंतिम रूप देने के लिए तीन महीने की सख्त समयसीमा दी। ये घटनाक्रम देश के युवाओं में पोषण संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाते हैं।

एक परेशान करने वाला पोषण विरोधाभास

- किशोरावस्था तेज़ शारीरिक और मानसिक विकास की अवधि है, जो भविष्य के स्वास्थ्य और उत्पादकता की नींव रखती है। हालाँकि, आज भारतीय किशोरों को एक अनोखे विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है: वे कुपोषण और बढ़ते मोटापे दोनों से पीड़ित हैं। कई क्षेत्रों में कुपोषण एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, फिर भी मोटापा और उससे जुड़ी जीवनशैली संबंधी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं।
- वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2024 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर बचपन के मोटापे में सबसे तेज़ वार्षिक वृद्धि का अनुभव कर रहा है। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण से पता चला है कि 5% से अधिक भारतीय किशोर या तो अधिक वजन वाले या मोटे हैं, कुछ राज्यों में यह आँकड़ा और भी अधिक (10-15%) है। यह देखते हुए कि भारत की आबादी में किशोरों की संख्या लगभग 20% है, यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है।

मोटापे की महामारी को कौन बढ़ावा दे रहा है?

- मोटापे में इस उछाल का एक प्रमुख कारण अस्वास्थ्यकर, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तक आसान पहुँच है। ये खाद्य पदार्थ, जिनमें अक्सर वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है, युवाओं को टेलीविज़न, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि स्कूलों में भी आक्रामक तरीके से बेचे जाते हैं। ये उत्पाद अक्सर स्वस्थ विकल्पों की तुलना में अधिक सुविधाजनक और व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं।
- किशोर, कमजोर और प्रभावित होने की उम्र में, साथियों के दबाव, विज्ञापनों और सामाजिक रुझानों से बहुत प्रभावित होते हैं। जबकि ऐसा लग सकता है कि उनके पास खाने के कई विकल्प हैं, वास्तव में स्वस्थ विकल्प अक्सर सीमित, महंगे या अनाकर्षक होते हैं। आहार पैटर्न में यह अस्वास्थ्यकर बदलाव मोटापे, मधुमेह और हृदय रोग जैसे दीर्घकालिक परिणामों को जन्म दे रहा है।

स्वास्थ्य से प्रेरणा

- खराब पोषण केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता है; यह मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। खराब आहार वाले किशोरों को अक्सर ध्यान केंद्रित करने, सीखने और नियमित रूप से स्कूल जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, पोषण केवल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक शैक्षिक और आर्थिक मुद्दा भी है।

क्या किया जाना चाहिए?

इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, भारत को दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए:

- **मज़बूत नियम**
 - उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने में मदद करने के लिए पैक के सामने स्पष्ट पोषण लेबल लागू करना।
 - उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से मीठे पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य कर लगाना।
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्कूलों में विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों को विनियमित और प्रतिबंधित करना।
- **किशोरों को सशक्त बनाना**
 - बच्चों को सूचित भोजन विकल्प बनाने में मदद करने के लिए स्कूलों में पोषण शिक्षा को मज़बूत करना।
 - किशोरों को पौष्टिक खाद्य पदार्थों की पहचान, तैयारी और चयन करना सिखाने के लिए जीवन कौशल के रूप में खाद्य साक्षरता का परिचय देना।
 - खेल के मैदानों और खेल के बुनियादी ढाँचे तक बेहतर पहुँच के माध्यम से शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना।

स्कूलों और समुदायों की भूमिका

- युवा लोगों की खाने की आदतों को आकार देने में स्कूल केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसर में केवल पौष्टिक भोजन ही उपलब्ध हो, पाठ्यक्रम में नियमित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल करें और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दें। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम इस संदेश को और फैला सकते हैं और परिवारों को घर पर स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

एकीकृत कार्रवाई की आवश्यकता

- वर्तमान में, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, उपभोक्ता मामले और कृषि जैसे कई मंत्रालय पोषण के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन उचित समन्वय के बिना, उनके प्रयास खंडित रह जाते हैं। पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम संयुक्त कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रभाव के लिए अधिक अभिसरण और सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

किशोरों में मोटापा केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं है; यह एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक चुनौती है। एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने के लिए, हमें बेहतर नीतियों, शिक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से अपने खाद्य वातावरण को बदलना होगा। स्वस्थ भोजन को सुलभ, किफ़ायती और आकांक्षी बनाया जाना चाहिए। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि युवा पीढ़ी मज़बूत, स्वस्थ और राष्ट्र को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हो।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में किशोरों में मोटापा एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभर रहा है। इस प्रवृत्ति के कारणों और परिणामों पर चर्चा करें। इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति का सुझाव दें, खासकर खाद्य वातावरण और युवा सशक्तिकरण के संदर्भ में। [250 शब्द | 15 अंक]

रिपोर्ट कार्ड 19: अप्रत्याशित विश्व में बच्चों की सेहत

चर्चा में क्यों: यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के कई सबसे अमीर और विकसित देशों में बच्चों ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अपने शैक्षणिक प्रदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय गिरावट देखी है।

रिपोर्ट: रिपोर्ट कार्ड 19: अप्रत्याशित विश्व में बच्चों की सेहत

गिरावट के प्रमुख क्षेत्र

- **शैक्षणिक प्रदर्शन और कौशल**
 - **सीखने की क्षमता में कमी:** कई देशों में बच्चों के शैक्षणिक कौशल में, खास तौर पर पढ़ने और गणित जैसी बुनियादी क्षमताओं में, तीन से 12 महीने तक स्कूल बंद रहने के कारण तेज गिरावट देखी गई, जिसके कारण दूरस्थ शिक्षा को मजबूर होना पड़ा।
 - **असफलताओं की मात्रा:** अनुमान है कि बच्चे औसतन सात महीने से एक साल तक शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहते हैं।
 - **वंचित परिवार:** वंचित परिवारों के बच्चों के लिए ये असफलताएँ सबसे गंभीर थीं।
 - **कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता:** 43 देशों में अनुमानित 8 मिलियन 15 वर्षीय (आयु वर्ग के लगभग आधे) को कार्यात्मक रूप से साक्षर और संख्यात्मक रूप से सक्षम नहीं माना गया, जिसका अर्थ है कि वे एक बुनियादी पाठ को समझ नहीं सकते थे। यह 2018 से 4% की वृद्धि दर्शाता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य**
 - **जीवन संतुष्टि में गिरावट:** बच्चों की जीवन संतुष्टि प्रभावित हुई, उपलब्ध डेटा वाले 32 देशों में से 14 में काफी गिरावट आई।
 - **जापान का सुधार:** जापान एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखा।
 - **युवा दृष्टिकोण:** युवा लोगों ने "मानसिक रूप से अभिभूत" और "संतुष्ट नहीं" महसूस करने की सूचना दी, जो अक्सर उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के कारण होता है।
- **शारीरिक स्वास्थ्य**
 - **अधिक वजन के स्तर में वृद्धि:** उपलब्ध डेटा वाले 43 देशों में से 14 में अधिक वजन के स्तर में काफी वृद्धि हुई, जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति को जारी रखता है।
 - **अस्वास्थ्यकर खाद्य पर्यावरण**

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश: नीदरलैंड और डेनमार्क ने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और कौशल के माप के आधार पर बच्चों के लिए शीर्ष दो स्थानों के रूप में अपनी रैंकिंग बरकरार रखी, उसके बाद फ्रांस का स्थान है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ)

- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) की स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य उन बच्चों और युवाओं का समर्थन करना था, जिनके जीवन और भविष्य खतरे में थे, भले ही उनका देश युद्ध में शामिल हो या न हो।
- आज, यूनिसेफ 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है, जो हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- इसके संचालन को पूरी तरह से व्यक्तियों, सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

- यूनिसेफ को अपने काम के लिए विश्व स्तर पर मान्यता मिली है, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार (1965), इंदिरा गांधी पुरस्कार (1989) और प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड (2006) जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं।

आगे की राह: रिपोर्ट में सिफारिशें

- **कौशल विकास:** संख्यात्मकता, साक्षरता और डिजिटल कौशल सहित आवश्यक कौशल के विकास का समर्थन करना, साथ ही सामाजिक और भावनात्मक दक्षताओं का भी, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो महामारी के दौरान पिछड़ गए और वंचित पृष्ठभूमि से हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य सुधार:** प्रचार और रोकथाम पहलों, विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान करने और ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से हिंसा और बदमाशी से निपटने के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- **शारीरिक स्वास्थ्य सुधार:** पौष्टिक भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करके और अस्वास्थ्यकर भोजन के विपणन और प्रचार को सीमित करके बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना।
- **बाल जुड़ाव:** बच्चों को उनके अनुभवों और विचारों को बेहतर ढंग से समझने के लिए शामिल करें, और उनके साथ मिलकर ऐसे समाधान खोजने के लिए काम करें जो उनकी भलाई को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

- बच्चों की ज़रूरतों को उनके जीवन के हर चरण में संबोधित करने के लिए एक "सुसंगत, समग्र, संपूर्ण बचपन दृष्टिकोण" की आवश्यकता है, खासकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. रिपोर्ट 'रिपोर्ट कार्ड 19: अप्रत्याशित विश्व में बाल कल्याण' निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है?

- | | |
|----------------|--------------------|
| (a) यूनेस्को | (b) यूनिसेफ |
| (c) डब्ल्यूएचओ | (d) सेव द चिल्ड्रन |

(9) : 2022

किशोर स्वास्थ्य और कल्याण

चर्चा में क्यों: किशोर स्वास्थ्य और कल्याण पर सेकंड लैंसेट आयोग की एक हालिया रिपोर्ट ने विश्व के किशोरों के भविष्य के बारे में एक शक्तिशाली चेतावनी दी है कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है जब तक कि सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन किशोरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाते।

मुख्य अवलोकन

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रगति हुई है, आयोग ने चेतावनी दी है कि तत्काल और बढ़े हुए निवेश के बिना, वर्ष 2030 तक, विश्व के कम से कम आधे किशोर - लगभग 1 बिलियन युवा लोग - "बहु-भार वाले देशों" में रह रहे होंगे। ये ऐसे देश हैं जो कुपोषण, गैर-संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और उचित स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच की कमी सहित कई और अतिव्यापी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

2030 के लिए अनुमान

आयोग का अनुमान है कि 2030 तक

- 464 मिलियन किशोर अधिक वजन वाले होंगे, जो खराब आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी पर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।
- मानसिक स्वास्थ्य विकारों और आत्महत्या के कारण वैश्विक स्तर पर 42 मिलियन वर्ष स्वस्थ जीवन खो जाएगा- यह इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ लाखों युवाओं को चुपचाप कैसे प्रभावित कर रही हैं।
- ये अनुमान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है जब तक कि सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन किशोरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाते।

स्वास्थ्य निधि का अनुपातहीन हिस्सा

- आयोग का एक प्रमुख संदेश यह है कि किशोरों की आबादी के आकार और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के पैमाने को देखते हुए, किशोरों के स्वास्थ्य के लिए वर्तमान निधि बहुत कम है।
- 2016 और 2021 के बीच, स्वास्थ्य के लिए वैश्विक विकास सहायता का केवल 2.4% विशेष रूप से किशोरों को आवंटित किया गया था, भले ही वे विश्व की आबादी का 25% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।
- आवश्यकता और वित्तपोषण के बीच यह ब्रेमेल वैश्विक विकास, समानता और शांति के लिए गंभीर दीर्घकालिक परिणाम हो सकता है।

किशोरों के लिए एक वैश्विक आवाज़

लैंसेट आयोग की शुरुआत 2021 में की गई थी और इसमें शामिल थे:

- विभिन्न क्षेत्रों के 44 आयुक्त;
- किशोरों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 युवा आयुक्त;
- और विश्व भर के 122 किशोर जिन्होंने जमीनी स्तर पर समाधान पेश करने के लिए युवा समाधान प्रयोगशालाओं में भाग लिया।

यह समावेशी दृष्टिकोण इस बढ़ती मान्यता को दर्शाता है कि युवाओं को उनके भविष्य को प्रभावित करने वाली नीतियों को आकार देने में शामिल होना चाहिए।

कुछ लाभ, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयसस ने पिछले 20 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालते हुए द लैंसेट में एक लेख लिखा:

- पोषण में सुधार, संक्रामक रोगों में कमी और शिक्षा तक बेहतर पहुँच के कारण किशोर मृत्यु दर में 27% की गिरावट आई है - विशेष रूप से लड़कियों के लिए।
- ये लाभ लैंगिक समानता और युवाओं के लिए बेहतर जीवन परिणामों की दिशा में आवश्यक कदम हैं।
- हालांकि, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये लाभ तब तक अपर्याप्त रहेंगे जब तक कि किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण में लक्षित और दीर्घकालिक निवेश द्वारा समर्थित न हों।

इतिहास की सबसे विशाल पीढ़ी

आज, विश्व भर में लगभग 2 बिलियन किशोर हैं, जो विश्व की कुल आबादी का लगभग 24% हिस्सा बनाते हैं। अनुमानों के अनुसार:

- 2100 तक, सभी किशोरों में से 46% अफ्रीका में रहेंगे, और
- 85% अफ्रीका या एशिया में रहेंगे।

यह जनसांख्यिकीय बदलाव इन क्षेत्रों में सरकारों के लिए अपनी तेजी से बढ़ती युवा आबादी का समर्थन करने के लिए मजबूत स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक नीतियों को विकसित करना आवश्यक बनाता है।

संघर्षरत क्षेत्रों में अधिक प्रभाव

एक और चिंताजनक प्रवृत्ति संघर्षरत प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि है। 1990 के दशक से, यह संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, और आज, लगभग 3.40 मिलियन किशोर संघर्षरत क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सुरक्षा तक पहुँच अक्सर सीमित या न के बराबर होती है।

डिजिटल मूलनिवासी के समक्ष नई चुनौतियाँ

किशोरों की यह पीढ़ी वास्तव में पहली डिजिटल पीढ़ी भी है। रिपोर्ट उन्हें "डिजिटल मूलनिवासियों की पहली वैश्विक पीढ़ी" कहती है।

- वैश्विक स्तर पर, 15-24 वर्ष की आयु के 79% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं।
- उच्च आय और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में, 95% से अधिक किशोर ऑनलाइन हैं।

जबकि डिजिटल कनेक्टिविटी सीखने और वैश्विक संचार के अवसर खोलती है, यह साइबरबुलिंग, गलत सूचना, हानिकारक ऑनलाइन सामग्री और अत्यधिक या अस्वस्थ सोशल मीडिया उपयोग से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे जोखिम भी लाती है।

क्या किया जाना चाहिए?

रिपोर्ट में सहायक कानूनों और नीतियों के निर्माण का आह्वान किया गया है जो किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा और बढ़ावा देते हैं। इनका उद्देश्य होना चाहिए:

- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना,
- स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले वाणिज्यिक कारकों को विनियमित करना, जैसे कि अस्वास्थ्यकर खाद्य विपणन और नशे की लत वाली तकनीकें,
- सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्थानों के सुरक्षित और स्वस्थ उपयोग को बढ़ावा देना।

इस तरह के ढांचे से ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकता है, जहाँ किशोर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित हो सकें।

निष्कर्ष

द्वितीय लैंगेजट आयोग का संदेश स्पष्ट और जोरदार है: विश्व अपने किशोरों की उपेक्षा नहीं कर सकती। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और डिजिटल कल्याण में निवेश करना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है - यह मानवता के भविष्य के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है।

यदि हम अभी कार्य करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानव इतिहास में किशोरों की यह सबसे बड़ी पीढ़ी स्वस्थ, सशक्त वयस्कों के रूप में विकसित हो, जो सभी के लिए एक उज्ज्वल, अधिक न्यायसंगत विश्व को आकार दे सकें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक आबादी का एक चौथाई हिस्सा होने के बावजूद, किशोरों को वैश्विक स्वास्थ्य निवेश का अनुपातहीन रूप से कम हिस्सा मिलता है। किशोर स्वास्थ्य और कल्याण पर द्वितीय लैंगेजट आयोग के निष्कर्षों के प्रकाश में, वैश्विक स्तर पर किशोरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। [250 शब्द | 15 अंक]

सहकारिता में महिलाएँ

चर्चा में क्यों: इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में भारत के बढ़ते सहकारिता आंदोलन में महिलाओं को सबसे आगे रखने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से 2025 में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मद्देनजर।

सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- लाभ-संचालित व्यवसायों के विपरीत, एक सहकारी समिति एक स्वैच्छिक, सदस्य-स्वामित्व वाला संगठन है जो स्व-सहायता, पारस्परिक सहायता और सामुदायिक कल्याण के माध्यम से साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
- चिट फंड, कुरी और भिशी के शुरुआती प्रकार, जिनकी उत्पत्ति कोल्हापुर, महाराष्ट्र और केरल के मालाबार क्षेत्र में हुई थी, महिलाओं पर बहुत अधिक निर्भर थे।
- स्वतंत्रता-पूर्व भारत में 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित होने के बाद से, सहकारी समितियों का औपचारिक इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है।

प्रमुख पहल

- संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है: थीम - "सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है"।
- सहकारिता मंत्रालय का निर्माण 2021 में हुआ था।
- **स्वयं शक्ति सहकार योजना:** महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहकारी समितियों के लिए 3 साल तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है ताकि महिला एसएचजी को सामान्य/सामूहिक सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त बैंक ऋण की सुविधा मिल सके।
- **उदाहरण:** लिज्जत पापड़: घर से उपभोग की वस्तुएँ बनाने वाली महिलाएँ, अमूल: लाखों महिला डेयरी किसानों को शामिल करता है, सेवा: महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देता है।

महिलाओं के लिए सहकारिता का महत्व

- **आर्थिक:** ग्रामीण महिलाओं को सहकारी समितियों से लाभ हुआ है क्योंकि उनकी घरेलू आय और बचत बढ़ी है, साथ ही उनकी वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता क्षमताएँ भी बढ़ी हैं।
- **सामाजिक पूंजी:** पारस्परिकता, विश्वास और समूह प्रयास के नेटवर्क के माध्यम से, सहकारी समितियाँ महिलाओं को सामाजिक पूंजी तक पहुँच प्रदान करती हैं, जो बदले में लचीलापन बढ़ाती है।

- **कृषि:** यह महिलाओं को जोखिम और लाभ-साझाकरण के आधार पर कृषि इनपुट और उपकरण खरीदने में मदद करती है और साथ ही कृषि निवेश को बढ़ाती है।
- **लैंगिक समानता:** महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने और निर्णय लेने में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करके, महिला सहकारी समितियाँ पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देती हैं और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं।

महिला सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियाँ

- **वर्तमान स्थिति:** 2023 के सहकारिता मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 24,264 महिला सहकारी समितियों में से केवल 10,806 ही कार्यात्मक थीं, जबकि बाकी अपर्याप्त संस्थागत समर्थन, खराब वित्त और प्रशिक्षण की कमी के कारण निष्क्रिय या परिसमापन के अधीन थीं।
- **सांस्कृतिक मानदंड:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएँ अवैतनिक श्रम के बोझ और प्रतिबंधित गतिशीलता जैसे सांस्कृतिक मानदंडों से विवश हैं।
- **अपर्याप्त कौशल:** कम साक्षरता, कम शिक्षा और व्यवसाय, तकनीकी और विपणन कौशल की कमी ग्रामीण सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं। यह उनकी भागीदारी, नेतृत्व और आउटपुट में बाधा डालती है।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:** महिला सदस्यों के बीच खराब समन्वय के कारण कमज़ोर और अनियमित ऑडिट

आगे की राह

- **संस्थागत और वित्तीय सहायता:** विशेषज्ञ सलाह, कौशल विकास और बाज़ार कनेक्शन के माध्यम से, निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना। उपकरण पहुँच, कम ब्याज वाले ऋण और समर्पित निधि सुनिश्चित करना।

- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, नियमित रूप से मेंटरशिप और नेतृत्व कोटा के साथ-साथ विपणन, वित्त, डिजिटल साक्षरता और शासन में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **समावेशन और दक्षता के लिए डिजिटल प्रोत्साहन:** दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए PACS और ARDB को कम्प्यूटरीकृत करते हुए वित्तीय समावेशन, विपणन और प्रशिक्षण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- **कमज़ोर सहकारी समितियों का विलय:** यह स्थानीय क्षेत्रों में एक मजबूत महिला सहकारी बनाने में मदद करेगा, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग बेहतर होगा।

निष्कर्ष

सहकारिता भारत में महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती है और सही उपकरणों, नेतृत्व और प्रशिक्षण के साथ, केवल महिला सहकारी समितियाँ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ा सकती हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कानूनों को बदलने और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने का एक उचित अवसर प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. यद्यपि महिलाओं ने भारत में सहकारी प्रथाओं में ऐतिहासिक रूप से योगदान दिया है, लेकिन आधुनिक सहकारी समितियों में उनका नेतृत्व और भागीदारी सीमित है। सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में महिला सहकारी समितियों की भूमिका की जाँच करें और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करने के उपाय भी सुझाएँ। [250 शब्द] [15 अंक]

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

'इंडियन एक्सप्रेस' में क्या पढ़ें?

क्यू आर कोड स्कैन करें



नालंदा विश्वविद्यालय वैश्विक पुनरुत्थान के लिए तैयार

परिचय

चर्चा में क्यों: भारत की उच्च शिक्षा की प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला है।

आधुनिक समय में पुनर्जागरण

- प्राचीन नालंदा महाविहार के खंडहरों के पास पुनः स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय - जो दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण केंद्रों में से एक है - को वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।
- यह विदेश मंत्रालय के अधीन संचालित होता है, जो भारत के अपने प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के साथ मिलाने के प्रयास का प्रतीक है।
- विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र में लगभग 900 छात्रों के नामांकन की तैयारी कर रहा है।
- वर्तमान में, विभिन्न धाराओं में प्रवेश पहले ही 540 छात्रों तक पहुंच चुके हैं, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है और संस्थान में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
- नए कुलपति ने शांति को बढ़ावा देने, जटिल अंतःविषय अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और भारतीय दर्शन को समकालीन वैश्विक चुनौतियों से जोड़ने के विश्वविद्यालय के मिशन को रेखांकित किया।
- विचार एक ऐसा मंच बनाने का है जहाँ शोधकर्ता, राजनयिक और नीति-निर्माता बातचीत कर सकें, सहयोग कर सकें और अधिक न्यायपूर्ण और ज्ञान-संचालित वैश्विक व्यवस्था में योगदान दे सकें।
- बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय के परिसर के लिए लगभग 500 एकड़ भूमि आवंटित की है। इसमें से 100 एकड़ भूमि जल निकासी के लिए आरक्षित की गई है, जिससे पारिस्थितिकी स्थिरता बढ़ेगी, जबकि 300 एकड़ भूमि को वन भूमि के रूप में संरक्षित किया गया है, जो हरित और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील परिसर के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

प्राचीन नालंदा का इतिहास

- प्राचीन दुनिया में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है - यह भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। सदियों की खामोशी के बाद, इस प्राचीन विश्वविद्यालय को अब एक आधुनिक संस्थान के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है जो विरासत को नवाचार और ज्ञान को स्थिरता के साथ जोड़ता है।
- नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ई. में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम (शक्रदित्य) के शासनकाल के दौरान आधुनिक बिहार में की गई थी। लगभग 600 वर्षों तक, यह उच्च शिक्षा का एक जीवंत केंद्र रहा, जिसने पूरे एशिया से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया।

- सम्राट हर्षवर्धन (606-647 ई.) और बाद में पाल वंश के शासनकाल के दौरान, नालंदा प्रसिद्धि और प्रभाव के अपने शिखर पर पहुंच गया।
- प्रसिद्ध चीनी भिक्षु और विद्वान ह्वेन त्सांग ने नालंदा में पांच वर्ष तक अध्ययन किया। वे कई बौद्ध धर्मग्रंथ भी साथ ले गए, जिनका बाद में उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया और पूर्वी एशिया में भारतीय दर्शन का प्रसार किया।
- एक अन्य चीनी तीर्थयात्री, इ-त्सिंग ने 670 ई. में नालंदा का दौरा किया और बताया कि विश्वविद्यालय में लगभग 2,000 छात्र पढ़ते थे और लगभग 200 गांवों से दान प्राप्त होता था।
- नालंदा ने चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, इंडोनेशिया और एशिया के अन्य हिस्सों से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान का एक प्रारंभिक उदाहरण बन गया।
- नागार्जुन, आर्यभट्ट, धर्मकीर्ति और अन्य जैसे महान विचारक और वैज्ञानिक इस प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े थे।
- इंडोनेशियाई शैलेंद्र राजवंश ने भी विश्वविद्यालय के भीतर एक मठ का निर्माण करके नालंदा का समर्थन किया, जो इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच को दर्शाता है।
- यह क्षेत्र आध्यात्मिक महत्व भी रखता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने इसके आसपास ध्यान किया था

विनाश और पतन का काल

यद्यपि नालंदा सदियों तक समृद्ध रहा, फिर भी इसे अनेक आक्रमणों और विनाश के दौर का भी सामना करना पड़ा।

- पहला आक्रमण (455-470 ई.):**
 - मध्य एशियाई जनजातीय समूह हूणों द्वारा संचालित।
 - उनका लक्ष्य मुख्य रूप से विश्वविद्यालय की संपत्ति लूटना था।
 - सम्राट स्कंद गुप्त ने बाद में विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया और इसके प्रसिद्ध पुस्तकालय की स्थापना की।
- दूसरा आक्रमण (7वीं शताब्दी):**
 - सम्राट हर्षवर्धन के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण बंगाल के गौड़ शासकों द्वारा किया गया।
 - एक बार फिर, हर्षवर्धन ने नालंदा को पुनर्स्थापित किया और इसके मिशन का समर्थन किया।
- अंतिम विनाश (1193 ई.):**
 - नालंदा को अंततः तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया।
 - हजारों अमूल्य पांडुलिपियाँ, पुस्तकें और स्क्रॉल नष्ट कर दिए गए और विश्वविद्यालय को छोड़ दिया गया।

खंडहरों की पुनः खोज

- 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन-हैमिल्टन ने नालंदा के खंडहरों की फिर से खोज की।

- बाद में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल को प्राचीन विश्वविद्यालय के स्थान के रूप में पुष्टि की।
- पिछले कुछ वर्षों में, पुरातात्विक उत्खनन में मंदिर, मठ, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष और छात्रावास मिले हैं, जो विश्वविद्यालय की समृद्ध वास्तुकला और बौद्धिक विरासत की पुष्टि करते हैं।

नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार

- सदियों तक खंडहर में पड़े रहने के बाद, 2000 के दशक की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार प्रस्तावित किया गया था। इस पहल का समर्थन निम्नलिखित लोगों ने किया था:
 - पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
 - सिंगापुर सरकार
 - पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के देश
- साथ मिलकर उन्होंने एक आधुनिक संस्थान की कल्पना की जो ज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में नालंदा की वैश्विक स्थिति को पुनः प्राप्त करेगा।

नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010

- 2010 में भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिससे नए विश्वविद्यालय को कानूनी दर्जा मिला।
- पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, जिसमें भारत पूर्वी एशियाई और आसियान देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

नया परिसर

- बिहार सरकार ने प्राचीन खंडहरों के पास 455 एकड़ भूमि आवंटित की है।
- प्रसिद्ध वास्तुकार बी.वी. दोशी ने एक पर्यावरण-अनुकूल, हरा-भरा परिसर डिजाइन किया है जो आधुनिक तकनीक को एकीकृत करते हुए अतीत के आध्यात्मिक और बौद्धिक माहौल को दर्शाता है।
- **परिसर में शामिल हैं:**
 - 100 एकड़ का जल निकास
 - एक सौर ऊर्जा संयंत्र
 - जल उपचार और पुनर्चक्रण प्रणाली
 - शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन - इसे 'शुद्ध शून्य' ग्रीन कैम्पस बनाता है।

पाठ्यक्रम और वैश्विक जुड़ाव

नया नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है:

- बौद्ध अध्ययन, दर्शन और तुलनात्मक धर्म
- ऐतिहासिक अध्ययन
- पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन

भारत तथा 20 से अधिक देशों से छात्र और प्राध्यापक यहां आते हैं, जिससे नालंदा एक बार फिर वास्तविक रूप से वैश्विक विश्वविद्यालय बन गया है।

यूनेस्को द्वारा मान्यता

- 2016 में, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को इसके विशाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को स्वीकार करते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

निष्कर्ष

- नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार केवल एक परिसर का पुनर्निर्माण नहीं है - यह एक सभ्यतागत विरासत का पुनरोद्धार है। यह शिक्षा, शांति और वैश्विक संवाद के प्रति भारत की प्राचीन प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रतीक है। आज, नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर सीखने, क्षेत्रीय सहयोग, अंतर-सांस्कृतिक समझ और अतीत के ज्ञान और भविष्य की आकांक्षाओं में निहित सतत विकास को बढ़ावा देने का एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए तैयार है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार केवल एक शैक्षिक पहल नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत कथन है। प्राचीन नालंदा के ऐतिहासिक महत्व और इसकी विरासत को बहाल करने के आधुनिक प्रयासों के प्रकाश में चर्चा करें। [150 शब्द | 10 अंक]

प्राकृतिक आपदा का एक दुर्लभ ऐतिहासिक रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों: एक उल्लेखनीय खोज में, जिसने भारत की ऐतिहासिक और पुरालेखीय विरासत में एक नया आयाम जोड़ा है, कर्नाटक के हावेरी जिले के गुट्टाला गांव में चंद्रशेखर मंदिर के पास एक पत्थर का शिलालेख मिला है, जो 480 साल पहले हुई एक विशाल मानवीय आपदा का दस्तावेजीकरण करता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है, जो पुरातात्विक अनुसंधान और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

- एएसआई देश भर में 3,650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- **इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:**
 - पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण
 - पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन
 - संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव

एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक बने। उन्हें व्यापक रूप से "भारतीय पुरातत्व का जनक" माना जाता है।

भारत में प्राकृतिक आपदा का पहला अभिलेख

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, यह शिलालेख के रूप में पहला ज्ञात ऐतिहासिक अभिलेख है जो भारतीय इतिहास में किसी प्राकृतिक आपदा - सूखे - के कारण बड़े पैमाने पर हुई मानवीय क्षति का स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकरण करता है।
- यह शिलालेख शक वर्ष 1461, विकारी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी का है, जो 18 अगस्त, 1539 ई. से मेल खाता है।

शिलालेख का विवरण

- यह शिलालेख कन्नड़ भाषा और लिपि में उत्कीर्णित है और एक पत्थर की पट्टिया पर पाया गया है। इससे पता चलता है कि भयंकर सूखे (जिसे स्थानीय रूप से बारा कहा जाता है) के कारण 6,307 लोगों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में भयावह मानवीय संकट पैदा हो गया।
- अभिलेख में आगे बताया गया है कि किस तरह गुट्टावालाला के ननिदेव ओडेया के बेटे मारुलाइह ओडेया नामक व्यक्ति ने मृतकों के शवों को दफनाया था। सामुदायिक सेवा और धार्मिक भक्ति के प्रदर्शन में, मारुलाइह ने शवों को अपने सिर पर टोकरियों में रखा और स्थानीय सीमा (एक क्षेत्रीय प्रभाग) के शासक तिममारासा स्वामी के सम्मान में और क्षेत्र के एक पूजनीय व्यक्ति बसवेश्वर को सम्मान देने के बाद उन्हें दफनाया।
- शिलालेख के साथ एक मूर्ति भी है जिसमें एक व्यक्ति - संभवतः मारुलाइह ओडेया - को अपने सिर पर दो या तीन शवों से भरी एक टोकरी उठाते हुए दिखाया गया है, जो दुखद घटनाओं को जीवंत दृश्य रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

खोज का महत्व

एएसआई के पुरालेख निदेशक के. मुनिरत्नम रेड्डी के अनुसार, यह शिलालेख कई कारणों से एक ऐतिहासिक खोज है:

- यह प्राकृतिक आपदा की मानवीय लागत को दर्ज करने में दुर्लभ और स्पष्ट है।
- यह हमें उस समय की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं की एक झलक देता है, खासकर यह कि समुदाय बड़े पैमाने पर संकटों से कैसे निपटते थे।
- साहित्यिक स्रोतों में आमतौर पर ऐसे रिकॉर्ड अनुपस्थित होते हैं, जिससे यह खोज इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद मूल्यवान बन जाती है।

अनुसंधान और जलवायु अध्ययन के लिए निहितार्थ

यह खोज न केवल ऐतिहासिक आपदाओं के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है, बल्कि निम्नलिखित के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है:

- समय और क्षेत्र के विभिन्न शिलालेखों के साथ तुलनात्मक अध्ययन।
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामुदायिक तन्त्रकता और सामना करने के तंत्र को समझना।
- ऐतिहासिक जलवायु पैटर्न का पता लगाना, संभावित रूप से शोधकर्ताओं को दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनों और उनके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने में मदद करना।
- ऐसी आपदाओं से उत्पन्न प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

भारत के अतीत की झलक के रूप में पुरालेख

- एएसआई की पुरालेख शाखा भारत की समृद्ध शिलालेखीय विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अकेले वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इसने देश भर से 1,000 से अधिक शिलालेखों की खोज की और उनकी प्रतिलिपि बनाई है - जिसमें दूरदराज और वन क्षेत्र भी शामिल हैं। इस वर्ष पहले ही 100 से अधिक शिलालेख मिल चुके हैं, जिससे भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय अतीत के बारे में हमारी समझ और बढ़ गई है।

निष्कर्ष

1539 के गुट्टला सूखे (Drought) के शिलालेख की खोज प्राकृतिक आपदाओं द्वारा लाई गई मानवीय त्रासदियों की एक गंभीर याद दिलाती है - सदियों पहले भी।

साथ ही, यह सामुदायिक भावना, धार्मिक भक्ति और बड़ी कठिनाई के समय लोगों की लचीलापन को दर्शाता है। जैसा कि शोधकर्ता भारत के विशाल अभिलेखीय अभिलेखों का पता लगाना जारी रखते हैं, ऐसे निष्कर्ष निस्संदेह हमारे इतिहास की अधिक सूक्ष्म और समग्र समझ में योगदान देंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. कर्नाटक के गुट्टाला में 1539 ई. के सूखे के अभिलेख की खोज से पूर्व-आधुनिक भारत में प्राकृतिक आपदाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। भारत के पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक अतीत के पुनर्निर्माण में ऐसे अभिलेखीय अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करें। [250 शब्द | 15 अंक]

अंतर्राष्ट्रीय वेसक दिवस

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय वेसक दिवस मनाया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को एक साथ लाया गया।

मुख्य विवरण

- **अंतर्राष्ट्रीय वेसक दिवस, 2025 का विषय:** “मानव मूल्य के लिए सद्भाव और समावेशिता: वैश्विक शांति और सतत उन्नति के लिए बौद्ध दृष्टिकोण”
- **स्थान:** वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी।
- हो ची मिन्ह सिटी में हान टैम मठ में पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन किया गया।
- विभिन्न कार्यक्रमों में बौद्ध परंपराओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, जैसे:
 - जातक कथाओं की डिजिटल प्रस्तुति
 - बुद्ध के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती मूर्तियां
 - भारत और वियतनाम की बौद्ध कलाकृतियों का तुलनात्मक विश्लेषण।
 - पहली बार, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के साथ मिलकर वियतनाम के सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष प्रस्तुत किए।

वेसक

- इसकी उत्पत्ति प्राचीन चंद्र महीने वैसाख से हुई है, जो मई में पूर्णिमा के दिन होता है।
- बुद्ध का जन्म ढाई हजार साल पहले 623 ईसा पूर्व में वेसक के दिन हुआ था।
- बुद्ध को वेसक के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी पवित्र दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी।
- महावंश इतिहास से पता चलता है कि वेसक की उत्पत्ति श्रीलंका में हुई थी, जहाँ राजा दुत्तगामनी के शासन के दौरान लगभग 2,100 साल पहले इस त्यौहार की स्थापना की गई थी।

गौतम बुद्ध

माना जाता है कि यह अनागत विष्णु के 8वें अवतार (दशावतार) हैं।

जन्म

- सिद्धार्थ के रूप में जन्म (563 ई.पू.)
- जन्मस्थान - कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी (नेपाल)

माता-पिता

पिता - कपिलवस्तु के निवाचित शासक, शाक्य गणतंत्रिक कुल के प्रभु
माता - कोशल राजवंश की राजकुमारी

आत्मज्ञान (निर्वाण)

समकालीन

- सर्धमिान महावीर
- विन्दिशार
- अनातपु

बुद्ध से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थान

- बोधगया (जागीर) (जान प्राप्ति के बाद इसका नाम बुद्ध स्था किया गया)
- सारनाथ (प्रथम उपदेश)
- वैशाली (अंतिम उपदेश)
- कुशीनगर (मृत्यु स्थान (487 ई.पू.))

मुख्य विवरण

- 70वें मठाधीश, श्री विजयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्य, ने अपने उत्तराधिकारी, जिनका जन्म डड्डु सत्य वेंकट सूर्य सुब्रह्मण्य गणेश शर्मा द्रविड़ के रूप में हुआ, को संन्यास दीक्षा समारोह आयोजित करके और 'तांडम' (कर्मचारी) सौंपकर 71वें मठाधीश (आचार्य) के रूप में शामिल किया।
- 70वें मठाधीश, श्री विजयेन्द्र सरस्वती, को 1983 में उनके पूर्ववर्ती श्री जयेन्द्र सरस्वती ने 15 साल की उम्र में पीतम का आचार्य बनाया था।
- 69वें मठाधीश जयेन्द्र सरस्वती को 1954 में श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती द्वारा आचार्य बनाया गया था।
- 71वें मठाधीश ऋग्वेद के एक निपुण विद्वान हैं। उन्होंने यजुर्वेद, सामवेद, षडंग और दशोपनिषद् का अध्ययन पूरा किया है।

कांची कामकोटि पीठम के बारे में

- श्री कांची कामकोटि पीठम तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित एक महत्वपूर्ण मठ है, जिसकी जड़ें प्राचीन वेद-धर्म परंपरा में हैं।
- इसमें 71 आचार्यों की एक अखंड परंपरा है।
- कांची कामकोटि पीठम की स्थापना का श्रेय श्री आदि शंकराचार्य (जिन्हें शंकर भगवत्पाद या शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है) को दिया जाता है।
- इसकी स्थापना 2500 साल से भी पहले हुई थी, उस समय जब विधर्म और गैर-वैदिक संप्रदायों को प्राचीन वेद-धर्म के लिए खतरा माना जाता था।
- कहा जाता है कि श्री शंकर भगवत्पाद कांचीपुरम में बस गए थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहीं मठ में बिताए थे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. श्री कांची कामकोटि पीठम की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?

- (a) आदि शंकराचार्य (b) श्री विद्यारण्य
(c) रामानुजाचार्य (d) माधवाचार्य

(ए) :१५६

वेसक का संयुक्त राष्ट्र दिवस

- 15 दिसंबर, 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 54/115 को अपनाया, जिसके तहत वेसक दिवस को दुनिया भर में एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव के रूप में मान्यता दी गई।
- यह दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यालयों में, उपयुक्त संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के समन्वय में मनाया जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में, 'वेसक' शब्द चर्चा में था। यह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है?

- (a) जैन धर्म (b) बौद्ध धर्म
(c) वैष्णव धर्म (d) इनमें से कोई नहीं

(9) :१५६

सरस्वती पुष्करालु

चर्चा में क्यों: सरस्वती नदी के लिए कुंभ मेले जैसा 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलु अनुष्ठान तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले में श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर के निवास स्थान, मंदिरों के शहर कालेश्वरम में शुरू हुआ।

सरस्वती पुष्करालु के बारे में

- 12 साल में एक बार होने वाला यह विशाल धार्मिक उत्सव भूमिगत सरस्वती नदी की पूजा के लिए समर्पित है, जो कालेश्वरम में त्रिवेणी संगमम नामक संगम बिंदु पर गोदावरी और प्राणहिता के साथ मिलती है।
- 12 दिवसीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के पंडितों द्वारा 'नदी हरथी' और कई भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- ऐतिहासिक महत्व:** कालेश्वरम में प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में एक ही चौकी पर दो शिव लिंग हैं जिन्हें भगवान कालेश्वर (यम) और भगवान मुक्तेश्वर (शिव) के नाम से जाना जाता है, जिनका गहरा धार्मिक महत्व है।

कांची कामकोटि पीठम

चर्चा में क्यों: श्री सत्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती को कांची कामकोटि पीठम का 71वां मठाधीश नियुक्त किया गया।

- पवित्र मंदिर परिसर में अन्य देवी-देवताओं के अलावा सरस्वती देवी और शुभानन्दा देवी को समर्पित अन्य मंदिर भी हैं।
- यह कुंभ मेले के समान एक नदी उत्सव है, जो तब मनाया जाता है जब बृहस्पति (गुरु) मिथुन राशि में प्रवेश करता है।

पुष्कर स्नान के आध्यात्मिक लाभ

- ऐसा माना जाता है कि मनुष्य द्वारा जन्म से ही किए गए पाप, चाहे वे जाने-अनजाने में किए गए हों, पुष्कर स्नान करने से धुल जाते हैं।
- भारतीय सनातन परंपराओं में, पुष्कर स्नान एक महान भक्तिपूर्ण कार्य है, और भक्तों का मानना है कि कालेश्वरम में त्रिवेणी संगम पर पुष्कर स्नान करने के बाद, देवी श्री महा सरस्वती के दर्शन करने से बहुत पुण्य मिलता है।
- पुष्कर स्नान में पवित्र डुबकी लगाने के सबसे आम आध्यात्मिक लाभों में मानसिक स्पष्टता में वृद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान और नकारात्मक ऊर्जा या कर्म को दूर करना शामिल है। माना जाता है कि यह अनुष्ठान मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे भक्तों को दिव्य संबंध और शांति की भावना का अनुभव होता है।

कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर

- कालेश्वरम, कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी नामक प्रसिद्ध शिव मंदिर का स्थल है, जो तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर है।
- कालेश्वरम, प्राणहिता नदी (गोदावरी की सहायक नदी) और गोदावरी नदी के संगम स्थल पर स्थित है।
- यह मंदिर दो शिव लिंगों के कारण अद्वितीय रूप से महत्वपूर्ण है जो एक ही पीठ पर स्थित हैं।
 - उनका नाम भगवान शिव और भगवान यम है, जिन्हें सामूहिक रूप से कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है।
- कालेश्वरम त्रिलिंग देशम (तीन लिंगों की भूमि) में वर्णित तीन शिव मंदिरों में से एक है और आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी क्षेत्र का दूसरा नाम है। (उल्लेखित अन्य दो स्थान द्रक्षरमम और श्रीशैलम हैं।)

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. 'सरस्वती पुष्करालु परंपरा' किस राज्य में मनाई जाती है:

- | | |
|-------------|--------------|
| (a) ओडिशा | (b) तेलंगाना |
| (c) कर्नाटक | (d) तमिलनाडु |

(Q) : 2018

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन

चर्चा में क्यों: 1 मई को 65वां महाराष्ट्र दिवस मनाया गया, जिसमें संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बारे में

- संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद के भारत में सबसे महत्वपूर्ण भाषाई और सांस्कृतिक आंदोलनों में से एक है, जिसकी परिणति 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य के गठन के रूप में हुई।

ऐतिहासिक संदर्भ और राजनीतिक आधार

• स्वतंत्रता-पूर्व की घटनाएँ

- 1940 की शुरुआत में ही एम.एस. अणे के नेतृत्व में महाविदर्भ समिति ने विदर्भ और नागपुर संभागों के आठ जिलों को मिलाकर एक मराठी भाषी राज्य बनाने का सुझाव दिया था।
- 12 मई, 1946 को बेलगाम में एक साहित्यिक बैठक में संयुक्त महाराष्ट्र के लिए औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गजानन त्र्यंबक मडखोलकर ने की, जिसके परिणामस्वरूप एक कार्यान्वयन समिति का गठन हुआ।
- **अकोला समझौता (1947):** 1947 के अकोला समझौते ने पश्चिमी महाराष्ट्र और मध्य प्रांतों और बरार के कांग्रेस नेताओं के बीच सहयोग के लिए एक प्रारंभिक रूपरेखा स्थापित की, जिसमें एक ही सरकार के तहत महाविदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र के दो उप-प्रांतों की परिकल्पना की गई थी। 8 अगस्त, 1947 को बैरिस्टर रामराव देशमुख और अन्य द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते ने मराठी भाषी क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक एकता की आवश्यकता की प्रारंभिक मान्यता को प्रदर्शित किया।

• स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक चुनौतियाँ

- कांग्रेस द्वारा भाषाई आधार पर राज्य बनाने की स्वतंत्रता-पूर्व प्रतिज्ञा के बावजूद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल इस तरह के पुनर्गठन के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाना विभाजनकारी हो सकता है।
- दिसंबर 1948 में धर आयोग की रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया और इस तरह के कदमों को राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताया गया।
- अक्टूबर 1953 में आंध्र राज्य के गठन ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन की व्यावहारिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित किया और महाराष्ट्र आंदोलन के लिए एक मिसाल कायम की।

संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व

• संयुक्त महाराष्ट्र समिति

- 6 फरवरी, 1956 को पुणे के तिलक स्मारक मंदिर में संयुक्त महाराष्ट्र समिति की औपचारिक स्थापना ने आंदोलन के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान की।
- नेतृत्व संरचना ने आंदोलन के व्यापक चरित्र को प्रतिबिंबित किया, जिसमें श्रीपाद अमृत डांगे अध्यक्ष, टी.आर. नरवाने उपाध्यक्ष और एस.एम. जोशी महासचिव थे।
- नारायण गणेश गोरे, नाना पाटिल और उद्धवराव पाटिल जैसे प्रमुख वामपंथी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ अन्नाभाऊ साठे, प्रल्हाद केशव अले और केशव सीताराम ठाकरे जैसे अन्य नेताओं को शामिल करना आंदोलन की वैचारिक विविधता को दर्शाता है।

• रणनीतिक समझौते और वार्ता

- **नागपुर समझौता (1953):** 28 सितंबर, 1953 का नागपुर समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता था, जिसने प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य के भीतर क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित किया।
- इस समझौते ने सभी क्षेत्रों के समान विकास को सुनिश्चित किया और नागपुर को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया, जिसमें वार्षिक विधायी सत्र और उच्च न्यायालय की पीठ के प्रावधान थे।

- **संघीय लोकतंत्र और भाषाई अधिकार**
 - 1 मई, 1960 को मुंबई को अपनी राजधानी बनाकर महाराष्ट्र के सफल गठन ने भारत में भाषाई पुनर्गठन और संघीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम की।
 - आंदोलन की उपलब्धियों ने यह प्रदर्शित किया कि सांस्कृतिक और भाषाई पहचान राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखते हुए राजनीतिक संगठन के लिए वैध आधार के रूप में काम कर सकती है।
- **समकालीन राजनीति के लिए सबक**
 - सांस्कृतिक प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए पारंपरिक सामाजिक सीमाओं को पार करने की आंदोलन की क्षमता समावेशी राजनीतिक आयोजन के लिए मॉडल प्रदान करती है जो समान उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए विविधता का सम्मान करती है।
 - संघवाद के बारे में आंदोलन की परिष्कृत समझ, नागपुर संधि जैसे समझौतों में प्रदर्शित होती है, इस बात के उदाहरण प्रदान करती है कि कैसे क्षेत्रीय स्वायत्तता को लोकतांत्रिक संघीय प्रणालियों में एकता के साथ संतुलित किया जा सकता है। संघीय डिजाइन में ये नवाचार शासन और क्षेत्रीय विकास के बारे में समकालीन चर्चाओं के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं।

निष्कर्ष

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन लोकतांत्रिक लामबंदी, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और संघीय डिजाइन में एक उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। लोक संस्कृति, बौद्धिक विश्लेषण और रणनीतिक राजनीतिक कार्यवाही के अभिसरण के माध्यम से, आंदोलन ने भाषाई अधिकारों और संघीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम करते हुए सफलतापूर्वक एक एकीकृत मराठी भाषी राज्य बनाया। अन्नाभाऊ साठे और डॉ. अंबेडकर जैसे लोगों के योगदान ने दिखाया कि कैसे सांस्कृतिक कार्यकर्ता और बौद्धिक नेता परिवर्तनकारी राजनीतिक परिवर्तन हासिल करने के लिए सहयोग कर सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. महाराष्ट्र के गठन को आकार देने के लिए विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक ताकतें कैसे एकजुट हुईं? संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की सफलता को किन रणनीतिक राजनीतिक चुनौतियों और समझौतों ने परिभाषित किया? [250 शब्द | 15 अंक]

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



'द हिंदू' और 'इंडियन एक्सप्रेस' से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें



मनरेगा 2024-25

चर्चा में क्यों: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की हाल ही में की गई समीक्षा से एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है - जबकि इस योजना के तहत पंजीकृत परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, वास्तव में प्रदान किए गए कार्य में कमी आई है।

नोट: ग्रामीण कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने वाले शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह लिबटेक इंडिया द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में इस पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के अनुसार

मनरेगा अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का वेतन रोजगार देने की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। हालाँकि, जमीनी हकीकत इस वादे से बहुत दूर लगती है।

- पंजीकृत परिवारों की संख्या में 8.6% की वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 13.80 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 14.98 करोड़ हो गई है।
- लेकिन वास्तव में प्रदान किए गए रोजगार में कमी आई है - व्यक्ति दिवस (उत्पन्न कार्यदिवसों की कुल संख्या) में 7.1% की गिरावट आई है।
- प्रति परिवार कार्यदिवसों की औसत संख्या में भी गिरावट आई है, जो 52.42 दिनों से घटकर 50.18 दिन हो गई है, यानी 4.3% की गिरावट।
- सबसे चिंताजनक बात यह है कि केवल 7% परिवार ही कानूनी रूप से किए गए वादे के अनुसार पूरे का 100 दिन काम पाने में कामयाब रहे।

इससे स्पष्ट रूप से बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति के बीच असंतुलन का पता चलता है - अधिक लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कम लोगों को काम मिल रहा है।

"व्यक्ति दिवस" क्या हैं?

मनरेगा में, व्यक्ति दिवस वर्ष के दौरान व्यक्तियों के लिए उत्पन्न कुल कार्यदिवसों की संख्या को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि 1 व्यक्ति 10 दिन काम करता है, तो उसे 10 व्यक्ति दिवस के रूप में गिना जाता है।

राज्य-स्तरीय रुझान

कार्य के वितरण में क्षेत्रीय अंतर हैं:

वे राज्य जहाँ व्यक्ति दिवसों में सबसे अधिक कमी आई:

- ओडिशा: -34.8%
- तमिलनाडु: -25.1%

- राजस्थान: -15.9%

वे राज्य जहाँ व्यक्ति दिवसों में वृद्धि हुई:

- महाराष्ट्र: +39.7%
- हिमाचल प्रदेश: +14.8%
- बिहार: +13.3%

इससे पता चलता है कि स्थानीय शासन और कार्यान्वयन के आधार पर योजना की प्रभावशीलता राज्यों में बहुत भिन्न होती है।

कारण

रिपोर्ट और विशेषज्ञ इस घटते प्रदर्शन के दो प्रमुख कारण बताते हैं:

अपर्याप्त बजट आवंटन

- केंद्र सरकार ने 2024-25 में मनरेगा के लिए केवल ₹86,000 करोड़ आवंटित किए।
- यह पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीएईजी) जैसे विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित ₹2.64 लाख करोड़ से बहुत कम है।
- बढ़ती मांग के बावजूद, कोई बजट संशोधन नहीं किया गया, जिससे कार्यक्रम को कम वित्तपोषित किया गया।

मजदूरी भुगतान में देरी

- कई राज्यों में, श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त करने में असाधारण देरी का सामना करना पड़ा है, जो भागीदारी को हतोत्साहित करता है।
- देर से भुगतान योजना की मूल भावना का उल्लंघन करता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को समय पर आय सहायता प्रदान करना है।

कर्मचारियों का विलोपन और परिवर्धन

- 2022 से 2024 तक, चौंकाने वाले 7.8 करोड़ श्रमिकों को मनरेगा रोल से हटा दिया गया (हटा दिया गया), जबकि केवल 1.92 करोड़ जोड़े गए। इससे समावेशन लुटियों और पारदर्शिता की कमी के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा हुईं।
- हालाँकि, 2024-25 के लिए एक सकारात्मक विकास यह रहा:
 - केवल 99 लाख श्रमिकों को हटाया गया, जबकि
 - 2.22 करोड़ नए श्रमिकों को जोड़ा गया।
- दो वर्षों में यह पहली बार है कि जुड़ने वालों की संख्या हटाए जाने वालों से अधिक है, जो पिछले बहिष्करणों में आंशिक सुधार का संकेत देता है।

बड़ा सवाल: क्या काम करने के अधिकार का सम्मान किया जा रहा है?

- निष्कर्ष भारत में लाखों ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा - मनरेगा के कार्यान्वयन और अखंडता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करते हैं।
- कानूनी अधिकार होने के बावजूद, 100 दिनों के काम तक पहुँच बहुसंख्यकों के लिए आधारहीन बनी हुई है। बजट में कटौती, तकनीकी बाधाओं और भुगतान में देरी के साथ, योजना में ग्रामीण समुदायों का विश्वास कम हो सकता है।

यह क्यों मायने रखता है?

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना: अंतर्निहित लागतों को कम करके, भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं।
- निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना: यह कदम आने वाले वर्षों में \$1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य हासिल करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।
- निर्यातोंमुख अवसररचना का समर्थन: SEZ और EOU निरंतर नीति समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं; RoDTEP को बहाल करने से नीति निरंतरता सुनिश्चित होती है।
- मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना: इनपुट और छिपे हुए करों को कवर करके, यह योजना घरेलू मूल्य संवर्धन और विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्ष

AA धारकों, EOU और SEZ इकाइयों को RoDTEP लाभों की बहाली निर्यातकों और निवेशकों को एक सकारात्मक संकेत भेजती है। यह दर्शाता है कि सरकार नीति स्थिरता, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करके भारत के निर्यात क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि वैश्विक व्यापार नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए भारत के लिए विश्व निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और व्यापार के माध्यम से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए ऐसे सहायक कदम महत्वपूर्ण हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. RoDTEP का उद्देश्य निर्यातकों को GST और सीमा शुल्क छूट जैसी मौजूदा योजनाओं के तहत पहले से वापस किए गए सभी शुल्कों और करों की प्रतिपूर्ति करना है।
2. यह योजना अग्रिम प्राधिकरण (AA), निर्यात-उन्मुख इकाइयों (EOUs) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के तहत निर्यातकों पर लागू है।
3. RoDTEP योजना को भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (MEIS) को बदलने के लिए पेश किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

(q) : 2018

पीएम मित्र

चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश ने ₹2,100 करोड़ के पीएम मित्र (PM MITRA) पार्क के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है, जो राज्य के कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाली परियोजना है। 2,100 एकड़ में फैले इस एकीकृत पार्क में उन्नत सुविधाएँ और आवासीय परिसर होंगे, जो महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करेंगे और कई रोजगार सृजित करेंगे।

पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA)

- कपड़ा मंत्रालय द्वारा पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) योजना शुरू की गई थी।
- भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री के 5F विजन (यानी खेत से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेशी) से प्रेरित होकर, पीएम मित्र पार्क भारत को कपड़ा विनिर्माण और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- MITRA पार्क भारत के कपड़ा उद्योग को उच्च आकार और पैमाने प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे, साथ ही एक स्थान पर आधुनिक और एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला का निर्माण करेंगे।

MITRA पार्क के लाभ

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश आकर्षण: यह भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएगा, बड़े निवेश आकर्षित करेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। यह भी अनुमान है कि प्रत्येक पीएम मित्रा पार्क 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगा।
- रोजगार सृजन और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी: टीएंडए उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को समायोजित करने के अलावा, मित्रा पार्क उद्योग को समर्थन देने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और संवर्धन करेंगे। एक बार पूरा हो जाने पर, प्रत्येक पार्क से सीधे 1,00,000 और अप्रत्यक्ष रूप से 2,00,000 नौकरियों के सृजन की सम्भावना है।
- आधुनिक बुनियादी ढांचा और वैश्विक मानक: ये पार्क प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे और कपड़ा क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बनाने में मदद करेंगे।
- मूल्य श्रृंखला में सहायता: आधुनिकीकरण, मापनीयता और कुशल कार्यबल के माध्यम से कपड़ा उद्योग के हर क्षेत्र के लिए लाभ।

विशेषताएँ

- MITRA पार्क प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, जो चलने के लिए तैयार, शुरू करने के लिए तैयार (प्लग एंड प्ले सुविधाओं के माध्यम से), सामान्य औद्योगिक अवसररचना और सुविधाओं के साथ, एक सन्निहित क्षेत्र में आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं के एकीकरण की अनुमति देंगे।
- पैमाने को सक्षम करने के लिए, MITRA पार्क के लिए न्यूनतम अनुमानित क्षेत्र 1,000 एकड़ है।
- मानव निर्मित फाइबर (MMF) और तकनीकी वस्त्र भी नए निवेश का एक महत्वपूर्ण घटक होने की उम्मीद है।
- MITRA पार्क ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड हो सकते हैं।
 - **ग्रीनफील्ड साइटें:** इस श्रेणी के तहत नई स्वतंत्र साइटें विकसित की जाएंगी।
 - **ब्राउनफील्ड साइटें:** आंशिक रूप से विकसित औद्योगिक ट्रंक अवसररचना और अन्य इच्छित सुविधाओं वाली साइटों को विकास को पूरा करने के लिए लिया जाएगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. PM-MITRA योजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. PM-MITRA का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला पार्क विकसित करना है।
2. यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(e) : 2022

स्वामित्व योजना

चर्चा में क्यों: ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की आबादी और मानचित्रण का सर्वेक्षण (स्वामित्व) योजना ने कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

योजना के बारे में

- अप्रैल 2020 में शुरू की गई, स्वामित्व योजना ड्रोन-आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है।
- स्वामित्व को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंफ (एनआईसीएसआई) के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड के साथ सशक्त बनाना, ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाना, विवाद समाधान और बेहतर नियोजन करना है।

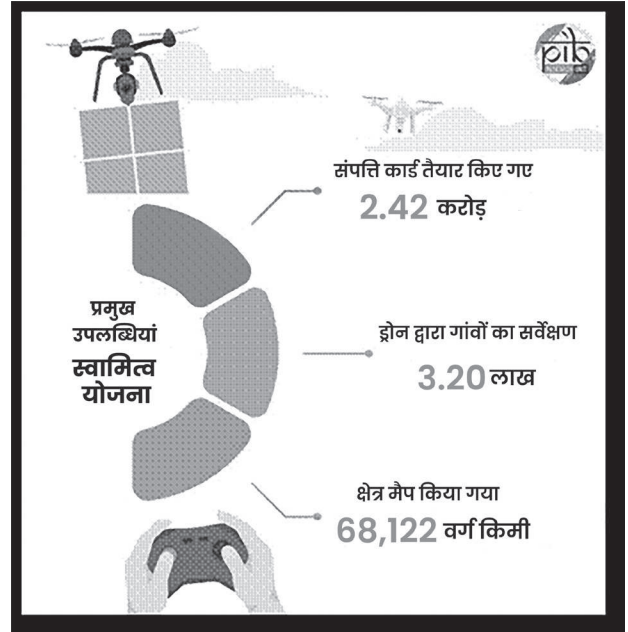
उद्देश्य

- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे ग्राम पंचायतों को उन राज्यों में मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा।
- सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जिसका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है।
- GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी का समर्थन करना।

स्वामित्व योजना के घटक

- निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशनों (सीओआरएस) नेटवर्क की स्थापना: सीओआरएस नेटवर्क ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की स्थापना में सहायता करता है, जो सटीक जियो-रेफरेंसिंग, ग्राउंड टुथिंग और भूमि के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

- **ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण:** ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण विभाग ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके मानचित्रण कर रहा है। यह स्वामित्व संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन और सटीक मानचित्र तैयार करता है। इन मानचित्रों या डेटा के आधार पर, ग्रामीण घरेलू मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पहल:** स्थानीय आबादी को योजना की कार्यप्रणाली और इसके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम।
- **स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग “ग्राम मंच” का संवर्धन:** ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी का समर्थन करने के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/मानचित्रों का लाभ उठाना।
- **ऑनलाइन निगरानी प्रणाली:** गतिविधियों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड की निगरानी की जाती है।
- **परियोजना प्रबंधन:** योजना कार्यान्वयन के साथ क्रमशः मंत्रालय और राज्य का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ।



प्रभाव के व्यापक क्षेत्र

- **समावेशी समाज:** पूरे इतिहास में, विद्वानों और विकास विशेषज्ञों ने ‘संपत्ति अधिकारों तक पहुंच’ को ‘गाँवों में कमज़ोर आबादी के सामाजिक-आर्थिक मानकों में सुधार’ के साथ जोड़ा है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य इसे सक्षम बनाना है।
- **भूमि प्रशासन:** विश्व में भौतिक संपदा के निर्माण के उद्देश्य से किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए भूमि एक आवश्यक संसाधन है। आबादी क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन न होने के कारण भूमि-संघर्ष के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत और दुनिया भर में लाखों लोग भूमि विवादों के प्रभाव से पीड़ित हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों के मूल कारण को संबोधित करना है।
- **संधारणीय आवास:** बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GDPDP) के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले डिजिटल मानचित्र, जिससे स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नदियों, स्ट्रीट लाइटों, सड़कों आदि जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार होता है, जिसके लिए धन का कुशल आवंटन और पहुंच में वृद्धि होती है।

- **आर्थिक विकास:** इसका मुख्य परिणाम लोगों को अपनी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में मुद्रीकृत करने में मदद करना है। इसके अलावा, उन राज्यों में संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करके भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जहाँ इसे लगाया जाता है, जिससे निवेश में वृद्धि होगी और व्यापार करने में आसानी होगी।

निष्कर्ष

स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व को बदल रही है। यह पुरानी चुनौतियों को विकास और सशक्तिकरण के नए अवसरों में बदल देती है। यह योजना विवादों को सुलझाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। यह लोगों को आर्थिक प्रगति के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने में मदद करती है। ड्रोन और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड के साथ, यह नई संभावनाएँ बनाने के बारे में है। स्वामित्व एक सरकारी कार्यक्रम से कहीं अधिक है, यह आत्मनिर्भरता, बेहतर नियोजन और एक मजबूत ग्रामीण भारत की ओर एक कदम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. स्वामित्व योजना का उद्देश्य है:

- कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व अधिकार स्थापित करना।
- ग्रामीण युवाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना।

(q) : 2018

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. स्वामित्व योजना संपत्ति के स्वामित्व को औपचारिक बनाकर ग्रामीण भारत को बदलने का प्रयास करती है। इसके कार्यान्वयन में चुनौतियों और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। [150 शब्द] [10 अंक]

उड़ान योजना

चर्चा में क्यों: अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, एक करोड़ 49 लाख से ज़्यादा यात्रियों को किफ़ायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा योजना उड़ान से लाभ मिला है।

मुख्य विवरण

- टियर-2 और टियर-3 शहरों को एक ऐसे मॉडल का उपयोग करके जोड़ने के लिए जो वित्तीय रूप से समर्थित और बाज़ार द्वारा संचालित दोनों हैं, उड़ान योजना की कल्पना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) 2016 के तहत 10 साल के विज़न के साथ की गई थी।
- **लॉन्च की तारीख:** 21 अक्टूबर, 2016 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) का अनावरण किया, जिसे उड़ान ("उड़े देश का आम नागरिक") के रूप में भी जाना जाता है।
- उड़ान का लक्ष्य लागत को कम करके और सभी के लिए उड़ान की पहुँच बढ़ाकर विमानन को लोकतांत्रिक बनाना है।
- **मूल मंत्रालय:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय

उड़ान योजना का महत्व

- **क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना:** पूरे भारत में कम सेवा वाले और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को चालू करके, उड़ान का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना है।
- **हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना:** हवाई यात्रा को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए परिचालन लागत में कमी और व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) का उपयोग करता है।
- **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना:** यात्रा को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है, जिसके परिणामस्वरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है।
- **रोज़गार सृजन:** विमानन उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करता है।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना:** सामाजिक-आर्थिक एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क में अंतर को कम करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना:** बाज़ार-संचालित रणनीति का उपयोग करके निजी विमानन भागीदारी को बढ़ावा देता है।

उड़ान की उपलब्धियाँ

(2016-2025)

- 1

625 मार्ग चालू किए गए, जो पूरे भारत में 90 हवाई अड्डों (15 हेलीपोर्ट और 2 जल एयरोड्रॉम सहित) को जोड़ते हैं।
- 2

मस्ती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से 1.49 करोड़ से अधिक यात्री लाभान्वित हुए।
- 3

देश भर में 3 लाख उड़ान उड़ानें संचालित की गईं।
- 4

हवाई अड्डे का नेटवर्क 74 (2014) से बढ़कर 159 (2024) हो गया।
- 5

2024: 102 नए मार्ग शुरू किए गए (पूर्वोत्तर में 20 सहित), 2024-25 में 66 जोड़े गए।
- 6

13 मार्च 2025 तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में ₹4,023.37 करोड़ वितरित किए गए।
- 7

क्षेत्रीय व्यापार, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और पर्यटन में वृद्धि, खजुराहो, अमृतसर, अजमेर, देवघर और पूर्वोत्तर भारत जैसे प्रमुख स्थलों के लिए हवाई संपर्क में सुधार।
- 8

फ्लाईविंग, स्टार एयर, इंडियावन एयर और फ्लाईश जैसी क्षेत्रीय एयरलाइनों के उदय में सहायता की।

उड़ान से जुड़ी सेवाएँ

- **उड़ान यात्री कैफ़े:** चेन्नई और कोलकाता के हवाई अड्डों पर उचित कीमत पर बढ़िया खाना परोसने वाले यात्री कैफ़े खोले गए हैं।
- **सीप्लेन संचालन:** देश भर में 50 से ज़्यादा नामित जल निकायों को उड़ान राउंड 5.5 के लिए बोलियाँ जमा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- **उड़ान पहल का नवीनीकरण:** उड़ान पहल को अगले दस वर्षों के दौरान 120 नए गंतव्यों को जोड़ने और अतिरिक्त 4 करोड़ यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को और अधिक किफ़ायती बनाने के लक्ष्य के साथ फिर से डिज़ाइन किया गया है।

- **कृषि उड़ान योजना:** कृषि उड़ान, जिसे किसानों की सहायता करने और कृषि-उत्पादों के मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, हवाई रसद को और अधिक कुशल और किफायती बनाता है, खासकर पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए।
- **हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का विकास:** अगले पाँच वर्षों में, सरकार 50 नए हवाई अड्डे बनाने की योजना बना रही है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत वैश्विक विमानन केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, उड़ान समावेशी विकास, लचीलापन और दूरदर्शी शासन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो एक समय में एक उड़ान के साथ नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. उड़ान योजना, भारत में हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है, लेकिन इसकी सफलता केवल सब्सिडी वाले किराए से कहीं अधिक पर निर्भर करती है। क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में उड़ान योजना के उद्देश्यों, उपलब्धियों और चुनौतियों की आलोचनात्मक जाँच करें। [250 शब्द] [15 अंक]

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (SEED)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (SEED) के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

योजना का उद्देश्य:

- आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से इन समुदायों का उत्थान करते हुए छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य कवरेज और आवास के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करना।

कार्यान्वयन

- यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से चलाई जाएगी।

- लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में पैसा भेजा जाएगा।
- अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसियों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) शामिल हैं।

चार घटक

- विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) के उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना।
- उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
- सामुदायिक स्तर पर आजीविका कार्यक्रमों को बढ़ाना; और
- इन समुदायों में व्यक्तियों के लिए घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

बजटीय आवंटन

- मंत्रालय को इस पहल के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जिसका उपयोग 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वित्तीय वर्षों में किया जाएगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (SEED) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना में लक्षित समुदायों के लिए निःशुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका सहायता और आवास सहायता के प्रावधान शामिल हैं।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों में से हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(C) : 2022

भारत की जन्म दर में गिरावट

चर्चा में क्यों: भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021 ने विभिन्न भारतीय राज्यों में जन्म दर में महत्वपूर्ण बदलाव का खुलासा किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कच्ची जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली जैसे दक्षिणी राज्यों में यह गिरावट बहुत तेज़ी से देखी जा रही है।

मूल अवधारणाएँ

1. अशोधित जन्म दर (सीबीआर)

- परिभाषा: जनसंख्या में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या।
- सूत्र:

$$\text{सीबीआर} = \frac{\text{एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या}}{\text{मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

उदाहरण: यदि किसी राज्य का सीबीआर 19.3 है, तो इसका अर्थ है कि वहां प्रति वर्ष प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 19.3 बच्चे पैदा होते हैं।

2. कुल प्रजनन दर (टीएफआर)

- परिभाषा: यदि वर्तमान जन्म दर जारी रहती है तो एक महिला के जीवनकाल में होने वाले बच्चों की औसत संख्या।
- मुख्य बिंदु: यदि टीएफआर 2.1 के आसपास है, तो इसे प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता कहा जाता है। इस स्तर पर, जनसंख्या का आकार समय के साथ स्थिर हो जाता है।

3. सकल प्रजनन दर (जीआरआर)

- परिभाषा: एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों के दौरान जन्मी बेटियों की औसत संख्या जो प्रजनन आयु तक जीवित रहती हैं और स्वयं बच्चे पैदा करती हैं।
- जीआरआर < 1 का अर्थ है कि समय के साथ जनसंख्या कम होने की संभावना है।

राष्ट्रीय बनाम राज्य रुझान: बढ़ता अंतर

- 2021 में, अखिल भारतीय अशोधित जन्म दर प्रति 1,000 लोगों पर 19.3 जन्म थी।
- 2016 और 2021 के बीच, यह दर औसतन 1.12% प्रति वर्ष घटी।
- लेकिन इसके विपरीत, कुछ राज्यों में बहुत अधिक गिरावट देखी गई:
 - जन्म दर में सबसे तेज़ गिरावट:
 - तमिलनाडु: प्रति वर्ष 2.35% की दर से गिरावट
 - दिल्ली: प्रति वर्ष 2.23% की दर से गिरावट
 - केरल: प्रति वर्ष 2.05% की दर से गिरावट
- ये दरें राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी हैं, जो इन क्षेत्रों में तेजी से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का संकेत देती हैं।

जन्म दर में सबसे धीमी गिरावट वाले राज्य:

- दूसरी ओर, कई राज्यों में जन्म दर में गिरावट काफी धीमी गति से हो रही है:
 - राजस्थान: 0.48%
 - बिहार: 0.86%
 - छत्तीसगढ़ और झारखंड: 0.98%
 - असम और मध्य प्रदेश: 1.05%

➤ पश्चिम बंगाल: 1.08%

➤ उत्तर प्रदेश: 1.09%

- ध्यान दें: दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस अवधि के दौरान जन्म दर वास्तव में बढ़ी है।

एसआरएस क्या है?

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) भारत का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है, जो वार्षिक आयोजित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण आँकड़ों का अनुमान प्रदान करता है जैसे:

- जन्म दर
- मृत्यु दर
- शिशु मृत्यु दर
- कुल प्रजनन दर (TFR)
- सकल प्रजनन दर (GRR)

ये आंकड़े नीति निर्माताओं और योजनाकारों को जनसंख्या के रुझान को समझने और सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं।

दक्षिणी राज्य गिरावट में अग्रणी

- एसआरएस रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र में, जन्म दर में गिरावट की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज थी:
 - आंध्र प्रदेश: 1.26%
 - तेलंगाना: 1.67%
 - कर्नाटक: 1.68%
 - केरल और तमिलनाडु: पहले से ही सबसे तेजी से गिरावट वाले राज्यों में शामिल हैं।
- यह दक्षिणी राज्यों में स्पष्ट जनसांख्यिकीय परिवर्तन को दर्शाता है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण और परिवार नियोजन पहलों ने प्रजनन पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

अन्य राज्यों में भी तीव्र गिरावट देखी जा रही है

- दक्षिणी राज्यों के अलावा, कुछ अन्य राज्यों में भी जन्म दर में औसत से अधिक तेजी से गिरावट देखी गई:
 - महाराष्ट्र: 1.57%
 - गुजरात: 1.24%
 - ओडिशा: 1.34%

- हिमाचल प्रदेश: 1.29%
- हरियाणा: 1.21%
- जम्मू और कश्मीर: 1.47%
- इस बीच, पंजाब की जन्म दर में राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर की दर से गिरावट आई।

पंजीकृत जन्म के बारे में

- नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) 2021 इस तस्वीर में एक और स्तर जोड़ती है। इसने दिखाया कि जन्म दर में धीमी गिरावट वाले कुछ राज्य वास्तव में अधिक पंजीकृत जन्मों की रिपोर्ट कर रहे हैं।
- **जन्म पंजीकरण में वृद्धि वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं:**
 - बिहार
 - राजस्थान
 - उत्तर प्रदेश
 - उत्तराखंड
 - पश्चिम बंगाल
 - अरुणाचल प्रदेश
 - मिजोरम
 - नागालैंड
 - जम्मू और कश्मीर
 - लद्दाख
 - लक्षद्वीप
- इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ राज्यों में बेहतर जन्म पंजीकरण प्रणाली और जनसंख्या वृद्धि एक साथ हो रही है।

प्रजनन संकेतक जन्म दर के रुझान से मेल खाते हैं:

- एसआरएस 2021 ने निम्नलिखित पर भी डेटा प्रकाशित किया:
 - कुल प्रजनन दर (टीएफआर): एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा होने वाली बच्चों की औसत संख्या।
 - सकल प्रजनन दर (जीआरआर): एक महिला द्वारा पैदा होने वाली बेटियों की औसत संख्या जो प्रजनन आयु तक जीवित रहती है।
- आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में टीएफआर और जीआरआर राष्ट्रीय औसत से अधिक है - जिसका अर्थ है कि इन राज्यों में परिवार अभी भी बड़े हैं, जो उनकी उच्च जन्म दर के अनुरूप है।

कुछ राज्यों में तीव्र गिरावट क्यों देखी जा रही है?

- **जन्म दर में तीव्र गिरावट के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी भारत में:**
 - महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि
 - परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच
 - स्वास्थ्य सेवा में सुधार
 - शहरीकरण और आर्थिक विकास
 - विवाह की बढ़ती उम्र
 - कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी
- ये रुझान परिपक्व होती जनसांख्यिकी रूपरेखा को दर्शाते हैं, जहां लोगों के छोटे परिवार चुनने के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है।

निष्कर्ष

- एसआरएस 2021 डेटा भारत की विभाजित जनसांख्यिकीय तस्वीर पेश करता है:
 - एक तरफ, दक्षिणी और कुछ पश्चिमी राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ जन्म दर पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से घट रही है।
 - दूसरी तरफ, उत्तरी और पूर्वी राज्यों में जन्म दर और प्रजनन स्तर उच्च बना हुआ है, जो जनसंख्या दबाव और संसाधन वितरण के मामले में चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है।
- संतुलित विकास, लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और देश के भावी कार्यबल के प्रबंधन के लिए इन पैटर्नों को समझना आवश्यक है

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में जन्म दर और प्रजनन पैटर्न में क्षेत्रीय भिन्नताओं की जांच करें। इन प्रवृत्तियों में कौन से सामाजिक-आर्थिक कारक योगदान करते हैं, और वे भविष्य की नीति नियोजन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

WESP 2025: मध्य-वर्षीय अद्यतन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) ने 'विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2025' का मध्य-वर्षीय अद्यतन प्रकाशित किया।

मुख्य विवरण

- **वैश्विक आर्थिक विकास**
 - आपूर्ति शृंखलाओं पर दबाव पड़ने की संभावना है, उत्पादन लागत बढ़ेगी, और उच्च टैरिफ और व्यापार नीति अनिश्चितता के परिणामस्वरूप कंपनियों कई उद्योगों में निवेश को स्थगित या कम कर सकती हैं।
 - वैश्विक विकास 2024 में 2.9% से 2025 में 2.4% तक धीमा होने की संभावना है, जो जनवरी के अनुमान से 0.4 प्रतिशत अंक की गिरावट है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार**
 - व्यापार वृद्धि के 2024 में 3.3% से 2025 में 1.6% तक गिरने का अनुमान है, वैश्विक वाणिज्य बदल रहा है।
 - कमजोर व्यापारिक व्यापार और धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण परिवहन, पर्यटन और अन्य सेवाओं की मांग धीमी हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निवेश और वित्त**
 - उच्च ब्याज दरों और बजटीय प्रतिबंधों के कारण कमजोर निवेश परिदृश्य के कारण दीर्घकालिक आर्थिक विकास और उत्पादकता जोखिम में है।
 - कमजोर विकासशील देशों को सख्त वित्तीय स्थितियों और आधिकारिक विकास सहायता में कमी की संभावना के परिणामस्वरूप गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- **श्रम बाजार**
 - अधिकांश विकसित और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजार मजबूत बने हुए हैं।
 - हालांकि, धीमी निवेश और कमजोर विकास संभावनाओं का वेतन और रोजगार वृद्धि पर प्रभाव पड़ने की आशंका है, और जनरेटिव एआई के तेजी से बढ़ते चलन से और अधिक उथल-पुथल हो सकती है।

- **मुद्रा स्फीति**
 - जनवरी के पूर्वानुमान की तुलना में, वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति में 0.2 प्रतिशत अंकों की कमी आने की संभावना है, जो 2024 में 4.0% से घटकर 2025 में 3.6% हो जाएगी।
 - भले ही तेल और कुछ अन्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट का रुझान मध्यम प्रभाव डाल सकता है, लेकिन टैरिफ बाधाएं, संभावित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव उपभोक्ता कीमतों को बढ़ा रहे हैं।
- **मौद्रिक और राजकोषीय नीति**
 - जैसे-जैसे व्यापार विवाद और वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है, केंद्रीय बैंकों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
 - धीमी होती वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति के जोखिम को संबोधित करने के लिए, नीति निर्माताओं को भविष्य के समायोजन के समय और दायरे को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।
 - यद्यपि बढ़ती अनिश्चितता निवेश को सीमित करना जारी रखती है, निर्यात राजस्व में गिरावट, विदेशी मुद्रा आय में गिरावट और घरेलू मांग में कमी ऋण प्रबंधन पर और अधिक बोझ डाल रही है।
- **भारत की संभावनाएं**
 - 2025 में 6.3% की अनुमानित वृद्धि के साथ - जो जनवरी के अनुमान से 0.3 प्रतिशत अंक कम है - भारत सबसे तेज विकास दर वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग(यूएन डीईएसए)

- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (यूएन डीईएसए), यूएन सचिवालय के विकास स्तंभ को बनाए रखता है, जिसका नेतृत्व यूएन महासचिव करते हैं।
- न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित, यूएन डीईएसए संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) में विचार-विमर्श का समर्थन करता है, और इन निकायों के निर्णयों के कार्यान्वयन में जल और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर भी सहयोग करता है।
- यूएन डीईएसए सतत विकास का अग्रणी है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का घर है, जहां प्रत्येक लक्ष्य को अपना स्थान मिलता है और जहां सभी हितधारक किसी को पीछे न छोड़ने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
- यूएन डीईएसए हमारे प्रकाशनों और डेटाबेस के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी), आयोगों, मंचों और अन्य निकायों में अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श के लिए हमारे समर्थन के माध्यम से जानकारी का खजाना प्रदान करके देशों को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में 'विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं' रिपोर्ट चर्चा में थी, इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था?

- (a) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग

- (b) विश्व बैंक
(c) विश्व आर्थिक मंच
(d) इनमें से कोई नहीं

(E) 2025

मानव विकास रिपोर्ट, 2025: यूएनडीपी

चर्चा में क्यों: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 2025 के लिए मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) जारी की।

मुख्य विवरण

- **इसका शीर्षक है 'ए मैटर ऑफ चॉइस:** पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई' और यह भविष्य के विकास पर एआई के प्रभाव पर एक नज़र डालता है।
- **आइसलैंड (एचडीआई स्कोर: (0.972)** सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद नॉर्वे और स्विटजरलैंड का स्थान है।
- **दक्षिण सूडान 0.388 स्कोर के साथ 193वें स्थान पर अंतिम स्थान पर है।**
- रिपोर्ट में जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के वर्षों और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों और आय के स्तर में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।

भारत की मानव विकास सूचकांक रैंकिंग

- भारत अपने मानव विकास सूचकांक मूल्य में सुधार करके मध्यम श्रेणी में बना रहा, जो 2022 में 0.676 (133वें स्थान पर) से बढ़कर 2023 में 0.685 (130वें स्थान पर) हो गया।
- भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 1990 से 53% से अधिक बढ़ा है, जो दक्षिण एशिया और वैश्विक औसत दोनों को पार कर गया है।
- भारत के आस-पास के सभी देशों में, चीन (75वें स्थान पर), श्रीलंका (78वें स्थान पर) और भूटान (127वें स्थान पर) भारत से ऊंचे स्थान पर हैं, जबकि बांग्लादेश (130वें स्थान पर) भी बराबरी पर है।
- नेपाल (145वें स्थान पर), म्यांमार (149वें स्थान पर) और पाकिस्तान (168वें स्थान पर) भारत से नीचे हैं।
- **जीवन प्रत्याशा में वृद्धि:** भारत की जीवन प्रत्याशा सूचकांक की स्थापना के बाद से सबसे अधिक हो गई है, जो 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष हो गई है। इस विकास को पोषण अभियान, जननी सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों से सहायता मिली है।
- **शिक्षा में सुधार:** 1990 में 8.2 वर्ष से बढ़कर 2023 में 13 वर्ष हो जाने से स्कूल में बिताए जाने वाले औसत वर्षों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे कानून महत्वपूर्ण रहे हैं।
- **आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन:** भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 1990 में \$2,167 से बढ़कर 2023 में \$9,046 हो गई, जो चार गुना वृद्धि है। 2015-16 और 2019-21 के बीच, 135 मिलियन भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।

उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियाँ

- **राष्ट्रीय आय:** भारत की प्रति व्यक्ति जीएनआई रैंकिंग उसकी एचडीआई रैंकिंग से सात रैंक नीचे है।
- **लैंगिक असमानता:** लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) के अनुसार, भारत 102वें स्थान पर है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रजनन स्वास्थ्य और कार्यबल भागीदारी जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों का संकेत देता है।
- भारत अभी भी मध्यम मानव विकास वर्ग (एचडीआई स्कोर 0.685) में बना हुआ है।

रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशें

- **एआई और मानव विकास:** एचडीआई 2025 का तर्क है कि एआई को मानवीय क्षमताओं को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनका पूरक होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए साहसिक नीतिगत निर्णयों का आह्वान करता है कि एआई-संचालित विकास से सभी लोगों को लाभ मिले।
- रिपोर्ट विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने के लिए समावेशी एआई नीतियों के कार्यान्वयन का आग्रह करती है।
 - एक पूरक अर्थव्यवस्था विकसित करना जहाँ मनुष्य और AI एक साथ काम करते हैं।
 - मानव क्षमता को अनलॉक करने के लिए नवाचार का निर्माण करना।
 - समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना।

निष्कर्ष

भारत ने मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन लैंगिक असमानता और आय असमानता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। रिपोर्ट में समावेशी, मानव-केंद्रित एआई नीतियों पर जोर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी न्यायसंगत और संधारणीय विकास का समर्थन करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में, मानव विकास संकेतकों में भारत की प्रगति की आलोचनात्मक जांच करें। समावेशी और मानव-केंद्रित एआई नीतियाँ मौजूदा विकास अंतराल को कैसे पाट सकती हैं? [250 शब्द [15 अंक]

भारत न्याय रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों: न्याय प्रदान करने के मामले में राज्यों की देश की एकमात्र रैंकिंग भारत न्याय रिपोर्ट (आईजेआर) 2025 के अनुसार, एक भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस में महिलाओं के लिए अपने स्वयं के आरक्षित कोटे को पूरा नहीं किया है।

भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के बारे में

- **भारत न्याय रिपोर्ट (आईजेआर) 2025** एकमात्र व्यापक मालात्मक सूचकांक है, जो विभिन्न राज्यों में संचालित औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को रैंक करने के लिए सरकार के आंकड़ों का उपयोग करता है।
- यह आईजेआर दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और टीआईएसएस-प्रयास के साथ साझेदारी में किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है।

- 2019 में पहली बार प्रकाशित, आईजेआर का चौथा संस्करण सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुलिस, न्यायपालिका, जेलों, कानूनी सहायता और मानवाधिकार आयोगों में बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढाँचे, कार्यभार और विविधता के मालात्मक माप के आधार पर न्याय प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और निरंतर घाटे को ट्रैक करना जारी रखता है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

न्यायतंत्र

- लगातार रिक्तियाँ, कम केस निपटान दर और बढ़ते बकाया औपचारिक न्यायालय प्रणाली को परेशान कर रहे हैं।
- 2024 तक, केसों का संचय पाँच करोड़ के आंकड़े को पार कर गया था - सभी न्यायालय स्तरों पर 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि: यह वृद्धि न्यायिक रिक्तियों, प्रक्रियात्मक अक्षमताओं और प्रत्येक वर्ष नए मामलों की आमद के साथ चल रही चुनौतियों को दर्शाती है।

पुलिस

- राष्ट्रीय स्तर पर, पुलिस-जनसंख्या अनुपात प्रति 100,000 जनसंख्या पर 155 पुलिस कर्मियों पर स्थिर रहा, जो स्वीकृत संख्या 197.5 से काफी कम है।
- यह कमी राज्यों में काफी भिन्न है - प्रति लाख केवल 81 पुलिस कर्मियों के साथ, बिहार इस स्थिति का उदाहरण है।
- **कमी के परिणाम:** जांच में अधिक समय लगता है, अपराध की रोकथाम के प्रयास विफल होते हैं, और सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता होता है।

फॉरेंसिक

- पूरे भारत में, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण और क्षमता काफी भिन्न है, जिससे उनकी दक्षता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों में, राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ पुलिस के सीधे नियंत्रण में काम करती हैं। इस व्यवस्था से फॉरेंसिक विश्लेषण की स्वतंत्रता से समझौता होने का जोखिम है।
- अन्यत्र, फॉरेंसिक सेवाएँ गृह विभाग के अधीन काम करती हैं, जिससे फॉरेंसिक जाँच में कुछ हद तक संस्थागत पृथक्करण सुनिश्चित होता है।
- **क्षमता की कमी:** कई फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ लगातार कम वित्त पोषण, पुराने बुनियादी ढाँचे और कुशल कर्मियों की भारी कमी से पीड़ित हैं।

जेल

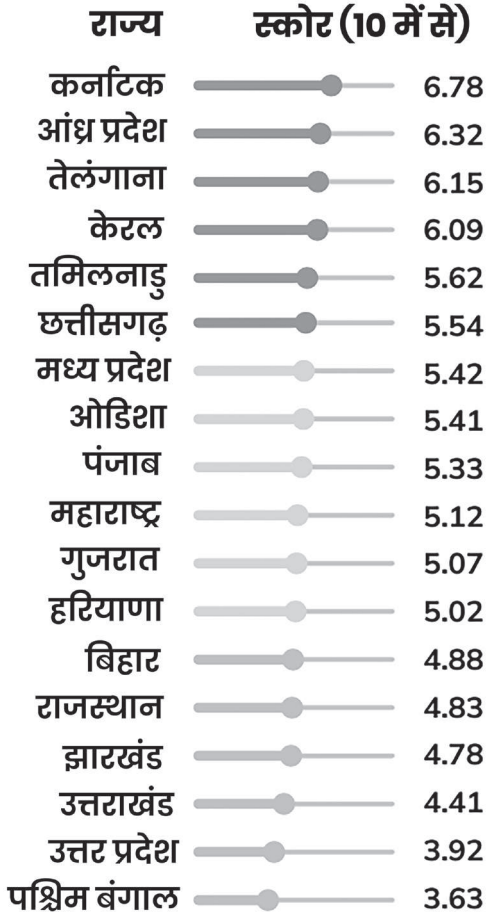
- संशोधित कानून, अनेक न्यायिक निर्देश, जनसंख्या कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और कई राज्यों द्वारा मॉडल जेल मैनुअल 2016 को अपनाने के बावजूद, जेल की स्थिति दयनीय बनी हुई है।
- पिछले दशक में, जेल की आबादी में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। विचाराधीन कैदियों का अनुपात - जांच या परीक्षण पूरा होने का इंतजार कर रहे लोग - 66% से बढ़कर 76% हो गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर, जेलों में औसत भीड़भाड़ 131% है।

कानूनी सहायता

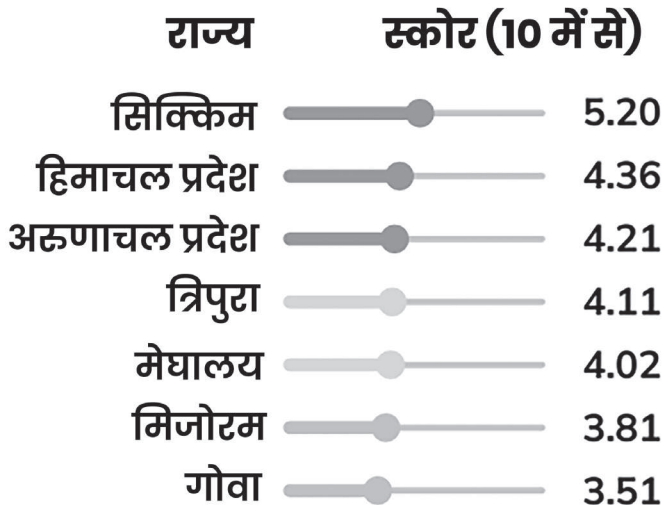
- पिछले दशक में कानूनी सहायता ने विशिष्ट तंत्रों, जैसे कि कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता (एलएडीसी) प्रणाली, जेल क्लिनिक, और राष्ट्रीय लोक अदालतों के लिए समयसीमा और निधियों के सावधानीपूर्वक अंशांकन के लिए समर्थन पर जोर दिया है।
- लक्षित हस्तक्षेपों पर इस फोकस के साथ-साथ व्यापक, समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए संसाधनों में महत्वपूर्ण कमी आई है।

- राज्य मानवाधिकार आयोग
 - भारत न्याय रिपोर्ट 2022 (2023 में प्रकाशित) ने पहली बार राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) की अपने व्यापक जनादेश को प्रभावी बनाने की क्षमता का आकलन किया।
 - दो वर्ष बाद भी, उनकी कार्यप्रणाली में बार-बार यह बात उभर कर सामने आती है कि उनके इच्छित अधिदेश और जमीनी स्तर पर वास्तविक क्षमता के बीच अंतर है।

बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों का प्रदर्शन और रैंकिंग



छोटे राज्यों का प्रदर्शन और रैंकिंग



राष्ट्रीय घाटा

पुलिस

50% देश भर में 10,000 से अधिक फोरेंसिक कर्मचारियों के पद रिक्त

1.25% पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का राष्ट्रीय औसत हिस्सा

0 पुलिस में महिलाओं के लिए अपने स्वयं के आरक्षित कोटे को पूरा करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

जेल

176 200% और उससे अधिक क्षमता वाली जेलें

20 राज्यों/केंद्र शामिल प्रदेशों में 20% से अधिक विचाराधीन केदी 1-3 वर्षों से हिरासत में हैं

25 देश में 5.7 लाख कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक की व्यवस्था है। 25 राज्यों/केंद्र शामिल प्रदेशों ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी है।

कानूनी सहायता

38% 2019 से पैरालीगल स्वयंसेवकों की संख्या में गिरावट

राज्य मानवाधिकार आयोग

4% कुल मामलों में से केवल 10 मामले ही स्वप्रेरणा से शुरू किए जाते हैं।

अच्छी खबर

पुलिस

देश के सभी पुलिस स्टेशनों में से **83%** में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा है

सभी पुलिस स्टेशनों में से **78%** में महिला हेल्पडेस्क हैं

न्यायतंत्र

जिला न्यायपालिका में **38%** महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी

जेल

8 राज्य प्रति महिला चिकित्सा अधिकारी महिला कैदियों के 1:300 मानक को पूरा करते हैं

86% कम से कम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से सुसज्जित जेलों का प्रतिशत

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत न्याय रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
2. 2025 की रिपोर्ट में केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला और सर्वोच्च रैंक वाला राज्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(P) : 2025

विश्व हृदय रिपोर्ट, 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में, विश्व हृदय महासंघ ने विश्व हृदय रिपोर्ट, 2025 प्रकाशित की, जिसमें दुनिया भर में मोटापे में चिंताजनक वृद्धि और हृदय-संवहनी स्वास्थ्य पर इसके बढ़ते प्रभाव पर जोर दिया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **वैश्विक मोटापे के आँकड़े:** 1990 के बाद से, मोटे वयस्कों की संख्या चार गुना बढ़ गई है, जो 2022 तक 878 मिलियन तक पहुँच जाएगी। यदि मौजूदा रुझान जारी रहे तो 2050 तक वैश्विक स्तर पर 25 वर्ष से अधिक आयु के लगभग दो-तिहाई वयस्क अधिक वजन वाले या मोटे हो सकते हैं।
- **मोटापा और बचपन:** 1990 के बाद से, भारत में मोटे बच्चों और किशोरों (5 से 19 वर्ष की आयु) की संख्या में लगभग 3% की वृद्धि हुई है, जिसमें 5.2 मिलियन लड़कियाँ (3%) और 7.3 मिलियन लड़के (4%) मोटे हैं।
- **मोटापा और युवा:** उच्च बीएमआई वाले बच्चों में उनके मध्य वर्षों में हृदय रोग (सीवीडी) विकसित होने की संभावना 40% अधिक होती है।
- **भारत और मोटापा:** एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट बताती है कि 24% भारतीय महिलाएँ और 23% भारतीय पुरुष मोटापे से पीड़ित हैं, जो देश में बढ़ते मोटापे के बोझ में योगदान देता है।
- **भारत में मोटापे और सीवीडी के बीच संबंध:** भारत में, हृदय संबंधी रोग सभी मौतों में से 25% के लिए जिम्मेदार हैं। मोटापा सीवीडी से होने वाली पुरुषों में 4.6% और महिलाओं में 7% मौतों से संबंधित है।
- **आर्थिक प्रभाव:** भारत में मोटापे का आर्थिक प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना है, जो 2019 में सकल घरेलू उत्पाद के 1% से बढ़कर 2060 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% हो जाएगा।

- **गलत सूचना:** समय पर और सफल हस्तक्षेप सामाजिक कलंक, सार्वजनिक गलत धारणाओं और मोटापे को एक पुरानी बीमारी के रूप में स्वीकार करने में विफलता के कारण बाधित होते हैं।

मोटापा क्या है?

- वसा का अत्यधिक या असामान्य निर्माण जो स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाता है उसे मोटापा कहा जाता है।
- ≥ 25 का बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) अधिक वजन को इंगित करता है, और ≥ 30 का बीएमआई मोटापे को इंगित करता है।

मुख्य अनुशंसाएँ

- **प्रणालीगत सुधार:** निदान, देखभाल और निरंतर सहायता तक निष्पक्ष पहुँच की गारंटी देना आवश्यक है।
- **व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया:** सरकारों को न केवल जीवनशैली से संबंधित मोटापे को संबोधित करना चाहिए, बल्कि इसे दीर्घकालिक और बहुक्रियाशील भी मानना चाहिए।
- **नैदानिक सलाह:** मोटापे से संबंधित प्रोटोकॉल को सीवीडी दिशा-निर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए।
- **नीतिगत उपाय:** चीनी से भरे पेय पदार्थों पर कर लगाना, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के लिए सस्तिडी प्रदान करना और जंक फूड के प्रचार को नियंत्रित करना।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य निवारक उपाय:** जोखिम कम करने की तकनीक, प्रारंभिक पहचान और जागरूकता पर केंद्रित। देखभाल वितरण में अंतराल को कम करना और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने वाले वाणिज्यिक दबावों का जवाब देना।

निष्कर्ष

- मोटापा अब सिर्फ जीवनशैली से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है जिसका हृदय संबंधी बीमारियों और बढ़ती आर्थिक लागतों से गहरा संबंध है। विश्व हृदय रिपोर्ट 2025 इस बढ़ते बोझ को कम करने और भावी पीढ़ियों की रक्षा के लिए नीतिगत सुधारों से लेकर निवारक स्वास्थ्य सेवा तक तत्काल, व्यवस्थित कार्रवाई का आग्रह करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

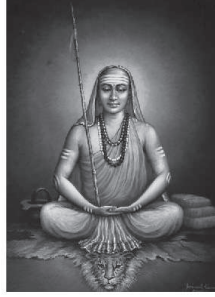
मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मोटापा, भारत में व्यापक स्वास्थ्य और आर्थिक परिणामों के साथ एक मूक महामारी के रूप में उभर रहा है। मोटापे और हृदय संबंधी बीमारियों के बीच संबंध पर चर्चा करें, और मोटापे को एक दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का सुझाव दें। [250 शब्द] [15 अंक]

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

आदि शंकराचार्य

चर्चा में क्यों: तंजावुर जिले के स्वामीमलाई के पास थिम्माकुडी गांव में कारीगरों की एक टीम द्वारा तैयार की गई आदि शंकराचार्य की चार पंचलौह मूर्तियाँ उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तरमण्य ज्योतिर्मठ में स्थापित की जाने वाली हैं।



आदि शंकराचार्य के बारे में

- **जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि**
 - आदि शंकराचार्य का जन्म वर्तमान केरल के एक गाँव कलाडी में शिवगुरु और आर्यम्बा नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण जोड़े के यहाँ हुआ था।
 - यद्यपि ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार उनकी सटीक जन्म तिथि विवादित हैं- अनुमान 507 ईसा पूर्व से 788 ईस्वी - सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत समयरेखा 8वीं शताब्दी ईस्वी है।
- **प्रारंभिक शिक्षा और आध्यात्मिकता के लिए प्रवृत्ति**
 - शंकर ने छोटी उम्र से ही असाधारण बौद्धिक और आध्यात्मिक कौशल का प्रदर्शन किया। पाँच वर्ष की आयु में, उन्होंने अपनी माँ के मार्गदर्शन में वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे सहायक ग्रंथों में महारत हासिल कर ली।
 - आठ वर्ष की आयु में, उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास (मठवासी जीवन) अपना लिया, माता-पिता की सहमति के बिना त्याग को हतोत्साहित करने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी।
- **अद्वैत वेदांत दर्शन की नींव**
 - **अद्वैत वेदांत के सिद्धांत**
 - ◆ **ब्रह्म सत्यम (केवल ब्रह्म ही वास्तविक है):** परम वास्तविकता ब्रह्म है, एक अनंत, अद्वैत चेतना जो समय, स्थान और कारणता से परे है।
 - ◆ **जगत मिथ्या (दुनिया भ्रामक है):** माया (ब्रह्मांडीय भ्रम) द्वारा आकार दिया गया माना जाने वाला ब्रह्मांड, ब्रह्म का एक क्षणिक प्रक्षेपण है, जो वास्तविकता पर आरोपित मृगतृष्णा के समान है।
 - ◆ **जीवो ब्रह्मैव नापरः (व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म है):** आत्मा (व्यक्तिगत स्व) ब्रह्म के समान है, जिसमें अज्ञान (अविद्या) से उत्पन्न स्पष्ट अलगाव है।
- **पवित्र ग्रंथों पर भाष्य:** शंकराचार्य ने प्रमुख हिंदू धर्मग्रंथों पर भाष्य (भाष्य) रचे।
 - **ब्रह्म सूत्र:** बादरायण के सूत्रों की उनकी व्याख्या ने वेदांत को व्यवस्थित किया, यह तर्क देकर द्वैतवाद का खंडन किया कि केवल ब्रह्म ही सभी अस्तित्व का आधार है।
 - **प्रमुख उपनिषद:** बृहदारण्यक, छांदोग्य और दस अन्य उपनिषदों पर भाष्य ने उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को रहस्यपूर्ण बनाया, ब्रह्म के सीमित विवरणों को नकारने के लिए नेति नेति ("यह नहीं, यह नहीं") पर जोर दिया।
- **भगवद् गीता:** उनके विश्लेषण ने गीता को ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से ब्रह्म को साकार करने पर एक संवाद के रूप में तैयार किया।
- **चार मठों की स्थापना:** अद्वैत वेदांत का प्रचार करने और हिंदू प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए, शंकराचार्य ने पूरे भारत में चार मठों (मठवासी केंद्र) की स्थापना की।
 - **श्रृंगेरी शारदा पीठ (कर्नाटक):** यजुर्वेद और ऐतरेय उपनिषद के अध्ययन के लिए समर्पित, यह दक्षिणी केंद्र वैदिक विद्वता का गढ़ बन गया।
 - **ज्योतिर मठ (उत्तराखंड):** हिमालय में स्थित, यह उत्तरी संस्थान ऋग्वेद और बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाओं पर केंद्रित था।
 - **गोवर्धन मठ (ओडिशा):** सामवेद और छांदोग्य उपनिषद से जुड़ा यह पूर्वी केंद्र अनुष्ठान और भक्ति पर जोर देता था।
 - **शारदा पीठम (गुजरात):** अथर्ववेद और मांडूक्य उपनिषद से जुड़ा पश्चिमी मठ, ध्यान और तत्वमीमांसा को एकीकृत करता था।
- **प्रमुख शिक्षाएं और धार्मिक बहसें**
 - **माया और अविद्या की भूमिका:** शंकराचार्य की सत्ता माया पर टिकी हुई है, जो ब्रह्माण्डीय शक्ति है जो ब्रह्म को आच्छादित करती है और अभूतपूर्व दुनिया को दर्शाती है। बौद्ध शून्यता (शून्यता) के विपरीत, माया निषेध नहीं बल्कि ब्रह्म की एक रचनात्मक शक्ति है, जो अद्वैत वास्तविकता के अधीन रहते हुए भी बहुलता को सक्षम बनाती है। अज्ञान (अविद्या) अलगाव के भ्रम को बनाए रखती है, जिसे केवल शास्त्र, चिंतन और गुरु मार्गदर्शन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान (ज्ञान) के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
 - **ज्ञान, कर्म और भक्ति का संश्लेषण:** ज्ञान योग (ज्ञान का मार्ग) को प्राथमिकता देते हुए, शंकराचार्य ने इसे भक्ति और कर्म के साथ सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने उच्च जांच के लिए मन को शुद्ध करने वाले प्रारंभिक अनुशासन के रूप में निष्काम कर्म (निस्वार्थ कर्म) की वकालत की। इसी तरह, शिव और विष्णु जैसे देवताओं के लिए उनके भजन (जैसे शिवानंद लहरी, विष्णु सहस्रनाम भाष्य) भक्ति को द्वैतवादी पूजा से परे जाने और दिव्य आत्मा को पहचानने के साधन के रूप में दर्शाते हैं।
 - **बौद्ध और जैन विचारों का प्रतिवाद:** शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन विद्वानों के साथ जोरदार बहस की, जिसमें उन्होंने वैदिक अधिकार को अस्वीकार करने की आलोचना की। उन्होंने ब्रह्म की स्थायित्व पर जोर देकर बौद्ध धर्म के क्षणिकवाद के सिद्धांत और बहुलवादी यथार्थवाद (अनेकान्तवाद) के जैन सिद्धांत का प्रतिवाद किया, जिसमें उन्होंने इसकी तार्किक असंगतियों को उजागर किया। इन संवादों ने प्रतिद्वंद्वी विद्यालयों से द्वंद्वत्मक तरीकों को शामिल करते हुए वेदांत की सर्वोच्चता को मजबूत किया।
- **विरासत और समकालीन प्रासंगिकता**
 - **हिंदू पहचान का संरक्षण:** शंकराचार्य के युग के दौरान, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने प्रमुखता हासिल की थी, जबकि वैदिक प्रथाओं को निम्नता का सामना करना पड़ा था। उपनिषदिक शिक्षाओं की पुनर्व्याख्या और अनुष्ठानों को मानकीकृत करके, उन्होंने हिंदू धर्म को एक गतिशील, समावेशी परंपरा के रूप में पुनर्जीवित किया। उनके मठ आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में काम करना जारी रखते हैं, जो वैश्विक साधकों को आकर्षित करते हैं।

- **आधुनिक विचार पर प्रभाव:** अद्वैत वेदांत का गैर-द्वैत ढांचा स्वामी विवेकानंद, रमण महर्षि और अरबिंदो जैसे विचारकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है, जिन्होंने इसके सिद्धांतों को अनुकूलित किया। क्वांटम भौतिकी के एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और पश्चिमी आदर्शवाद (जैसे, शोपेनहावर) के साथ इसकी समानताएं इसकी सार्वभौमिक अपील को रेखांकित करती हैं।
- **आलोचनाएँ और अनुकूलन:** यद्यपि आलोचक तर्क देते हैं कि अद्वैत का विश्व-निषेध सामाजिक जुड़ाव को हतोत्साहित करता है, आधुनिक व्याख्याकार इसके नैतिक निहितार्थों पर जोर देते हैं: सभी प्राणियों में ब्रह्म को पहचानना करुणा और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देता है। मठों की चल रही धर्मार्थ गतिविधियाँ - आपदा राहत से लेकर शिक्षा तक - इस एकीकृत दृष्टि को मूर्त रूप देती हैं।

राजा रवि वर्मा

चर्चा में क्यों: नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट ने वर्चुअल टूर के ज़रिए मशहूर चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा को उनकी 172वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।



राजा रवि वर्मा के बारे में

- 29 अप्रैल 1848 को तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के किलिमनूर में जन्मे रवि वर्मा की शाही परिवार, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और समकालीन हस्तियों की पेंटिंग्स की काफ़ी मांग थी और उन्हें काफ़ी सराहा गया।
- बारीकियों पर नज़र, रंगों का शानदार इस्तेमाल और समृद्ध बनावट ने उनकी पेंटिंग्स को एक बेहतरीन आकर दिया, यही वजह है कि आज भी उनकी कृतियाँ अनमोल हैं।
- धार्मिक और पौराणिक आकृतियों के उनके यथार्थवादी चित्रण और व्याख्याएँ जो आज घरों को सुशोभित करती हैं, ने देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भी मोहित और मोहित किया।
- उनकी कृतियाँ चित्रकला से परे थीं; वे अपने समय से कहीं आगे के कवि, विद्वान और दूरदर्शी भी थे।
- उनका उद्देश्य कला को आम आदमी तक पहुँचाना था और इसे सिर्फ़ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित नहीं रखना था।
- अपने कामों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक प्रेस की स्थापना करके, उन्होंने सभी से प्रशंसा और सम्मान की एक मज़बूत नींव सुनिश्चित की।
- एक कलाकार के रूप में, उन्होंने दो शैलियों को एक साथ मिलाया: यूरोपीय कला का तकनीकी और सौंदर्य ज्ञान, और भारतीय कला की भावनात्मक संवेदनशीलता और कहानी कहने की कला।
- उन्हें 1893 में शिकागो में विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपना अब तक का प्रसिद्ध भाषण दिया। रवि वर्मा ने वहाँ अपनी दस पेंटिंग प्रदर्शित कीं।
- 1894 में, उन्होंने रवि वर्मा फाइन आर्ट्स लिथोग्राफ़िक प्रेस की स्थापना की। इसने भारत में रंगीन लिथोग्राफ़ के प्रिंट आंदोलन की शुरुआत की।
- **राजा रवि वर्मा का प्रभाव**
 - पिछले कुछ वर्षों में, हममें से कई लोग भूल गए हैं कि राजा रवि वर्मा ने हमारे जीवन को किस तरह से सूक्ष्म लेकिन परिभाषित तरीकों से प्रभावित किया है।
 - देवी-देवताओं की उनकी दृश्य छवियाँ ने, जिन्हें दिव्य श्रद्धा प्राप्त हुई, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
 - इन्हें भारतीय कॉमिक पुस्तकों, मंदिर वास्तुकला, आभूषण, वस्त्र और चीनी मिट्टी की वस्तुओं पर उनके प्रभाव से जोड़ा जा सकता है।

राजा रवि वर्मा की कृतियाँ

- राजा रवि वर्मा की कृतियाँ भारत भर में राजा रवि वर्मा प्रेस और अन्य द्वारा पेंटिंग, पोर्ट्रेट और कृतियों के रूप में सूचीबद्ध हैं।
- उनकी दृष्टि ने भारतीय परंपरा और शास्त्रीय यूरोपीय तकनीक को मिलाकर भारतीय कला के लिए एक नई पहचान और कद बनाने में मदद की।
- **उदाहरण**
 - दमयंती
 - यशोदा कृष्ण
 - कोक्रेट
 - हनुमान का प्रवचन
 - राधा और कृष्ण
 - द रेवेरिए

पंचलौह मूर्तियाँ

- भारत की विविध और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध सांस्कृतिक ताने-बाने में पंचलोहा मूर्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है।
- सदियों से, इन पवित्र कलाकृतियों को उनकी अनूठी रचना और गहन आध्यात्मिक महत्व के लिए सम्मानित किया जाता रहा है।
- पंचलौह शब्द संस्कृत के शब्दों पंच (जिसका अर्थ है पाँच) और लौह (जिसका अर्थ है धातु) से लिया गया है।
- इन मूर्तियों को पाँच धातुओं के एक विशेष मिश्रण का उपयोग करके ढाला जाता है, जो उन्हें कलात्मक शिल्प कौशल और दिव्य अवतार का एक उल्लेखनीय प्रतीक बनाता है।
- पाँच धातुएँ – पंचलौह मूर्तियों की संरचना में आमतौर पर पाँच प्राथमिक धातुएँ शामिल होती हैं: सोना, चाँदी, तांबा, जस्ता और लोहा। प्रत्येक धातु को उसके विशिष्ट गुणों के लिए चुना जाता है, और सटीक संयोजन को एक प्राचीन कीमिया सूत्र माना जाता है। सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाने के लिए प्रत्येक धातु का अनुपात सावधानी से संतुलित किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें

	मठ	अवस्थिति
1	श्रृंगेरी शारदा पीठम	तमिलनाडु
2	ज्योतिर्मठ	उत्तराखंड
3	गोवर्धन मठ	गुजरात
4	शारदा पीठम	ओडिशा

उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

(C) २२५५ (D) २२६६

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राजा रवि वर्मा के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1894 में, उन्होंने रवि वर्मा फाइन आर्ट्स लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की।
2. उन्होंने यूरोपीय और भारतीय कला को एक साथ मिलाया।
3. उनके काम विशेष रूप से चित्रकला पर केंद्रित थे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(T 214 I 224) (Q) :224

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय कला परिदृश्य में राजा रवि वर्मा के योगदान को स्पष्ट करें। [150 शब्द] [10 अंक]

राजे रघुजी भोंसले प्रथम

चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में मराठा योद्धा राजे रघुजी भोंसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपये में वापस प्राप्त किया।

तलवार के बारे में

- बास्केट-हिल्ट तलवार में यूरोपीय शैली की एकधारी (सिंगल-एज्ड) तलवार होती है, जो थोड़ी मुड़ी हुई होती है, और उसमें दो फुलर होते हैं — ये ऐसे खांचे या नालियाँ होती हैं जो तलवार की पूरी लंबाई में बनी होती हैं।
- तलवार की पीठ (स्पाइन) पर देवनागरी लिपि में एक शिलालेख स्वर्ण जड़ाई के साथ उकेरा गया है। यह शिलालेख कहता है: “श्रीमंत रघुजी भोंसले सेना साहेब सूबाह फिरंग”, जो तलवार के औपचारिक (सेरेमोनियल) स्वरूप का संकेत देता है।
- ‘सेना साहेब सूबाह’ मराठा साम्राज्य से जुड़ी एक उच्च सैन्य रैंक की उपाधि थी, जिसे आमतौर पर सतारा के छत्रपतियों द्वारा प्रदान की जाती थी। उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक तलवार और एक लबादा भी मिलता था।
- यह विशेष तलवार संभवतः छत्रपति शाहू महाराज द्वारा रघुजी राजे भोंसले को उपहार स्वरूप दी गई थी, जिन्हें सेना साहेब सूबाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
- तलवार भारत से कैसे बाहर आई?**
 - 1817 में सीताबर्दी के युद्ध के बाद, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर भोंसले को हराया था, अंग्रेजों ने भोंसले के खजाने को लूट लिया, अमूल्य आभूषण और हथियार जब्त कर लिए।
 - यह तलवार उस युद्ध लूट का हिस्सा हो सकती है या युद्ध के बाद अंग्रेजों को भेंट किया गया एक उपहार भी हो सकता है।



नागपुर भोंसले के बारे में

- नागपुर भोंसले परिवार ने पेशवा, होल्कर, गायकवाड़ और सिंधिया परिवारों की तरह मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- यह परिवार मराठों के शाही या क्षत्रिय कुलों में से एक था, और खुद को उदयपुर के सिसोदिया राजपूतों का वंशज मानता था।
- नागपुर के भोंसले हिंगणीकर के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उनके पूर्वजों में से एक ने वर्तमान पुणे जिले में हिंगानी के पास बेराडी गांव का पुनर्वास किया था।
- शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, उनका अंतिम संस्कार संभाजी भोंसले ने किया था, क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे।

रघुजी राजे भोंसले प्रथम के बारे में

- रघुजी भोंसले प्रथम, 18वीं सदी के मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनकी शक्ति पारिवारिक संघर्ष और रणनीतिक गठबंधन दोनों से आकार लेती थी।
- 1728 में छत्रपति शाहू के समर्थन से, रघुजी भोंसले ने अपने चाचा कान्होजी का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया और सत्ता की विरासत बनाई, नई उपाधियाँ, भूमि और बरार और गोंडवाना में कर एकत्र करने का अधिकार अर्जित किया।
- 1730 में भाम की घेराबंदी के बाद उनकी निर्णायक जीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उनका नेतृत्व सुरक्षित हो गया और नागपुर में भोंसले राजवंश के उदय की नींव रखी गई।
- ओडिशा पर नियंत्रण:** 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब मुगल सत्ता ढह गई और मराठा शक्ति का विस्तार हुआ, रघुजी भोंसले प्रथम 1751 में नवाब अलीवर्दी खान के साथ संधि के बाद ओडिशा को मराठा शासन के अधीन लाने में प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, जिसने इस क्षेत्र और पुरी में जगन्नाथ मंदिर पर मराठा प्रशासन की शुरुआत की।
- श्री जगन्नाथ मंदिर को पुनर्जीवित करना:** रघुजी भोंसले प्रथम ने 1751 में ओडिशा पर नियंत्रण करने के बाद, श्री जगन्नाथ मंदिर की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मुगल शासन के तहत सुस्त पड़ गई थी।
 - उन्होंने पुजारियों की नियुक्ति की, दैनिक प्रसाद को फिर से शुरू किया, मंदिर के रखरखाव को सुनिश्चित किया, और उदार दान दिए- जिसमें उनकी मां द्वारा स्थापित मोहन भोग भी शामिल था- और इसके समर्थन के लिए 27,000 रुपये (सताई हजार महल) का भू-राजस्व आवंटित किया।
 - तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए, रघुजी भोंसले ने 22 से अधिक धर्मशालाएँ बनवाईं, पूरी भव्यता के साथ यात्रा का संचालन करने के लिए सालाना 20,000 रुपये खर्च किए, अन्नछत्र दान योजना शुरू की और पुरी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों का विकास किया, मंदिर की पवित्रता को बहाल किया और इसे फिर से हिंदू पूजा के लिए एक जीवंत केंद्र बना दिया।
- रघुजी भोंसले प्रथम ने मराठा साम्राज्य का विस्तार ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक किया। उन्होंने 1745 और 1755 तक बंगाल में महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राजे रघुजी भोंसले प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उन्होंने ओडिशा को मराठा शासन के अधीन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्री जगन्नाथ मंदिर को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2. उनकी तलवार पर देवनागरी लिपि में एक शिलालेख है जो इसकी औपचारिक प्रकृति का सुझाव देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(c) : 2022

महाराणा प्रताप

चर्चा में क्यों: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई, 2025 को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्य विवरण

- महाराणा प्रताप भारत के एक बहादुर राजपूत राजा थे, जिन्होंने 35 वर्षों तक मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए।
- वे मेवाड़ के 13वें महाराणा और सिसोदिया राजवंश के सदस्य थे।
- वे अपने साहस और आत्मसमर्पण से इनकार करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे वे कई लोगों के लिए प्रतिरोध और गर्व का प्रतीक बन गए हैं।



जन्म और प्रारंभिक जीवन

- 9 मई, 1540 को कुंभलगढ़, मेवाड़ (आधुनिक राजस्थान) में जन्मे।
- सिसोदिया के राजपूत वंश से संबंधित थे।
- रानी जीवंत कण्वा और महाराणा उदय सिंह द्वितीय के पुत्र।
- उन्होंने 1572 में 32 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली।
- उनके राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी।

मुगलों की चुनौतियाँ

- उन्होंने अकबर की विस्तारवादी मुगल नीतियों का सामना किया और स्वतंत्र रहे तथा मुगल आधिपत्य के अधीन होने से इनकार कर दिया।
- महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष हल्दीघाटी का युद्ध (1576) था, जो राजा मान सिंह की मुगल सेना के विरुद्ध था।
- संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने असाधारण वीरता दिखाई।
- हालांकि यह स्पष्ट जीत नहीं थी, लेकिन यह उनके प्रतिरोध का प्रतीक बन गई।
- हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनके अनुयायी अरावली पहाड़ियों पर चले गए।
- उन्होंने जंगल में रहते हुए मुगलों के विरुद्ध अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा।

हड़ता और संघर्ष

- महाराणा प्रताप के शासनकाल की विशेषता मुगलों के विरुद्ध निरंतर लड़ाई थी।
- अनेक बाधाओं और संघर्षों के बावजूद, वे अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए समर्पित रहे।
- 29 जनवरी, 1597 को मेवाड़ के चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई।

निष्कर्ष

महाराणा प्रताप वीरता, देशभक्ति और साम्राज्यवादी वर्चस्व के खिलाफ अडिग प्रतिरोध के एक चिरस्थायी प्रतीक बने हुए हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने झुकने से उनके हृढ़ इनकार ने उन्हें राजपूत गौरव और स्वाभिमान का एक शाश्वत प्रतीक बना दिया है। उनका जीवन पूरे भारत में साहस और बलिदान की भावना को प्रेरित करता है।

डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी 121वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की।



मुख्य विवरण

- भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त, 1974 से लेकर 11 फरवरी, 1977 को अपनी मृत्यु तक पद पर रहे।

प्रारंभिक जीवन

- अहमद का जन्म 13 मई, 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था और देश के प्रति उनके समर्पण का भारतीय राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव रहा।
- अहमद ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सरकारी हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की।
- इसके बाद वे दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज गए, जहाँ उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए, जहाँ उन्हें इनर टेम्पल से लंदन बार में बुलाया गया।

राजनीतिक करियर

- उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत की।
- वे महात्मा गांधी के समर्थक बन गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए।
- उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।
- स्वतंत्रता के बाद अहमद ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किया।
- वे 1952 में राज्यसभा के लिए और उसके बाद 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए।
- उन्होंने खाद्य और कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून जैसे विभिन्न विभागों को संभाला।
- अपने राष्ट्रपति पद के दौरान, उन्होंने 1975 में प्रधानमंत्री गांधी के साथ बैठक के बाद आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद क्षणों में से एक था।
- फखरुद्दीन अली अहमद का 11 फरवरी, 1977 को पद पर रहते हुए निधन हो गया, वे पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे भारतीय राष्ट्रपति थे।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति मुर्मू की आज की श्रद्धांजलि भारत के कानूनी, राजनीतिक और स्वतंत्रता आंदोलनों में फखरुद्दीन अली अहमद के योगदान की याद दिलाती है।

WAVES – वैश्विक मंच के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना

परिचय

1 से 4 मई, 2025 तक मुंबई में आयोजित पहला विश्व ऑडियो दृश्य-श्रव्य/विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) भारत को वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे-जैसे डिजिटल तकनीक वैश्विक मीडिया और मनोरंजन (M&E) को नया आकार दे रही है, भारत एक प्रमुख उपभोक्ता से वैश्विक निर्माता, नवोन्मेषक और सांस्कृतिक प्रभावक बनने की ओर बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री का विजन और घोषणाएं

- ‘मन की बात’ (29 दिसंबर, 2024):
 - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WAVES की घोषणा की।
 - भारत की रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए बॉलीवुड, क्षेत्रीय सिनेमा, एनीमेशन, गेमिंग, टीवी और मनोरंजन तकनीक से जुड़े हितधारकों को आमंत्रित किया।
 - सहयोगी संवाद और अवसर साझा करने के लिए एक वैश्विक क्रिएटर फोरम का प्रस्ताव रखा।
- स्वतंत्रता दिवस संबोधन (2024)
 - गेमिंग और एनिमेशन में भारत की नेतृत्व क्षमता पर जोर दिया गया।
 - गेम डेवलपमेंट के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत और साहित्य का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया गया।
 - भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के विजन के हिस्से के रूप में क्रिएटर अर्थव्यवस्था में युवाओं के नेतृत्व वाली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया।
- राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन (8 अप्रैल, 2025):
 - ‘भारत में सृजन करो, विश्व के लिए सृजन करो’ के मंत्र को सुदृढ़ किया।
 - भारतीय कलाकारों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया और वैश्विक रचनाकारों को भारत आमंत्रित किया।
 - रचनात्मक आंदोलन में युवाओं की भागीदारी का आग्रह किया।

WAVES: उद्देश्य और संरचना

WAVES को एक वैश्विक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है:

- सीमा पार सहयोग और नवाचार।
- सिनेमा, ओटीटी, एनीमेशन, गेमिंग और इमर्सिव कंटेंट (एआर/वीआर) में ज्ञान साझा करना।
- पूर्वी और पश्चिमी रचनात्मक परंपराओं को जोड़ना।
- रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना।

मूलभूत प्रकार्य:

- रचनात्मक उद्यमियों को सशक्त बनाना।
- डिजिटल सामग्री निर्माताओं का समर्थन करना।
- स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक बाजारों से जोड़ना।

मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत एक उभरती हुई शक्ति है

भारत के उत्थान को निम्नलिखित से समर्थन प्राप्त है:

- सांस्कृतिक पूंजी: समृद्ध कहानी कहने की कला, विविध क्षेत्रीय आख्यान।
- जनसांख्यिकीय लाभ: युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी।
- तकनीकी ताकत: उभरता हुआ डिजिटल बुनियादी ढांचा



WAVES के स्तंभ:

- सिनेमा और सीरीज:
 - अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सहयोग को बढ़ावा देता है।
 - सह-निर्माण और क्षेत्रीय सिनेमा के वैश्विक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता है।
- AVGC-XR (एनीमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, विस्तारित वास्तविकता):
 - भारत को प्रतिभा और आउटसोर्सिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है।
 - AR/VR जैसी इमर्सिव तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देता है।
- ओटीटी और डिजिटल मीडिया:
 - नए ज़माने की कहानी कहने और डिजिटल प्लेटफॉर्म साझेदारी को बढ़ावा देता है।
 - वैश्विक पहुंच के लिए मुद्रांतरण मॉडल पर ध्यान केंद्रित करता है।
- संगीत और लाइव मनोरंजन:
 - भारत की संगीत परंपराओं पर प्रकाश डालता है।
 - वैश्विक सहयोग और लाइव कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है।

भारत और ऑरेंज अर्थव्यवस्था

- **परिभाषा:** ऑरेंज अर्थव्यवस्था में रचनात्मकता, सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक संपदा पर आधारित क्षेत्र शामिल हैं।
- **भारत का योगदान:**
 - एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और युवा-संचालित रचनात्मकता।
 - क्षेत्रीय सामग्री और स्थानीय रचनाकारों का उदय।
 - सामग्री उपभोक्ता से वैश्विक सामग्री निर्माता तक का संक्रमण।
- **शामिल क्षेत्र:**
 - सिनेमा, ओटीटी, गेमिंग, एनीमेशन, कॉमिक्स, इमर्सिवमीडिया।

नीति समर्थन और बुनियादी ढांचा पहल

- **सरकारी सुधार:**
 - विदेशी निवेश मानदंडों का सरलीकरण।
 - एकल खिड़की निकासी प्रणाली की शुरुआत।
 - उत्पादन और AVGC निर्यात के लिए प्रोत्साहन।
- **प्रमुख संस्थान और पहल:**
 - **AVGC-XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई):**
 - ◆ मुंबई में स्थित।
 - ◆ कौशल, क्षमता निर्माण और इमर्सिव तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - **कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र:**
 - ◆ प्रतिभा विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करना।
- **मंत्रिस्तरीय समर्थन:**
 - **अश्विनी वैष्णव (केन्द्रीय मंत्री):**
 - ◆ WAVES को “गेम-चेंजर” बताया।
 - ◆ M&E सेक्टर के लिए मजबूत भौतिक, डिजिटल और संस्थागत बुनियादी ढांचे की वकालत की।

WAVES का रणनीतिक प्रभाव

- फिल्मों, संगीत और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है।
- सांस्कृतिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण को सुगम बनाता है।
- रोजगार, निर्यात और नवाचार को उत्प्रेरित करता है।
- वैश्विक रचनात्मक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक केंद्रीय नोड के रूप में स्थापित करता है।

निष्कर्ष

WAVES एक शिखर सम्मेलन से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है - यह एक परिवर्तनकारी मंच है जो भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक महाशक्ति बनने की आकांक्षाओं के साथ संरेखित है। भारत की कहानी कहने की विरासत, युवा ऊर्जा और डिजिटल गतिशीलता का उपयोग करके, WAVES स्थायी रचनात्मक उद्योगों के निर्माण और भारत को रचनात्मक अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। ऐसी दुनिया में जहाँ रचनात्मकता मुद्रा है, WAVES भारत का अगला बड़ा सांस्कृतिक निर्यात इंजन है।

भारत द्वारा विश्व की रचनात्मक क्रांति का नेतृत्व

परिचय: भारत की कहानी कहने की विरासत

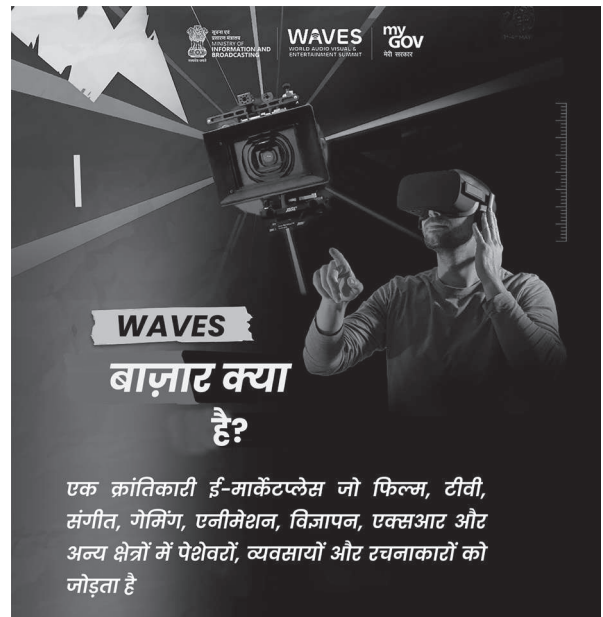
- भारत लंबे समय से कहानी कहने में अग्रणी रहा है - रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य साहित्य से लेकर लोककथाओं और जीवन शैली को दर्शाने वाली प्राचीन मंदिरों की जटिल मूर्तियों तक।
- कहानी कहने के सार ने भारत की विविध संस्कृतियों को एकजुट किया है और आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में वैश्विक दर्शकों को जोड़ना जारी रखा है।
- 21वीं सदी में, कहानी कहना मीडिया और मनोरंजन का आधार है - रील, पॉडकास्ट, ब्लॉग, कॉमिक्स, इंटरैक्टिव गेम और बहुत कुछ के माध्यम से - जो भारत को वैश्विक रचनात्मक क्रांति में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करता है।

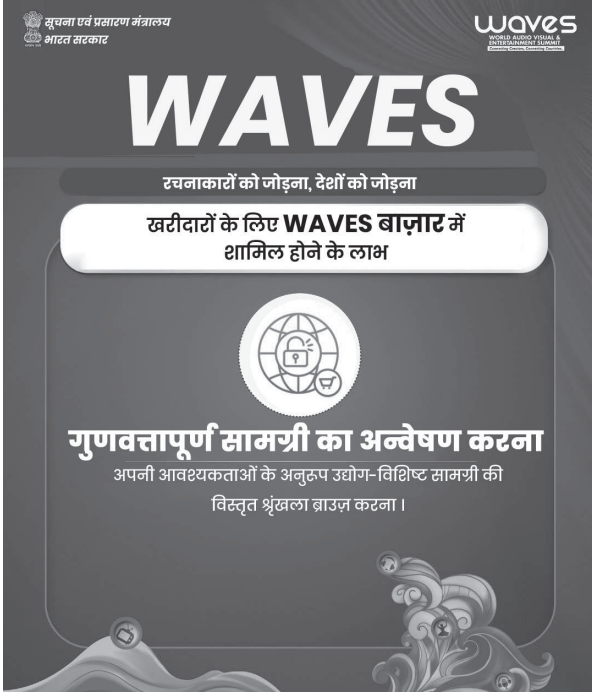
WAVES 2025: एक वैश्विक रचनात्मक आंदोलन

- मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वैश्विक केंद्र बनने के लिए भारत की प्रमुख पहल है।
- **इसकी आकांक्षा है:**
 - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना के तहत वैश्विक रचनाकारों को एकजुट करना।
 - भारत को एक रचनात्मक केंद्र से वैश्विक रचनात्मक नेता में बदलना।
 - रचनाकारों को पहचान, सहयोग और मुद्राकरण के लिए एक मंच प्रदान करना।

भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति का निर्माण

- **वैश्विक सहभागिता:**
 - भारत ने अपने दूतावासों के माध्यम से 100 से अधिक देशों तक पहुंचकर रचनाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं को WAVES में आमंत्रित किया।
 - इसका उद्देश्य दावोस (WEF) और कान्स (फिल्म महोत्सव) जैसे वैश्विक मॉडलों का अनुकरण करना और उनसे आगे निकलना है।
- **रणनीतिक सॉफ्ट पावर के रूप में सांस्कृतिक पूंजी:**
 - प्राचीन और आधुनिक कहानियाँ सीमाओं के पार गूंजती हैं।
 - भारत की बहुभाषी, बहु-जातीय कहानियों में वैश्विक आकर्षण और गहराई है।





- लाइव पिचिंग की सुविधा देता है, M&E में उद्यमशीलता के विकास को बढ़ावा देता है।

रचनात्मक नेतृत्व को समर्थन देने के लिए नीति और बुनियादी ढांचा

- भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), मुंबई के लिए ₹391.15 करोड़ का आवंटन
 - आईआईटी और आईआईएम पर आधारित।
 - एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविकता (AVGC-XR) पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - आईपी निर्माण, नवाचार और कौशल विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
- 1 बिलियन डॉलर का क्रिएटर फंड:
 - सामग्री निर्माताओं को पूंजी, कौशल उन्नयन और वैश्विक पहुंच के साथ सशक्त बनाता है।
 - उत्पादन को बढ़ाने, गुणवत्ता बढ़ाने और तकनीकी उन्नति का समर्थन करता है।

ऑरेंज अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति

- ऑरेंज अर्थव्यवस्था परिभाषित:
 - इसमें रचनात्मकता, संस्कृति और आईपी द्वारा संचालित क्षेत्र शामिल हैं - फिल्म, एनीमेशन, गेमिंग, संगीत, डिजाइन और मीडिया।
- भारत के सामरिक लाभ:
 - युवा-संचालित जनसांख्यिकीय लाभांश।
 - भाषाओं और क्षेत्रों में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत।
 - तीव्र डिजिटल परिवर्तन और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र।
- वैश्विक बाजार की संभावना
 - वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के 2029 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
 - भारत एफडीआई अनुकूल नीतियों, सह-उत्पादन और व्यापार सुविधा के माध्यम से महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है।

वैश्विक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में WAVES

- वैश्विक मीडिया संवाद:
 - आम चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत को सुगम बनाता है।
 - सार्थक कहानी सुनाने के माध्यम से शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देता है।
- स्वस्थ मनोरंजन को बढ़ावा देना:
 - सामाजिक रूप से प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करता है जो उत्थान और एकजुटता प्रदान करता है।
 - वैश्विक रचनाकारों के बीच प्रतिस्पर्धा पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष: भारत एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में

- WAVES 2025 सिर्फ एक शिखर सम्मेलन नहीं है - यह एक आंदोलन है।
- यह भारत को रचनात्मक और ऑरेंज अर्थव्यवस्था की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करता है।
- रचनाकारों को सशक्त बनाकर, प्रौद्योगिकी को अपनाकर और परंपरा का सम्मान करके, भारत वैश्विक रचनात्मक क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।
- WAVES स्वामी विवेकानंद की वैश्विक सांस्कृतिक पहुंच की विरासत को आगे बढ़ाता है, यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय कहानियाँ दुनिया को प्रेरित करें, स्वस्थ करें और एकजुट करें।

रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी का सम्मिश्रण

- डिजिटल युग में कहानी सुनाना:
 - आधुनिक सामग्री (एआर/वीआर/एक्सआर, एआई-एन्हांस्ड एनिमेशन) भारतीय लोकाचार के साथ इमर्सिव अनुभवों को जोड़ती है।
 - हाई-टेक स्टोरीटेलिंग अब पारंपरिक कथा कला की गहराई से मेल खाती है।
- प्रभावशाली कथाएँ:
 - भारतीय रचनाकारों के पास संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को सूक्ष्मता से संबोधित करने का सिद्ध रिकॉर्ड है।
 - वैश्विक प्रासंगिकता पारंपरिक ज्ञान को समकालीन चिंताओं के साथ मिलाने में निहित है।

सृजनकर्ता अर्थव्यवस्था उत्प्रेरक के रूप में WAVES

- डिजिटल समावेशिता और लोकतंत्रीकरण:
 - WAVES ग्रामीण, अर्ध-शहरी और वंचित क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सशक्त बनाता है।
 - कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण सत्र और नेटवर्किंग कार्यक्रम डिजिटल विभाजन को पाटते हैं।
- क्रिएटोस्फीयर टैलेंट ज़ोन:
 - पूरे भारत से 800 से ज़्यादा क्रिएटर्स को चुनता और उनका मार्गदर्शन करता है।
 - गेमिंग, कॉमिक्स, ब्रॉडकास्टिंग, म्यूज़िक, एनिमेशन और दूसरे क्षेत्रों से पेशेवर निकाय प्रतिभाओं को शॉर्टलिस्ट करते हैं।
 - प्रतिभागियों को इंडस्ट्री मेंटरशिप और फंड सुविधा सहायता मिलती है।
- WAVES बाज़ार:
 - रचनाकारों के लिए अपने आईपी-संरक्षित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बाज़ार।
 - प्रमुख मनोरंजन कंपनियाँ प्रतिभा और नवाचारों की खोज में भाग लेती हैं।
- वेवएक्सीलरेटर:
 - स्टार्टअप को निवेशकों और सलाहकारों से जोड़ता है।

भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से एमएसएमई को सशक्त बनाना

परिचय

भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इसकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक का योगदान करते हैं और 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था ज्ञान-आधारित, डिजिटल-प्रथम पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित होती है, एमएसएमई को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, संधारणीय और लचीले उद्यमों में बदलने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यह दस्तावेज़ उन बहुआयामी तरीकों की खोज करता है जिनसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप भारत में एमएसएमई को पारंपरिक बाधाओं को दूर करने और समावेशी और संधारणीय विकास के चालक के रूप में उभरने के लिए सशक्त बना रहे हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्व:

- **आर्थिक योगदान:** भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ~30% और निर्यात में 48% का योगदान।
- **रोजगार सृजनकर्ता:** कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोजक।
- **उद्यमों की विविधता:** विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं, कृषि प्रौद्योगिकी और रचनात्मक उद्योगों में फैली हुई है।
- **क्षेत्रीय विकास:** अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को विकेंद्रीकृत करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण।

भारतीय एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ:

- वित्त तक सीमित पहुंच
- उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास का अभाव
- कम उत्पादकता और परिचालन अक्षमताएं
- कौशल और प्रतिभा की कमी
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में कम एकीकरण
- अनुपालन और विनियामक बाधाएं

एमएसएमई सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों में प्रक्रिया नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, लागत दक्षता और गुणवत्ता आश्वासन को सक्षम करके इन चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है। वे निम्नलिखित रणनीतिक मार्गों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता, मापनीयता और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं:

(i) प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और नवाचार समर्थन

- **एमएसएमई नवाचार योजना (एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत विलयित योजनाएं):**
 - **घटक:** इनक्यूबेशन, डिज़ाइन, आईपीआर सहायता।

- **उद्देश्य:** बिजनेस इनक्यूबेटर और स्टार्टअप को सहायता के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना।

- **डीएसटी और बीआईआरएसी (बायोटेक इन्निशियेशन ग्रांट) के तहत प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई):**

- सीड फंडिंग, मेंटरिंग और लैब एक्सेस प्रदान करना।
- डीप-टेक और बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना।

(ii) डिजिटल परिवर्तन और उद्योग 4.0 अपनाना

- **समर्थ (स्मार्ट एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग एवं रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब):**

- AI/ML, IoT, एडिटिव मैनुफैक्चरिंग सहित उद्योग 4.0 को अपनाना।
- स्मार्ट कारखानों और लीन उत्पादन को बढ़ावा देना है।

- **डिजिटल एमएसएमई योजना:**

- क्लाउड-आधारित ईआरपी, सीआरएम और साइबर सुरक्षा उपकरणों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
- लागत कम करता है और उत्पादकता बढ़ाता है।

- **उद्योग 4.0 केंद्र (C4i4) प्रयोगशालाएं:**

- एमएसएमई के लिए I4.0 प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी।

(iii) अनुसंधान-उद्योग सहयोग मंच

- **एमएसएमई-प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (टीडीसी) नेटवर्क:**

- 18 केंद्र डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग और कौशल विकास सहायता प्रदान करते हैं।

- **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर):**

- एमएसएमई को किफायती, स्केलेबल प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस देना।
- स्वच्छ ऊर्जा, कृषि-तकनीक, प्रक्रिया पुनर्रचना का समर्थन करता है।

- **तकनीकी शिक्षा-उद्योग इंटरफेस सेल:**

- इंजीनियरिंग कॉलेजों और एमएसएमई के बीच सहयोग को सुगम बनाना।
- अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा इंटरशिप मॉडल को बढ़ावा देना।

(iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन

- **ऋण संबद्ध पूंजी सस्सिडी योजना (सीएलसीएसएस):**

- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 15% पूंजी सस्सिडी।

- **ZED (शून्य दोष शून्य प्रभाव) प्रमाणन:**

- लीन विनिर्माण, गुणवत्ता आश्वासन और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना है।


- **अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन (आईएसओ, सीई, आदि) के लिए समर्थन:**

- एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाया गया।


(v) संधारणीय और हरित प्रौद्योगिकी एकीकरण

- ऊर्जा दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र (बीईई):
 - ऊर्जा-कुशल मशीनों, सोलर ड्रायरो, बायोमास गैसीफायरों को अपनाने को बढ़ावा देना।
- अपशिष्ट से धन और वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मंच:

- औद्योगिक उप-उत्पादों के पुनः उपयोग में नवाचार।
- डीएसटी, अटल इनोवेशन मिशन और स्थानीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रोत्साहित किया गया।
- हरित एमएसएमई योजना:
 - पर्यावरण प्रबंधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है।




भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES





मौजूदा विद्यमान
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम


सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

उद्देश्य

 मौजूदा क्लस्टर में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए भारत सरकार (जीओआई) अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

 नये औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन के लिए।






भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES

एमएसएमई चैंपियंस योजना


एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न योजनाओं और हस्तक्षेपों को एकीकृत, समन्वित और अभिसरण करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण।

इसका उद्देश्य क्लस्टरों और उद्यमों को चुनना, उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुगम बनाना है।


इस योजना के 3 घटक हैं:



एमएसएमई-संधारणीय
(जेडईडी)



एमएसएमई-अभिनव
(इन्क्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन के लिए)



एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी
(Lean)

(vi) ग्रामीण एवं कृषि आधारित प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण

- सीएसआईआर-ग्रामीण प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर:
 - खाद्य प्रसंस्करण, हर्बल उत्पादों, ग्रामीण शिल्प में एमएसएमई के लिए ग्रामीण नवाचार को सुविधाजनक बनाना।
- एमजीआईआरआई (महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान):
 - खादी, वस्त्र, ग्रामीण विनिर्माण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है।
- स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना):
 - आधुनिक तकनीक और क्षमता निर्माण के माध्यम से पारंपरिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करना।
- उन्नत भारत अभियान:
 - ग्रामीण उद्यमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए शैक्षणिक-ग्रामीण-औद्योगिक साझेदारी।

एमएसएमई में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने का वित्तपोषण

- स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) और सिडबी का इंडिया एस्पिरेशन फंड:
 - तकनीक-संचालित एमएसएमई के लिए उद्यम निधि और इक्रेटी निवेश।
- सिडबी के अंतर्गत प्रौद्योगिकी एवं नवाचार निधि (टीआईएफ):
 - उभरते तकनीकी क्षेत्रों (ग्रीन टेक, मेडटेक, एआई) को लक्ष्य बनाया गया है।
- पीएसबीलोनसइन59मिनट्स और क्रेडिट गारंटी योजनाएं:
 - तकनीक अपनाने के लिए ऋण तक त्वरित पहुंच

निधि ने स्टार्टअप इंडिया अभियान को बढ़ावा दिया

भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ शुरू किया गया निधि कार्यक्रम सफल स्टार्टअप के लिए विचारों और नवाचारों को पोषित कर रहा है।

- 12000+ स्टार्टअप इनक्यूबेटर
- 16000+ महिला स्टार्टअप
- 65000+ नौकरियां सृजित

विज्ञान सेविकाएँ



आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड

आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाना



व्यवहार्य एमएसएमई को विकास पूंजी प्रदान करने में निजी क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया।



उद्देश्य

- एमएसएमई को इक्रेटी/इक्रेटी जैसे वित्तपोषण में वृद्धि करना
- एमएसएमई को उनके विकास और विस्तार में सहायता प्रदान करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना।
- एमएसएमई क्षेत्र से आगे बढ़ने तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय घेरेयन बनने की क्षमता रखने वाले उद्यमों को समर्थन प्रदान करना।
- प्रासंगिक वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य में एमएसएमई को समर्थन देना।

कौशल, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास

- प्रौद्योगिकी केंद्र (टूल रूम):
 - उन्नत विनिर्माण प्रशिक्षण (सीएनसी, सीएडी/सीएएम, रोबोटिक्स) प्रदान करना।
- स्किल इंडिया और एनएसडीसी के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम:
 - उद्योग 4.0, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, एआर/वीआर पर विशिष्ट माॅड्यूल।
- TIDE 2.0 केंद्र:
 - टियर-2 शहरों में तकनीकी उद्यमिता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना।
- महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए डिजिटल कौशल:
 - प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण प्लेटफार्मों का उपयोग करके MeitY और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रचारित।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण

- उद्यम पोर्टल और ओएनडीसी एकीकरण:
 - ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स में डिजिटल रूप से एकीकृत एसएमई।
- B2B ग्लोबल टेक मार्केटप्लेस (जैसे, GeM, अमेज़न ग्लोबल सेलिंग):
 - यह एमएसएमई को अनुरूप तकनीकी उत्पादों के साथ बाजार तक पहुंच प्रदान करता है।
- निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन:
 - ईईपीसी, ईपीसी और एक्जिम बैंक द्वारा प्रवर्तित।

प्रभाव संबंधी केस स्टडी

- (a) मोरबी सिरेमिक क्लस्टर (गुजरात)
 - सीएसआईआर के सहयोग से ऊर्जा-कुशल भट्टों और डिजिटल डिजाइन सॉफ्टवेयर को अपनाया गया।
 - उत्पादन लागत में 25% की कमी आई, निर्यात ऑर्डर में वृद्धि हुई।
- (b) कोयंबटूर फाउंड्री क्लस्टर
 - SAMARTH और C4i4 लैब्स के माध्यम से उद्योग 4.0 में परिवर्तन।

- कास्टिंग संचालन में IoT को एकीकृत किया गया, जिससे दोषों में 30% की कमी आई।

(c) पूर्वोत्तर भारत में बांस एमएसएमई

- लेमिनेटेड बांस बोर्ड और बांस कंपोजिट में सीएसआईआर-एनईआईएसटी और एमजीआईआरआई के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लाभ हुआ।
- विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए स्थायी आजीविका का सृजन हुआ।

(d) ओडिशा में ग्रामीण कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ

- उन्नत भारत अभियान और डीएसटी के सीड कार्यक्रम द्वारा समर्थित।
- सोलर ड्रायर, कोल्ड चैन और डिजिटल गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई।
- किसान-एमएसएमई एकीकरण में सुधार हुआ और कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई।

नीतिगत सिफारिशें और आगे की राह

- तकनीकी प्रसार नेटवर्क को बढ़ावा देना:
 - टियर-2/3 शहरों में टीडीसी, टीबीआई और टीआईडीई केंद्रों का विस्तार करना।
- सार्वजनिक-निजी-शैक्षणिक सहयोग को बढ़ाना:
 - उच्च प्रभाव वाले एमएसएमई क्षेत्रों (बायोटेक, ग्रीनटेक, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण) के लिए मिशन-मोड नवाचार गठबंधनों को बढ़ावा देना।
- टेक फाइनेंस तक पहुंच को सरल बनाना:
 - वास्तविक समय पात्रता फिल्टर के साथ एकीकृत एमएसएमई तकनीक-वित्तपोषण पोर्टल।
- क्षेत्र-विशिष्ट उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण:
 - रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मेडटेक, एग्रीटेक में।
- तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार:
 - मिश्रित शिक्षण, एआई-आधारित अनुकूली प्रशिक्षण मॉड्यूल, उद्योग गठजोड़।
- अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना:
 - भारत-आसियान, भारत-यूरोपीय संघ एमएसएमई टेककॉरिडोर और आईपी सह-निर्माण मॉडल को सुविधाजनक बनाना।
- डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा:
 - ग्रामीण एमएसएमई के लिए अंतिम मील ब्रॉडबैंड, क्लाउड एक्सेस, साइबर सुरक्षा सेवाएँ।

निष्कर्ष

भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा काफी हद तक इसके एमएसएमई के तकनीकी सशक्तिकरण पर निर्भर करती है। डिजिटलीकरण, नवाचार, स्थिरता और कौशल विकास में रणनीतिक और समन्वित विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप पहले से ही परिवर्तनकारी परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, सरकार, शिक्षा, उद्योग और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण आवश्यक है। सशक्त एमएसएमई, मजबूत प्रौद्योगिकी ढांचे द्वारा समर्थित, न केवल समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, बल्कि भारत को संघारणीय, तकनीक-संचालित उद्यमिता में वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं।

एमएसएमई वित्त के भविष्य को दिशा देना

परिचय: आर्थिक विकास के आधार के रूप में एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का आधार हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एमएसएमई वैश्विक व्यवसायों का 90%, वैश्विक रोजगार का 60-70% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% हिस्सा हैं। भारत में, उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल, 2025 तक, भारत में 6.23 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई थे, जो लगभग 26.66 करोड़ लोगों को रोजगार देते थे, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और निर्यात में 45% से अधिक का योगदान करते थे।

ये उद्यम समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खास तौर पर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। भारत में एमएसएमई विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं - खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र से लेकर ऑटो घटकों और यहां तक कि अंतरिक्ष मिशन घटकों जैसे उच्च-स्तरीय अनुप्रयोगों तक। पंजीकृत एमएसएमई का लगभग 70% सेवा क्षेत्र में काम करता है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम बहुसंख्यक हैं।

वैश्विक प्रासंगिकता

- वैश्विक व्यवसायों का 90% हिस्सा।
- वैश्विक कार्यबल का 60-70% हिस्सा रोजगार देता है।
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% योगदान देता है।

भारतीय संदर्भ

- 6.23 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई (अप्रैल 2025 तक)
- लगभग 26.66 करोड़ लोगों को रोजगार
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और निर्यात में लगभग 45% का योगदान

समावेशी विकास में भूमिका

- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में फैला हुआ
- खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र से लेकर अंतरिक्ष के लिए उच्च स्तरीय घटकों तक के क्षेत्रों को कवर करना।

एमएसएमई वर्गीकरण और औपचारिकता का विकास

वर्गीकरण मील के पत्थर

- **एमएसएमईडी अधिनियम (2006):** संयंत्र/मशीनरी में निवेश द्वारा परिभाषित
- **जुलाई 2020:** निवेश + टर्नओवर (ट्विनक्राइटेरियन) में बदलाव
- **2025 का बजट:**
 - ◆ टर्नओवर सीमा दोगुनी की गई
 - ◆ निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ाई गई
 - ◆ विनिर्माण और सेवाओं के लिए एकीकृत परिभाषा

औपचारिकीकरण उपकरण

- उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) और उद्यम असिस्टेडप्लेटफॉर्म (यूपीपी)
 - ◆ पंजीकरण और क्रेडिट लिंकेज को सरल बनाना
- **प्रभाव:** पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 1.65 करोड़ (2023) से बढ़कर 6.23 करोड़ (2025) हो गई।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बजट 2025-26 की घोषणा

एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा क्रमशः
2.5 और 2 गुना बढ़ाई जाएगी

(1 अप्रैल 2025 से प्रभावी)

एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन				
वर्ग	निवेश (करोड़ रुपये में) से अधिक नहीं	(संशोधित) निवेश (₹ करोड़ में) से अधिक नहीं	टर्नओवर (₹ करोड़ में) से अधिक नहीं	(संशोधित) टर्नओवर (₹ करोड़ में) से अधिक नहीं
सूक्ष्म	1	2.5	5	10
लघु	10	25	50	100
मध्यम	50	125	250	500

- पुरोबंध लचीलापन
 - आरबीआई का फरवरी 2025 का मसौदा: फ्लोटिंग-रेट एमएसएमई ऋणों पर कोई फोरक्लोज़र/प्रीपेमेंट शुल्क नहीं

ऋण गारंटी तंत्र

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
 - कवरेज सीमा: ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ (अप्रैल 2025)
 - गारंटी कवरेज:
 - ◆ 90%: महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम
 - ◆ 85%: एससी/एसटी उद्यम
 - ◆ 80%: पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख
 - ◆ 75%: अन्य एमएसएमई
- प्रदर्शन:
 - 2000-2023: ₹4.27 लाख करोड़ मूल्य की 71 लाख गारंटी
 - 2023-2025: ₹5.02 लाख करोड़ मूल्य की 44 लाख गारंटी
 - गारंटी शुल्क में 50% कटौती के कारण बढ़ावा (अप्रैल 2023)

एमएसएमई के लिए प्रमुख वित्तपोषण योजनाएं

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
 - गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम
 - ऋण: परियोजना लागत का 95% तक
 - सब्सिडी: 35% तक
 - 10.18 लाख उद्यमों को सहायता, 83 लाख नौकरियाँ (2025 तक)
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES

एमएसएमई अभिनव योजना

इन्क्यूबेशन

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

डिज़ाइन

उद्देश्य

इन्क्यूबेशन और डिज़ाइन हस्तक्षेप के माध्यम से विचारों को नवीन अनुप्रयोगों में विकसित करने से लेकर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सभी प्रकार के नवाचारों को बढ़ावा देना।

एमएसएमई क्षेत्र की बौद्धिक संपदाओं की अवधारणा से लेकर बाजार तक के विकास, डिज़ाइन प्रतिस्पर्धात्मकता और संरक्षण एवं व्यवसायीकरण के लिए उपयुक्त सुविधाएं और सहायता प्रदान करना।

उद्योग, शिक्षा, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के बीच ज्ञान साझाकरण और सहयोग के माध्यम से नवाचार और टचनात्मक समन्वय समन्वयन की संस्कृति को बढ़ावा देना।

नए उत्पाद विकास और मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक/शैक्षणिक नेताओं और नवप्रवर्तकों के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करना।

ऐसे किरायायती नवाचारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल सके और साथ ही वे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और संघारणीय भी हों।

गौरवशाली वर्ष
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के

व्यवसायों को सशक्त बनाना:
व्यापार में लगे लोगों के लिए जमानत मुक्त मुद्रा ऋण

उत्पादन

सेवाएं

व्यापार

कृषि से संबंधित गतिविधियाँ

52 करोड़+ ऋण स्वीकृत

₹33 लाख करोड़+ स्वीकृत राशि

70% महिला उद्यमी (ऋण स्वीकृत)

31% नये उद्यमी (स्वीकृत राशि)

50% एनसी/एसटी/ओबीसी (ऋण स्वीकृत)

वित्त के माध्यम से एमएसएमई को मजबूत बनाना

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल)
 - बैंकों के ANBC का 40% PSL में, 7.5% सूक्ष्म उद्यमों के लिए आरक्षित
 - वर्ष-दर-वर्ष (YoY) ऋण देने के अधिदेश:
 - ◆ एमएसई ऋण में 20% की वृद्धि
 - ◆ सूक्ष्म उद्यम खातों में 10% की वृद्धि
 - ◆ सूक्ष्म इकाइयों को कुल एमएसई ऋण का 60%
- संपार्श्विक-मुक्त ऋण
 - पीएसएल/पीएमईजीपी के तहत बिना किसी जमानत के ₹10 लाख का ऋण
 - ऋण पात्रता के आधार पर इसे ₹25 लाख तक बढ़ाया जा सकता है

- 2015 में शुरू किया गया, सूक्ष्म इकाइयों के लिए बिना किसी जमानत के ऋण
- ₹32.61 लाख करोड़ मूल्य के 51.67 करोड़ ऋण वितरित किए गए

- पीएम विश्वकर्मा योजना
 - लक्ष्य: पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार
 - लाभ: कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, मार्केटिंग और 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक का ऋण
 - प्रगति: 29.6 लाख पंजीकृत, 4 लाख को ऋण प्राप्त (मध्य-2025)
- आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआई)
 - सरकार: ₹10,000 करोड़, निजी पूंजी के माध्यम से ₹50,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य
 - उद्देश्य: स्केल-अप और लिस्टिंग के लिए इक्विटी समर्थन
 - स्थिति: 577 एमएसएमई में ₹10,979 करोड़ का निवेश (मार्च 2025 तक)
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)
 - कोविड-19 राहत, मार्च 2023 तक बंद
 - ₹2.42 लाख करोड़ मूल्य की 1.13 करोड़ गारंटी प्रदान की गई

➤ एसबीआई अध्ययन: 14.6 लाख एमएसएमई एनपीए को रोका गया

बजट 2025 नवाचार और आगे की राह

- नई पहल
 - सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड
 - स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड
 - एससी/एसटी/महिला उद्यमियों के लिए समर्पित क्रेडिट (पहली बार)
 - निर्यातक एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए विस्तारित क्रेडिट गारंटी

निष्कर्ष: एक लचीले वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की ओर

- एमएसएमई अब भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर आर्थिक परिवर्तन के लिए केंद्रीय हैं।
- पीएसएल से लेकर इक्विटी इन्फ्यूजन तक मजबूत वित्तीय संरचना एमएसएमई विकास को उत्प्रेरित कर रही है।
- बजट 2025 “अमृत काल” लक्ष्यों और 2047 में विकसित भारत के विजन की नींव रखता है।

CCHAHAL ACADEMY

यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा

2026/27/28

प्रवेश प्रारंभ

एनसीईआरटी+जीएस+सीसैट
फाउंडेशन बैच के लिए

माध्यम



English

हिंदी

द्विभाषी (Bilingual)

वैकल्पिक
विषय

राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (PSIR) - भूगोल
समाज शास्त्र - इतिहास - मानव शास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)



चहल एकेडमी, 22-B, ग्राउंड फ्लोर, करोल बाग, मेट्रो पिलर नंबर 112,
ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ☎ 9313218122, 9625993995

हमारी शाखाएँ

नई दिल्ली, अहमदाबाद, आनंद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी,
जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागालैंड, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, वडोदरा

उभरता संकट: जलवायु परिवर्तन किस तरह भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है

संदर्भ: जैसे-जैसे वर्षा अनियमित होती जा रही है और तापमान बढ़ता जा रहा है, चाय की पैदावार घट रही है - और महिला श्रमिकों को कम वेतन, बिना किसी सुरक्षा और बढ़ते जोखिम के साथ इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

भारत में चाय उद्योग

- भारत, चीन के बाद दुनिया भर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और काली चाय के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है। यह दुनिया भर में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसके अतिरिक्त, भारत काली चाय का अग्रणी उपभोक्ता है, जो वैश्विक चाय की खपत का 18% हिस्सा है।
- भारत में चाय की खेती की देखरेख भारतीय चाय बोर्ड करता है। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र पूर्वोत्तर, विशेष रूप से असम और उत्तरी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, जिसमें दार्जिलिंग जिला और दोआर्स क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण भारत में, नीलगिरी पहाड़ियों में भी चाय व्यापक रूप से उगाई जाती है।
- चाय ठंडी से गर्म जलवायु में सबसे अच्छी तरह से उगती है, जहाँ प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे धूप मिलती है। स्वस्थ विकास के लिए आदर्श वार्षिक तापमान सीमा 15°C और 23°C के बीच है। इसके लिए हर साल 150 से 200 सेमी के बीच वर्षा की भी आवश्यकता होती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **काम करने की परिस्थितियाँ:** महिलाएँ हर साल लगभग नौ महीने चाय तोड़ती हैं और कम बारिश के मौसम में वे मिट्टी खोदने, बगीचे की सफाई करने और सूखे पत्तों के ढेर को हटाने का काम करती हैं।
- **जलवायु परिस्थितियाँ:** महिलाएँ चिलचिलाती धूप और अनियमित बारिश के दौरान भी काम करती हैं। चूँकि बगीचों में छाया नहीं है, इसलिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
- **अपर्याप्त मज़दूरी:** महिलाएँ 250 रुपये के आसपास दैनिक मज़दूरी कमाती हैं।
- **मानव-पशु संघर्ष:** बगीचों में अक्सर तेंदुए देखे जाते हैं और महिला तोड़ने वालों पर हमले की घटनाएँ भी हुई हैं।
- **पालनाघर की सुविधा का अभाव:** पालनाघर की सुविधा के अभाव में बच्चों को कपड़े के पालने में लटकया जाता है और पेड़ की शाखाओं से बाँधा जाता है।
- **वर्षा:** कम लेकिन तीव्र बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में वर्षा का पैटर्न अनियमित हो गया है। अपर्याप्त वर्षा के कारण मिट्टी सूख जाती है और भूजल स्तर गिर जाता है।
- **फसल की पैदावार:** जलवायु परिवर्तन चाय की झाड़ियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे कीटों और बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

आगे की राह

- **मृदा अपरदन को रोकना:** मल्लिंग और फलियों के साथ अंतर-फसल जैसी मिट्टी संरक्षण विधियाँ अचानक होने वाली बारिश के दौरान मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती हैं।
- **जल प्रबंधन:** ड्रिप सिंचाई और वर्षा जल संचयन सूखे या अप्रत्याशित वर्षा के दौरान उपज को संरक्षित करने और पानी बचाने में मदद करता है।
- **मिट्टी का पुनर्जनन और संरक्षण:** ऐसी तकनीकें जो मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बढ़ाती हैं, जैसे कि भूमि संरक्षण फसलें, समोच्च रोपण और जैविक खाद का उपयोग, दीर्घकालिक स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- **जलवायु-स्मार्ट किस्में:** चाय की फसल की किस्मों का विकास जो कीटों और सूखे के लिए प्रतिरोधी हैं।
- **प्रारंभिक चेतावनी और सलाह के लिए प्रणाली:** मोबाइल सलाह, मौसम पूर्वानुमान और सामुदायिक प्रशिक्षण का उपयोग करके, चाय उत्पादक गर्मी की लहरों या बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं के लिए तैयार हो सकते हैं।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन और अनसुलझे श्रम मुद्दे कुछ चाय बागानों को बंद होने की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन संस्थागत समर्थन और जलवायु-लचीली फसल प्रणालियों के साथ, चाय बागानों के साथ-साथ महिला श्रमिकों की बढ़ी हुई लाभप्रदता हासिल की जा सकती है।

पहुंच और लाभ साझाकरण: केंद्र द्वारा जैव विविधता के उपयोग के लिए नए नियम

संदर्भ: हाल ही में, जैविक विविधता (जैविक संसाधनों और उससे जुड़े ज्ञान तक पहुंच और लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा) विनियमन 2025 को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और 29 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों की मुख्य विशेषताएं

- **पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी):** जैविक संसाधनों तक पहुंच की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति या उद्योग को अनुमोदन के लिए एनबीए को पहले से सूचित करना होगा, यह आवश्यकता बीडीए 2002 के तहत अधिसूचित खेती वाले औषधीय पौधों तक पहुंच पर लागू नहीं होती है।
- **लाभ साझाकरण स्लैब:** लाभ साझाकरण स्लैब की संख्या संसाधन का उपयोग करने वाले व्यक्ति या उद्योग के वार्षिक कारोबार द्वारा निर्धारित की जाती है।
 - 5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले उपयोगकर्ताओं को लाभ साझा करने से छूट दी गई है।
 - जबकि 5 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच वार्षिक कारोबार वाले उपयोगकर्ताओं को उत्पाद की सकल एक्स-फैक्ट्री बिक्री मूल्य (सरकारी करों को छोड़कर) का 0.2% साझा करना आवश्यक है।

- शेष दो स्लैब के अनुसार, 50 से 250 करोड़ रुपये के बीच तथा 250 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर का क्रमशः 0.4% तथा 0.6% वितरित करना होगा।
- वार्षिक उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का व्याख्यान देने वाला विवरण एक करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किया जाना चाहिए।
- उच्च संरक्षण या आर्थिक मूल्य वाले जैविक संसाधनों के लिए लाभ साझा करना बिक्री या नीलामी आय या खरीद मूल्य के 5% से कम नहीं होना चाहिए, तथा वाणिज्यिक उपयोग के मामले में यह 20% से अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगरवुड, लाल चंदन, आदि।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यावसायीकरण:** आवेदक को एनबीए को सहमत मौद्रिक या गैर-मौद्रिक लाभ देना होगा।
- जैविक संसाधनों तक पहुँच और संबंधित ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियमों पर 2014 के दिशानिर्देश इस विनियमन द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं।

पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (एबीएस) क्या है?

- "पहुँच और लाभ-साझाकरण" (एबीएस) शब्द बताता है कि आनुवंशिक संसाधन कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं और उनके उपयोग से होने वाले लाभ उन व्यक्तियों या राष्ट्रों के बीच कैसे वितरित किए जाते हैं जो संसाधनों का उपयोग करते हैं (उपयोगकर्ता) और उन व्यक्तियों या राष्ट्रों के बीच जो उन्हें आपूर्ति करते हैं (प्रदाता)।
- पहुँच और लाभ-साझाकरण पर जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आनुवंशिक संसाधन भौतिक रूप से सुलभ हों और उनके उपयोग से प्राप्त लाभ प्रदाताओं को उचित रूप से वितरित किए जाएँ।

- इसमें आईएलसी से प्राप्त आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण पारंपरिक ज्ञान भी शामिल है।
- साझा किए जाने वाले लाभ गैर-मौद्रिक हो सकते हैं, जैसे अनुसंधान कौशल और ज्ञान की वृद्धि, या मौद्रिक, जैसे वाणिज्यिक उत्पाद बनाने के लिए संसाधनों का उपयोग किए जाने पर रॉयल्टी साझा करना।

कार्यप्रणाली

- आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित लाभों के न्यायोचित और समान वितरण की गारंटी देने के लिए, पहुँच और लाभ-साझाकरण प्रदाता द्वारा उपयोगकर्ता को पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) दिए जाने और दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमत शर्तों (एमएटी) पर बातचीत किए जाने पर आधारित है।
- **पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी):** उपयुक्त राष्ट्रीय कानूनी और संस्थागत ढांचे के अनुसार, पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) उपयोगकर्ता को आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने से पहले प्रदाता देश के सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया प्राधिकरण है।
- **पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें (एमएटी):** यह उपयोगकर्ताओं और आनुवंशिक संसाधन प्रदाताओं के बीच पहुँच और उपयोग की शर्तों के साथ-साथ दोनों पक्षों द्वारा साझा किए जाने वाले लाभों के बारे में एक समझौता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, नए अधिनियम ने औषधीय पौधों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया तथा भारतीय चिकित्सकों को उनका उपयोग करने या उनसे लाभ उठाने के लिए अनुमति देने से मुक्ति दे दी।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



'द हिन्दू' में क्या पढ़ें?

क्यू आर कोड स्कैन करें



‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ से महत्वपूर्ण आलेख (मई 2025)

परिसीमन और गहराता संघवाद

संदर्भ: लेख में भारत में आगामी परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा की गई है, तथा संघवाद और राज्यों के समान प्रतिनिधित्व को कमजोर करने की इसकी क्षमता पर चिंता व्यक्त की गई है।

आसन्न परिसीमन संकट और इसके संघीय निहितार्थ

- परिसीमन अभ्यास संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
- यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 82 द्वारा अनिवार्य है, जिसे 2003 में संशोधित किया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि इसे 2026 के बाद प्रकाशित पहली जनगणना के बाद किया जाना चाहिए।
- हालांकि मूल रूप से यह अनुमान 2031 की जनगणना के बाद लगाया गया था, लेकिन अब इसके स्थगित 2021 की जनगणना के बाद होने की अधिक संभावना है।
- यदि परिसीमन अभ्यास को संघीय सिद्धांत को दरकिनार करते हुए किया जाता है तो इसे समस्याग्रस्त माना जाता है। मुख्य चिंता यह है कि संसदीय सीटों के असंतुलित आवंटन से आम चुनाव के नतीजों और विधायी प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में "कुछ राज्यों की दबंग शक्ति" हो सकती है, जिससे भारतीय लोकतंत्र की संघीय प्रकृति कमजोर हो सकती है।
- दक्षिणी राज्यों का डर:** दक्षिणी भारतीय राज्यों के नेता इस डर के कारण परिसीमन के खिलाफ मामले का नेतृत्व कर रहे हैं कि इससे उत्तरी भारतीय राज्यों के लिए संसदीय सीटों में अनुपातहीन वृद्धि होगी। बदले में, इसे संसद में दक्षिणी राज्यों की आवाज़ को कम करने के रूप में माना जाता है।
- संवैधानिक दुविधा:** परिसीमन के विरोधी दक्षिणी राज्यों को समान आवाज़ बनाए रखने के लिए इस अभ्यास को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का सुझाव देते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 का खंडन करता है और "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के सिद्धांत को नष्ट करता है। यह जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक जनादेश और उन राज्यों के राजनीतिक प्रभाव की रक्षा करने की इच्छा के बीच तनाव को उजागर करता है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है।
- दक्षिणी राज्यों में चिंता का कारण:** दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ हाल के वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों से प्रदर्शित चिंताओं में निहित हैं। दक्षिणी राज्यों को उनकी जनसांख्यिकीय उपलब्धियों, जैसे जन्म दर और जनसंख्या में गिरावट के लिए "दंडित" नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, कुछ राज्यों में उच्च जनसंख्या और जन्म दर को "सामूहिक नैतिक विफलता" के लिए नहीं बल्कि "असमान विकास के संरचनात्मक परिणाम" के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

भारत के संघीय चरित्र के लिए चुनौतियाँ

- अनुपातहीन राज्य शक्ति:** मौजूदा व्यवस्था, नए परिसीमन के बिना भी, ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जहां अधिक संसदीय शक्ति वाले राज्यों की चिंताएँ छोटे राज्यों की चिंताओं पर हावी हो जाती हैं।

- उदाहरण:** मणिपुर का संकट, जहां असाधारण संकट होने के बावजूद, इसने बड़े क्षेत्रों में हुए संकटों जितना संसदीय ध्यान आकर्षित नहीं किया है।
- केंद्रीकरण की प्रवृत्ति:** दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से बढ़ गई हैं, जो राज्य की स्वायत्तता को दबाने का प्रयास करती है।
- राज्यपाल की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने विधिवत निर्वाचित राज्य सरकारों की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को नष्ट करने के लिए राज्यपाल के कार्यालय के दुरुपयोग को उजागर किया है।

संघवाद को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित सुधार

- बढ़ी हुई राज्य स्वायत्तता**
 - राज्यों की स्वायत्तता बढ़ाना
 - संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का विस्तार करना तथा संघ सूची को न्यूनतम करना।
 - समवर्ती सूची में विषयों की साझा प्रकृति की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
- राज्यपाल के पद में सुधार:** राज्यपाल के पद को समाप्त करने (कम से कम इसके वर्तमान स्वरूप में) या राज्यपाल की शक्तियों में भारी कटौती करने पर बहस शुरू करना अगले कदम के रूप में प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य संघ सरकार को "चुने हुए राज्य सरकारों के संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों और शक्तियों" पर अतिक्रमण करने से रोकना है।
- द्विसदनीयता पर पुनर्विचार**
 - सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य परिषद (राज्य सभा) का पुनर्गठन करना।
 - छोटे राज्यों की संसदीय स्थिति और कद को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट जैसे उदाहरणों का अनुकरण करना, उन्हें आश्रित संघवाद से दूर ले जाना।
- चुनाव प्रणाली सुधार**
 - फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट चुनावी प्रणाली पर पुनर्विचार करना।
 - जर्मन बंडेस्टैग या श्रीलंका की संसद द्वारा नियोजित प्रणालियों की तर्ज पर मौजूदा प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तत्व पेश करना। इससे "संघ में राज्यों का अधिक प्रतिनिधित्व" संभव होगा, जो "चुनावी प्रणाली के बढ़ते संघीयकरण" में योगदान देगा।

निष्कर्ष

आसन्न परिसीमन अभ्यास, हालांकि संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, संघीय तनाव को बढ़ाने के लिए तैयार है, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों के लिए जो संसद में कम होती आवाज़ के बारे में चिंतित हैं। इस संकट को सफलतापूर्वक पार करने के लिए संघीय सिद्धांतों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने और राज्यसभा और राज्यपाल की भूमिका पर पुनर्विचार करने जैसे संस्थागत सुधार शामिल हैं। भारत में एक सच्चे लोकतंत्र को अपने विविध घटक राज्यों के बीच समान आवाज़ और विश्वास के साथ संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को संतुलित करना चाहिए।

जल्दी और अक्सर: गर्म लहरों पर ध्यान

संदर्भ: लेख में भारत में गर्म लहरों (हीट वेव) की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता पर प्रकाश डाला गया है, तथा जलवायु-प्रेरित जोखिमों के मूल कारणों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिक्रिया से लेकर हरित बुनियादी ढांचे, जल पहुंच, ऊर्जा समानता और सामाजिक संरक्षण को शामिल करते हुए व्यापक प्रणालीगत परिवर्तनों की ओर बदलाव का आग्रह किया गया है।

हीटवेव और उनके प्रभाव को समझना

- हीटवेव को निचले इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **कारण:** वे तब होते हैं जब उच्च दाब वाले वायुमंडलीय तंत्र (एंटीसाइक्लोन) गर्म वायु को अवरुद्ध करते हैं, जिससे इसका प्रसार रुक जाता है, जिससे वायु और स्थल पर कई दिनों तक उच्च सौर विकिरण का जोखिम बना रहता है।
- **स्वास्थ्य और मृत्यु दर जोखिम**
 - वर्ष 2024 में कई मौतों के लिए हीटवेव को जिम्मेदार ठहराया गया।
 - हीटवेव अवधि के दौरान शहरी निवासियों को मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है।
 - हृदय और श्वसन संबंधी घटनाओं की प्रवृत्ति जैसे दृश्यमान तनाव प्रभावों के अलावा, बढ़ते तापमान के बाद शीत आंधी के कारण समय के साथ ऑटोइम्यून रोग फैल सकते हैं।
- **कमज़ोर आबादी और परिवेश**
 - बड़े सार्वजनिक समारोह और बाहरी काम जोखिम भरे हैं। प्रभावित लोगों में पर्यटक, चुनाव अधिकारी, तीर्थयात्री, निर्माण और कृषि श्रमिक और बुजुर्ग शामिल हैं।
 - प्रवासी अनौपचारिक श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, घर के अंदर खाना बनाने वालों और आजीविका की आवश्यकताओं के कारण गर्मियों के संपर्क में आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

शमन के व्यापक आयाम: सामाजिक न्याय और ग्रहीय स्वास्थ्य

- जलवायु जोखिम को तकनीकी क्रांति और उपभोक्ता पूंजीवाद द्वारा आकार दिए गए "सामाजिक सफलता" के परिणाम के रूप में देखा जाता है, फिर भी ये जोखिम समान रूप से वितरित नहीं हैं।
- **हरे (वृक्ष) और नीले (जल) स्थान**
 - **हीट आइलैंड प्रभाव:** दुनिया भर के शहरों की शानदार वृद्धि, जो अक्सर वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर निर्मित संरचनाओं की ओर ले जाती है, हीट आइलैंड प्रभाव उत्पन्न करती है। रहने योग्य सूक्ष्म जलवायु को बनाए रखने के लिए वृक्ष आवरण की रक्षा करना और अभेद्य पदार्थों के उपयोग को कम करना आवश्यक है।
 - **सार्वजनिक सहभागिता:** तकनीकी और नागरिक विशेषज्ञों को हीट आइलैंड प्रभावों को कम करने में हरित स्थानों और जल निकायों की भूमिका के बारे में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परामर्श में शामिल होना चाहिए। न्यायिक आदेशों और पर्यावरण कानूनों के बावजूद, दिल्ली और हैदराबाद जैसे गर्मियों की लहरों से ग्रस्त शहरों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई एक नियमित अभ्यास है।

पेय जल

- **कमी और गुणवत्ता:** बढ़ती गर्मियों के कारण गरीब परिवारों, खास तौर पर कम पानी वाले शहरी और ग्रामीण समुदायों में पानी की कमी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** पुणे में गिलियनबैरे सिंड्रोम के प्रकोप का कारण पीने के पानी का सीवेज से दूषित होना बताया गया।
- **शमन उपाय:** गर्मियों से निपटने की कार्ययोजना में कम पानी वाले क्षेत्रों, यातायात चौराहों और निर्माण स्थलों पर शुद्ध पानी की आपूर्ति शामिल होनी चाहिए।
- **उदाहरण:** दिल्ली सरकार गर्मियों में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस ट्रैकर-सक्षम जल टैंकर प्रणाली लागू कर रही है।

ऊर्जा उपयोग और गरीबी

- **बढ़ी हुई खपत:** गर्म मौसम आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में उच्च ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देता है।
- **असमानता और प्रदूषण:** ऊर्जा का उपयोग और वितरण आम तौर पर विषम और असमान है। धनी वर्गों में ऊर्जा-घनी खपत होती है, जिसके लिए शिक्षा, सूचना और विनियमन के माध्यम से स्थिरता उपायों की आवश्यकता होती है।
- **इनडोर वायु प्रदूषण:** ग्रामीण क्षेत्रों में हीटवेव जोखिम का एक कम दिखाई देने वाला लिंक बायोमास खाना पकाने के ईंधन के इनडोर उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव हैं। NFHS-5 के अनुसार, 56.1% ग्रामीण और 9.5% शहरी परिवार खाना पकाने के लिए टोस ईंधन का उपयोग करते हैं। उच्च आय वाले परिवार कम आय वाले परिवारों की तुलना में अधिक तरल पेट्रोलियम गैस और बिजली का उपभोग करते हैं।
- **औद्योगिक प्रदूषण:** अत्यधिक घने शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिमी तट पर, केंद्रित औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों के कारण उच्च वायु प्रदूषण का सामना करते हैं। ऊर्जा उपयोग, ऊर्जा गरीबी और हीटवेव के बीच संबंध पर आगे चर्चा की आवश्यकता है।

सामाजिक सुरक्षा उपाय

- **सरकारी प्रतिक्रिया:** पिछले साल की भीषण गर्मियों के बाद, कुछ राज्य सरकारों (जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना) ने सलाह, कार्य योजनाएँ और अग्रिम प्रतिपूर्ति उपाय लागू किए हैं। उन्होंने गर्मियों से होने वाली मौतों के लिए ₹4,00,000 तक की अनुग्रह राशि घोषित की है।
- **कार्य योजनाएँ:** स्थानीय भाषाओं में गर्मियों से संबंधित सलाह प्रकाशित की जाती हैं, स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य सेवा का वादा किया जाता है, तथा गर्मियों की आपात स्थितियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं से अधिक प्रतिक्रिया पर चर्चा की जाती है।
- **कार्यक्रमों को सक्रिय करना:** भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम तथा आयुष्मान भारत योजना जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा जैसे मौजूदा कार्यक्रमों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा उपायों को सक्रिय करना अत्यावश्यक है।

निष्कर्ष

हीटवेव का जल्दी और बार-बार आना यह दर्शाता है कि बढ़ते तापमान से ग्रहीय जीवन किस तरह खतरे में पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए, राज्यों और नागरिकों की भूमिका हरित शहरों, प्रदूषण रहित पानी, संधारणीय ऊर्जा और सबसे कमज़ोर समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। हीटवेव फोकस में न केवल 'साइट' बल्कि जलवायु-प्रेरित जोखिमों के 'स्रोत' को भी शामिल किया जाना चाहिए।

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन)

मई माह के महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिवस	विवरण
1 मई	अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस	<ul style="list-style-type: none"> 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है जो विश्व भर के सभी श्रमिकों और मजदूरों को समर्पित है। यह दिन उन मेहनती लोगों का सम्मान करता है जिनकी प्रतिबद्धता और काम ने विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को आकार दिया है।
3 मई	विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	<ul style="list-style-type: none"> यूनेस्को की संस्तुति के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई थी। तब से, 3 मई, विंडहोक घोषणा की वर्षगांठ को विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 इस बात पर केंद्रित है कि एआई प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना के मुक्त प्रवाह, मीडिया की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के वैश्विक लक्ष्य (एसडीजी 16.10) को कैसे प्रभावित करता है।
10 मई	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस	<ul style="list-style-type: none"> विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2025 थीम: साझा स्थान: पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय बनाना
11 मई	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	<ul style="list-style-type: none"> 11 मई, 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में सफल परमाणु परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों सहित भारत के वैज्ञानिक समुदाय के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
12 मई	अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस (IDPH) घोषित किया है, ताकि वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके कि कैसे पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने से भुखमरी को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य वर्ष 2020 की एक प्रमुख विरासत है। 2025 थीम: द इम्पोर्टन्स ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ
16 मई	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस	<ul style="list-style-type: none"> अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है, जो भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में किए गए पहले सफल लेजर ऑपरेशन की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। इस दिन, यूनेस्को वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने का आह्वान करता है।
17 मई	विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस	<ul style="list-style-type: none"> विश्व दूरसंचार दिवस 1969 से प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है, जो ITU की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर का प्रतीक है। इसे 1973 में मलागा-टोरेंमोलिनोस में प्लेनिपोटेंटियरी कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित किया गया था। नवंबर 2005 में, सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित करने का आह्वान किया ताकि आईसीटी के महत्व और डब्ल्यूएसआईएस द्वारा उठाए गए सूचना समाज से संबंधित मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। नवंबर 2006 में, तुर्की के अंताल्या में ITU प्लेनिपोटेंटियरी कॉन्फ्रेंस ने 17 मई को दोनों घटनाओं को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।

20 मई	विश्व मधुमक्खी दिवस	<ul style="list-style-type: none"> परागणकों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया है। इसका लक्ष्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की सुरक्षा के लिए उपायों को मजबूत करना है, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को हल करने और विकासशील देशों में भुखमरी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 2025 थीम: बी इन्स्पाइअर्ड बाइ नेचर टू नरिश अस ऑल
21 मई	राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस	<ul style="list-style-type: none"> भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु की याद में मनाया जाता है, जिनकी हत्या 1991 में इसी दिन LTTE आतंकवादियों द्वारा की गई थी। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा से दूर रखना है।
22 मई	अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस	<ul style="list-style-type: none"> दिसंबर 2022 में, विश्व एक साथ आई और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के लिए एक वैश्विक योजना पर सहमत हुई। कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाने से 2030 के लिए 23 लक्ष्य और 2050 के लिए 5 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि 25 वर्षों में प्रकृति के नुकसान को रोका जा सके और उसे उलटा जा सके। इसके लक्ष्यों में शामिल हैं: 20% खराब हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश या बसावट को 50% तक कम करना। 2025 थीम: हार्मनी विद नेचर एण्ड सस्टेनबल डेवलपमेंट
29 मई	संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	<ul style="list-style-type: none"> लगभग 80 वर्षों से, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने विश्व भर के समुदायों में ठोस बदलाव लाए हैं। इस वर्ष “शांति स्थापना का भविष्य” थीम के तहत मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पिछले लगभग आठ दशकों में सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति सैनिकों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान पर नज़र डाली जाती है।
31 मई	विश्व तंबाकू निषेध दिवस	<ul style="list-style-type: none"> विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने तंबाकू महामारी और इसके कारण होने वाली रोगी जा सकने वाली मृत्यु और बीमारी की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की। 1987 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल 1988 को “विश्व धूम्रपान निषेध दिवस” मनाने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 1988 में, एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया।

समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन

	सम्मेलन	विवरण
1.	बीआरएस सीओपी 2025	<ul style="list-style-type: none"> भारत ने रसायनों और अपशिष्टों, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्टों के प्रबंधन पर मजबूत वैश्विक कार्रवाई का समर्थन किया। यह सम्मेलन जिनेवा, स्विटजरलैंड में आयोजित किया गया था। थीम: मैक विज़बल द इनविज़बल: साउन्ड मैनिज्मन्ट ऑफ़ केमिकल एण्ड वेस्ट
2.	वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, 2025	<ul style="list-style-type: none"> भारत ने वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, 2025 में स्वामित्व योजना की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। थीम: जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुँच को सुरक्षित करना
3.	वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र (UNFF20)	<ul style="list-style-type: none"> यह कार्यक्रम 5 से 9 मई, 2025 तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। सम्मेलन में वन संरक्षण, सतत वन प्रबंधन, बड़ी बिल्लियों का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
4.	समावेशी भारत शिखर सम्मेलन, 2025	<ul style="list-style-type: none"> वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल सुगम्यता को बढ़ावा देना है।
5.	अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> यह कार्यक्रम वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वाणिज्य भवन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की चाय निर्यात उपस्थिति और घरेलू मूल्य पहचान को मजबूत करना है।

6.	78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा	<ul style="list-style-type: none"> यह 21 मई, 2025 को जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता से पुष्टि की। भारत ने आयुष्मान भारत के तहत अपनी उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।
7.	उभरते पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> शिखर सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विविध क्षेत्रों में निवेश और भागीदारी को आकर्षित करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विकास को गति देना है।
8.	9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक	<ul style="list-style-type: none"> यह बैठक ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। विषय: अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। भारत ने सीमा पार स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने और समावेशी औद्योगिक विकास की वकालत करने के लिए एक नई पहल का अनावरण किया।

समाचारों में चर्चित पुरस्कार

	पुरस्कार	विजेता	विवरण
1.	मानवतावादी पुरस्कार	अभिनेता सोनू सूद	<ul style="list-style-type: none"> सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी परोपकारी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मिस वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन द्वारा दिया गया।
2.	सम्मान पदक	भुवन रिभु	<ul style="list-style-type: none"> भुवन रिभु विश्व विधि कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए। यह पुरस्कार विश्व न्यायवादी संघ द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार मानव तस्करी, विशेष रूप से बाल संरक्षण कानूनों के क्षेत्र में उनके कानूनी कार्य को रेखांकित करता है।
3.	58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार	गुलज़ार और रामभद्राचार्य	<ul style="list-style-type: none"> यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्यिक उपलब्धियों के लिए दिया गया। गुलज़ार को उनकी गीतात्मक कविता और पटकथा लेखन के लिए सम्मानित किया गया, जबकि रामभद्राचार्य को उनके संस्कृत महाकाव्यों और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।
4.	अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार	बानू मुश्ताक	<ul style="list-style-type: none"> कन्नड़ लघुकथा संग्रह हार्ट लैप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दीपा भाष्ठी द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक। यह पुस्तक दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का सशक्त चित्रण है।

समाचार में महत्वपूर्ण शब्दावली

	चर्चित शब्दावली	अर्थ एवं विवरण
1.	लापु-लापु दिवस	<ul style="list-style-type: none"> लापु-लापु दिवस 1521 में लड़ी गई मैकटन के युद्ध की सालगिरह पर मनाया जाता है। इस युद्ध में, मैकटन द्वीप के सरदार (या दातु), लापुलापु ने फर्डिनेंड मैगलन के नेतृत्व वाली स्पेनिश सेना को हराया था।
2.	केटामाइन	<ul style="list-style-type: none"> केटामाइन एक एनेस्थेटिक है जिसे यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक मतिभ्रम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे "विघटनकारी एनेस्थेटिक मतिभ्रम" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह दर्द और पर्यावरण से अलगाव की भावना पैदा करता है। केटामाइन का सेवन उन रोगियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने पारंपरिक उपचारों पर प्रतिक्रिया नहीं की है। केटामाइन का उपयोग एक मनोरंजक दवा के रूप में भी किया जाता है, जिसे क्लब जाने वालों के बीच K या स्पेशल K के नाम से जाना जाता है।
3.	फील्ड मार्शल	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं ब्रिटिश सेना की रैंक और विशेषाधिकारों की प्रणाली पर आधारित हैं। फील्ड मार्शल या एफएम एक पांच सितारा अधिकारी रैंक है, और जनरल से ऊपर सबसे उच्च प्राप्त करने योग्य रैंक है। भारतीय सेना में एफएम रैंक भारतीय नौसेना में बेड़े के एडमिरल और भारतीय वायु सेना के मार्शल के बराबर है। भारत में दो एफएम रहे हैं: सैम मानेकशां पहले थे, जो जनवरी 1973 में इस रैंक पर चढ़े थे। केएम करिअप्पा दूसरे फील्ड मार्शल थे और जनवरी 1986 में पदोन्नत हुए थे। भारत में वायु सेना के एक मार्शल अर्जन सिंह भी थे, जिन्हें 2002 में इस रैंक पर पदोन्नत किया गया था।

4.	कुआउतेमोक	<ul style="list-style-type: none"> कुआउतेमोक नामक एक मैक्सिकन जहाज न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया। कुआउतेमोक एक अकादमी प्रशिक्षण पोत है, जो मैनहट्टन से निकला था और माना जाता था कि वह समुद्र की ओर जा रहा था।
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन

	व्यक्ति	विवरण
1.	सुब्बान्ना अव्यप्पन	<ul style="list-style-type: none"> वह एक अग्रणी मत्स्य वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। उन्हें भारत की नीली क्रांति के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है।
2.	डॉ. सरोज घोष	<ul style="list-style-type: none"> वह एक प्रसिद्ध विज्ञान संचारक और भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के संस्थापक व्यक्ति थे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) के संस्थापक महानिदेशक के रूप में, डॉ. घोष ने भारत में अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा में क्रांति ला दी, और देश भर में विज्ञान केंद्रों के एक मजबूत नेटवर्क की नींव रखी।
3.	एम.आर. श्रीनिवासन	<ul style="list-style-type: none"> वे भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी नेताओं में से एक थे और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व प्रमुख थे। डॉ. होमी भाभा के करीबी सहयोगी श्रीनिवासन ने भारत के परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक के रूप में सम्मानित, उन्होंने देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिपेक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का काफी विस्तार किया।
4.	जयंत नार्लीकर	<ul style="list-style-type: none"> वह एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक, दूरदर्शी विज्ञान संचारक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने पुणे में इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) की स्थापना की। संस्थापक निदेशक के रूप में, उन्होंने IUCAA को एक विश्व स्तरीय अनुसंधान और शिक्षण संस्थान के रूप में आकार दिया।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



'द हिंदू' और 'इंडियन एक्सप्रेस' से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें






दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विभिन्न विषयों में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए एक माइक्रोग्रैविटी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
2. ISS लगभग हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित हैं?

- (a) शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी प्रकार के जबरन श्रम, बाल श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाना।
- (b) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
- (c) अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार का अधिकार।
- (d) नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि को संरक्षित करने का अधिकार, और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद निपटान तंत्र की वर्तमान स्थिति का सही वर्णन करता है:

1. नियुक्तियों के अवरुद्ध होने के कारण WTO का अपीलीय निकाय वर्तमान में निष्क्रिय है।
2. देश अभी भी WTO में विवाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन अंतिम अपीलीय निर्णय नहीं दिए जा सकते।
3. WTO ने अपने विवाद समाधान कार्य को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 4. हीट एक्शन प्लान (HAP) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. HAP में हीटवेव की प्रारंभिक भविष्यवाणी, जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना जैसे उपाय शामिल हैं।
2. HAP में दीर्घकालिक उपाय पाकों और पेड़ों की संख्या बढ़ाने और बगीचों को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने पर केंद्रित हैं।
3. हीट स्ट्रेस और मृत्यु दर के आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना HAP का हिस्सा नहीं है।
4. HAP का सफल कार्यान्वयन काफी हद तक शहर के अधिकारियों, राज्य सरकारों और सामुदायिक संगठनों के बीच सहयोग पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है/हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 5. 'त्सांगपो नदी' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. त्सांगपो नदी तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और अंततः असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है।
2. यह दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है और दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक होने के लिए जानी जाती है।
3. तिब्बत में त्सांगपो नदी को यारलुंग त्सांगपो भी कहा जाता है।
4. यह नदी महान हिमालय पर्वतमाला से होकर गुजरती है, जिससे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जलविद्युत क्षमता पैदा होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन पूर्वी लद्दाख की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है जिसका भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व है?

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (a) पैगोंग त्सो | (b) ज़ांस्कर रेंज |
| (c) सियाचिन ग्लेशियर | (d) तवांग पठार |

प्रश्न 7. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक ब्याज आय को अनुकूलित करके लाभप्रदता का एक निश्चित स्तर बनाए रखें।
- बैंक के उत्तोलन अनुपात को बढ़ाना, जिससे उसे जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों में बड़ा निवेश करने की अनुमति मिले।
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्तर की उच्च-गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) रखें।
- मंदी की स्थिति में बैंकों के लिए न्यूनतम आरक्षित आवश्यकता निर्धारित करना।

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क का सबसे विशिष्ट स्वास्थ्य प्रभाव है?

- त्वचा का हाइपरपिगमेंटेशन और हाइपरकेराटोसिस
- रिकेट्स
- गुर्दे की पथरी
- लिवर सिरोसिस

प्रश्न 9. आमेर किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यह किला अपनी जटिल राजपूत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और माओटा झील के ऊपर स्थित है।
- किले का निर्माण मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा शुरू किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 10. पहलगाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

- यह लिद्दर नदी और शेषनाग झील के संगम पर स्थित है।
- यह वार्षिक अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है।
- यह जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

प्रश्न 11. निम्नलिखित में से कौन जीडीपी की गणना में शामिल नहीं है?

- निजी खपत
- सरकारी खर्च
- वस्तुओं और सेवाओं का आयात
- व्यवसायों द्वारा निवेश

प्रश्न 12. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।
- अनुच्छेद 32 के तहत उपाय स्वयं एक मौलिक अधिकार है।
- उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से कम है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है/हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- उपर्युक्त सभी

प्रश्न 13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- F-35B वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग (VTOL) में सक्षम है।
- F-35B मुख्य रूप से वाहक संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 14. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- सीसीएस की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।
- यह रक्षा व्यय और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है।
- विदेश मंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं।
- सीसीएस के निर्णय संसद द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है/हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- उपर्युक्त सभी

प्रश्न 15. निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- यह तब होता है जब एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है।
- यह वह घटना है जहाँ मानव चयापचय में परिवर्तन के कारण एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं।
- यह तब होता है जब बैक्टीरिया जैसे रोगजनक दवाओं के प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है।
- यह एंटीबायोटिक दवाओं के लिए शरीर के प्राकृतिक अनुकूलन को संदर्भित करता है, जो उन्हें समय के साथ अनावश्यक बनाता है।

प्रश्न 16. प्राचीन शहर पाल्मेरा कहाँ स्थित है?

- इटली
- ग्रीस
- सीरिया
- इराक

प्रश्न 17. अक्सर चर्चा में देखा गया शब्द 'समायोजित सकल राजस्व' (एजीआर) का प्रयोग ...

- नदी-जल परिवहन
- अंतरिक्ष पर्यटन
- दूरसंचार क्षेत्र
- कृषि सहकारी क्षेत्र

प्रश्न 18. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम युद्धपोत है?

- INS नीलगिरी
- INS वाघशीर
- INS सूरत
- INS विशाखापत्तनम

प्रश्न 19. वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रमुख परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि
- यूरोप में रूसी प्राकृतिक गैस पर निर्भरता में कमी
- रूसी तेल प्रतिबंधों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में वृद्धि

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- उपर्युक्त सभी
- इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 20. महाराजा हरि सिंह द्वारा 1947 में जम्मू और कश्मीर के लिए हस्ताक्षरित विलय पत्र का क्या महत्व है?

- इसने जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान में एकीकरण को चिह्नित किया

- इसने जम्मू और कश्मीर को अपनी संप्रभुता बनाए रखने की अनुमति दी

- इसने भारत को रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार पर नियंत्रण दिया

- इसने राज्य को स्वयं शासन करने की पूर्ण स्वायत्तता दी

प्रश्न 21. उर्वरकों के लिए नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम (एनपीके) का आदर्श औसत अनुपात है:

- 1:2:3
- 3:2:1
- 4:2:1
- 1:2:4

प्रश्न 22. शिमला समझौते 1972 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- शिमला समझौता 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, जिसने 1971 की युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा (एलओसी) में परिवर्तित कर दिया।
- भारत और पाकिस्तान दोनों ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय विवादों को हल करने पर सहमति व्यक्त की।
- यह एक देश द्वारा संधि के उल्लंघन के मामले में विवादों को हल करने के लिए दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- उपर्युक्त सभी
- इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 23. अमेरिका और ईरान परमाणु वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- अमेरिका और ईरान ने दो दौर की वार्ता की है, जिसमें ओमान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।
- ट्रम्प प्रशासन 2018 से ईरान के साथ परमाणु वार्ता का पूरी तरह से समर्थन कर रहा है।
- ईरान ने प्रतिबंधों और खतरों को हटाने के बदले में अपनी परमाणु गतिविधियों को कम करने की इच्छा का संकेत दिया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- उपर्युक्त सभी
- इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 24. 'स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

- यह कार्यक्रम सरकार के स्वच्छ भारत अभियान पहल का हिस्सा है।

2. इसका उद्देश्य स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण गतिविधियों को लागू करना है, जैसे नियमित स्वास्थ्य जांच, परामर्श और शारीरिक शिक्षा।
3. स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम केवल सरकारी स्कूलों में लागू किया जाता है।
4. यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 25. पूर्वी एशियाई बाघ कहे जाने वाले देशों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. हांगकांग | 2. जापान |
| 3. दक्षिण कोरिया | 4. ताइवान |
| 5. सिंगापुर | |

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (a) केवल 1, 3, 4 और 5 | (a) केवल 1, 3, 4 और 5 |
| (c) केवल 1, 2, 3 और 4 | (d) 1, 2, 3, 4 और 5 |

प्रश्न 26. पोषण विकास (N4G) शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. शिखर सम्मेलन की मेजबानी विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा की जाती है।
2. इसका उद्देश्य वैश्विक कुपोषण को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण और प्रयासों को संरेखित करना है।
3. यह कुपोषण से निपटने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 27. भारत में मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत मुख्य रूप से आसपास के महासागरों के सापेक्ष भारतीय उपमहाद्वीप के विभेदक तापन द्वारा होती है।
2. पूर्वोत्तर मानसून भारत के अधिकांश भागों में वार्षिक वर्षा का प्रमुख स्रोत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 28. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. FATF की बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्राधिकारों को आमतौर पर ब्लैक लिस्ट कहा जाता है।
2. उत्तर कोरिया, ईरान और रूस FATF ब्लैक लिस्ट में मौजूद हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 29. राजमन्त्र समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे भारत सरकार ने 1969 में केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए स्थापित किया था।
2. इसने अनुच्छेद 263 के तहत एक मजबूत अंतर-राज्य परिषद के पक्ष में अनुच्छेद 356 को निरस्त करने की सिफारिश की।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 30. निम्नलिखित गैसों पर विचार करें:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. ओजोन | 2. नाइट्रस ऑक्साइड |
| 3. क्लोरोफ्लोरोकार्बन | 4. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन |

उपर्युक्त में से कौन सी गैसें वायुमंडल में पाँच सबसे प्रचुर ग्रीनहाउस गैसों (GHG) में से हैं?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 1 और 3 |
| (c) केवल 2 और 3 | (d) केवल 2 और 4 |

प्रश्न 31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र में एकमात्र निकाय है जो किसी राज्य के खिलाफ सैन्य बल के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के निर्णय संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 32. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. उपाध्यक्ष की भूमिका पूरी तरह से औपचारिक होती है और संसदीय कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती है।
2. उपाध्यक्ष से पार्टी संबद्धता की परवाह किए बिना निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
3. उपाध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक वे इस्तीफा नहीं दे देते, हटा दिए जाते हैं या संसद के सदस्य नहीं रह जाते।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 33. 'RBI की बैंक ऋण दर' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर हमेशा रेपो दर से अधिक होती है।
2. बैंक ऋण दर केवल RBI द्वारा निर्धारित रेपो दर से प्रभावित होती है।
3. बैंक ऋण दर का उपभोक्ता ऋण और गृह ऋण पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
4. RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक ऋण दर का उपयोग करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 34. निम्नलिखित में से कौन 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (PPP) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (a) पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए प्रदूषक जिम्मेदार है
- (b) पर्यावरण प्रदूषण को साफ करने के लिए सरकार को भुगतान करना चाहिए
- (c) पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय समुदाय की है
- (d) प्रदूषण से प्रभावित श्रमिकों को प्रदूषक को मुआवजा देना चाहिए

प्रश्न 35. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निवर्तमान CJI और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है।

2. मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने और सर्वोच्च न्यायालय में विशिष्ट मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 36. निम्नलिखित हीरों पर विचार करें:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. आर्चड्यूक जोसेफ | 2. कोह-ए-नूर |
| 3. दरिया-ए-नूर | 4. होप डायमंड |

उपर्युक्त हीरों में से कितने गोलकुंडा में खनन किए गए थे?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 37. दक्षिण चीन सागर में 'नाइन-डैश लाइन' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. नाइन-डैश लाइन दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर चीन के क्षेत्रीय दावे को संदर्भित करती है।
2. नाइन-डैश लाइन को क्षेत्र के सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है।
3. नौ-डैश लाइन के कारण चीन और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हुए हैं। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 38. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
2. ILO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
3. ILO का प्राथमिक अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करना है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 39. निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए 'शिव-शक्ति बिंदु' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (a) इसरो के चंद्रयान-3 मिशन का चंद्र लैंडिंग स्थल।
- (b) हिंद महासागर में एक गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट।

(c) चंद्रयान-2 मिशन द्वारा खोजी गई चंद्रमा पर एक पर्वत श्रृंखला।

(d) भारत के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रक्षेपण स्थल।

प्रश्न 40. WAVES 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. WAVES 2025 विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण है।
2. इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के संचार नेटवर्क और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 41. निजी सदस्य विधेयकों (PMB) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. PMB को केवल संसद के सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है जो मंत्री नहीं है।
2. PMB पर संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को विशेष रूप से चर्चा की जाती है।
3. दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने वाला अंतिम निजी सदस्य विधेयक 1970 में था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 42. आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFTA) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा था?

- (a) मलेशिया (b) थाईलैंड
(c) सिंगापुर (d) इंडोनेशिया

प्रश्न 43. सबसे गहरे रंग की कृत्रिम सामग्रियों में से एक, वैटाल्ब्लैक, किससे बना होता है?

- (a) क्षैतिज रूप से व्यवस्थित ग्राफीन शीट
(b) लंबवत संरेखित कार्बन नैनोट्यूब
(c) अनाकार कार्बन कण
(d) पॉलिमर मैट्रिक्स में धातु नैनोकण

प्रश्न 44. भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1881 से, यह हर 10 साल में आयोजित किया जाता है लेकिन 2021 में नहीं किया गया।
2. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 45. भारतीय संसद में विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (DRSC) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) DRSC की स्थापना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज से संबंधित मामलों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए की जाती है।
(b) प्रत्येक DRSC को एक विशिष्ट मंत्रालय या विभाग को सौंपा जाता है और यह उसके बजट, नीतियों और कार्यक्रमों की जाँच से संबंधित कार्य करता है।
(c) DRSC का गठन हर साल बजट सत्र की शुरुआत से पहले किया जाता है।
(d) प्रत्येक DRSC के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

प्रश्न 46. बांडुंग सम्मेलन (1955) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य अफ्रीकी-एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था।
2. इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने भाग लिया।
3. सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर दिया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 47. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) सूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST), आधिकारिक सूचियाँ 1950 के संवैधानिक आदेशों के तहत अधिसूचित की जाती हैं।
2. संसदीय संशोधनों के माध्यम से SC और ST सूचियों को अद्यतन किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 48. निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की पांचवीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है?

- (a) ल्होत्से (b) मकालू
(c) धौलागिरी (d) नंदा देवी

प्रश्न 49. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. CPEC बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला है जो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंजियांग क्षेत्र से जोड़ती है।
2. CPEC को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
3. इससे चीन और अरब सागर के बीच यात्रा के समय को कम करने और व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 50. ऑपरेशन पराक्रम में कौन सी भारतीय सैन्य शक्ति सबसे प्रमुख रूप से शामिल थी?

- (a) भारतीय वायु सेना (b) भारतीय नौसेना
(c) भारतीय सेना (d) सीमा सुरक्षा बल (BSF)

प्रश्न 51. भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 52. 'संधारा' या 'सल्लेखना' की प्रथा भारत में निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ी है?

- (a) बौद्ध धर्म (b) सिख धर्म
(c) जैन धर्म (d) यहूदी धर्म

प्रश्न 53. भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान है।
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संदर्भ में किसी भी विवाद या शिकायत की सुनवाई करने और निर्णय लेने का विशेष अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 54. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है।
2. यह केवल राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कर सकता है और व्यक्तियों या निजी संस्थाओं से जुड़े मामलों को संबोधित नहीं कर सकता।
3. इसके निर्णय किसी मामले में शामिल सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 55. "विज्ञानजाम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट" के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है:

1. बंदरगाह को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया गया है, जिसमें केवल केंद्रीय हिस्सेदारी है।
2. विज्ञानजाम भारत का पहला पूर्ण स्वचालित बंदरगाह है जो रिमोट-नियंत्रित क्रेन और AI-संचालित पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है।
3. यह पूर्व-पश्चिम शिपिंग अक्ष के साथ स्थित है, जो यूरोप, पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व को जोड़ता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 56. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग की सिफारिशों केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर लागू होंगी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए शैक्षणिक आरक्षण को प्रभावित नहीं करेंगी।
2. आयोग को ओबीसी आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों में बदलाव की सिफारिश करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 57. अनुच्छेद 370 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. जम्मू-कश्मीर को अस्थायी विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 डाला गया था।
2. अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान था, जो भारतीय संविधान से अलग था।
3. अनुच्छेद 35A, जो जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था, को बरकरार रखा गया।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 58. 2024 में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मौतों में से आधे से अधिक मौतें किस क्षेत्र में हुईं?

- | | |
|----------------|------------------------|
| (a) मध्य पूर्व | (b) दक्षिण एशिया |
| (c) साहेल | (d) दक्षिण पूर्व एशिया |

प्रश्न 59. त्रिशूर पूरम (Thrissur Pooram) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केरल में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है।
2. यह एक जीवंत मंदिर उत्सव है जिसमें भव्य हाथी जुलूस और पारंपरिक तालवाद्य प्रदर्शन शामिल होते हैं।
3. यह फसल कटाई का त्यौहार है और पारंपरिक दीप जलाकर मनाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 60. संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (a) युद्ध से प्रभावित सभी देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- (b) संघर्ष क्षेत्रों में शरणार्थियों को सैन्य सहायता प्रदान करना
- (c) विश्व भर में विस्थापित आबादी के लिए स्थायी बस्तियाँ स्थापित करना
- (d) फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं में सहायता प्रदान करना

प्रश्न 61. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किन इलाकों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (a) कराची और इस्लामाबाद | (b) बालाकोट और रावलपिंडी |
| (c) मुरीदके और बहावलपुर | (d) लाहौर और क्वेटा |

प्रश्न 62. महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिकी-भारत पहल (आईसीईटी) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 5जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
2. यह पहल चीन पर तकनीकी निर्भरता को कम करने और दोनों देशों के लिए तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।
3. इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम का निर्माण शामिल है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 63. स्टारलिक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक उपग्रह इंटरनेट तारामंडल परियोजना है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करना है।
2. स्टारलिक उपग्रह भू-समकालिक कक्षा में परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रह हैं।
3. ये उपग्रह रेडियो शोर पैदा करके खगोलविदों के काम में बाधा डाल रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 64. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, यदि उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता का संकेत देने वाले ठोस सबूत हों।
2. पीएमएलए के तहत, यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है कि संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 65. 'भारत के इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी)' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारत का ईईपीसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. यह भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सहायता प्रदान करता है।
3. इसकी सदस्यता इंजीनियरिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक सीमित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 66. पोप के चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. पोप सम्मेलन वेटिकन सिटी के सिस्टिन चैपल में आयोजित किया जाता है।
2. केवल 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल ही पोप सम्मेलन में मतदान करने के पात्र होते हैं।
3. चुनाव के बाद, नए पोप के चुनाव की घोषणा करने के लिए चिमनी से सफेद धुआँ छोड़ा जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 67. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीएबीएम) एक पहल है ...

- (a) अफ्रीकी संघ (b) आसियान
(c) यूरोपीय संघ (d) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)

प्रश्न 68. निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक जूनोटिक वायरस है और मनुष्यों के बीच भी फैल सकता है।
2. निपाह वायरस का प्राथमिक स्रोत चमगादड़ है, विशेष रूप से फ्रूट बैट।
3. वर्तमान में निपाह वायरस के संक्रमण के लिए कोई दवा या कोई टीका नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 69. सोंगर ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सोंगर ड्रोन एक मानव-पोर्टेबल सामरिक यूएवी है जिसे इज़राइल द्वारा वास्तविक समय की निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विकसित किया गया है।
2. यह एक घूमने वाला हथियार है जिसे विस्फोटक पेलोड ले जाने और आत्मघाती मिशन को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 70. भीष्म क्यूब्स (BHISHM cubes) का उपयोग किया जाता है...

- (a) नेविगेशन सैटेलाइट बनाना
(b) सुपर कंप्यूटर के लिए कूलिंग सिस्टम विकसित करना
(c) आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करना
(d) हल्के लड़ाकू वाहन विकसित करना

प्रश्न 71. 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5)' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. एनएफएचएस-5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का पाँचवाँ दौर है।
2. एनएफएचएस-5 प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण जैसे विभिन्न संकेतकों पर डेटा प्रदान करता है।
3. यह वर्ष 2020-21 में आयोजित किया गया था और इसमें भारत के सभी 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था।
4. एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 72. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री करते हैं।
2. यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
3. यह आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 73. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।
2. इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं, एक तकनीकी और एक प्रशासनिक।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 74. विस्तारित निधि सुविधा (ईईएफ) निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार/वित्तपोषण के प्रावधानों से संबंधित है?

- (a) एशियाई विकास बैंक
(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल
(d) विश्व बैंक

प्रश्न 75. राज्य-विशिष्ट विनिर्माण पार्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. इन पार्कों के भीतर प्रोटोटाइप विकास के लिए इन-हाउस क्षमताएँ बनाई जानी चाहिए।

2. राज्य-विशिष्ट विनिर्माण पार्कों को नई इकाइयों की त्वरित स्थापना के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए।
3. इन पार्कों को केवल सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 76. अर्धचालकों (सेमीकंडक्टर) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सिलिकॉन का उपयोग आमतौर पर अर्धचालक पदार्थ के रूप में किया जाता है।
2. गैलियम आर्सेनाइड एकीकृत परिपथों के निर्माण के लिए सबसे आम पदार्थ है।
3. अर्धचालक को डोप करने से पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों या छिद्रों की संख्या बढ़ जाती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 77. लचीलापन और स्थिरता सुविधा (RSF) निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण/वित्तपोषण के प्रावधानों से संबंधित है?

- (a) एशियाई विकास बैंक (b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल
(d) विश्व बैंक

प्रश्न 78. 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं की अवधारणा पेश की। निम्नलिखित में से कौन संशोधन के तहत परिभाषित नगर पालिकाओं के प्रकारों में से एक नहीं है?

- (a) नगर निगम (b) नगर परिषद
(c) जिला परिषद (d) नगर पंचायत

प्रश्न 79. "मेक इन इंडिया" पहल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. पहल का एक लक्ष्य 2022 तक भारत के विनिर्माण उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद के 25% तक बढ़ाना है।
2. यह पहल विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने से बाहर रखती है।
3. "मेक इन इंडिया" 2025 तक 100 मिलियन नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करता है।
4. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 80. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित में अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
3. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 81. निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. फ्रांस | 2. जर्मनी |
| 3. स्विट्जरलैंड | 4. यूनाइटेड किंगडम |

उपर्युक्त देशों में से कितने देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 82. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को समय-समय पर अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने का आदेश देता है।
2. आरटीआई अधिनियम ने सरकारी अधिकारियों को अपने संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों को अपनी संपत्ति सालाना घोषित करने के लिए प्रेरित किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 83. भारत के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. DGMO भारतीय सेना में एक वरिष्ठ रैंकिंग अधिकारी है, जो आमतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल का पद रखता है।
2. डीजीएमओ अंडमान और निकोबार कमांड सहित भारत की लि-सेवा कमांड के कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

3. डीजीएमओ-स्तरीय संचार 1971 के युद्ध के बाद सैन्य-से-सैन्य संपर्क सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक विरासत तंत्र है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 84. भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के प्राथमिक उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत करना।
2. नीति-निर्माण और योजना के लिए जनसंख्या गतिशीलता पर डेटा एकत्र करना।
3. सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण का रिकॉर्ड रखना।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 85. 'पर्सोना नॉन ग्राटा' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. यह एक राजनयिक शब्द है जिसका उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किसी विदेशी राजनयिक का अब मेजबान देश में स्वागत नहीं है।
2. किसी व्यक्ति को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।
3. राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के तहत, मेजबान देश किसी व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 86. भारतीय रक्षा के संदर्भ में आदमपुर एयरबेस का क्या महत्व है?

- (a) यह भारतीय सेना के लिए प्रशिक्षण बेस के रूप में कार्य करता है।
- (b) यह पश्चिमी क्षेत्र में हवाई युद्ध संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण बेस है।
- (c) यह उत्तरी भारत में मुख्य नौसैनिक एयरबेस है।
- (d) इसका उपयोग मुख्य रूप से मानवीय एयरलिफ्ट के लिए किया जाता है।

प्रश्न 87. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ICAO एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो विमानन सुरक्षा और दक्षता के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।
2. इसकी स्थापना 1944 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन द्वारा की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 88. भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं, जबकि कोर मुद्रास्फीति में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है।
2. कोर मुद्रास्फीति अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों का एक अधिक स्थिर उपाय है क्योंकि यह खाद्य और ऊर्जा बाजारों में अस्थायी मूल्य झटकों से प्रभावित नहीं होती है।
3. खुदरा मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है।
4. RBI द्वारा निर्धारित मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य $4+/-2$ प्रतिशत है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 89. मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. यूएवी का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य निगरानी और टोही कार्यों के लिए किया जाता है।
2. यूएवी का उपयोग कार्गो डिलीवरी और कृषि जैसे वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नहीं किया जा सकता है।
3. यूएवी स्वायत्त रूप से संचालित हो सकते हैं या मानव ऑपरेटरों द्वारा दूर से नियंत्रित किए जा सकते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 90. स्काईस्ट्राइकर लोडिंग मुनिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. स्काईस्ट्राइकर एक स्वायत्त लोडिंग मुनिशन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से टोही और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है।
2. यह निर्धारित लक्ष्यों पर उच्च-सटीक हमलों के लिए 5-10 किलोग्राम के वारहेड से लैस है।
3. स्काईस्ट्राइकर की अधिकतम सीमा 100 किलोमीटर तक है।
4. यह इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन द्वारा संचालित है, जो ऑपरेशन के दौरान चुपके और कम शोर प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 91. चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (LUPEX) ... का एक संयुक्त मिशन है।

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) NASA और ESA | (b) ISRO और NASA |
| (c) ESA और JAXA | (d) ISRO और JAXA |

प्रश्न 92. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति संबंधित है:

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| (a) परमाणु अप्रसार समझौतों को लागू करना। |
| (b) केवल तालिबान से जुड़ी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना। |
| (c) ISIL (दाएश), अल-कायदा और उससे जुड़े व्यक्तियों और समूहों को निशाना बनाना। |
| (d) संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करना। |

प्रश्न 93. फ्री मूवमेंट रिजिम (एफएमआर) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. यह भारत-म्यांमार सीमा पर रहने वाले आदिवासी लोगों को बिना वीजा के सीमा पार 16 किमी तक की यात्रा करने की अनुमति देता है।
2. एफएमआर भारत और म्यांमार के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
3. एफएमआर की स्थापना सीमावर्ती समुदायों के बीच सदियों पुराने सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए की गई थी।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 94. 'ऑपरेशन ऑल-क्लियर' का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

- (a) पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संदर्भ स्थापित करना।
- (b) भूटानी क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही समूहों को खदेड़ना।
- (c) भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना।
- (d) दक्षिणी भूटान में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

प्रश्न 95. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह 8 दिसंबर 1953 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के "शांति के लिए परमाणु" संबोधन का परिणाम था।
2. 2005 में, इसे एक सुरक्षित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
3. IAEA सुरक्षा उपाय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों में अंतर्निहित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 96. एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (IACCS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह भारत को दिया गया इजराइल का एक स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली है।
2. यह विभिन्न वायु रक्षा स्रोतों से डेटा एकीकृत करता है।
3. यह प्रतिक्रिया समय को कम करने में मदद करता है और कमांडरों को वायु रक्षा परिसंपत्तियों को प्रभावी ढंग से तैनात करने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 97. वाघा-अटारी सीमा क्रॉसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र सड़क सीमा क्रॉसिंग है।
2. प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट समारोह यहाँ प्रतिदिन आयोजित किया जाता है।
3. यह भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर शहर के पास स्थित है।

4. यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख व्यापार और पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 98. समय पोषण (पोषण) के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. पोषण का उद्देश्य बच्चों में बौनापन, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन को कम करना है।
2. इसे 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
3. पोषण विभिन्न मंत्रालयों में पोषण संबंधी विभिन्न योजनाओं को एकीकृत और अभिसरण करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 99. टीकों और उनके व्यापक स्वास्थ्य प्रभावों पर हाल के शोध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दाद का टीका हृदय संबंधी बीमारियों और मनोभ्रंश दोनों के जोखिम को कम कर सकता है।
2. वेरिसेला-जोस्टर वायरस, जो चिकनपॉक्स और दाद का कारण बनता है, शरीर में निष्क्रिय रहता है और बाद में पुनः सक्रिय हो सकता है।
3. शिंग्रिक्स एक जीवित क्षीणित टीका है, जबकि ज़ोस्टावैक्स पुनः संयोजक तकनीक पर आधारित है।
4. कुछ अध्ययनों में डिप्थीरिया, न्यूमोकोकल और हेपेटाइटिस ए जैसे सामान्य टीकों के उपयोग से डिमेंशिया के जोखिम में कमी के बीच संदर्भ पाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 100. टैरिफ और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में उच्च टैरिफ ने विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करके अकुशल घरेलू उत्पादकों की रक्षा की है।
2. कम और समान दरों के साथ सरलीकृत टैरिफ संरचना बेहतर आर्थिक दक्षता की ओर ले जाती है।
3. टैरिफ कम करने से उपभोक्ता कीमतें कम हो सकती हैं और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 101. EOS-09 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. इसे सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करके उच्च-गुणवत्ता वाली रडार छवियों को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
2. यह नागरिक भूमि-उपयोग मानचित्रण और रक्षा निगरानी दोनों के लिए डेटा प्रदान करता है।
3. यह मुख्य रूप से मौसम पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग के लिए अभिप्रेत था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 102. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारत, FATF का संस्थापक सदस्य है।
2. FATF उन देशों की "ब्लैकलिस्ट" रखता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में असहयोगी हैं।
3. FATF की सिफारिशें सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 103. कलादान परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. परियोजना की मदद से, कार्गो बांग्लादेश पर निर्भर हुए बिना, विजाग और कोलकाता से पूर्वोत्तर तक पहुँच जाएगा।
2. म्यांमार में बामर जातीय समूह 65% से अधिक आबादी बनाते हैं।
3. परियोजना में सड़क, नदी और समुद्री परिवहन घटक शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 104. भारत में मुद्रास्फीति माप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोर मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) टोकरी से खाद्य और ईंधन की कीमतों को बाहर करती है।

2. मौसमी और वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव के कारण सामान्य CPI मुद्रास्फीति कोर मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति निर्धारित करते समय मुख्य रूप से कोर मुद्रास्फीति को लक्षित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 105. भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. राज्यपाल को अपनी नियुक्ति से कम से कम पाँच वर्ष पहले राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. राज्यपाल राष्ट्रपति के विवेक के अधीन अनिश्चित काल के लिए पद धारण कर सकता है।
3. राज्यपाल अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 106. कारगिल युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. युद्ध मुख्य रूप से भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा लड़ा गया था।
2. नियंत्रण रेखा को नियमित पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने आतंकवादियों के वेश में पार किया था।
3. युद्ध के तुरंत बाद भारत-पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों में सुधार हुआ।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 107. डिग्लोसिया की सही परिभाषा क्या है?

- (a) किसी व्यक्ति की दो असंबंधित भाषाओं के बीच स्विच करने की क्षमता।
(b) एक ऐसी स्थिति जहाँ दो भाषाओं को मिलाकर एक नई भाषा बनाई जाती है।
(c) विभिन्न सामाजिक संदर्भों में इस्तेमाल की जाने वाली एक ही भाषा की दो अलग-अलग किस्मों का सह-अस्तित्व।
(d) भाषण उत्पादन में कठिनाई से संबंधित एक विकार।

प्रश्न 108. वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- ओआरओपी यह सुनिश्चित करता है कि एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सभी सशस्त्र बल कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन मिले।
- भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में

सर्वोच्च न्यायालय ने ओआरओपी योजना की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर कुंजी

प्रश्न 1	c	प्रश्न 23	b (केवल 1 और 3)	प्रश्न 45	b	प्रश्न 67	c	प्रश्न 89	c
प्रश्न 2	c	प्रश्न 24	b (केवल 2 और 4)	प्रश्न 46	b (केवल 1 और 3)	प्रश्न 68	c	प्रश्न 90	c
प्रश्न 3	a	प्रश्न 25	a	प्रश्न 47	c	प्रश्न 69	d	प्रश्न 91	d
प्रश्न 4	c (केवल 1, 2 और 4)	प्रश्न 26	b (केवल 2 और 3)	प्रश्न 48	b	प्रश्न 70	c	प्रश्न 92	c
प्रश्न 5	d	प्रश्न 27	a	प्रश्न 49	b (केवल 1 और 3)	प्रश्न 71	b	प्रश्न 93	c
प्रश्न 6	a	प्रश्न 28	c	प्रश्न 50	c	प्रश्न 72	c	प्रश्न 94	b
प्रश्न 7	c	प्रश्न 29	b	प्रश्न 51	a	प्रश्न 73	d	प्रश्न 95	c
प्रश्न 8	a	प्रश्न 30	a	प्रश्न 52	c	प्रश्न 74	b	प्रश्न 96	b
प्रश्न 9	c	प्रश्न 31	c	प्रश्न 53	a	प्रश्न 75	a	प्रश्न 97	c
प्रश्न 10	b	प्रश्न 32	b	प्रश्न 54	c	प्रश्न 76	b	प्रश्न 98	a
प्रश्न 11	c	प्रश्न 33	b (केवल 1 और 3)	प्रश्न 55	a	प्रश्न 77	b	प्रश्न 99	b
प्रश्न 12	c (केवल 1, 2 और 3)	प्रश्न 34	a	प्रश्न 56	d	प्रश्न 78	c	प्रश्न 100	c
प्रश्न 13	a	प्रश्न 35	c	प्रश्न 57	a	प्रश्न 79	c	प्रश्न 101	a
प्रश्न 14	c (केवल 2, 3 और 4)	प्रश्न 36	d	प्रश्न 58	c	प्रश्न 80	c	प्रश्न 102	a
प्रश्न 15	c	प्रश्न 37	a (केवल 2)	प्रश्न 59	b	प्रश्न 81	a	प्रश्न 103	d
प्रश्न 16	c	प्रश्न 38	b (केवल 1 और 2)	प्रश्न 60	d	प्रश्न 82	b	प्रश्न 104	b
प्रश्न 17	c	प्रश्न 39	a	प्रश्न 61	c	प्रश्न 83	c	प्रश्न 105	a
प्रश्न 18	c	प्रश्न 40	c	प्रश्न 62	b	प्रश्न 84	b	प्रश्न 106	a
प्रश्न 19	b (केवल 1 और 2)	प्रश्न 41	c	प्रश्न 63	b	प्रश्न 85	c	प्रश्न 107	c
प्रश्न 20	c	प्रश्न 42	c	प्रश्न 64	a	प्रश्न 86	b	प्रश्न 108	c
प्रश्न 21	c	प्रश्न 43	b	प्रश्न 65	b	प्रश्न 87	a		
प्रश्न 22	a (केवल 1)	प्रश्न 44	a	प्रश्न 66	c	प्रश्न 88	d		



दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास प्रश्न

- प्रश्न 1. हाथ से मैला ढोने की प्रथा जातिगत भेदभाव, मानवाधिकार और स्वच्छता जैसी गंभीर चिंताओं को उजागर करती है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के प्रचलन के कारणों पर चर्चा करें। (जीएस 1, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 2. मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों और प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डालें। भारत में सिविल सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने में इसकी प्रभावशीलता की जाँच करें। (जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 3. संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C से नीचे सीमित करने के लिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 2016 में पृथ्वी दिवस चुना। जलवायु परिवर्तन से निपटने में 1.5°C सीमा के महत्व का वर्णन करें। दुनिया इस सीमा के भीतर कैसे रह सकती है? (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)

- प्रश्न 4. भूमि क्षरण दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक के रूप में उभर रहा है। भूमि क्षरण के कारणों और भूमि पुनर्स्थापन के महत्व पर चर्चा करें। (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 5. भारत जितनी जल्दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का स्थायी सदस्य बन जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के लिए उतना ही बेहतर होगा। टिप्पणी करें। (जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 6. देश में आतंकवाद और उग्रवाद की सुरक्षा चुनौतियों के बीच, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के कार्यालय की आलोचनात्मक जांच करें। (जीएस 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 7. संवैधानिक समर्थन और डिजिटल हस्तक्षेप के बावजूद, पंचायती राज संस्थाएँ वित्तीय स्वायत्तता और पारदर्शिता के साथ संघर्ष कर रही हैं। टिप्पणी करें। (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 8. कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कृषि अनुसंधान और विकास के महत्व पर प्रकाश डालें। भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास पर कृषि अनुसंधान और विकास (R&D) में कम निवेश के क्या निहितार्थ हैं? (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 9. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति क्या है और यह सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है? भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता का मूल्यांकन करें। (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 10. हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ के स्तर में गिरावट जल और जलवायु सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा कर रही है। जल सुरक्षा और जैव विविधता पर बर्फ के घटते आवरण के प्रभाव पर चर्चा करें। इन प्रभावों को दूर करने के लिए अनुकूलन रणनीतियों का सुझाव दें। (जीएस 1 और 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 11. भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक सतत समस्या रही है। भारत में बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रणनीतियों और नीतियों पर चर्चा करें। (जीएस 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 12. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) क्या है और इसे आर्थिक विकास का एक प्रमुख उपाय क्यों माना जाता है? जीडीपी को मापने के विभिन्न तरीकों और आर्थिक विकास के उपाय के रूप में जीडीपी की सीमाओं पर चर्चा करें। (जीएस 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 13. भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उपशामक देखभाल का क्या महत्व है? भारत में उपशामक देखभाल को लागू करने में चुनौतियों और उपशामक देखभाल तक पहुँच को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करें। (जीएस 1 और 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 14. चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात को निलंबित कर दिया है। दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ और उनके प्रमुख भौगोलिक हॉटस्पॉट क्या हैं? चर्चा करें कि दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को प्रौद्योगिकी का बीज क्यों कहा जाता है। (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 15. पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के विकास पर चर्चा करें। पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) में क्या कदम शामिल हैं? (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 16. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ व्यवस्था के बीच भारत का राजकोषीय घाटा एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के व्यापक आर्थिक घाटे क्या हैं? राजकोषीय घाटे के प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर चर्चा करें। (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)

- प्रश्न 17. एआई प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ, इंटरनेट पर डीपफेक आम होते जा रहे हैं और उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डीपफेक से जुड़ी चिंताओं का वर्णन करें। डीपफेक से निपटने और उन्हें विनियमित करने के लिए वैश्विक और भारतीय पहल क्या हैं? (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 18. संवैधानिक और न्यायिक हस्तक्षेप किस तरह से राज्यपाल के औपचारिक अधिकार को निर्वाचित राज्य सरकार के लोकतांत्रिक कामकाज के साथ संतुलित करने का लक्ष्य रखते हैं? (जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 19. भारत में मौजूदा गहन कृषि प्रणाली से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? खाद्य, पोषण और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी विकल्प के रूप में पुनर्योजी खेती के लाभों का मूल्यांकन करें। (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 20. भारत की नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश प्रणाली दशकों से बहस और राजनीतिक घर्षण का विषय रही है। पार्श्व प्रवेश की नीति क्या है? नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश की आवश्यकता और आलोचना की जाँच करें। (जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 21. जैसे-जैसे भारत संधारणीय परिवहन में अपने परिवर्तन को तेज़ कर रहा है, विभिन्न क्षेत्र हरित हाइड्रोजन गतिशीलता को अपना रहे हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों के विरुद्ध उनके परिचालन लाभों की जाँच करें। (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 22. हाल ही में आईक्यूएयर की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के बीस सबसे प्रदूषित शहरों में से तेरह भारत में हैं। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति की जाँच करें। प्रमुख वायु प्रदूषकों के प्रभाव पर चर्चा करें। (जीएस 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 23. क्वांटम तकनीक और क्वांटम यंत्रिकी के सिद्धांत क्या हैं? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के प्रमुख डोमेन पर चर्चा करें। (जीएस 3, 10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 24. स्वामित्व ग्रामीण शासन को बदल रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमि तकनीक को प्रदर्शित कर रहा है। योजना के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा करें। (जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 25. भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संदर्भ व्यापार और ऊर्जा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। टिप्पणी करें। (जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 26. डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) हमला क्या है? यह वितरित डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) हमले से किस प्रकार भिन्न है? DoS हमले किस तरह से किए जाते हैं और ऐसे हमलों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करें। (जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)

विस्तृत व्याख्या के लिए

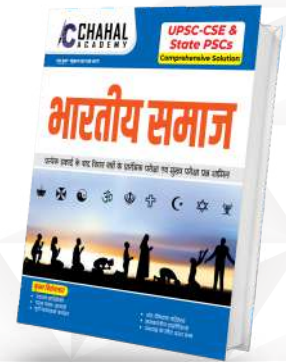
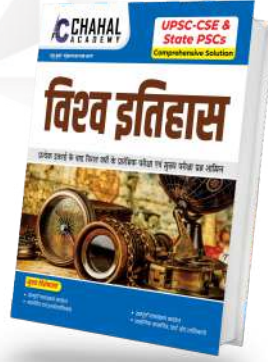
क्यूआर कोड स्कैन करें



नोट

चहल एकेडमी द्वारा ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें



किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए  9205927650



CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)

www.chahalacademy.com

Follow Us    

MRP. ₹ 120.00